Fourth Series Vol. X No.-18

Thursday, December 7, 1967
Agrahayana 16, 1889 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Third Session)

(Vol. X contains Nos. 11-20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 1.00

CONTENTS

No. 18—*Thursday, December* 7, 1967/*Agrahayana* 16, 1889 (*Saka*)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 511 to 515	5201-30
Short Notice Question No. 10	5230-37
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 516 to 536, 538 to 540	5238-51
Unstarred Questions Nos. 3256 to 3270, 3273 to 3303, 3305 to 3310, 3312 to 3342, 3344, 3346 to 3352, 3354, 3356 to 3376, 3378 to 3417, 3419 to 3465, 3465-A, 3465-B, 3465-C, 3465-D, 3465-E, 3465-F, 3465-G, 3465-H, 3465-I and 3465-J	5251-5391
Correction of Answer to U.S.Q. 753 dated 16-11-1967.	5391
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Reported Russian interference with the last General Elections in India	5392-5405
Papers Laid on the Table	5405-06
Correction of Answer to S.Q. No. 366 *Re.* Bonus for Employees of Ashoka Hotel	5407
Official Languages (Amendment) Bill and Resolution *Re.* Official Languages	5407-5534
Motion to Consider	5407-5534
Shri Y. B. Chavan	5419-21, 5447-51
Shri Surendranath Dwivedy	5473-87
Shrimati Tarkeshwari Sinha	5487-99
Shri R. R. Singh Deo	5499-5502
Shri Amrit Nahata	5502-13
Shri Jagannath Rao Joshi	5513-25
Shrimati Sucheta Kripalani	5525-34
Business Advisory Committee—	
Tenth Report	5534

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

LOK SABHA

Thursday, December 7, 1967/ Agrahayana 16, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

in

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

DEFEAT OF INDIAN NOMINEE AT WORLD HEALTH ORGANISATION

+

*511. SHRI GEORGE FERNANDES :
SHRI JAGESHWAR YADAV :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian nominee for the post of Regional Director of the World Health Organisation for South East Asia was defeated by the Ceylonese nominee at the recently held Regional Conference in Ulan Bator;

(b) whether Government are aware of the allegations made by the Ceylonese Government of the breach of faith by the Indian Government in regard to the election of the Ceylonese to the post; and

(c) if so, the substance of the allegations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) Yes Sir.

(b) No, Sir. The Government of Ceylon have not made any allegations of breach of faith against us in this matter.

(c) Does not arise.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह मामला, अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री महोदय बताना चाहते हैं, उतना मामूली मामला नहीं है । अपने उम्मीदवार की जो वहां पर हार हुई है, उस के पीछे बहुत लम्बा इतिहास है, जिस में हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बहुत बड़ी गलती है । इन्होंने जैसा कहा है कि इस में कोई ऐसी बात नहीं है, ये वास्तव में सच्चाई को सदन के सामने आने नहीं दे रहे हैं । मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि जब 1948 में डा० मणि को वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का रिजनल डाइरेक्टर चुना गया था, उस वक्त सीलोन के प्रतिनिधि को हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि पांच साल की अवधि खत्म होने के बाद अगले चुनाव में सीलोन के प्रतिनिधि का समर्थन हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि की ओर से किया जायेगा ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : I would like to tell the hon. Member that it is not true to say that at any time India had assured that India would not put up a candidate, because the point is that the post is filled not by rotation but on merit as per the resolution of the Nineteenth Regional Committee of the World Health Organisation in 1966. On election every country was to nominate a candidate. As such the Indian candidate was put up to stand on merit. But the Committee's approach was rotation which is not always good for the region. The Indian candidate happens to be the Chairman of the Executive Board of the World Health Organisation and President of World Federation of Public Health Organisations besides having other qualities for the post such as distinguished record of service to the Government of India as well as World Health Organisation. On that basis his name was nominated. I do not think there was any assurance written as per requirement of World Health Organisation that India would not put up a candidate since the present incumbent, Shri Mani, happened to be an Indian national.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब साफ नहीं आया । उन्होंने कहा है कि लिखित आश्वासन नहीं दिया है, क्या उन्होंने कोई ओरल आश्वासन दिया था ....

MR. SPEAKER : Is that his second question?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : नहीं, अध्यक्ष महोदय, वे बड़ी चालाकी से जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन नहीं दिया था, क्या कोई ओरल आश्वासन दिया था—पहले इस का खुलासा आ जाये, तब दूसरा प्रश्न करूंगा ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : My predecessor might have given an oral assurance in a casual conversation. I am not aware of it.

श्री रवि राय : यह क्या जवाब है ? आप जानते हैं या नहीं ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बयान में झूठ व्यक्त किया है ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : All I can say is that my predecessor might have given an oral assurance in the course of a casual conversation of which I have no record.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आपका मुझे स्पष्ट जवाब आना चाहिये—यह क्या चीज है ?

श्री मधु लिमये : इस से साफ जाहिर है कि ओरल आश्वासन दिया है ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या जेनेवा में चुनाव होने के पहले जब आप वहां गये, तो क्या सीलोन के प्रतिनिधि ने आपसे यह नहीं कहा था कि डा० सुशीला नैयर ने 1965 में काबुल की बैठक में हमें यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इस के पहले तीन बार जो हमने आश्वासनों को तोड़ा था, उस को इस बार हम नहीं तोड़ेंगे और 1967 में जो चुनाव होगा, उस में सीलोन के प्रतिनिधि को उम्मीदवार कर के मानेंगे ? क्या आप की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने यह सलाह नहीं दी थी कि डा० के० एन० राव को, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के दामाद हैं, खड़ा नहीं किया जाये और सीलोन को दिये हुए आश्वासन को पूरा किया जाये ? क्या आपने सीलोन के प्रतिनिधि से यह नहीं कहा कि पहले के मंत्री ने चाहे जो आश्वासन दिया हो, लेकिन चुनाव के बाद नया मंत्रीमंडल आया है और मैं नया मंत्री हूं, इस लिये पहले के मंत्री के आश्वासन से मैं बंधा हुआ नहीं हूं ?

DR. S. CHANDRASEKHAR : I would like to inform the hon. Member that when I went as the Leader of the Indian Delegation to the World Health Organisation Conference in this summer, not only the Ceylon Ambassador but also the Head of Ceylon, Nepal, Afganistan, Burmese and Indonesian delegations met me and suggested that they respectively would like to put forward their own candidates. By that time I had been assured by the External Affairs Ministry, emanating from the Geneva office of our government that the name of our Director-General Health Services was already forwarded as a nominee of the Government of India. This happened before I took charge. As such, as a Minister I was bound to support the candidate put forward by the Government of India.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । क्या इन्होंने यह नहीं कहा था कि पहली सरकार के मंत्री के दिये हुए आश्वासन से .....

MR. SPEAKER : He says that before he took over as Minister the other name was put up.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : वह ठीक है । लेकिन वहां जाने के बाद जब उन को सीलोन के एम्बेसेडर ने यह कहा कि देखिये डा० सुशीला नैयर ने 1965 में यह आश्वासन दिया है, 20 साल से हमें फंसा रखा है, इस बार मत फंसाइये—क्या उन्होंने ऐसा आपको कहा था और आपने उन को ऐसा जवाब दिया था

कि सरकार बदली है, इस लिये मैं पहले के आश्वासन से बंधा हुआ नहीं हूं ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : As I have said earlier, a number of Ambassadors and leaders of delegations from the South East Asian region met me and......

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं सीलोन के बारे में पूछ रहा हूं ।

DR. S. CHANDRASEKHAR : ...... pressed their claims, mentioning the merits of their candidates. I was bound to tell them that I am bound by the directive of the Government of India since I am a government representative.

MR. SPEAKER : The question of the hon. Member is whether the Ceylon representative referred to the assurance given by the previous Minister.

DR. S. CHANDRASEKHAR : I am not aware of any such private conversation. I do not record them.

श्री राम सेवक यादव : कैसा साफ झूठ बोला गया है !

विदेशों से सहायता

+

*512. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
महंत दिग्विजय नाथ:
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धीरे-धीरे विदेशी सहायता की राशि को कम करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जैसा कि 'तीसरी पंचवर्षीय आयोजना' में बताया गया था, आर्थिक आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि विदेशी सहायता पर निर्भर रहने को धीरे-धीरे कम करके आत्म निर्भरता प्राप्त की जाये । आयोजन का ही एक उद्देश्य होने के कारण इसे ऐसा स्वतन्त्र प्रस्ताव नहीं समझा जा सकता जिसके बारे में अलग से निश्चय करने की आवश्यकता हो ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में अथवा दूसरे विकास कार्यक्रमों में भी भारत ने जो विदेशों से सहायता ली है, अथवा कम्पनियों में समझौते के रूप में जो विदेशों का धन भारत में लगा हुआ है, उस की कुल मात्रा कितनी है और उसके सूद के रूप में भारत को प्रतिवर्ष कितना देना पड़ता है ?

श्री मोरारजी देसाई: तीसरे प्लान में अब तक जो मिला है वह धनराशि 6,006 मिलियन डालर है तथा सब प्लानों में मिलाकर आज तक 9,433 मिलियन डालर मिला है । इस के सूद की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री रवि राय : तैयार होकर आना चाहिये था ।

श्री मोरारजी देसाई : सूद के आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, बाद में दूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपना यह वक्तव्य दिया था जिसमें यह कहा था कि उस देश की आर्थिक स्थिति की इस से ज्यादा दयनीय अवस्था और क्या हो सकती है जिस देश को सूद निबटाने के लिये भी बाहर से ऋण लेना पड़े तो मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की अपनी दुर्बल आर्थिक स्थिति को सम्भालने के लिये क्या भविष्य में वित्त मंत्रालय ने कोई योजना बनाई है, अगर बनाई हो तो उस की रूपरेखा क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : शुरू में तो जो ऋण अदा करना है वह ऋण अदा करने के लिये

ऋण लेना पड़ेगा उस में तो कोई अस्वाभाविकता नहीं होती है । उस को अदा करने के लिये आखिर में जो ऋण का उपयोग हम ने किया है उस में से जो आमदनी होगी उस में से ऋण अदा किया जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

हाल में कुछ ज्यादा तकलीफें व कठिनाइयां आर्थिक स्थिति में हैं इसी लिये हम ने उन को कहा है वर्ल्ड बैंक को और दूसरे देशों को कि इस ऋण के बाद फिर से लम्बी मुद्दत दी जाये तो ज्यादा आसानी से दिया जायेगा । उस के ऊपर वे लोग सोच रहे हैं । फैसला पूरा हुआ नहीं है ।

श्री रामावतार शर्मा : अभी जैसा आप ने फरमाया कि ऋण अदा करने के लिये भी ऋण लिया जाये और भी तो उस में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हम लोगों का प्रश्न यह था कि क्या धीरे-धीरे विदेशी सहायता की राशि को कम करने का प्रस्ताव है या कोई सुझाव है, उस को अदा करने का विचार सरकार के सम्मुख है या नहीं, इस का हम को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं ने जो जवाब दिया माननीय सदस्यों ने उसे बराबर सुना नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूं या फिर मैं अपनी बात को पूरी तरह उन पर स्पष्ट नहीं कर पाया । मैंने यह कहा है कि शुरू में ऋण अदा करने के लिये ऋण लेना जरूरी होता है, बाद में जरूरी नहीं पड़ता है और मैंने यह भी बताया था कि किस तरीके से इस ऋण को हम अदा करेंगे ।

श्री शिवकुमार शास्त्री : अभी वित्त मंत्री जी जब विदेश में गये थे तो वहां पर उन की धनराशि मांगने के लिये और सूद देने के लिये कि आसानी से आप दे सकें क्या इस विषय में कुछ बातचीत हुई थी और उस का क्या परिणाम निकला ?

श्री मोरारजी देसाई : यह भी अभी बता दिया था ।

श्री शिव नारायण : देश में इस स्माल सेविंग्स स्कीम द्वारा अपने देशवासियों से कर्ज के लिये कुछ धन इकट्ठा करने का भी प्रोग्राम आप के पास है ?

श्री मोरारजी देसाई : स्माल सेविंग्स की स्कीम तो है और वह देश में चल रही है मगर सिर्फ स्माल सेविंग्स स्कीम से ही देश ऊंचा नहीं उठ जायेगा ।

श्री रवि राय : क्या मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान गया है कि जब-जब विदेशी सहायता बढ़ती जाती है, देश के विकास की दर घटती जाती है और इस के चलते हम बैंकरप्ट हो जाते हैं और जिसका कि नतीजा डीवैल्यूएशन है और जैसे कि अमरीका के कहने पर हम लोगों को अपने रुपये का मूल्य घटाना पड़ा तो उन का क्या इरादा है और कब तक यह विदेशी सहायता चलेगी ? क्या यह व्यक्तिगत देशों से जो विदेशी सहायता लेते हैं इस तरीके की उन के मन में कोई योजना है कि कोई एक वर्ल्ड डेवलपमेंट अथारिटी या विश्व विकास संस्था बनेगी और उस के जरिये यह विदेशी सहायता लायें ताकि कोई व्यक्तिगत देशों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े या हमारा जो सार्वभौमित्व है उस को फिर हम खतरे में न डालें ?

श्री मोरारजी देसाई : वर्ल्ड बैंक से भी मिलता है । वहां से हमें ऋण मिलता है और अन्य देशों से भी ऋण मिलता है, मगर ऐसा ही एक संस्था के मार्फत सारा ऋण लेना यह सम्भव नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने विदेशी सहायता न लेने के लिये ऐड फौर नो ऐड ····(व्यवधान) आप अंग्रेजी की गुलामी मत करो ।

MR. SPEAKER : Order, order. Go ahead with the question.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में जो डा० लोहिया साहब से वायदा किया था कि मैं इस के बाद में हिन्दी

में बोलने की कोशिश करूंगी तो मैं अब हिन्दी में ही यहां पर बोला करूंगी । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह विदेशी सहायता न लेने के लिये, ऐड फौर नो ऐड यह जो प्रधान मंत्री ने बोला है तो उस स्वावलम्बी अवस्था के लिये हम को विदेशी सहायता आने से रुकावट क्यों है उस का कारण क्या है और उस को ठीक करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : विदेशी सहायता हमारी आजादी को आजाद रख कर ही आती है उस को छोड़ कर नहीं आती है । उस में कोई ऐसी रुकावट नहीं है । कोई बाधा का सवाल नहीं है । आखिर को जिन लोगों के पास से हम यह लेते हैं जो हमें देते हैं उन की परिस्थिति पर हम आधार रखते हैं । हम किसी के बैंक में तो पैसा रखते नहीं हैं कि जब चाहें मांग लें और वह आशा और अपेक्षा भी हमें नहीं करनी चाहिये और उस में भी मुझे कोई शक नहीं है ।

SHRI N. K. SOMANI : Is it not a fact that, generally, the lender and the donor countries are not satisfied with the utilisation of loans and aid given to us so far—that fact has been reiterated by the World Bank—which is one of the main reasons for the decline in foreign aid to us?

SHRI MORARJI DESAI : I do not agree with the presumption of the hon. Member.

SHRI S. R. DAMANI : During the last five years, our foreign debt has increased by Rs. 2,320 crores. During this year, there is an imbalance in our exports and imports. Our exports are lower than what we import. May I know what action Government is proposing to increase our exports to meet our liability of imports?

SHRI MORARJI DESAI : This has been stated from time to time by me and also by the Commerce Minister.

श्री रामसेवक यादव : जो यह विदेशी कर्ज और विदेशी मुद्रा का संकट और आर्थिक संकट मौजूद है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या अब भी विदेशों से जो हम को कर्ज मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है उस में हम खपत की चीजें अधिक मंगाते हैं या उस की मात्रा पहले से कम हुई है और अगर कम हुई है तो वह कितनी कम हुई है ?

श्री मोरारजी देसाई : खपत की चीजें तो हम अभी नहीं मंगाते हैं । वह कम से कम होंगी, ऐसा मैं मानता हूं । जो अभी हालत है उस में मैं कहता हूं कि हम बाहर से सिर्फ कच्चा माल मंगाते हैं वह कच्चा माल जो कि हमारे उद्योगों के लिये चाहिये और जो कि यहां हमारे देश में पैदा नहीं होता है वह ही मंगवाते हैं । कुछ मशीनरी मंगाते हैं और साथ में कुछ यंत्र सामग्री, पुर्जे आदि मंगाते हैं जिनकी कि हमें जरूरत होती है और जो कि यहां नहीं बनते हैं उन को मंगवाने के अलावा और कोई दूसरी चीज हम नहीं मंगवाते हैं ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : For every developing country foreign assistance and aid is also necessary. In the context of the statement just now made by the Deputy Prime Minister that we are trying to achieve self-sufficiency and not to depend any more on foreign aid, may I know whether this will influence the thinking of the Finance Ministry and also the Government of India in the formulation of the Plan to take adequate steps not to get more foreign aid as we have been doing before?

SHRI MORARJI DESAI : This is exactly the thinking on which the Planning Commission is working and the Government of India is also working. We hope that in the course of next 8 to 10 years, we will arrive at that position. पहले जो सवाल पूछा गया था उस का जवाब देते हुए ऐसी बात रह गयी थी और वह यह कि खपत की चीजों में हम बाहर से अनाज मंगवाते हैं ।

श्री राम चरण : अभी जब वित्त मंत्री जी रीसेंटली दौरे पर गये थे तो क्या अपने सुपुत्र को भी अपने साथ ले गये थे और उस के लिये

फारेन एक्सचेंज किसी इंटरनेशनल आर्गेनाइ-ज़ेशन ने दिया था या गवर्नमेंट का खर्च किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका जवाब देना हो तो मैं दे सकता हूं ।

श्री तुलशीदास जाधव : जवाब जरूर दीजिये ताकि बात का खुलासा हो जाये ।

SHRI RANDHIR SINGH : What is this? This is very bad....(*Interruption*)

श्री तुलशीदास जाधव : जरूर इसका जबाव दीजिये ।

SHRI MORARJI DESAI : May I say that a written question has been answered a few days ago and it is before the House?

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे सवाल के दो भाग हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस साल जो आपको विदेशी सहायता मिलने का अनुमान था क्या यह ठीक है कि उतनी सहायता आपको नहीं मिलने जा रही है और अगर नहीं मिल रही है तो कितनी कम मिलने जा रही है और उसको पूरा करने के लिये आप क्या इंतजाम करने जा रहे हैं ?

दूसरा भाग यह है कि कौन-कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है कि ब्याज वे ज्यादा देर तक लेंगे या नहीं लेंगे ? ऐसे कौन-कौन से देश हैं और कितना उसका असर पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : सारी तफसील इस वक्त बताना तो मुश्किल है । अगर आप चाहें तो मैं बाद में दे सकता हूं । नहीं दे सकता हूं, ऐसी बात नहीं है । मैं दूंगा । लेकिन जो कर्ज कम मिलनेवाला है इस साल में उसकी वजह यह है कि यू० एस० में वहां के सेनेट ने जितना पैसा प्रेज़ीडेंट ने मांगा था उतना नहीं दिया है और उसको कम कर दिया है और इसी लिये वे कम देंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : कितना कम देंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो बाद में मालूम होगा । उसका पूरा पता चला नहीं है । जब बतायेंगे तब पता चलेगा कि कितना कम होगा । दो सौ मिलियन डालर कम हो जायेगा या कितना कम हो जायेगा इसको मैं नहीं कह सकता हूं । यह आंकड़ा बताना भी यह सजैस्ट करना होगा कि इतना कम हो जाये । इस लिये वह हितावह नहीं है । जितना कम मिलेगा उसके बगैर काम चलायेंगे और क्या करेंगे । दूसरों के पास मांगने जाने-वाला मैं नहीं हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : ब्याज के बारे में भी मैंने पूछा था कि किन-किन देशों ने ब्याज कम किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने शुरू में कहा है कि तफसील चाहते हो तो मैं बाद में दे सकता हूं । इस वक्त मेरे पास नहीं है । लेकिन इंग्लैंड ने जो पहले छः परसेंट ब्याज लेता था अब उन्होंने बदल दिया है । पच्चीस साल तक वह हमें कर्जा अदा करने का मौका देगा और पहले दस साल तक नहीं देना होगा और सूद बिल्कुल नहीं । यह तो इंग्लैंड ने किया है । जर्मनी ने भी कुछ तबदीली की है । ब्याज कम कर दिया है और मुद्दत बढ़ाई है । जापान ने भी कुछ कम किया है और मुद्दत बढ़ाई है । लेकिन सारी तफसील मैं नहीं दे सकता हूं ।

श्री तुलशीदास जाधव : हर वह देश जो स्वतंत्र होता है वह दूसरे देशों से पैसा ले कर अपने यहां डिवेलपमेंट करता है और उसको पैसा लेना पड़ता है । हमारे देश में भी यही चलता है । मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे देशों का जो यह पीरियड है और जो दर्जा उन्होंने लिया है उसकी तुलना में हमारे देश के पीरियड और दर्जे के प्रोपोर्शन में क्या ज्यादा अन्तर है ? क्या दूसरे देशों की तुलना में कर्जा हम ने ज्यादा लिया है और पीरियड भी कर्जा लेने का हमारे यहां ज्यादा है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस की तुलना करना तो मुश्किल है । लेकिन दुनिया में कोई

भी देश दूसरे देशों से मदद लिये बगैर बढ़ा हो नहीं है, बढ़ सकता नहीं है । हमारे देश ने दूसरे देशों से कोई ज्यादा लिया है, ऐसा मेरा मानना नहीं है ।

SHRI INDRAJIT GUPTA : At the time when the rupee was devalued, when his predecessor was in office, one of the main arguments which was put forward before this House and before the country was that this measure would help to attract a greater volume of foreign assistance. I want to know from the hon. Finance Minister whether in the subsequent period this expectation has been realised or whether there has been a shortfall in the expectation. Does he consider devaluation to be an effective method of securing or inviting or attracting further foreign aid and if so, is there any truth in the rumours which are afloat that we are in for a second dose of devaluation? Or does he consider that it has failed to attract foreign assistance?

SHRI MORARJI DESAI : I do not think that devaluation was done in order to attract a larger dose of foreign aid; at least I was not in the Government then; I cannot say what was the reason for it. But the step of devaluation was taken, devaluation was adopted, for purposes of benefiting our economy which was not in a good condition at that time. But, as I have said earlier, the good effects that were supposed to follow from this have not turned out. Any measure can be devised and can fail. In my view that is no criticism of the method at all. There are two views in this matter. Even now there are two views in the matter. I have said before that as far as it lies within my power there will be no further devaluation.

SHRI VASUDEVAN NAIR : What does that mean ?

SHRI MORARJI DESAI : That means what it means. It does not mean anything else. It only means that I shall not do it. That is the meaning of it. It does not mean anything else. But in this matter, whatever one may say will always be open to some doubts by some people because they will say that it will be done after that. Whenever it is done.....

SHRI VASUDEVAN NAIR : If the World Bank asks you?

श्री रवि राय : दबाव में आकर करेंगे ।

SHRI MORARJI DESAI : Yes, if I have to do it, I will resign and go. That is quite true. Therefore, there is no difficulty for me about it.

श्री आर्ज करनेन्डीज : चूंकि आपने अपनी किल्ली बता दी है इस वास्ते अब वे आपको हटाने का निश्चय करेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे लिये आपको निश्चित करने का मौका भी नहीं मिलेगा और न जरूरत होगी । मेरी एक मान्यता है । मेरे दूसरे जो साथी हैं उन की दूसरी मान्यता हो सकती है । इस बारे में दो रायें हो सकती हैं । इस लिये मेरे लिये दूसरों को दोष देना ठीक नहीं होगा । दोष मुझ में भी हो सकता है । मेरी बात भी गलत हो सकती है । उनकी बात सही हो सकती है । यह जो डिवैल्यूएशन हुआ है, इसके बारे में भी इकोनोमिस्ट्स की दो मान्यताएं हैं । अभी भी लोग कहते हैं कि वह जरूरी था । वे भी प्रामाणिक लोग हैं । यह मैं नहीं कह सकता हूं कि वे प्रामाणिक लोग नहीं हैं और मैं ही इस बारे में जो कहता हूं वह सही है । यह मैं नहीं कह सकता हूं । इंग्लैंड ने भी पहले कहा था कि हम नहीं करेंगे । अब उन्होंने किया । क्या करोगे उसको । अलग-अलग दृष्टि बिन्दु होते हैं । जिन का जो दृष्टि बिन्दु होता है उसके अनुसार उसको फैसला करना होता है और वैसा फैसला वे कर लेते हैं । जिनका फैसला दूसरा होता है वे अपने दृष्टि बिन्दु से उस को ठीक समझते हैं । इसी लिये मैंने आपको यह बताया है । सब के लिये मैं नहीं बता सकता हूं । सब गवर्नमेंट्स के लिये नहीं कह सकता हूं । यह मेरा काम भी नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है, हक भी नहीं है । इस लिये इस तरीके से बात करने से क्या फायदा ?

SHRI HEM BARUA : Sir, is it a fact that the Government had been forced to suspend or postpone the present Fourth

Five Year Plan due to the fact that adequate foreign assistance is not coming in spite of hon'ble Finance Minister's feelings and in spite of devaluation?

SHRI MORARJI DESAI: In the first place, I do not see how it arises from this. But I am prepared to say that the Fourth Five Year Plan is getting delayed, not because of any foreign exchange difficulty; it is getting delayed because of our own difficulties, of our own internal-resources difficulties and the conditions in the country. That is why it is getting delayed in formulation.

SHRI HEM BARUA: Our Five Year Plans mostly depend on foreign assistance.

SHRI R. K. AMIN: Has the hon'ble Finance Minister fixed any maximum limit to our foreign aid in terms of our national income and export capacity?

SHRI MORARJI DESAI: The maximum limit is the limit of our capacity to use it usefully.

SHRI BEDABRATA BARUA: It is a well known fact that the United States is generally allergic to public enterprises or enterprises run by the State. This is well known and it also came out in the case of steel plants. Will the hon'ble Finance Minister say whether there is any truth in the reports that the United States wants to advise us in regard to how we should run our public enterprises and how we should not enter into public enterprises and all that?

SHRI MORARJI DESAI: As far as I know, we have received no advice from the United States or any other Government whether to run our public enterprises or how to run them. If anybody gives that advice, well, anybody can give advice, but that advice will depend upon whether we consider that advice useful. If we consider that advice useful, then it becomes our idea; if it is not useful, we reject it outright.

श्री मधु लिमये : एक ओर तो सरकार अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या यह बात सही है कि जो सहायता हम लोगों को मिली है, उस का इस्तेमाल तत्काल और समय पर इस लिये नहीं होता है कि हमारी योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जहां हमारी योजना तैयार नहीं है वहां हम ने कोई मदद नहीं मांगी है। मगर बाहर से जो मदद दी जाती है, वह सब सिर्फ योजना के लिये दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक साल के लिये कितनी मदद देनी है, यह हिसाब कर के वे लोग मदद देते हैं। फिर अलग-अलग योजनाओं का भी हिसाब लगाया जाता है। लेकिन हर एक योजना एक साल में पूरी नहीं होती है। कुछ योजनाएं चार-पांच साल तक चलती हैं और कुछ छः साल तक चलती हैं। इस लिये जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती है, वैसे-वैसे जो मदद मिलती है, उस का उपयोग होता जाता है। मान लीजिये कि एक योजना के लिये चार साल पहले हमें 200 करोड़ रुपये की मदद मिली और वह योजना छः साल तक पूरी होगी। तो हम हर साल उस 200 करोड़ रुपये में से आवश्यक मात्रा में पैसा लेते रहेंगे और बाकी पैसा पड़ा रहेगा इस लिए इस का मतलब यह नहीं है कि हम उस का उपयोग नहीं करते हैं और नहीं कर पा रहे हैं।

अन्तर्राज्यीय नदी विवाद

*513. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदी विवादों को निपटाने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है; और

(ख) सरकार को इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सिंचाई, बाढ़ और बिजली से सम्बद्ध कई एक

महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय समस्याओं का सम्बद्ध राज्यों के बीच बातचीत द्वारा मित्रतापूर्वक समाधान हो चुका है । कुछ विवादों का समाधान अभी बाकी है । इन बाकी विवादों के मित्रतापूर्वक निपटारे के लिये प्रयत्न जारी रखे जा रहे हैं । जिन-जिन विवादों का निपटारा हो चुका है और जिन-जिन का अभी बाकी रहता है, उनमें से कुछ की जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT-1900/67]

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब नर्बदा नदी प्राजैक्ट के बारे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही एक समझौता हो चुका है और दोनों प्रदेश उस पर अमल करना चाहते हैं, तो फिर केन्द्रीय सरकार उस में क्यों बाधक बन रही है ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : I am sorry the hon. Member is not correctly informed. There is no agreement between the States concerned in regard to the development of the Narmada river, but that is what we are trying for. If there had been an agreement we would have proceeded with the development of that river rapidly. We are hoping to have a settlement shortly by discussion on the subject.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : अभी मुख्य मंत्री स्तर पर जो मीटिंग हुई थी, क्या उस में केन्द्रीय सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पर यह दबाव डाला गया था कि वह गुजरात से समझौता करें ?

DR. K. L. RAO : As I have submitted already, we are having a discussion on the 18th of this month and we hope that it will be possible to arrive at some amicable settlement.

SHRI MANUBHAI PATEL : There was an agreement between the Chief Minister of Madhya Pradesh and the Chief Minister of Gujarat, the late Shri Balwantray Mehta, that there should be a proper development of this river basin. First the agreement was signed, but afterwards that agreement was broken by one party. If there is a dispute, I could understand the Central Government stepping in because there is some provision in the Act in this behalf. But in case of failure by one of the parties to honour the agreement, what is the procedure to be adopted?

Further, during the last session, when I had put a question regarding this dispute, the hon. Minister was pleased to reply that by August this dispute would be settled but that has not happened. Now, the date is fixed as the 18th. If the talks on the 18th of this month are not fruitful, will the Central Government take some steps to implement this national project?

DR. K. L. RAO : I am not aware of any agreement between the Chief Minister of Gujarat and the Chief Minister of Madhya Pradesh. Probably, the hon. Member is referring to a signed document between the various Ministers of both the States in regard to the Narmada, but that was way back in 1963. But that was not signed by the Chief Ministers or ratified by the State Governments so, we do not recognise that as an agreement at all.

With regard to the second question, it is not possible in the case of these disputes and negotiations to fix any date. All that we can say is that we are trying our best and we are hoping that some satisfactory settlement would be reached; if both the parties approach the problem in a constructive manner and with the national point of view, it will be possible for us to arrive at some satisfactory settlement.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : नर्बदा पानी-विवाद हल करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा पुनासा बांध को पूरा करने की जिम्मेदारी ले कर मध्य प्रदेश शासन को मनाने की अन्दरूनी बात हो रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 18 तारीख को जो बातें होंगी, उन में केन्द्र केवल शर्त के रूप में ही पुनासा बांध पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा, या वाद-विवाद वैसे ही चलता रहेगा और केन्द्र पुनासा बांध को पूरा करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश को सब आवश्यक सहायता देने के लिये तैयार होगा ।

DR. K. L. RAO : The Punasa dam is the most important structure for the development of the Narmada. If the river has to be developed, Punasa has to be constructed. Punasa is located in Madhya Pradesh; naturally it is for the Madhya Pradesh Government to approach the Centre for necessary assistance the project has to be taken up as it is a very important project.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : The reply has not come : I wanted a categorical assurance that the Centre would help.

श्री देवराव पाटिल : कृष्णा-गोदावरी की समस्या बहुत दिनों से चल रही है । मुख्य मंत्रियों की बैठक भी हुई और प्रधान मंत्री के साथ भी बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तीनों स्टेट्स की डेवलपमेंट की समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्टर-स्टेट रिवर डिसप्यूट्स एक्ट के मुताबिक इस समस्या के तुरन्त हल के लिये सरकार तुरन्त विचार करेगी ?

DR. K. L. RAO : I presume the hon. Member is referring to the Narmada....

SHRI GEORGE FERNANDES : Krishna-Godavari.

DR. K. L. RAO : About Krishna-Godavari, after the last meeting of the Chief Ministers with the Prime Minister we required some data to be collected about the total water flow in the river and about the westward diversion of the water as also the crest gates in Nagarjunasagar. These are the three outstanding problems. As soon as the data are collected, necessary action will be taken.

SHRI J. H. PATEL : **

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं इस प्रश्न का हिन्दी में अनुवाद कर देता हूं । जब पिछले आठ सालों से गुलाटी कमीशन के जरिये और हर साल विभिन्न बैठकों के जरिये इस समस्या को हल करने का प्रयास करने के बावजूद भी कोई हल नहीं हो पाया, तो फिर सरकार क्यों नहीं एक ट्रिब्यूनल नियुक्त कर के उस के जरिये इस प्रश्न को हल करने का फैसला कर रही है ?

SHRI K. LAKKAPPA : He is not understanding Hindi also. I will translate it into English.

DR. K. L. RAO : I could follow the hon. Member better in Kannada than the Hindi translation of the question.

In regard to this question, we are trying to do our best. Actually in the Krishna-Godavari, no work has been held up. Nevertheless, we realise that in the best interests of the country, it should be possible to settle this dispute. That is what we are trying to do. In case this procedure of settlement by negotiation is not possible, naturally we will resort to the Inter-State River Disputes Act; then the question of tribunal will come.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह मामला आठ सालों से चल रहा है ।

SHRI M. N. NAGHNOOR : In view of the fact that both Maharashtra and Mysore have desired that the matter be settled under the Inter-State River Disputes Act, will Government give an assurance that until the matter is settled, the rights of the two States will not be prejudiced ever since the time they raised the issue that is 1960-61? Also, is it a fact that the Government are not clearing the project and that they are delaying financing the project which ought to be treated as a national project ? Under the circumstances, will the Government assure us that the rights of these two States will not be prejudiced since the year 1960, and that no new rights will be created?

DR. K. L. RAO : I am sorry the hon. member is not correctly informed . I think I can give the information for the sake of the hon. House that in the last seven years practically no project was sanctioned in Andhra Pradesh except two or three small tanks.

SHRI KAMALANATHAN : Regarding the Hogenekal power project, there is a dispute between Madras and Mysore Governments. May I know whether the Central Government has taken any action

**Spoke in Kannada.

regarding this to settle this matter and come to an agreement?

DR. K. L. RAO: Actually, there is no dispute as such between Mysore and Madras regarding this project. We are trying to understand the significance of this project, and we are having discussions about it on the 30th December.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: May I know from the hon. Minister if, for the settlement of water disputes, he would advise settlement on an *ad hoc* basis, or he would consider the catchment area, the total water supplied by the States, the command area and the culturable area of the basins?

DR. K. L. RAO: There is an Act passed under the Constitution called the Inter-State Water Disputes Act, and if the Government of India is satisfied that a solution is not possible by negotiation, we will resort to that.

SHRI K. LAKKAPPA: In these long-standing problems among various States regarding river waters, negotiations have completely failed. In view of that failure, may I know whether this Government will invoke the provisions of article 262 of the Constitution, or whether the matter will be referred to a Board, and whether this Government will take an early decision or fix a time-limit for the solution of these disputes? What is the reaction of this Government?

DR. K. L. RAO: For a big country like India where there are a large number of inter-State rivers, probably it has the largest number, the number of disputes is very small. In fact, it is very creditable that in this country there are only two outstanding problems. I do not agree, therefore, with the hon. member that there has been any question of inter-State disputes in this country. These two problems we are trying to settle.

श्री नाथूराम अहिरवार : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को इस बात पर बाध्य कर रही है कि पुराना बांध हम तभी पूरा करेंगे जब मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार जितना पानी चाहती है उतना पानी उस को देने के लिये तैयार हो जाये ?

DR. K. L. RAO: Naturally, when any project is being sanctioned on an inter-State river, settlement has to be reached between the States concerned. If the Punasa dam is delayed, it is no doubt due to this lack of agreement.

SHRI TENNETI VISWANATHAN: In view of the continuous deficit in food production and our food scarcity, is it not possible for the Government to delink the food production problem with the permanent solution of this sharing of waters, that is to say satisfy the claims in terms of food supplies, allow the water to go where it can be usefully utilised for increased food production and, in respect of the claim of share, give them the paddy which is produced?

DR. K. L. RAO: It is a suggestion.

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि गांधी सागर डैम से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को आधा-आधा पानी देने की योजना थी लेकिन सन् 66 में मध्य प्रदेश के ज्यादा पानी ले लेने से राजस्थान की फसलें सूखी रह गईं, तो क्या अब भी यही हाल रहेगा या दोनों को बराबर पानी देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? क्या इसी तरह से मध्य प्रदेश आगे भी ज्यादा पानी लेता रहेगा ? नहीं तो, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी और सरकार ने उस के लिये क्या किया है ?

DR. K. L. RAO: The Gandhisagar dam project is one of the very good projects in this country where there has been complete agreement between Madhya Pradesh and Rajasthan. Having regard to the water distribution last year and this year, we have drawn up an elaborate schedule at the centre by which the water is distributed between these two States. If there is any difficulty of which the hon. Member is aware, he can kindly write to us and we will take action.

SMUGGLING OF RAW JUTE

+

*514. SHRI BABURAO PATEL :
SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH :
SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI :
SHRI MAYAVAN :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI Y. A. PRASAD :
SHRI N. K. SANGHI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the quantity and cost of raw jute smuggled daily from Purnea to the Nepal border because of better prices offered by dealers at Biratnagar in Nepal;

(b) whether Police is posted on the Bihar-Nepal border to detect such crimes;

(c) whether this smuggling has affected the raw jute industry in India and if so, to what extent; and

(d) the steps taken by Government to stop this smuggling?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) There have been some reports of smuggling of jute from India to Nepal because of better prices offered by dealers in Nepal. It is not possible to estimate precisely the actual quantity and cost of raw jute smuggled from Purnea to Nepal.

(b) There are police check-posts at certain places on the Bihar-Nepal border, but no police has been posted exclusively to detect smuggling of jute.

(c) As far as the Government are aware, the smuggling of raw jute from India to Nepal has not affected the jute industry in India.

(d) All preventive and intelligence formations on the border have been alerted and additional Central Excise preventive staff have been deployed for this purpose in Bihar and West Bengal areas adjoining the border.

SHRI BABURAO PATEL : Is it a fact that because we have withdrawn our export incentive scheme, smuggling has stepped up in this area and because Nepal is offering 70 per cent as export incentive most of the jute merchants from Calcutta are dealing in smuggling?

SHRI MORARJI DESAI : No, Sir.

SHRI BABURAO PATEL : In that case, I would like to know whether the Government intends to take serious steps about finding out from some of these merchants who have been obtaining good prices and collecting money in the black market in Nepal.

SHRI MORARJI DESAI : If the hon. Member gives me the information which is in his possession, I shall be obliged to him and I shall take steps.

SHRI BABURAO PATEL : It is the duty of the Government to find out.

SHRI MORARJI DESAI : This is what I am performing—asking the hon. Member.

श्री महाराज सिंह भारती : जैसा कि मंत्री जी ने बताया, नेपाल में कुछ ज्यादा अच्छी कीमत की वजह से स्मगलिंग थोड़ा हुआ है, मैं यह जानना चाहूंगा कि सूखे के दो सालों में हम को पटसन की कुछ जरूरत पड़ी तो हम ने मेस्ता थाईलैंड से और इसी नेपाल से पटसन मंगाया था तो क्या यह सच नहीं है कि पटसन की पैदावार में जो हाई क्लास का बढ़िया पटसन है उस की कीमत इतनी कम यहां रखी गई है कि जिस नेपाल से हम पटसन खरीद रहे थे उसी नेपाल के माध्यम से वह विदेश जा रहा है और सरकार ऊंचे किस्म के पटसन की कीमतों को मुनासिब दाम पर ऊंचा करने के लिये और जितनी तादाद में वह पैदा हुई है उतनी बड़ी तादाद में खरीदने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बात सही नहीं है कि उस को खरीदने के लिये आज प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । प्रयत्न कर रहे हैं । मगर कितना भी करो कुछ न कुछ स्मग्लिंग तो होती ही रहेगी । हमारे यहां भी पाकिस्तान से कुछ आ जाता है । यहां से कुछ वहां चला जाता है । स्मग्लिंग को रोकने के लिये हर दम कोशिश करते रहना है और उस को कम से कम करने के लिये प्रयास करते रहना है । वह हम कर रहे हैं ।

श्री हरदयाल देवगुण : श्रीमन्, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह पटसन, दालें और जो चीजें यहां से बाहर जाती हैं जिन के बारे में बार-बार पूछा गया है इन का और चीन से जो माल आता है इन का क्या संबंध है और इस सारी स्मगिलंग को रोकने के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है । हर एक प्रश्न में बता दिया जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं । लेकिन एक-एक कर के यह मालूम होता है कि स्मगिलंग बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है । अगर नहीं कर रही है तो त्यागपत्र दे दे ।

श्री मोरारजी देसाई : त्यागपत्र मांगने का सम्मानित सदस्य को सब जगह तो अधिकार नहीं है । यह हाउस का जरूर है·····

श्री हरदयाल देवगुण : यह हाउस में ही मांग रहे हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : अकेले मांगने से कुछ नहीं होगा·····

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम भी साथ में हैं·····(**व्यवधान**)·····

श्री मोरारजी देसाई : आप चार-पांच, पचास मांगेंगे तो भी कुछ नहीं होता । मेजारिटी मांगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा ।

मैंने डी में इसकी तफसील दी है । सम्मानित सदस्य उस को सुनते नहीं हैं तो हम क्या करें ?

जापान के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

*515. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के उद्योग मंत्री ने केरल में उद्योग स्थापित करने के लिये जापान की कुछ फर्मों के साथ करार करने के उद्देश्य से हाल में जापान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस की अनुमति दी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या रवैया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). हालांकि यात्रा की अनुमति उन प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये दी गई थी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार सिद्धान्त रूप से मंजूरी दे चुकी थी, लेकिन अनुमति देते समय यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि तकनीकी सहयोग की शर्तों के अन्तिम रूप से तय किये जाने से पहले, इनके लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होगा और सारी बातचीत इस शर्त के साथ की जानी चाहिये ।

श्री मोहन स्वरूप : आज देश में प्रवृत्ति इस तरह की हो रही है कि चारों तरफ अलगाव की भावना बढ़ रही है । यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है—इस के पहले भी एक बार पैरादीप पोर्ट के सिलसिले में जापान ने यहां की सरकार के साथ बात की थी, अब फिर इस तरह की बात सामने आई है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि इस तरह से राज्यों को स्वतन्त्रता दे दी जाये कि वे अपनी तरफ से बाहर के देशों से बात करें—क्या यह देश के लिये घातक सिद्ध नहीं हो सकता है ? इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये आगे क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : उन को जिन शर्तों पर बात करने की अनुमति दी गई थी, वह अभी बताई गई हैं । यदि इन शर्तों पर उन्होंने बात नहीं की और दूसरी बातें की होंगी, तो इस से नुक्सान उन मंत्री को होगा, राज्य को नहीं होगा ।

श्री मोहन स्वरूप : मैंने पूछा था कि भविष्य में इस के लिये क्या रोकथाम करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कहा है कि उन को माना नहीं जायेगा । यही उसकी सब से बड़ी रुकावट होगी, इस के लिये और दूसरी रुकावट क्या चाहिये ?

श्री मो० प्र० त्यागी : जापान ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, अपने यहां छोटे उद्योगों को अधिक महत्व दिया है । भारतवर्ष की भी यही समस्या है, क्या इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जापान के इस अनुभव का लाभ उठाने की चेष्टा की है कि यहां भी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय ?

श्री मोरारजी देसाई : उस का भी ध्यान किया जाता है और इस सिलसिले में भी कुछ न कुछ काम किया गया है ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The hon. member, Shri Mohan Swarup, put a very fundamental question, whether the State Governments, may be with the permission of the Central Government, can carry on negotiations with foreign governments for collaboration and aid. May I know whether this is in consonance with the federal character of our Constitution and this will not lead to disintegration of the country and, if so, whether Government is going to lay down a firm policy to see that whatever negotiations are to be carried on with foreign countries, they are carried on by the Central Government alone ?

SHRI MORARJI DESAI : I have already explained that these negotiations which are carried on by any State minister can be carried on only within the limits of the permission given by the Government of India. Any other negotiations which are carried on by them will be invalid and no action will be taken on them. They cannot make anything final.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : But you allow them to go and negotiate.

SHRI MORARJI DESAI : Yes; we allow them to go out only for schemes which have been agreed to by the Government of India and not for other schemes.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : You can send your representative.

SHRI MORARJI DESAI : If private parties can negotiate with other private parties in foreign countries with the approval of this Government, I do not see why State Governments cannot carry on negotiations with another Government within the limits prescribed for that. Surely, the State Governments should not have less rights than a private individual.

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री अभी जापान गये थे, उस समय क्या कुछ ऐसी बातें हुई थीं कि जापान की कुछ प्राइवेट और सरकारी फर्में इस बारे में इन्टरस्टेड हैं कि हमारे देश में कुछ उद्योग लगायें ? यदि हुई थीं, तो सरकार की उन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने किसी खास उद्योग के लगाये जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, मैंने तो यह प्रयत्न किया कि जिससे हमारे सामान्य सम्बन्ध अच्छे बनें, और वहां के लोग यहां आना चाहें, तो आयें । यही बात हुई थी, किसी खास उद्योग के बारे में बात नहीं हुई थी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे उप-प्रधान मंत्री के इस उत्तर को सुन कर ताज्जुब हुआ । जो काम प्राइवेट कम्पनीज़ कर सकती हैं, उस को करने के लिये मुख्य मंत्री को छूट क्यों नहीं होनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि प्राइवेट पार्टियां केवल कम्पनी को बांधती हैं, जब कि मुख्य मंत्री अपने प्रदेश के शासन को बांधता है, कुछ हद तक देश को बांधता है । उप प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम जो शर्तें तय करते हैं, उन शर्तों के आधार पर वह समझौता कर सकते हैं । अगर उन शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे तो वह समझौता नहीं माना जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उप-प्रधान मंत्री यह स्वीकार नहीं करते कि इस तरह से—वह समझौता कर के आये और फिर उस को न माना जाय—देश के सामने कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं ? क्या यह सम्भव नहीं है कि जब इस तरह मुख्य मंत्री बातचीत करने के लिये जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि या वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि भी उन के साथ जाये ताकि इस तरह से भविष्य में कोई कठिनाई पैदा न हो ?

श्री मोरारजी देसाई : जो शंका सम्माननीय सदस्य ने उठाई है, वह शंका हो सकती है। परन्तु मुख्य मंत्री तो नहीं गये थे, यहां तो उद्योग मंत्री गये थे। अब उद्योग मंत्री जायें और उन के साथ किसी को भेजें....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन की मदद के लिये भेजें।

श्री मोरारजी देसाई : अगर उन को जरूरत हो तो भेजें, लेकिन वह मदद न मांगे तो क्यों भेजें। जब ऐसी हालत मालूम होगी कि उन्होंने शर्तों के बाहर कुछ किया है, तो हम उस को नामंजूर कर देंगे, और दूसरी बार उन को नहीं भेजेंगे।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Mr. Speaker, Sir, as far as Kerala is concerned neither private industrialists go there to start industries nor the Government of India sanctions more industries for Kerala. I would like to ask, when private persons, as agreed to by the hon. Deputy Prime Minister, negotiate with foreign firms, go abroad and bring some contracts and the Government of India gives clearance for starting those industries, what is the harm in permitting the State Government to set up small-scale industries, to solve the unemployment problem, beyond the Five Year Plan and with the clearance of the Government of India ?

SHRI MORARJI DESAI : Where have I objected to it ? If they can find money they can start anything they like.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Will you be standing in the way if they get any foreign loan from governments of other countries ?

SHRI MORARJI DESAI : I shall certainly prevent them from doing so if they do so without my approval.

SHRI S. KUNDU : Sir, of the many visits abroad of the Deputy Prime Minister, one was to Japan. In the statement laid before the House he has said that he met some businessmen in Japan and also some politicians. He has further said that the meeting was useful. I would like to know precisely whether there were any concrete business projects with collaboration drawn up during his visit and meeting with businessmen and politicians in Japan ?

SHRI MORARJI DESAI : I have said very clearly that no such specific proposals were ever considered or discussed. There was therefore no question of any finalisation. It was only in general terms that discussion took place. They wanted to understand several policy matters and conditions in this country. I wanted to understand what was going on there and what was troubling them. They wanted to know what was troubling us. These are the things which we discussed and on which we had an understanding.

SHRI S. S. KOTHARI : What is the Government's attitude to collaborations in small and medium scale industries with Japanese counterparts just as they have in large-scale industries ?

SHRI MORARJI DESAI : The same policy will apply. If the collaboration is necessary and useful, it will be allowed.

SHORT NOTICE QUESTION

बरौनी तेल शोधक कारखाने के इंजीनियर

SNQ 10. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने ने अपने तेल शोधक कारखाने के निर्माण खण्ड में काम करने-वाले ३५ इंजीनियरों को छंटनी का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छंटनी किये गये इंजीनियरों में कितने इंजीनियर बिहार के हैं तथा कितने अन्य राज्यों के ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केवल एक फालतू इंजीनियर की हाल ही में छंटनी की गई है, जो मैसूर राज्य से था ।

But I may, with your permission, add that although retrenchment notices have not been served, about 48 engineers and assistant engineers are likely to become surplus during 1967-68. We are trying to provide alternative employment to as many as possible, failing which retrenchment will become inescapable.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, यह 35 इंजीनियर्स जो पहले भी गोहाटी में काम कर चुके हैं और उसके बाद बरौनी में उन्होंने काम किया है उसके बाद भी उन लोगों की अब छंटनी होने जा रही है तो उसका जवाब मंत्री जी ने यह दिया है कि उनको अन्यत्र खपाने का वह भविष्य में इंतजाम करेंगे तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब तक वह उनका इंतजाम करने की हालत में होंगे तब तक वह अपने काम से हटाये नहीं जायेंगे क्या इस बात का स्पष्टीकरण मंत्री जी करेंगे ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : How is it possible ? These people were employed for this specific purpose of construction. In fact, they should have been retrenched as soon as the second million Barauni plant was commissioned. But, because of the working of the third million plant they were kept, and we are trying to absorb them in our other installations. But if we cannot, what is the alternative ?

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया है । मेरा कहना है कि यह 35 इंजीनियर्स गोहाटी रिफ़ाइनरी में काम कर चुके हैं उसके बाद अभी बरौनी में काम पूरा किया है तो अब हलदिया में जो नया कारखाना शुरू होने वाला है वहां के लिए नई बहाली की क्या जरूरत है और क्यों नहीं लगातार इन्हीं लोगों को हलदिया के लिए भी रख लिया जाता ? आखिर सरकार को इस तरह का ऐलान करने में क्या दिक्कत है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : So far as the Haldia refinery is concerned, when it is going to be constructed it is going to be done by Engineers (India) Limited, who have their own engineers. Even so, we hope to absorb some of them in Haldia and some of them in other installations. Probably 11 of them are likely to be absorbed. The rest of the name we have forwarded to the various public sector undertakings and also certain other institutions for likely absorption.

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि बरौनी तेलशोधक कारखाने में यह जो इंजीनियर्स लोग हैं उनमें बहुत असन्तोष है और वह असन्तोष इस बात को लेकर है कि उनको नाजायज ढंग से काम से अलग किया जा रहा है और उन्होंने मांग की है कि इस बात की एक निष्पक्ष जांच की जाये ? जहां तक उनकी शिकायत का सवाल है उनकी शिकायत वहां के मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट के लोग पक्षपात की वजह से भाई-भतीजावाद की वजह से ऐसे लोगों को नाजायज ढंग से रख रहे हैं और उनको प्रमोशन दे रहे हैं जिनकी कि उपयुक्त क्वालिफिकेशन भी नहीं है और इस सिलसिले में क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि वहां पर जो 4 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, श्री एस० के० कानूनगो, ए० सी० आहूजा, के० के० मदन और वाई० के० मुर्दू, यह चारों व्यक्ति रैक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं । वहां पर रैक्विजिट क्वालिफिकेशन जो इन इंजीनियर्स के लिए है और जो कि हम लोगों को कारपोरेशन से जवाब में इत्तिला मिली है वह यह है कि इनको ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग का ऐक्सपीरिएंस होना चाहिए लेकिन उन चारों में से कोई भी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट नहीं है, फिर भी उनको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया है जब कि ऐसी जो रैक्विजिट क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको या तो डिस्चार्ज किया जा रहा है या काम नहीं है जब कि भाईभतीजावाद के आधार पर दूसरों की भरती की जा रही है हालांकि वह उतने क्वालिफ़ाइड भी नहीं हैं और इस के लिए वहां के इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों की जो एक मांग है कि वहां पर एक निष्पक्ष जांच की जाये ताकि यह जो

बदइंतजामी है, पक्षपात है, मनमानी है और कानूनों का उल्लंघन है उसको दूर किया जा सके और इस तेलशोधक कारख़ाने को ठीक तरीक़े से चलाया जा सके तो उसके लिए मंत्री जी को क्या कहना है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : The hon. Member has made many statements which are not quite necessarily relevant to the point at issue. If there are undue promotions and favouritism shown, he may forward to us those cases and we will look into them. So far as retrenchment goes, I have satisfied myself—I have got here a list of people likely to be retrenched—that retrenchment is going to be generally in the order of seniority except that where an officer is acting in an officiating position he will be reverted to his permanent position or where he is a specialist. On the other point I have no information; he can write to us.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : Is the hon. Minister aware that many of the Indian engineers who have gone outside India for acquiring higher qualifications in chemical engineering are feeling discouraged to come back to India because of the dismal nature of employment facilities offered to them ? Secondly, in view of this state of things, is he prepared to prepare an integrated plan in consultation with the Planning Commission to provide employment for these people ?

MR. SPEAKER : This is about Barauni. You, are going into the all-India problem. If you have something to ask about Barauni, you can.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : Let him answer the first part of the question; I shall be satisfied.

SHRI S. M. BANERJEE : In reply to the question of Shri Yogendra Sharma, the hon. Minister of State, Shri Raghu Ramaiah, stated that he had satisfied himself that retrenchment will be on seniority-juniority basis. I would like to know whether he has received any complaint that those engineers who were recruited later on, and who are junior actually, were promoted, before the senior engineers were promoted, just to retain them which involves favouritism and nepotism. Has he satisfied himself about that; if not, will he investigate this ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I do not personally remember to have received any such complaint myself. Whether there is any complaint received in the office which has not come to my notice is a matter to be ascertained, if a proper notice is given.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : May I say, Sir, that no complaint to that effect has been received from any Member of Parliament by us ?

SHRI S. M. BANERJEE : We are not dealing with it. . . (*Interruption*).

MR. SPEAKER : He says, they have not received any.

श्री भोगेन्द्र झा : हम लोगों ने मेहता साहब से इस बारे में बातचीत की है, उन्हें बतलाया है कि इस मामले में गड़बड़ियां हुई हैं और उस सम्बन्ध में जांच की जाय तो हमें उन्होंने यह जवाब दिया था कि हम जवाब वहां से मंगा रहे हैं और उसके आने के बाद हम उसमें देखेंगे . . .

SHRI ASOKA MEHTA : When the hon. Member came and saw me I said, I have not received this memorandum. He said that these engineers had drawn up the memorandum for the Government of Bihar and I said that if the Barauni Refinery had got a copy of it I would get a copy and look into it. If they have sent it directly to the Government of Bihar, I have no access to the Government of Bihar. So, I requested the hon. Member to find out if the engineers had sent it directly to the Government of Bihar and to get a copy and send it to me. I am sure, the hon. Member will bear me out that this is what I told him.

SHRI YOGENDRA SHARMA : They have no access to the Bihar Ministry, but they have sent it to the Oil Corporation which is under the Ministry.

MR. SPEAKER : He has made it very clear.

SHRI HEM BARUA : This problem of discarded engineers arose at the Gauhati

Refinery also when the construction was over there and the problem was solved to a certain extent by absorbing them in the Barauni Refinery construction work. Since these engineers are sufficiently experienced people—they worked both at the Gauhati Refinery construction work and at Barauni also—why is it that Government have not drawn up a plan to absorb them when the construction work of the refineries is over ?

SHRI ASOKA MEHTA : Unfortunately, refinery construction is not determined only for the purpose of finding jobs for engineers; there are many other considerations. As far as the Haldia Refinery is concerned, the construction period will be reached only after 18 months. During that period I cannot have people merely for the purpose of finding them jobs. Secondly, it has been pointed out that the Haldia Refinery is being undertaken by the Engineers India Limited. They have got their own staff also. Whatever additional people are neeed, my colleague made it very clear, in the light of the experience that these people have, naturally every attempt will be made to take advantage of their experience and expertise. But here is no way whereby I can say that even when their services are not needed, they will be retained.

SHRI HEM BARUA : My question is not replied to. I just wanted to know whether these engineers who are now discarded and thrown out in the streets will be absorbed in the plants themselves. When the Minister stated that Haldia Refinery construction work could start only after 18 months, are we to understand that after 18 months, these engineers are going to be absorbed at Haldia ?

SHRI ASOKA MEHTA : It may or may not be; some may be absorbed and some may not be absorbed. The Engineers India Ltd. also have their own complement of engineers who are doing this work. I am sure the hon. Member knows all very well.

SHRI INDRAJIT GUPTA : The hon. Minister said a little while ago that if they have to be retrenched, then all attempts will be made to absorb them in other refineries or other public sector projects. This kind of assurance is always given at the time of retrenchment now-a-days. I would like to know whether, as a matter of fact, those engineers or other skilled workers who have already been declared surplus to requirements at Barauni during the entire period of construction, as the construction went on, and have been retrenched, have been absorbed anywhere else or they are walking in the streets ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : So far as my present information goes, only one man was recently retrenched. Otherwise, either they were permanently absorbed or voluntarily retired. I would like to have confirmation of this.

SHRI HEM BARUA : What does voluntary retirement mean ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I meant they have gone out voluntarily.

श्री महाराज सिंह भारती : जो प्राइवेट कम्पनियां निर्माण कार्य करती हैं उनके अपने कारखाने नहीं होते हैं और वे इसी सरकार से और दूसरों से ठेके ले कर अपने इंजीनियरों को लगातार काम देते रहती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारी योजनायें चल रही हैं, इतने कारखाने बनते हैं और वे कारखाने चलते भी जाते हैं तो क्या आप कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर सकते हैं कि लगातार उनको काम देते रह सकें ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : As I said, in this case, we have made a reference to the Bokaro Steel Plant, the Hindustan Steel Plant, the Hindustan Steel Construction, the Triveni Structurals Ltd., the Fertilizer Corporation and various other public and private undertakings.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : May I know from the hon. Minister, in view of the answer given by him that engineers who are engaged in the construction of the Refinery are not suitably to be absorbed in the working of the refinery as such, whether this will be a permanent feature of shifting the engineers after the construction work is over from place to place and, if so, what are the arrangements that Government propose to make for

giving a sort of orientation course by which they could be absorbed in the refinery itself ?

SHRI ASOKA MEHTA : I find it difficult to understand. The construction people do construction work. There may be periods when no construction is going on. Normally, there are all kinds of construction work going on. They are qualified construction engineers with experience and in the construction of refineries, their experience will be useful. Certainly, they will be absorbed wherever construction work is carried on. I cannot use construction engineers for the purpose of production, that is, for producing refinery products. That is a different job. Different Kinds of skill are needed there. Therefore, we are making every effort to see that these gentlemen are absorbed in other construction activities that are being carried on. I am sure, if they are absorbed, somebody else will be left out. We are equally concerned with the employment of all our young engineers, not merely for 'A', 'B' or 'C'.

श्री हुकम चन्द कछवाय : बरौनी तेल शोधक कारखाने के अन्दर तथा अन्य तेल कारखानों के अन्दर जिन इंजीनियरों की नियुक्ति होती है क्या उनकी नियुक्ति करते समय आप यह शर्त लगाते हैं कि कारखाने का निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद आप चाहेंगे तो उनकी छंटनी कर देंगे ? यदि यह शर्त रखते तो इस शर्त के खिलाफ क्या इन इंजीयिनरों द्वारा कोई आपत्ति की जाती है और कोई आपत्ति आज तक की गई है ? यदि हां, तो कौन-सी आपत्ति अब तक की गई है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : When an engineer is appointed for construction work, he is made to understand and told that he is only for construction work. There is no doubt about it.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

National Policy on Banking

*516. SHRI D. C. SHARMA :
SHRI BIBHUTI MISRA :
SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI R. K. AMIN :
SHRI SHARDA NAND :
SHRI SHRI CHAND GOEL :
SHRI AMRIT NAHATA :
SHRI N. S. SHARMA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have framed any national policy on banking; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). It is proposed to bring about social control over banks through legislation and administrative action. The proposals include the setting up of a National Credit Council for the better alignment of credit policies with developmental needs and certain measures for further tightening of the supervision over banks in certain respects. The detailed proposals will be placed before Parliament soon.

Deficit Financing

*517. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY :
SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the total State budgets deficit for 1966-67 was about Rs. 120 crores in spite of Central assistance of Rs. 256 crores; if so, the reasons therefor;

(b) whether this deficit is likely to increase in future and if so, by how much;

(c) whether it is a fact that as a consequence of this recurring annual deficit in the State budgets and its anticipated rise in future, the States will not be able to repay their debt-instalments to the Centre and this in result will affect national economy; and

(d) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The State Budgets (Revised Estimates) for 1966-67 showed a total deficit of Rs. 81.23 crores in eleven States. These estimates take into account receipts of *ad-hoc* loans from the Centre amounting to Rs. 108 crore (net) given to seven States to enable them to repay their overdrafts. The deficits arose because State Governments undertook commitments which were in excess of the resources available.

(b) The latest appraisal of State Budgets indicates that, on the basis of present commitments, thirteen States may have deficits during the current year on their budgetary transactions. However, it is not possible, at the present stage, to anticipate the exact amount of the deficit or the order of increase, if any, relative to 1966-67.

(c) To the extent that any State Government is unable to take steps to avoid recurring annual deficits, it would find it difficult to meet all its commitments including the repayment of Central loans. Since the Central resources take into account the repayments due from the States, any default' in this regard would affect the national economy.

(d) All the State Governments have been advised to restrict their expenditure to the resources clearly in sight.

RETRENCHMENT OF STAFF BY FOREIGN OIL COMPANIES

*518. SHRI K. M. ABRAHAM :
SHRI P. P. ESTHOSE :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI UMANATH :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the foreign oil companies are propagating that Government's oil policy and activities of the Indian Oil Corporation are responsible for their staff being declared surplus;

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) The Gokhale Commission of Inquiry appointed by the Government of India is examining the above views and other cognate matters.

ALLOCATION FOR TRIBAL WELFARE

*519. SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI C. K. CHAKRAPANI :
SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a cut in the Central allocation for the tribal welfare for the current year;

(b) if so, the reasons therefor and the amount allotted for the tribal welfare for the current year;

(c) whether Government propose to increase the financial assistance for tribal welfare work;

(d) if so, when; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) No.

(b) Does not arise; Rs. 7.94 crores.

(c) An effort is being made.

(d) and (e). The matter is under consideration.

FAMILY WELFARE PLANS

*520. SHRI MARANDI :
SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI S. M. BANERJEE :
SHRI S. C. BESRA :

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Society Welfare Board in a draft programme for the Fourth Plan has suggested new pattern for family welfare plans; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) No new pattern for family welfare plans was suggested by the Central Social Welfare Board.

(b) Does not arise.

LOSS IN PRODUCTION OF OIL DUE TO STRIKE IN OIL AND NATURAL GAS COMMISSION

*521. SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI N. K. SANGHI :
SHRI D. N. PATODIA :
SHRI Y. A. PRASAD :
SHRI BEDABRATA BARUA :

Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether as a result of the strike in the Oil and Natural Gas Commission, there had been any fall in the production of oil and gas; and

(b) if so, the loss sustained as a result of the strike ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SURVEY OF GULF OF CAMBAY FOR OIL EXPLORATION

*522. SHRI MAYAVAN :
DR. RANEN SEN :
SHRI RAJDEO SINGH :
SHRI DEORAO PATIL :

Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the final report of the seismic survey conducted by the Soviet experts to explore oil deposits in the Gulf of Cambay has been received by Government; and

(b) if so, the main recommendations thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) The report has been received by the Oil & Natural Gas Commission on 14-11-67.

(b) Further seismic serveys to cover the structures that have been discovered but not surveyed in detail and regional seismic survey to cover the area south of Bombay and the area southwest of the Kathiawar Peninsula, have been recommended. Deep exploratory drilling on one of the structures that has already been surveyed in detail, has also been recommended.

COMMITTEE TO EXAMINE ORGANISATIONAL CHANGES IN PUBLIC SECTOR FERTILIZER UNITS

*523. SHRI C. JANARDHANAN :
SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI P. GOPALAN :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRI S. C. BESRA :

Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have appointed a Committee to examine the possibility of organisation changes in the public sector fertilizer units;

(b) if so, the personnel of the Committee; and

(c) its terms of reference ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) Yes, Sir, A Study Team has been appointed.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1901/67]

EXCHANGE VALUE OF RUPEE

*524. SHRIMATI TARKESHWARI SINHA :
SHRI PASHABHAI PATEL :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the value of rupee in the foreign market is below its official value of exchange;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether this will lead to a further devaluation of the rupee in the future ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The value of the Indian rupee in foreign markets is below its official value of exchange only in respect of those quotations which relate to marginal transactions which are illegal and unauthorised. These transactions have limited economic significance.

(c) No, Sir.

राज्यों द्वारा विदेशों के साथ सहयोग करार किए जाना

*525. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा सहयोग तथा वित्तीय सहायता के लिये विदेशों से सीधे बातचीत किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकने वाली कठिनाइयों पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन लाने का सरकार का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मौजूदा कार्य-विधि के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को, सहयोग और वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना अन्य देशों के साथ सीधी बातचीत करने का अधिकार नहीं है।

ALLOTMENT OF LAND TO LAND LESS TILLERS

*526. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 965 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether Government have since taken any decision on the question of allotment of land to the landless tillers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). Draft Rules for allotment of land to landless tenants and others in Rajasthan Canal area are being revised by the Government of Rajasthan in the light of the comments received from the Governments of Punjab and Himachal Pradesh. Revised Rules are awaited from that Government.

INDIAN OIL CORPORATION

*527. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the total volume of the present business of the Indian Oil Corporation;

(b) whether public sector undertakings have been instructed to give preference to the Indian Oil as a matter of policy; and

(c) if so, the extent to which these instructions have been complied with ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) The current monthly sales of the Indian Oil Corporation are about 5 lakh kiloliters of various petroleum products.

(b) The public sector undertakings have been requested to make their purchases of petroleum products from the Indian Oil Corporation to the extent to which the latter is able to meet the demands, subject to the terms offered by the Corporation being competitive.

(c) There are reasons to believe that Government's request is being generally observed.

परिवार नियोजन की योजनाएं

*528. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री मीलचन्द गोयल :
श्री शारदा नन्द :
श्री न० स्वा० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर अब तक कितनी धन राशि खर्च हो चुकी है तथा चालू वर्ष में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और ये लक्ष्य कहां तक पूरे हुए हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) इस सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या 1902/67]।**

(ख) लूप कार्यक्रम के लक्ष्य 1965-66 से निर्धारित किये गये थे और लूप तथा नसबन्दी दोनों योजनाओं के लिए 1966-67 से निर्धारित किये गये थे। एक और विवरण भी सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें इन लक्ष्यों और 10-11-67 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 1965-66, 1966-67 और 1967-68 की अवधि में प्राप्त सफलताएं दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या —1903/67]।**

PESTICIDES

*529. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a study conducted by the National Council of Applied Economic Research, India will require 344,000 tonnes of pesticides to save the annual loss of 20% of the farm products every year;

(b) whether it is also a fact that according to the present rate of production of pesticides, it will take nearly 15 years to come up to the required production level; and

(c) if so, the measures Government propose to take to meet the demand of pesticides ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) Yes Sir. The calculation is based on the assumption that every area can and will be covered by the recommended package of plant protection practices.

(b) and (c). No, Sir. It would be realistic to relate the required level of production to the level of estimated effective demand from time to time. All efforts are being made to increase the production of pesticides in the country so as to meet the target of covering 210 million acres by 1970-71 with about 84,000 tonnes. Industrial licences have accordingly been issued to a number of parties to set up units to produce various pesticides. Till these units go into full production the gap between demand and supply will be met through imports.

RETAIL OUTLETS COMMITTEE

*530. SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI MOHAMAD ISMAIL :
SHRI UMANATH :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have studied the recommendations made by the Retail Outlets Committee headed by Shri R. R. Morarka regarding installation of new retail petrol pumps by the Indian Oil Corporation; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) The Report of the Retail Outlets Committee is under the consideration of the Government.

(b) Does not yet arise.

SHORTAGE OF SPIRIT IN HOSPITALS

*531. SHRI RABI RAY : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that shortage of spirit has forced many hospitals not to perform emergency operations;

(b) whether patients visiting Delhi hospitals are being asked by doctors that their treatment would start if they bring spirit from the market; and

(c) if so, whether Government have made any probe about it and the steps being taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No, Sir.

(b) No specific case has been brought to the notice of Government.

(c) There is a shortage of spirit in Delhi. However the Excise Department has been asked to keep a reserve stock for supply to hospitals.

WORKING OF REFINERIES

*532. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Refinery Units of the Indian Oil Corporation Ltd. started production two years behind schedule;

(b) if so, the delay involved and the loss incurred thereby in each unit;

(c) whether any inquiries have been made to find out the causes of delay in each case; and

(d) if so, with what results ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) Yes, Sir. There has been delay in the commissioning of the various units of the Barauni and Gujarat refineries.

(b) The delay in respect of different units of the above two refineries ranges between 12 to 24 months. It is not possible to estimate the loss resulting from delays in the different units.

(c) and (d). Delays arose mainly as a result of difficulties with some construction contractors and delays in the receipt of necessary equipment and materials.

UNIFORM MARRIAGE LAW

*533. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government, while drawing plan for population control, have considered the fact that for successful implementation of the Family Planning Scheme, a uniform marriage law should be introduced throughout the country and among people of all religious denominations;

(b) if so, the steps taken by Government to introduce a uniform marriage law in India; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) and (c). The question of uniform marriage law has many implications and the Government have, therefore, not yet considered it desirable to enact such a law in the country.

(b) Does not arise.

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण

*534. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण अनिवार्य करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के नियंत्रण के प्रश्न पर लगातार विचार किया जाता है और आवश्यकतानुसार स्थिति में सुधार करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

GOLD SMUGGLING IN WEST COAST

*535. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the series of raids conducted in the West Coast and the Bombay area in particular, in which large quantities of smuggled gold were seized;

(b) if so, the number of such raids since 1st January, 1967, and the total quantity of gold seized;

(c) the origin of this gold and the *modus operandi* of the smugglers and middle-men;

(d) whether any people have been arrested/prosecuted/convicted; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (e). Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

CONSTRUCTION OF BUILDING BY NEWSPAPERS IN DELHI

*536. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some of the daily Newspapers have constructed or are constructing big buildings on Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, after taking loans from the banks or from Government; and

(b) if so, the names of such Newspapers, the amount of loan and the name of the gaurantor or the details of security against which loans have been taken ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). No loans have been given by Government for the construction of buildings by newspapers in Delhi. According to the practices and usages customary among bankers, the banks do not divulge information relating to the affairs of their constituents. However, the names of the newspapers who have been allotted land on Bahadur Shah Zafar Marg are as under :—

Indian Express
Times of India
Patriot
Pratap
National Herald
Milap
Tej

HALDIA-BARAUNI PIPE LINE

*538. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the replies given to Starred Question Nos. 211 and 212 on the 1st June, 1967 and state :

(a) whether all the cases regarding Haldia-Barauni Pipeline pending in Calcutta High Court have been disposed of; and

(b) if so, the amount of compensation paid to the owners of collieries in the Raniganj coal-field area ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) Yes, Sir.

(b) No compensation has been paid so far. A copy of the judgment has not yet been made ayailable by the Calcutta High Court.

PENDING INCOME-TAX CASES

*539. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the end of the assessment year 1965/66, the number of income-tax cases pending was about 21.7 lakhs; and

(b) the action, if any, taken by Government on the recommendation of the Tyagi Committee on Direct Taxes on small income cases ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The No. of assessments pending for disposal on 31-3-1966 was 21, 69, 529.

(b) The recommendation of the Tyagi Committee on Direct Taxes was accepted by the Government and instructions were issued for disposal of small income cases in October, 1960.

STRIKE BY EMPLOYEES OF POST GRADUATE INSTITUTE, OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH

*540. SHRI SHRI CHAND GOEL : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class III and class IV employees of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh have gone on a general strike;

(b) whether it is also a fact that all the 750 beds of the Institute have been left unattended; and

(c) if so, the steps taken by Government or proposed to be taken to meet the situation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) to (c). Yes, Sir. The Class III and Class IV employees of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, went on one day's strike on the 16th November, 1967. They did not attend to the Hospital beds on that day.

But during the absence of the striking employees, the work in the Hospital was managed by the Post Graduate students and the nursing and teaching staff. Assistance was also rendered by the staff of the Military Hospital, located in the campus of the Institute.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की रियायतें

3256. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उपरोक्त रियायतों को लाभ राज्य-वार कितने विद्यार्थी उठा रहे हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेनु गुह): (क) ट्यूशन फीस से छूट । छात्रवृत्तियां । बोर्डिंग अनुदान । पुस्तकें, वर्दियां इत्यादि मुफ्त देना । दोपहर का भोजन ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT—1904/67]** ।

समाज कल्याण योजनाएं

3257. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण योजना के आरंभ होने के समय से लेकर अगस्त 1967 तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने इन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि के वार्षिक अनुदान मंजूर किये तथा उनमें से कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) ये अनुदान किन-किन मदों पर खर्च किया गया तथा यदि अनुदान की कुछ राशि वापिस लौटाई गई हैं तो कितनी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तथा (ख). यह सूचना सुलभ नहीं है। इस सूचना को एकत्रित करने में कार्फी समय, परिश्रम तथा रुपया लगेगा, जो प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणामों के सम्मेय नहीं होगा। इन परिस्थितियों में इस सूचना को एकत्रित करने में सरकार सखेद अपनी अयोग्यता प्रकट करती है।

आय कर दाता

3258. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के राज्यों और संघीय क्षेत्रों में करदाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कर दाताओं में से कितने व्यक्ति विधान सभा, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदस्य हैं और कितने व्यक्ति किसान, व्यापारी और उद्योगपति हैं; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर विभाग के जनरल इन्डेक्स रजिस्टर पर 30 सितम्बर 1967 को निर्धारितियों की संख्या 27,53,388 थी ।

(ख) और (ग). ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है ।

Power Generation

3259. **SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH** : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the total installed capacity for the power generation in the country is over 60,000 m. Kwh;

(b) whether it is also a fact that the total availability of power transmission facilities in the country exists for less than 42,000 m. Kwh;

(c) the estimated waste of the power generated in the country for want of power transmission facilities; and

(d) the reasons as to why Government have not asked the State Electricity Boards to take up the task of laying of transmission lines without delay?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) The aggregate installed generating capacity in the country, at present is about 12.5 million kW which has a potential for generating 50,000 million kWh per annum.

(b) and (c). In certain areas in the country it has not been possible to supply power for want of transmission facilities particularly where power could have been transmitted from one State to another. It is not possible to estimate the generating capacity thus under-utilised in view of the fact that in each case transmission facilities for carrying additional power to the existing load centres were being reinforced and/or new transmission lines were being constructed for carrying power to new areas.

(d) Central Government have already requested all State Electricity Boards to take steps to reinforce their transmission system.

UTILISATION OF ELECTRICAL ENERGY

3260. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the reasons for not publishing data by the Central Power and Water Commission on the utilisation of electrical energy generated by the recently installed power projects such as the Sharavathy project (Mysore), Kothagudam (Andhra Pradesh), Pamba (Kerala) and Talcher (Orissa); and

(b) the latest figures of the utilisation of electric energy generated by the power projects referred to in part (a) above?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). Electrical energy generated by various power projects in any State is fed into the common transmission & distribution network for distribution to various consumers. Hence it is not practicable to maintain statistics of utilisation of energy in respect of each power project separately. Accordingly Central Water and Power Commission publishes the data on energy sales (utilisation) in respect of each power system of the various State Electricity Boards.

Details of electrical energy generated in the following power projects during 1966-67 are given below :—

	Million kwh
Sharavathy	1254.981
Kothagudam	307.983
Pamba	272.567

The Talcher Project has not yet been commissioned.

PRESS PRINTING FORGED CURRENCY UNEARTHED IN DELHI

3261. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a printing press which was turning out forged currency notes of Rs. 100 denomination has been recently unearthed in Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps proposed to be taken to withdraw from the market the forged currency notes which might have been floated by this ring; and

(d) the steps proposed to be taken to ensure that such forgery does not take place in future?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes Sir.

(b) Two persons were arrested in September 1967 for uttering five forged hundred rupee notes. Following subsequent investigations, eleven more forged notes, 265 partially printed notes, a pressing machine and several accessories and raw materials required for printing notes were recovered. Four more persons were also arrested later.

(c) The Reserve Bank of India and other note issuing authorities have general instructions to impound forged notes whenever presented to them.

(d) The offences relating to counterfeiting of currency and Bank notes come under the Indian Penal Code which already provides for deterrent punishment. The offences of counterfeiting and forgery are dealt with by the State Police authorities who keep a watch in this behalf. The

Central Bureau of Investigation under the Ministry of Home Affairs also keeps the problem of counterfeiting of Indian currency under continuous study by keeping records of different techniques adopted and by reviewing periodically appearance of counterfeit Indian currency. They also assist the State Police authorities in specific cases.

M/s. PRAMODE PICTURE

3262. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the date on which the house and office of Shri Pramode Chakravarty, Producer of "Love in Tokyo" and proprietor of M/s Pramode Picture, was raided and the amount and nature of evidence found during the searches;

(b) the number of similar raids and the names of persons in the film industry whose houses were raided during the last three years ending 31st March, 1967 with a list of cash valuable and other evidence found in each raid; and

(c) the steps taken by Government against these persons?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The business and residential premises of Shri Pramode Chakravarty, producer of the film 'Love in Tokyo' and proprietor of M/s. Pramode Films, Bombay were searched by the Enforcement Directorate on 16-8-67 and some documents were seized. No currency was seized during these searches. It is not possible to disclose the nature of the evidence found, at this stage, as the investigations are still in progress.

(b) and (c). The information is being collected.

INCLUSION OF BANJARA IN SCHEDULED TRIBES LIST

3263. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Akhil Bhartiya Banjara Sewa Sangh have demanded that the Banjaras all over the country might be included in the list of Scheduled Tribes on all India level;

(b) if so, the decision taken by Government in this matter; and

(c) the action taken to make an all-India List of Banjara community?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Government's decisions in the matter of revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are incorporated in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967, introduced in the House on 12th August, 1967.

(c) The Constitution does not permit the identification of Scheduled Tribes on an All-India basis.

TRIBAL COLONIES IN ANDHRA PRADESH

3264. SHRI V. NARSIMHA RAO : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to construct more tribal colonies in Andhra Pradesh;

(b) the number and names of tribal colonies under construction and the acres of land given to each person; and

(c) the progress made in respect of tribal colonies in Jatapukota and Chinogora in Srikakulam district in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) to (c). Necessary information is being collected and will be placed on the table of the House as soon as possible.

INVESTMENT IN PUBLIC SECTOR IN GUJARAT

3265. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount invested in the public sector in Gujarat; and

(b) its proportion to the all India averages with regard to investments in other States?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). Presumably the question refers to Central

Government industrial and commercial public sector undertakings. As at the end of March 1966, the value of such assets in Gujarat was Rs. 26.6 crores as compared to Rs. 1916 crores in the various other States in India. These figures do not include the value of aircrafts, ships etc., not assignable to any particular State as well as others like oil, pipelines, exploration equipment etc., for which State-wise break-up figures are not readily available.

ASSISTANCE TO GUJARAT

3266. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total contribution made by the Central Government to Gujarat during 1966-67 for the famine relief works; and

(b) the extent to which it was utilised?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Central assistance of Rs. 3.03 crores was provided to the State Government during 1966-67, towards the expenditure incurred on drought relief measures in 1965-66 and 1966-67.

(b) The assistance provided has been fully utilised.

SUPPLY OF DRINKING WATER TO GUJARAT VILLAGES

3267. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state the number of villages in Gujarat where drinking water has been made available as a result of rig boring machines supplied to that State by the Central Government during 1966-67?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : The information is being collected and will be laid down on the Table of the Sabha.

LEPROSY IN GUJARAT

3268. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether according to a survey of the World Health Organisation, thousands of persons are suffering from leprosy in Gujarat; and

(b) if so, the steps Government propose to take to control and eliminate this disease?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) and (b). The World Health Organisation has not done any survey of leprosy patients in Gujarat. Under the National Leprosy Control Programme launched since 1955, 3 Leprosy Control Units and 70 Survey Education and Treatment Centres have been established in this State. Besides, 2 Voluntary Organisations are also being assisted for participating in this programme. So far 3.1 million population in the State has been covered under the National Leprosy Control Programme and out of 31860 estimated cases 13527 cases have been recorded.

CENTRAL ASSISTANCE UNDER NATIONAL WATER AND SANITATION SCHEME TO GUJARAT

3269. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the extent and nature of assistance provided by Government to Gujarat during the Third Five Year Plan under the National Water Supply and Sanitation Scheme in rural and urban areas of the State; and

(b) the number of cities and villages where this scheme has been introduced or is being introduced?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) In accordance with the procedure in vogue upto 1966-67, Central assistance to States for Centrally Aided Schemes had been allocated/released in lump-sum for all 'HEALTH' Schemes including Rural Water Supply Schemes. It is, therefore, not possible to indicate the amount of Central assistance sanctioned to any State for any

particular Centrally-Aided 'HEALTH' Scheme. The Government of Gujarat was allocated the following amounts during the Third Five Year Plan on account of all 'HEALTH' Schemes including Rural Water Supply :—

Year	(*Rs. in Lakhs*)
1961-62	96.70
1962-63	79.86
1963-64	77.25
1964-65	77.89
1965-66	123.46

In so far as 'Urban Water Supply Sanitation Programme, central assistance in Gujarat was given central assistance in the shape of 'loan' during the Third Five Year Plan period as detailed below :—

Year	(*Rs. in Lakhs*)
1961-62	9..72
1962-63	55.14
1963-64	101.96
1964-65	83.73
1965-66	135.89

Under the National Water Supply and Sanitation Programme, central assistance is being given in accordance with the following pattern :—

Urban Water Supply Schemes—100% loan
Rural Water Supply Schemes—50% grant -in-aid.

(b) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

HOUSING LOANS TO SOCIETIES

3270. SHRI SRINIBAS MISRA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) how much of the Housing loans granted by the Central Government to low and middle income groups have been utilised through the cooperative Societies, State-wise;

(b) whether there is any uniform percentage for such utilisation through cooperative societies; and

(c) if so, whether it has been enforced ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

COOLEY FUNDS

3273. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there was any increase in allocations for Cooley Funds during the year 1966-67 for different objectives; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). Cooley funds are meant for loans to U.S. affiliated business firms and enterprises in India. During 1966-67 the total accruals for Cooley Funds were Rs. 20.66 crores as follows :

	(*Rs. crores*)
Total accruals upto 31-3-1967 :	112.79
Total accruals upto 31-3-1966 :	92.13
Accruals during 1966-67	20.66

LOANS SANCTIONED BY AGRICULTURE FINANCE CORPORATION IN U.P.

3274. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Agriculture Finance Corporation sanctioned any loans assistance for the functioning of the agricultural projects in Uttar Pradesh during the year 1966-67; and

(b) if so, the actual disbursement of utilisation during the above period?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). No scheme for refinance was received by the Agricultural Refinance Corporation from Uttar Pradesh during the year 1966-67. However, one scheme received in September 1967 for sinking of tube-wells has been sanctioned in November 1967, involving a total financial outlay of Rs. 147.70 lakhs; the Corporation's commitment being Rs. 132.93 lakhs. No disbursement has so far been made against this sanction.

HOUSES FOR TRIBAL PEOPLE IN RAJASTHAN

3275. SHRI MEETHA LAL MEENA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a housing scheme was implemented by the Department of Social Welfare in Rajasthan;

(b) if so, the names of the villages where houses have been built so far under the above scheme;

(c) the reasons for not undertaking or completing the houses in other villages; and

(d) the expenditure incurred on this scheme so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) to (d). In the schematic budget for every Tribal Development Block, there is a provision of Rs. 1.20 lakh for 'Social Services' including housing. As the provision is limited, it is not possible to cover all villages. The names of Tribal Development Blocks in Rajasthan are given below :—

1. Kushalgarh	Distt.	Banswara
2. Bhukiya	,,	,,
3. Simalwara I	,,	Dungarpur
4. Kherwara I	,,	Udaipur
5. Pipalkhunt	,,	Banswara
6. Simalwara II	,,	Dungarpur
7. Kherwara II	,,	Udaipur
8. Sajjangarh	,,	Banswara
9. Dungarpur I	,,	Dungarpur
10. Kotra I	,,	Udaipur
11. Dungarpur II	,,	Dungarpur
12. Kotra II	,,	Udaipur
13. Talwara I	,,	Banswara
14. Partapgarh	,,	Chittorgarh
15. Bichiwara I	,,	Dungarpur
16. Bichiwara II	,,	,,
17. Aspur	,,	,,
18. Sagwara I	,,	,,

ASSISTANT ENGINEERS IN C.P.W.D.

3276. SHRI DEVINDER SINGH : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently 22 direct recruited Assistant Engineers who have not completed their training as required under the rules have been posted as incharge of Sub-Divisions in C.P.W.D.;

(b) whether it is also a fact that panel approved by the Departmental Promotion Committee from the grade of Section Officers for promotion to the grade of Assistant Engineers is awaiting posting; and

(c) if so, the reasons for posting the untrained direct recruits in preference to Section Officers on the approved panel?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (c). The competent authority having found adequate the training imparted to some of the direct recruits for holding independent charge of Sub-Divisions it curtailed the prescribed training period in respect of 22 such direct recruits to the grade of Assistant Engineer.

(b) Owing to shortage of direct recruits in the grade of Assistant Engineer, promotion from the grade of Section Officer in excess of the quota prescribed for them has had to be resorted to. Promotion panels for regular appointment as Assistant Engineers have been exhausted. For short-term appointment of Section Officers to the grade of Assistant Engineers on an *ad hoc* basis pending appointment of direct recruits, panels are drawn up and one such panel is current presently. The Section Officers promoted as Assistant Engineers on an *ad hoc* basis are however to revert as and when direct recruits to the cadre of Assistant Engineers are available.

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड

3277. **श्री निहाल सिंह :**

श्री ओंकार सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही परिवार मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड और मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड को चला रहा है;

(ख) इन फर्मों ने पिछले पांच वर्षों में कितना आयकर दिया, उनमें कितनी भारतीय पूंजी लगी है, उन्होंने किन वस्तुओं का निर्माण किया है और उनके निदेशकों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या इन दोनों कम्पनियों के कार्य के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऐसे ठेके जिनमें श्रमिक के सम्बन्ध में बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े दिये गये हैं की जांच पूरी कर ली गई है;

(च) क्या सरकार ने 1965 से पूर्व के इन कम्पनियों के मामलों की जांच पूरी कर ली है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ये लिमिटेड कम्पनियां हैं, फर्म नहीं हैं । मैकेन्जीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है। मैकेन्जीज लिमिटेड के पांच डायरेक्टरों में से तीन डायरेक्टर तथा ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के सभी डायरेक्टर एक ही परिवार के सदस्य हैं।

(ख) दोनों कम्पनियों ने जो कर अदा किया है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

कर निर्धारण वर्ष	उस वर्ष के लिये अदा किया गया कर	
	मैकेन्जीज लिमिटेड (रुपये)	ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (रुपये)
1963-64	2,86,877	31,700
1964-65	2,54,893	हानि
1965-66	3,18,869	हानि
1966-67	3,50,359	हानि
1967-68	3,75,659	हानि

मैकेन्जीज लिमिटेड की लगी पूंजी 22 लाख रुपये है तथा ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड की 20 लाख रुपये। सम्पूर्ण पूंजी भारतीय है । मैकेन्जीज लिमिटेड द्वारा रेल की बैगनें, कांक्रीट वाइब्रेटर्स, ट्रेलर्स इत्यादि बनाये जाते हैं तथा इंजीनियरी काम के ठेके भी लिये जाते हैं। ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा विभिन्न किस्म का कागज बनाया जाता है।

उनके वर्तमान डायरेक्टरों के नाम इस प्रकार हैं :—

मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड

श्री पुरुषोत्तम झुनझुनवाला
श्री रामजीलाल झुनझुनवाला
श्री माणिकलाल प्रेमचन्द
श्री एम० के० हाण्डू
श्री गिरधारी लाल झुनझुनवाला

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड

श्री बनवारी लाल झुनझुनवाला
श्री भगवती प्रसाद झुनझुनवाला
श्री चम्मालाल झुनझुनवाला
श्री राधाकृष्ण रांगटा
श्री आश्विन लाल शाह
श्री घासीराम जे० जालान

(ग) इन दोनों कम्पनियों के नियमित कर-निर्धारण के सम्बन्ध में जांच चल रही है।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) मजदूरियों के ऐसे बढ़ाये चढ़ाये आंकड़े अभी तक देखने में नहीं आये हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) सवाल ही नहीं उठता।

मैसर्स रामजीलाल झुनझुनवाला की फर्म

3278. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8693 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रामजीलाल झुनझुनवाला

की फर्मों के बारे में की जा रही जांच अब पूर्ण हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्यम आय वर्ग के लिये मकान

3279 **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार नें दिल्ली में कार्य कर रहे मध्यम आय वर्ग के कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये योजना के आरंभ से अब तक नये मकानों का निर्माण किया है;

(ख) इन मकानों को कब तक कर्मचारियों को दे दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उन शिकायतों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि इनमें से बहुत-से मकानों में पानी, बिजली और सफ़ाई का उचित प्रबन्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (घ). ११० रुपये से ६९९ रुपये तक लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए टाईप II II I तथा IV के लगभग 1800 मकान राम-कृष्णपुरम के सेक्टर VIII, IX तथा XII में निर्माणाधीन हैं। उनमें से कुछ तैयार हो गये हैं तथा शेष अभी बन रहे हैं। इन क्वार्टरों के लिए बिजली नहीं मिली है। इसी कारण से निगम द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकी क्योंकि बग़ैर बिजली के पानी ऊपर नहीं खींचा जा सकता। अब सरकार ने ऊपर की टंकियों में पानी चढ़ाने के लिए बिजली उत्पादन-यंत्र लगा दिये हैं। इस प्रकार पानी की तो व्यवस्था हो गयी है तथा स्वच्छता की भी व्यवस्था है। घरेलू काम के लिए बिजली की सप्लाई की अगले वर्ष संभावना है।

(ख) पानी की सप्लाई से युक्त किन्तु बग़ैर बिजली के मकानों का आवंटन संपदा निदेशालय के द्वारा बैचों में किया जा रहा है, पहिले तीन बैचों के 864 क्वार्टरों में से 176 अक्तूबर, 1967 में तथा 688 नवम्बर, 1967 में आवंटित किये गये थे। 398 और मकान 15 दिसम्बर, 1967 से पूर्व आगामी बैचों में आवंटित किये जाने की संभावना है।

अस्थायी वर्क्स असिस्टेंटों को सेवा निवृत्त किया जाना

3280. **श्री ओंकार लाल बरवा** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गतवर्ष और चालू वर्ष में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुल अस्थायी वर्क्स असिस्टेंटों को सेवा निवृत्त किया गया है जबकि उन्होंनें लगभग 41 वर्ष तक नौकरी की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा निवृत्त किये गये इन वर्क्स असिस्टेंटों को न तो कोई उपदान दिया गया और न ही पेंशन दी गई;

(ग) यदि हां, तो सेवा निवृत्त किये गये उन कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, जिन्होंनें बीस वर्ष या इससे अधिक समय नौकरी की थी परन्तु जिन्हें पेंशन और उपदान नहीं दिया गया; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह असंभव है कि कोई एक व्यक्ति जिसने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक कार्य सहायक के रूप में ४१ वर्ष तक कार्य किया हो वह अस्थाई की हैसियत से सेवा निवृत्त हुआ हो; किन्तु

यदि कोई विशेष मामला नोटिस में लाया जाये तो उसकी जांच की जायेगी तथा उत्तर दिया जायेगा ।

(ख) नियमानुसार, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित वर्गीकृत स्थापना से सेवानिवृत्त होते हैं वे किसी पेंशन अथवा मृत्यु के साथ सेवानिवृत्त उपदान के पात्र नहीं हैं। कार्य सहायक जो कि कार्य प्रभारित स्थापना से अस्थाई हैसियत में सेवानिवृत्त होते हैं अथवा वे जो कि कार्य प्रभारित स्थापना में थे तथा बादमें नियमित स्थापना में स्थानान्तर हो गये, वे कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के पात्र होंगे जिसमें एक निर्धारित ब्याज की दर से सरकार का अंशदान होता है ।

नियमित वर्गीकृत स्थापना से सेवानिवृत्त होने वाले अस्थाई कार्य सहायक नियमानुसार सावधिक उपदान के पात्र हैं, बशर्ते कि सेवानिवृत्त के समय उन्होंने ५ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो ।

(ग) इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कर्मचारी वार्धक्य आयु पर पहुंचने पर जो कि नियमित स्थापना में 58 वर्ष है, तथा कार्यप्रभारित स्थापना में 60 वर्ष है, सेवानिवृत्त हो जाता है । नियमानुसार, केवल स्थाई कर्मचारी ही पेंशन के पात्र हैं । अतएव पेंशन की पात्रता सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी की स्थाई अथवा अस्थाई स्थिति पर निर्भर करती है ।

SALE OF CHINESE PENS IN KERALA

3281. SHRI BABU RAO PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that very large quantities of Chinese fountain pens called 'Hero' and 'Youth' are being sold in Kerala and their sale collections pocketed by the Communist Party;

(b) whether Government are aware that the barrels of these fountain pens are reported to have contained powdered gold and herein which are sold for augmenting the funds of the local Communists;

(c) whether Government are aware that fountain pens, currency notes and many other contraband goods are smuggled regularly into Kerala in hundreds of Chinese dhows which unload their cargo in the night at the unguarded points on the long coastline of Kerala; and

(d) if so, the steps Government have taken to stop this smuggling and sabotage of our economy?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Fountain pens of Chinese origin including 'Hero' and 'Youth' fountain pens are occasionally sold in various parts of Kerala. Such goods enter the country mostly as part of the baggage of passengers coming from Singapore and Malaysia disembarking at the ports on the south-eastern coast. There is no indication that Chinese goods are being smuggled or sold in large quantities in Kerala and their sale-proceeds pocketed by the Communist Party.

(b) and (c). The Government have no such information.

(d) Does not arise.

हैदराबाद का निजाम

3282. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मरंडी :
श्री स० च० बेसरा :

क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के वर्तमान निजाम ने करोड़ों रुपये जिसमें २५ करोड़ रुपये के मूल्य के 'होप' और 'जेकोन' नामक रत्न भी शामिल हैं, तुर्की भेजे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निजाम के अंगरक्षकों और दिवंगत निजाम के बड़े राजकुमारों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हैदराबाद के वर्तमान निजाम ने खरब रुपये की सम्पत्ति टर्की भेज दी है और उसमें 25 करोड़ रुपये के मूल्य के 'होप' और 'जेकोन' रत्न भी शामिल हैं।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में स्वर्गीय निजाम के अंगरक्षकों अथवा ज्येष्ठ राजकुमारों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अन्य स्रोतों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यह अवश्य है कि इस तरह के आरोप उस रिट दरख्वास्त में लगाये गये हैं जो स्वर्गीय निजाम की पुत्री अहमदुन्निसाव ने आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर की है। यह दरख्वास्त अभी उच्च न्यायालय के विचारार्थ पेश होनी है। इसके अलावा, एक मीर महबूद अली खान और नाजनीबेगम ने भी एक दूसरी अदालती कार्यवाही के दौरान ऐसे ही आरोप लगाये थे। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि निजाम ने बेशकीमती जवाहरात को चोरी-छिपे विदेशों में भेजकर वहां उन्हें बेचने की कोशिश की है।

(ग) किसी भी वस्तु के गैर-कानूनी ढंग से देश के बाहर भेजे जाने पर पाबन्दी रखने के लिए सभी सम्भव औपचारिक सतर्कतात्मक और निरोधक उपाय किये जाते हैं।

नलकूपों के लिये बिजली का दिया जाना

3283. श्री ओं० प्र० त्यागी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान नल कूपों के लिये बिजली के कनक्शन लेने के लिये कुल कितनें किसानों ने आवेदन किया है;

(ख) मार्च, 1967 तक कुल कितने किसानों को बिजली दी जा चुकी है;

(ग) बिजली न मिलने के कारण कितने नलकूप बेकार पड़े हैं; और

(घ) उन्हें बिजली न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) सब प्रकार के नलकूपों को ऊर्जित करनें के लिए आवेदन पत्रों की विशेष रुप से बनाई गई संख्या 1,23,765 है।

(ख) 31 मार्च, 1967 तक 6,48,061 कुंए ऊर्जित किए गए।

(ग) नलकूपों को ऊर्जित करने के लिए 39,230 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना बाकी है, ऐसा विशेष रूप से बताया गया है।

(घ) इन आवेदकों को बिजली के कनक्शन न देनें का मुख्य कारण धन की कमी है।

PUBLIC SECTOR INDUSTRIAL CONCERNS

3284. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Administrative Reforms Commission has suggested setting up of sector corporations for public sector industrial concerns; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The recommendation is under consideration of the Government.

IMPORT OF NYLON YARN

3285. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any proceedings have been launched against (i) S.Y.A. Patel, (ii) M/s. Aslam Trading Company, (iii) M/s. Noble Trading Co., and (iv) M/s. Khimji Toalani & Sons and/or their partners for breach of import regulations and/or any other offences connected with the import and sale of nylon yarn in the country;

(b) if so, the exact nature of the offence and the circumstances under which the offences came to light;

(c) when the delinquents were apprehended; and

(d) at what stage are the investigations or prosecutions against these firms/partners?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). On the basis of information received the Customs authorities searched, amongst others, the premises of the firms mentioned below :—

(1) Shri Y. A. Patel

(2) M/s. Aslam Trading Company

(3) M/s. Noble Trading Company

(4) M/s. K. Topandas & Company.

As a result of the searches various quantities of foreign nylon yarn which on investigation were found to have been smuggled into the country or imported under valid licences but sold in contravention of the conditions laid down in the relevant import licences were recovered from the premises of serial No. (1), (3) and (4) above.

Proceedings have been launched under the Customs regulations against the following :—

(1) Shri Y. A. Patel

(2) Shri Abdul Sattar, Abubaker of M/s. Noble Trading Company,

(3) Shri Khimji Topandas, proprietor M/s. K. Topandas & Company.

No proceedings have been launched against M/s. Aslam Trading Company. The abovementioned three persons were arrested on 3-4-67 and 5-4-67.

(d) In the case of M/s. Aslam Trading Company, some documents recovered are still under scrutiny, while in the other three cases investigations have been completed and the cases are under departmental adjudication.

ESTATE DUTY ON NIZAM'S PROPERTY

3286. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the estate duty payable on the deceased Nizam's property has been finally assessed; and

(b) if so, the amount payable and the value of the estate on which this duty is payable?

THE DEPUTY PRIME MINISTER & MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

HOTEL AKBAR, NEW DELHI

3287. SHRI BABU RAO PATEL : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have taken a final decision to name the proposed new hotel on the plot next to the Janpath Hotel as Hotel Akbar; and

(b) if so, the reasons for naming the hotel after Akbar?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

भूतपूर्व शासकों की सम्पत्ति

3288. श्री रा० कृ० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व शासकों की सम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है;

(ख) क्या उनमें हैदराबाद भी है;

(ग) कितने अन्य भूतपूर्व शासकों की सम्पत्ति के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करनें का विचार है तथा अब तक की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है;

(ङ) उन भूतपूर्व शासकों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, जिनकी सम्पत्ति का कम मूल्यांकन किया गया है और जिन्होंने अपनी वास्तविक सम्पत्ति से कम सम्पत्ति घोषित करके करों की चोरी की है अथवा कम कर दिया है; और

(च) ऐसे भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) धन-कर अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत जिन भूतपूर्व शासकों के मामलों में पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गयी थी अथवा शुरू की जा रही है उनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। देश में सभी धन-कर परिमण्डलों से सूचना इकट्ठी करने में काफी समय लगेगा क्योंकि पिछले ११ वर्षों के कागजों की जांच करनी पड़ेगी।

(ख) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के मामले में वर्ष १९५७–५८ के लिये धन-कर के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही फिर से की गयी थी और वह कार्यवाही १८–१–१९६५ को पूरी की गयी।

(ग) से (च). जिन भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध उनकी सम्पत्तियों के बारे में अथवा कर का अपवंचन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सभी के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। देश के विभिन्न धन-कर परिमण्डलों से यह सूचना इकट्ठी करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा। जब कभी कोई सूचना अथवा शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करन की कार्यवाही की जाती है और जांच पड़ताल के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए कर-निर्धारण अथवा कर के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो, की जाती है।

बम्बई में छापे मार कर बरामद किया गया सोना

३२८९. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९६७ के पहले सप्ताह में सीमा शुल्क अधिकारियों न बम्बई में छापे मार कर २१ लाख रुपये मूल्य का विदेशी सोना बरामद किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त सोना किस प्रकार का है और उस पर किस देश के निशान अंकित हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों नें सितम्बर के पहले सप्ताह में बम्बई में दो मामलों में विदेशी मार्के का सोना पकड़ा, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य १,०८,००० रुपये होता है।

(ख) दोनों मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है। एक मामले में जिस व्यक्ति के पास से सोना पकड़ा गया था उसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(ग) पकड़े गये सोने का कुल वजन ११०० तोला है। पकड़े गये सोने पर फ्रांस की मोहर लगी है।

तेल उत्पादकों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा

3290. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामजी राम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर स्पिरिट, नैफथा, एच० एस० डी० तथा पैराफीन वैक्स के निर्यात से सरकार को वार्षिक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मोटर स्पिरिट, नेफथा, एच० एस० डी० फरनेस आयल तथा पैराफीन वैक्स के निर्यात से उपलब्ध विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

	लाख रुपयों में
1966	875.63
1967 (जनवरी से अक्तूबर तक)	1180.43

'भारतीय दलित वर्ग संघ' को अनुदान

3291. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गत 20 वर्षों में 'भारतीय दलित वर्ग संघ' को वार्षिक अनुदान के रूप में लाखों रुपये दिये हैं;

(ख) क्या ये अनुदान केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सामाजिक कल्याण के लिये दिये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संस्था अथवा संघ के हिसाब किताब की लेखापरीक्षा की है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि अनुदानों की राशियों का राजनैतिक कार्यों के लिये दुरुपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की संस्था को अनुदान देना बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 1953–54 से भारतीय दलित वर्ग संघ को अनुदान मंजूर किए जा रहे हैं। 1961–62 से 1966–67 की कालावधि के लिए निम्नलिखित अनुदान दिये गये है :—

वर्ष	दिए गए अनुदान रुपये
1961–62	1,30,671
1962–63	1,33,821
1963–64	1,00,930
1964–65	1,31,753
1965–66	1,20,129
1966–67	1,16,600

(ख) अनुदान अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये दिए जाते हैं।

(ग) लेखापरीक्षण महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा किया गया है।

(घ) कर्मचारियों द्वारा सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त राजनीतिक कार्य किए जाने के इक्के दुक्के मामले हुए हैं।

(ङ) हां; परन्तु जिन मामलों की सूचना मिली, वे मामूली प्रकार के थे, इसलिए उस संस्था को सुधारक उपाय करने के लिए कहना ही पर्याप्त समझा गया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सम्पत्ति के विवरण

3292. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति संबंधी वार्षिक विवरणों में दी जाने वाली सूचना का सचाई का सत्यापन करने के सम्बन्ध म सरकार ने किन कारणों से संबंधित नियमों में उपयुक्त उपबन्ध नहीं किया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति विवरण केवल आवश्यक जांच के बाद रेकार्ड कर दिये जाते हैं। वर्तमान सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली में यह व्यवस्था शामिल है कि जहां सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, उन उचित मामलों में सूचना की सत्यता को सत्यापित करें।

Dues from Ex-M.Ps.

3293. **SHRI N. S. SHARMA :**
SHRI SHARDA NAND :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the names of ex-M.Ps. who have not paid their dues regarding house rent,

furniture, electrical appliances etc. for more than the last six months;

(b) the amount due in each case; and

(c) the steps taken as proposed to be taken by Government to recover these dues?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). It is a long list. The number involved is over 250 and the amount due from them is over Rs. 1,30,000.

(c) The amount of arrears is intimated to the Secretariat of the Lok Sabha or Rajya Sabha to effect recovery from the final dues of the ex-Members concerned. If recovery is not possible from the final dues, the ex-Members or their heirs are addressed to make the payment. Where any ex-Member became a Member of a State Legislature, the Secretariat of that Legislature is requested for effecting recovery from the salaries and allowances of the Member. If these efforts fail, legal action is taken to effect recovery to the extent possible.

EXPORT OF OPIUM

3294. SHRI S. S. KOTHARI :
SHRI RAM GOPAL SHALWALE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the steps which Government have been taking to stimulate export of opium;

(b) whether Government propose to adopt more liberalized policy for granting increased pattas (licences) to cultivators for growing opium; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) In accordance with the International Conventions, the consumption of opium is strictly limited to scientific and medicinal use and the export/import of opium is controlled by the Governments concerned. Therefore, the world demand for raw opium and consequently the scope for increasing export of opium from India, is limited. However, in order to increase exports from India to the extent possible, Government have been taking the following steps :—

(i) The price of opium is reviewed every year taking into consideration the international trends and in particular, the price charged by our main competetitors.

(ii) As an incentive to purchase larger quantity of opium from India, a rebate is allowed to customers in certain countries in respect of that much quantity of Indian opium utilized by them in manufacture and exported to other countries.

(iii) Agents have been appointed for those countries where there is a possibility of increasing sale of Indian opium.

(b) and (c). The area to be licensed for poppy cultivation mainly depends on the requirement of opium for export and the licensing policy relating to grant of licences for poppy cultivation is reviewed every year so as to enable the requisite area to be licensed.

While evolving the licensing principles it is also borne in mind that risks of leakages are minimized and average yields maximized through steps such as—

(i) elimination of inefficient cultivators and unproductive tracts,

(ii) confining cultivation to compact areas, and

(iii) creating the conditions for better and more economic control.

So far as 1967-68 season is concerned, requisite area is likely to be available under the licensing principles already evolved for this season and the question of further liberalisation of the licensing policy, therefore, does not arise.

बम्बई में बरामद सोना

3295. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 के अन्तिम सप्ताह में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में छापा मार कर 7.50 लाख रुपये का सोना बरामद किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) बम्बई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों ने 27 सितम्बर, 1967 को बम्बई की लेमिंगटन रोड स्थित एक दुकान से विदेशी मार्के का 2000 तोला सोना पकड़ा, जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर से 1,97,000 रुपये है।

(ख) मामले में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

RUBY GENERAL INSURANCE COMPANY

3296. SHRI J. B. SINGH :
SHRI KAMESHWAR SINGH :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the refusal of the demand of a shareholder of the Ruby General Insurance Company by the General Manager to furnish him with the Special Audit Report and a list of Company's shareholders; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b) . Shri Prabhat Kumar Bhanu, a shareholder of the Ruby General Insurance Company, asked for a copy of the report of the auditor appointed by the Controller of Insurance. The auditor's report could not be supplied to him, as it is treated as a privileged document; Shri Bhanu has been informed of this position.

As regards the list of shareholders, it is open to a shareholder to obtain a copy from the company on payment of statutory charges.

INCOME-TAX ASSESSMENT OF SHRI RAMNARAYAN RUIA'S FAMILY

3297. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the unusual circumstances in which the income-tax case/cases of Shri Ramnarayan Ruia family (Bombay) was/were settled by the income-tax authorities in 1956-57;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any inquiry has been ordered; and

(d) if so, the result of the inquiry ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The attention of the Government has been drawn to the assessments made in March 1955 in the case of Ramnarayan Sons (P) Ltd. There were no unusual circumstances.

(b) The assessee claimed speculation losses of Rs. 58.72 lakhs. The details of losses claimed and suspected to be fictitious of each assessment year are as under :—

Assessment year	Speculation losses suspected to be fictitious (Rs. in lakhs)
1944-45	11.57
1945-46	3.28
1946-47	5.45
1947-48	1.82
1948-49	10.41
1949-50	14.67
195 -51	9.16
1951-52	2.36
	Rs. 58.72

The Income-tax Officer completed the assessment for the assessment years 1944-45, 1948-49 and 1949-50 on 6-2-1954, 31-3-1953 and 30-6-1954 respectively, and disallowed the entire loss of Rs. 36.65 lakhs suspected to be fictitious.

The Income-tax Officer was making enquiries about the genuineness of losses in respect of the remaining assessment years. The jurisdiction over the case was transferred to an investigation circle in the Bombay Central charge to enable investigations being made properly.

The Director of Inspection (Investigation), after examining the evidence on record and the report of the Income-tax Officer, gave instructions as to the manner of completion of the assessment on 12-3-1955 to the Commissioner of Income-tax. In accordance with these findings, the assess-

ments for the assessment years 1944-45 to 1951-52 were completed. The details of speculation losses allowed and disallowed in each assessment year and the dates of these assessments are as under :—

	Speculation losses disallowed as fictitious.	Speculation losses allowed as genuine.	Date of assessment.
	(Rs. in lakhs.)	(Rs. in lakhs.)	
1944-45	2.73	8.84	15-3-1955
1945-46	3.00	.28	16-3-1955
1946-47	nil	5.45	30-4-1947
1947-48	1.50	.32	16-3-1955
1948-49	2.50	7.91	14-3-1955
1949-50	nil	14.67	22-3-1955
1950-51	7.00	2.16	23-3-1955
1951-52	1.50	.85	24-3-1955

(c) and (d) . No inquiry has been considered necessary as it is part of the duty of the Director of Inspection (Investigation) to examine cases of this nature and give instructions to the field officers.

Loops

3298. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while participating in a Seminar in New Delhi the Minister of State in his Ministry had acknowledged that the Lippe's Loop had instructural defects and that 100 million Soviet Loops ordered by Government were claimed to be 100 per cent successful;

(b) if so, the expenditure incurred so far in popularising Lippe's Loop;

(c) the clinical or other tests which were carried out before Government could come to the conclusion that the Russian loops would be suitable to the Indian conditions;

(d) whether the opinion of the experts both in India and foreign countries was obtained; and

(e) whether Government have taken steps to withdraw the defective loops ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) The Lippe's Loop used at present has been found to have some minor side-effects, like bleeding, headache etc. in a small percentage of cases, but these can be removed by a proper follow-up A few Russian Loops have been obtained for testing. No clinical trials have yet been undertaken.

(b) The publicity and motivational efforts of Government are for the propagation of the entire Family Planning Programme. It is not possible to calculate the expenditure on publicity for Loop alone.

(c) to (e). Do not arise.

Subordinate Offices of the Ministry of Irrigation and Power

3299. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the technical and other staff recruited in all the subordinate offices of his Ministry for formulating or implementing schemes under all the three Five Year Plans have completed their job;

(b) whether it is also a fact that they do not have in hand as many subsidiary schemes in the Fourth Plan as they had during first three Plans;

(c) if so, whether Government propose to retrench or transfer the officials who have no work; and

(d) whether Government have thoroughly looked into the working of all the subordinate offices ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (d). A number of schemes in included in the Third Five Year Plan are still continuing and some new schemes are also being taken up. Temporary staff engaged on any one item of work are, on completion of the assignment, shifted to another work as far as possible, and only when it is found that it is not possible to absorb surplus staff that they are given notice of termination of service. The work load of subordinate offices is constantly reviewed and all possibilities of providing alternative employment to those who might become surplus are explored.

PRODUCTION OF FERTILIZERS

3300. SHRI SHRI CHAND GOEL :
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI :
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI:
DR. SURYA PRAKASH PURI :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the requirements of the country for fertilizers to increase agricultural production to the desired limit;

(b) the installed capacity of the country at present; and

(c) the steps taken to meet the full requirements ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PEROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The requirements of fertilizers by 1970-71 have been estimated as follows :—

(i) Nitrogenous Fertilizers:	2·4 million tonnes of nitrogen
(ii) Phosphatic fertilizers:	1·0 ,, ,, of P_2O_5
(iii) Potassic fertilizers	0·7 ,, ,, of K_2
(b) Nitrogenous fertilizers:	6,81,00 tonnes of Nitrogen
Phosphatic fertilizers	2,86,830 tonnes of Nitrogen P_2O_5

(c) It is proposed to meet the requirements by establishing new fertilizer factories and expanding the existing factories. Apart from the fertilizers projects which will go into production shortly, *viz.* Namrup and Gorakhpur in the public sector and Visakhapatnam and Ennore Expansion in the private sector, additional fertilizer factories are being built or have been approved at Durgapur, Cochin, Madras, Barauni, Namrup (Expansion) and Trombay (Expansion) in the public sector.

New fertilizer factories in the private sector have been approved at Kota, Kanpur, Goa, Mangalore, Gaziabad, Mirzapur, Visakhapatnam (Expansion) and Bajwa (Expansion) near Baroda. Besides a fertilizer factory is being set up at Kandla in the cooperative sector. As some of these factories are not likely to reach their full production capacity by 1970-71, import of nitrogenous and phosphatic fertilizers is also envised. In the case of Potash, the entire requirement will have to be imported.

दिल्ली में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

3301. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रामजी राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल दिल्ली में तस्करी की वस्तुएं बड़े पैमाने पर बेंची जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं में अधिकांशत: फाउन्टनपेन, कास्मेटिक्स तथा अन्य इसी प्रकार की छोटी वस्तुएं शामिल हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का यत्न किया है कि ये वस्तुएं वहां कैसे पहुंची हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). घड़ियां, फाउन्टन पेन तथा सौंदर्य प्रसाधन जैसी विदेशी वस्तुएं दिल्ली में थोड़ी बहुत मात्रा में बेची जाती हैं। ऐसी वस्तुएं विदेशों से आने वाले यात्रियों द्वारा अपने असबाब के रूप में प्राय: लायी जाती हैं और उसके बाद ये वस्तुएं बाजार में पहुंच जाती हैं। ये वस्तुएं कभी-कभी भारत में पश्चिमी समुद्रतट के मार्ग से भी चोरी-छिपे लाई जाती हैं।

मंदी

3302. श्री ना० स्व० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मंदी और उसके बाद" पर आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा व्यक्त निष्कर्ष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार वर्तमान मंदी के कारणों को जानती है और उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए, वह समय-समय पर, उपाय करती रही है।

AIRFIELD NEAR BARMER

3303. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is fact that a number of complaints about corruption and pilferage of cement have been made against the behaviour and conduct of the Executive Engineer incharge of Buliding on airfield near Barmer in Rajasthan; and

(b) if so, the steps taken by Government to investigate the complaints ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Three complaints have been received against the behaviour and conduct of the Executive Engineer in charge of the constructions at Barmer in Rajasthan. Two of them were anonymous and the other was found to be pseudonymous on investigation.

(b) An Engineer Officer of the Vigilance Unit of the C.P.W.D. was deputed to investigate into the allegations at site. No cases of corruption were established and there was found to be no pilferage of cement.

LIVING CONDITIONS OF SCAVENGERS ETC.

3305. SHRI RANDHIR SINGH : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether any financial assistance has been given to State Governments to improve the lot of scavengers and their pay scales and wages during the current year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हड़ताल

3306. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि सिन्दरी उर्वरक कारखानें के कर्मचारियों द्वारा हाल में की गई हड़ताल के कारण प्रतिदिन अनुमानत: कितना नुकसान हो रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : १२ दिनों की हड़ताल की अवधि में ६७ लाख रुपये की हानि अनुमानित है अर्थात् प्रति दिन लगभग ५.५८ लाख रुपये।

LOSS IN P.W.D., MANIPUR

3307. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether any inquiry has been made into the loss and disappearance of (i) 500 cement bags from the P.W.D. godown at Chingmierong (Manipur) in the early part of 1964 and (ii) loss of Rs. 15,000/- in the Imphal East Division P.W.D., Manipur recently during the current year, and

(b) if so, the result of the inquiry ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes. Inquiry has been made both by the Police and departmentally. The cash lost in Imphal East Division is Rs. 18.502 and not Rs. 15,000/-.

(b) *Case (i)*. Found true but undetected by Imphal Police. Preliminary departmental inquiry is also being made and has not yet been concluded.

Case (ii). This is still under investigation by Imphal Police and has not concluded. The Manipur Administration have suspended the Cashier of the Division and have asked the Chief Engineer, C.P.W.D. to initiate departmental action against the concerned Executive Engineer who was the drawing and disbursing officer of the Division. This is being done.

RELIEF FUND FOR ORISSA

3308. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to allocate additional funds for Orissa State for its Fourth Plan as a special case in view of the unprecedented floods, cyclone and drought in that State; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

RAMAGUNDA PROJECT

3309. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ramagunda site on the Akravathy river for the Ramagunda project is not considered suitable and an alternative site has been proposed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to make their own estimate and collect data for the proposed project before coming to any conclusion as regards the two sites ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) A dam at Ramagunda site with F.R.L. 2445 will not be able to control floods and any level higher than this for the dam is not practicable, as it will affect the water works for Bangalore located at Tippagondanahalli.

(c) No. The Government of Mysore have been requested to carry out further investigations on the Manchanabele site.

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

3310. श्री निहाल सिंह :

श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बतानें की कृपा करगे कि :

(क) क्या गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने ने ठीक प्रकार से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितना धन व्यय हो चुका है;

(ग) क्या यह कारखाना किसी विदेशी फर्म अथवा कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में निश्चित की गई शर्तें क्या हैं ? और

(घ) इस कारखाने में किस किस्म के उर्वरकों का उत्पादन होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । उपकरणों की कार्यान्विति के परीक्षण प्रगति पर हैं ।

(ख) अक्तूबर, 1967 तक कारखाने के निर्माण पर लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(ग) जी, नहीं । परन्तु मुख्य सन्यन्त्र, जापान की टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन से प्राप्त किये गये हैं ।

(घ) उत्पादन शुरू हो जाने पर कारखाने में फर्टीलाइजर ग्रेड परिल्लड यूरिया (Fertiliser grade prilled urea) तैयार होगा ।

IMMORAL TRAFFIC IN WOMEN IN DELHI

3312. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the steps so far taken by Government to check immoral traffic in women in Delhi; and

(b) the result achieved so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, which has been enforced in Delhi since 1st May, 1958, prohibits immoral traffic in women. Necessary steps, *e.g.*, setting up of Protective Home; appointment of Special Police Officers; constitution of non-official Advisory Committee, etc., as contemplated in the Act have been taken by the Delhi Administration.

(b) As a result of the enforcement of the Act, the red light areas have been closed.

क्षतिग्रस्त बांध

3313. श्री निहाल सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 20 वर्षों में कितने बांध बनाये गये और उनमें से जनवरी 1967 मे लेकर अब तक कितने बांध टूटे हैं;

(ख) इससे कितनी जनहानि हुई है और सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इन बांधों में दरारें पड़नें के कारणों का पता लगाने के लिय जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इनके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 1967 की मानसून में केवल एक नानक सागर नामक बांध में ही दरार आई थी जो कि उत्तर प्रदेश की द्योहा नदी पर स्थित है ।

(ख) इस दरार से नैनीताल और पीलिभीत के जिलों में निम्नलिखित क्षतियां हुई :—

	लाख एकड़
प्रभावित क्षेत्र	2.76
क्षतिग्रस्त मकान	822
मृत व्यक्ति	46
मृत मवेशी	522

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की है । इस समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

PROHIBITION LAWS IN DELHI

3314. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have asked the Delhi Administration to liberalise prohibition laws in Delhi;

(b) if so, the broad proposals thereof; and

(c) the reaction of the Delhi Administration thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) (a) to (c). There is a ban on drinking in public and 132 days in the year are observed as dry days in Delhi. There has been a relaxation of the ban on drinking in public in

favour of foreign tourists as part of the measures to promote tourist traffic to India. These are :

(i) The provision of a separate room in select hotels for the exclusive use of foreign tourists where alcoholic beverages can be served to them with or without food;

(ii) foreign tourists have been permitted to entertain their guests both foreign and Indian in the separate room;

(iii) foreign tourists have been permitted to consume alcoholic beverages along with their meal in the dining rooms of the select hotels;

(iv) Indian residents of the select hotels have been permitted to entertain their foreign guests in the separate room except on dry days;†

(v) foreign tourists can buy alcoholic bevergaaes even on dry days.†

TAKING OVER OF CALTEX INSTALLATION, CALCUTTA

3315. SHRI P. GOPALAN :
SHRI VISHWANATHA MENON :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI E. K. NAYANAR :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation is going to take over Paharpur installation of Caltex (India) Ltd. in Calcutta; and

(b) if so, the policy Government propose to adopt about the staff of this installation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

OUTLAY ON IRRIGATION AND RURAL ELECTRIFICATION

3316. SHRI MARANDI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to increase the outlay on irrigation and rural electrification by Rs. 50 crores in the current year;

(b) if so, how this amount is likely to be utilised;

(c) whether it is also a fact that Government have asked the Reserve Bank of India to grant loans to the farmers for irrigation and electricity through the Agricultural Finance Corporation of India; and

(d) whether any negotiations are also being conducted with the World Bank for funds for this purpose ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) A proposal for the financing of such works through Agricultural Refinance Corporation is under consideration.

(d) No.

INFRUCTUOUS EXPENDITURE ON DRINKING WATER SUPPLY IN DELHI

3317. SHRI MARANDI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of rupees spent on finding new sources of drinking water supply to the capital have gone waste;

(b) whether the schemes did not materialise due to the objections raised by the Governments of U.P. and Haryana; and

(c) if so, the nature of these objections ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) No.

(b) The following scheme was given up due to objections raised by the Government of Haryana :

Arangpur Reservoir Scheme.

Government of U.P. objected to Ghaziabad Tubewell Scheme.

(c) The Government of Haryana did not agree to the building of a reservoir at Arangpur for water supply to Delhi as, according to them, it involved the problem of submergence of a developing village. Alternative sites at Dhauj and Kot are being investigated.

As regards the Ghaziabad Tubewells Scheme the Government of U.P. felt that tubewells for water supply to Delhi will interfere with their programme of utilisation of ground water resources for development of irrigation in the State. Investigations are however, being undertaken for deep tubewells in nearby areas.

ANTI-ADULTERATION DRIVE IN DELHI

3318. SHRI DHIRESHWAR KALITA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the anti-adulteration drive in Delhi has not been effective because the local bodies do not have enough resources to fight the evil; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No.

(b) The following steps have been taken for prevention of food adulteration in Delhi :—

1. Very careful checking of quality is done at the mills and godowns.

2. The Delhi Municipal Corporation has employed 8 wholetime Food Inspectors to lift samples under the Prevention of Food Adulteration Act. Besides, all Sanitary Inspectors in Delhi have been delegated the powers to act as Food Inspectors under the Act.

3. The Delhi Municipal Corporation have designated one Assistant Health Officer specially for implementation and co-ordination of Prevention of Food Adulteration activities in Delhi. All Deputy Health Officers, Assistant Health Officers, and Chief Sanitary Inspectors of Municipal Corporation of Delhi, are empowered to exercise the powers of Food Inspectors.

4. One Municipal Prosecutor assisted by Assistant Municipal Prosecutor has been engaged exclusively by the Delhi Municipal Corporation for dealing with the cases under the Prevention of Food Adulteration Act in the Courts.

5. The Food Laboratory of Municipal Corporation, Delhi has been fully equipped and staffed to deal with the problem.

6. Frequent raids are conducted.

7. A very close check is being kept on the sale of unwholesome food stuffs exposed to dust and flies.

8. The Central Bureau of Investigation and Delhi Administration review and co-ordinate the activities in this field.

DRILLING OPERATIONS IN THE GULF OF CAMBAY

3319. SHRI MAYAVAN :
SHRI RAJDEO SINGH :
Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the oil and Natural Gas Commission has considered the question of carrying out drilling operations of some of the structures in the Gulf of Cambay directly; and

(b) whether any settlement has been reached with the foreign countries for drilling on the other structures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) Not yet.

SIMPLIFICATION OF DIRECT TAX LAW

3320. SHRI MAYAVAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have implemented all the recommendations made in the interim report of Shri Bhoothalingam on rationalisation and simplification of direct tax law;

(b) if not, how many of them have been accepted by Government;

(c) the steps taken to implement them; and

(d) the reasons for not accepting the remaining recommendations ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) to (d). A list of recommendations in Shri Bhoothalingam's First Interim Report on rationalisation and simplification of direct tax laws, with remarks indicating the

action taken thereon, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1905/67].

PAVEMENT SLEEPERS

3321. SHRI MOHAN SWARUP :
SHRI K. P. SINGH DEO :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of pavement sleepers is more than five thousand in the Capital;

(b) whether it is also a fact that the Corporation has asked for a grant of Rs. 15 lakhs for the construction of pucca shelters for the use of these pavement sleepers; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH : (a) Yes, but the number of persons requiring night shelters has been assessed to be between 4,000 to 5,000.

(b) No.

(c) Does not arise.

CONSTRUCTION OF HOUSES

3322. SHRI MOHAN SWARUP :
SHRI DHIRESWAR KALITA :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while the shortage of houses in the country had been increasing, the construction of new houses had lagged far behind the demand; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard during the next annual plans being envisaged shortly ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes. At the end of the Third Five-Year Plan, the overall shortage of houses was estimated at 714 lakhs—114 lakhs in urban areas and about 600 lakhs in rural areas including about 530 lakhs of 'kacha' houses which required to be rebuilt or improved substantially.

(b) Due to pressing demands on limited national resources for other developmental projects such as agriculture, irrigation, power, etc., it is not possible to provide sufficient funds for housing unless it is given a sufficiently high priority in the National Plan. However, during the recent Conference of Ministers of Housing, Urban Development and Town Planning held in Madras in November, 1967, it was impressed upon the State Governments that they should give adequate priority and provide larger funds for housing and that funds provided for housing should not be diverted to other development projects. It is expected that the annual State Plans for Housing for 1968-69 would provide for construction of over 30,000 houses.

TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION

3323. SHRI DHIRESWAR KALITA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether there is any move to accelerate the activities of Town and Country Planning Organisation; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). Town and Country Planning is a State subject. However, the Government of India initiated a Scheme for providing cent per cent financial assistance to the State Governments for the preparation of comprehensive development plans for 93 cities and towns included in the Third Five Year Plan. Against an allocation of Rs. 3 crores, the States incurred an expenditure of about Rs. 1.60 crores only during Third Plan period. For 1966-67 and 1967-68 an allocation of Rs. 1.65 crores has been made to the State Governments. As against 93 projects included in the Third Five Year Plan, 206 more projects have been included in the Draft Outline of the Fourth Plan. The State Governments have also been requested to enact suitable legislation to facilitate the implementation of the development plans. The Town and Country Planning Organisation has been directed to provide necessary technical advice to the State Governments to achieve the targets. It has also been asked to undertake the preparation of the development plan for the South East Region besides the National Capital Region.

दिल्ली में तस्करी

3324. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में दिल्ली कलैक्टोरेट ने कितनी मोटर-गाड़ियां जब्त कीं ;

(ख) कितनी मोटर-गाड़ियों का नीलाम किया गया और कितनी बिना बिकी पड़ी हैं; और

(ग) नीलाम की गई मोटर-गाड़ियों की बिक्री से कितनी आय हुई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले पांच सालों में दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, ने तस्कर व्यापार के सिलसिले में 53 वाहन पकड़े। इनमें से 45 वाहन जब्त कर लिय गये और आठ छोड़ दिय गये।

(ख) 9 वाहन नीलाम कर दिये गये हैं और 36 वाहनों का निपटान होना है।

(ग) 25,900 रुपये।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

3325. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रामजी राम :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व तथा उत्पादन-शुल्क बोर्ड में काम कर रहे पांच निदेशकों के अधीन कितनें विभाग हैं जहां कोई भी भर्ती नियम आदि नहीं बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या शिकायतें मिली हैं और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को दो बोर्डों अर्थात् केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड में पुर्नगठित किया गया है। इन दो बोर्डों के अधीन निम्नलिखित पांच निदेशालय हैं :

(1) निरीक्षण निदेशालय (आयकर);
(2) निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल);
(3) निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा, आसूचना तथा प्रकाशन);
(4) निरीक्षण निदेशालय (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क);
(5) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय

जहां तक उपर्युक्त (1) से (3) तक के निदेशालयों का सम्बन्ध है, अराजपत्रित श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों के सम्बन्ध में भर्ती नियम बनाये तथा अधिसूचित किये गये हैं। इन निदेशालयों के अराजपत्रित पद सामान्य रूप से आयकर विभाग के सम्बन्धित संवर्गों के अधिकारियों से भरे जाते हैं।

जहां तक उपर्युक्त (4) तथा (5) निदेशालयों का सम्बन्ध है, श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों पर भर्ती सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये कार्यकारी आदेशों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। औपचारिक भर्ती नियमों की रूप-रेखा तैयार की गयी है तथा उन पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है।

जहां तक निरीक्षण निदेशालय (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क) तथा

राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय का सम्बन्ध है, इन निदेशालयों में, प्रशासनिक अधिकारी के पदों को छोड़ कर, राजपत्रित श्रेणी I तथा II के सभी पद; सीमित कार्यकाल के आधार पर, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालयों से आने वाले अधिकारियों से भरे जाते हैं। निरीक्षण निदेशालय (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क) में श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों के सम्बन्ध में भर्ती के नियम अधिसूचित किये गये हैं। राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के सम्बन्ध में, प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिये भर्ती के नियम बनायें तथा अधिसूचित किये गये हैं, अन्य पदों के सम्बन्ध में भर्ती के नियम तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को अभी तक कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गर्भपात से मृत्यु

3326. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रामजी राम :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कुछ समय पूर्व कलकत्ता में कहा था कि गर्भपात के कारण प्रतिवर्ष दो लाख महिलाओं की मृत्यु होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। 7 नवम्बर, 1967 को कलकत्ता में "परिवार नियोजन" की एक गोष्ठी के उद्घाटन भाषण में मैंने कहा था कि अनुभवहीन-चिकित्सकों और नौसिखिए व्यक्तियों के हाथों गर्भपात के कारण प्रतिवर्ष दो लाख महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

(ख) इस समस्या को सुलझाने वाले उपायों पर विचार किया जा रहा है। एक ऐसा उपाय गर्भपात कानून को उदार बनाना हो सकता है। शांतिलाल शाह समिति ने भी इसकी सिफारिश की है।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में क्वाटरों का आवंटन

3327. श्री रामजी राम : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् में सेक्टर 8 में हाल ही में जिन क्वाटरों का आवंटन किया गया है, उनमें बिजली और पानी नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने क्वाटर पाने वाले लोगों को स्पष्टतया कह दिया है कि कम-से-कम एक वर्ष तक बिजली नहीं दी जा सकती और अलाटियों को स्वयं प्रकाश का अपना प्रबन्ध करना होगा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पानी तथा बिजली की पर्याप्त व्यवस्था किये बिना क्वाटरों का आवंटन किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जो क्वार्टर आवंटन के लिये दिये गये हैं उन सब में पानी की व्यवस्था कर दी गयी है किन्तु बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ): दिल्ली में सामान्य पूल में निवास स्थानों की अत्यधिक कमी है तथा निवास स्थान के आवंटन के लिए निरन्तर सरकारी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया कि जब तक दिल्ली नगर निगम बिजली देने में समर्थ नहीं होता, रामकृष्णपुरम् के सेक्टर VIII के बगैर बिजली के क्वार्टरों का आवंटन कर दिया जाये।

NEW FERTILIZER FACTORIES

3328. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) when the four new fertilizers factories in the public sector will go into production; and

(b) the total estimated production capacity of each of them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The dates of production of the new fertilizers projects in the public sector under various stages of construction are given below :

(i) Gorakhpur—December, 1967.

(ii) Namrup—January, 1968.

(iii) Durgapur—October, 1969.

(iv) Cochin—October, 1969.

(v) Madras—March, 1970.

(b) the capacities of the projects are as follows :

Nitrogen

(i) Gorakhpur—80,000 tonnes/annum.

(ii) Namrup—45,000 tonnes/annum.

(iii) Durgapur 1,52,000 tonnes/annus.

(iv) Cochin—1,52,000 tonnes/annum.

(v) Madras—1,90,000 tonnes/annum.

LOCATION OF WORLD BANK'S STAFF IN DELHI

3329. SHRI JANARDHANAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the World Bank has a proposal to base a large staff in New Delhi to collect information directly about India;

(b) whether the Bank has sought Government's approval for its proposal; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). The World Bank has decided, in consultation with the Government of India, to have seven professional staff in India. This has been done to enable the Bank to have current information about the progress of projects for which the Bank grants loans; and, in its capacity as the leader of the Aid India Consortium, to enable it together information about current economic development, without having to send large and frequent missions.

चांदी का मूल्य

3330. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चांदी के बढ़ते हुए मूल्यों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि चांदी के आभूषणों का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जी, हां । सरकार ने हिदायतें जारी की हैं कि चांदी के जेवरों, चांदी की बनी वस्तुओं आदि के निर्यात के लिए तभी लाइसेंस दिया जाय जब उनका घोषित मूल्य चांदी के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और उसके पांच प्रतिशत भाग के जोड़ से कम न हो । इन चीजों को चोरी से लाना ले जाना रोकने के लिए जोरदार कार्रवाई की गई है ।

दिल्ली विकास प्राधिकार के कर्मचारियों को बोनस

3331. श्री राम गोपाल शालवाले : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने अपने कर्मचारियों को 10 प्रतिशत बोनस देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन अन्य कार्यालयों को ऐसा कोई बोनस नहीं दिया जाताहै; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को 4 प्रतिशत बोनस का अन्तरिम भुगतान किया है। प्रतिशत का अन्तिम रूप से अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अधीन सरकारी कर्मचारी बोनस के अधिकारी नहीं हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, 1947 की परिभाषा के अनुसार "औद्योगिक कर्मचारी" (इंडस्ट्रियल वर्कर्स) हैं अतएव वे बोनस एक्ट, 1965 में आ जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि की खरीद

3332. **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अर्जित भूमि किस दर पर खरीदी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही भूमि, विकास के बाद उसके द्वारा ऊंचे दामों पर बेची गई थी; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष में उक्त प्राधिकार ने इस प्रकार कितना लाभ कमाया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

Cancer by Mainpuri Tobacco

3333. **SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :**
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI SHARDANAND :
SHRI N. S. SHARMA :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a survey on cancer of mouth sponsored by the World Health Organisation and carried out by a team headed by the Principal of the S. N. Medical College, Agra, has reported that Mainpuri tobacco is the main cause of Oropharyngeal Cancer; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes.

(b) Health education is directed at discouraging the chewing of tobacco.

पालम हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

3334. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4835 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा के पकड़े जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग). पकड़ी गई मुद्रा भारतीय थी; विदेशी नहीं थी। करनिर्धारिती द्वारा दायर की गई रिट दरख्वास्त पर उच्च न्यायालय के आदेश से इस मामले में आगे की पूछताछ रोक दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

3335. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 के तीसरे सप्ताह में बम्बई में लखोनी बेदार में 30 लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 21 अगस्त 1967 को लकड़ी बन्दर के पास, विदेशी मार्का के सोने के पाये पकड़े थे जिनका मूल्य उस समय के बाजार भाव से लगभग 29 लाख रुपये होता था।

(ख) आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और जमानत पर छोड़ दिये गये । आगे जांच पड़ताल चल रही है।

दिल्ली के बैंकों में मियादी जमा की रकमें

3336. **श्री शशिभूषण वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान, दिल्ली के ऐसे बैंकों की ओर दिलाया गया है, जिन में 1947 से बहुत से ऐसे लोगों की मियादी जमा की रकमें मौजूद हैं, जो जमाकर्ताओं को 1948 में लौटा दी जानी चाहिए थीं, लेकिन अभी तक वापस नहीं की गयी हैं ? और जब जमाकर्ता इस सम्बन्ध में अफसरों से मिलते हैं, तो उनको किसी प्रकार टाल दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पंजाब और कश्मीर बैंक की ओर दिलाया गया है, जो अभी कारबार कर रहा है और जिसने जमाकर्ताओं को अभी तक उस रकम की अदायगी नहीं की है, जो उसके पास 1947 से पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों से जनता को रकमों की अदायगी कराने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है; और

(ङ) विभाजन से पहले जमा की गयी रकमों की वापसी से सम्बन्धित नियम क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) उन बैंकों को छोड़ कर जिनका परिसमापन हो रहा हो या जो किसी न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत काम कर रहे हों या उस स्थिति को छोड़कर जिस में जमा की गयी रकमें ऐसी जमानतों के रूप में हों, जो करार (काण्ट्रैक्ट) पूरा होने पर ही वापस की जा सकती हैं, सरकार को दिल्ली के ऐसे किसी भी बैंक के बारे में जानकारी नहीं हैं जिसने मियादी जमा की रकमें मियाद पूरी होने पर वापस न की हों।

(ग) और (घ) पंजाब और कश्मीर बैंक, पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा मई 1948 में स्वीकृत और समय समय पर संशोधित प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत काम कर रहा है। न्यायालय के निदेशों के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को देय रकम का 10 प्रतिशत बैंक के शेयर खरीद कर चुकाया जा चुका है। जिन जमाकर्ताओं ने 15 अगस्त 1947 को बैंक के पास जमा अपनी रकमों का कम से कम 25 प्रतिशत वापस नहीं लिया है उन्हें उतनी रकम की अदायगी की जायगी जिससे उनके द्वारा निकाली गयी रकमें उनकी उपर्युक्त जमा रकमों के 25 प्रतिशत के बराबर हो जायें। उन्हें यह अदायगी बैंक द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार से मुआवजे की रकम मिलने की तारीख से छः महीने की अवधि के अन्दर की जायगी। वसूली न होने और जिन दावेदारों से बैंक को रकमें मिलनी हैं, उनका पूरा ब्योरा प्राप्त न होने के कारण मुआवजे

की लगभग 53 प्रतिशत रकम अभी तक चुकायी नहीं गयी है।

(ङ) विभाजन से पूर्व उन क्षेत्रों में जमा की गयी रकमों की निकासी के बारे में कोई विशेष नियम नहीं हैं, जो अब भारत के अंग हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य चिकित्सा सेवा

3337. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि मैडिकल कालेजों में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थियों को ग्रामों में कार्य करने के लिये भेजा जाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के कब से क्रियान्वित किऐ जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री पति चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) डीन और प्रिंसिपल सम्मेलन में इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की गई, उस पर सरकार विचार कर रही है और राज्य सरकारों तथा चिकित्सा सकायों (मेडिकल फैकल्टियों) से सलाह मांगी गई है।

करेंसी नोटों की छपाई

3338. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1966–67 में प्रतिदिन 1.3 करोड़ रुपये के मूल्य के करेंसी नोट छापने का फैसला किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मार्च 1967 में हर रोज 3 करोड़ रुपये के मूल्य के करेंसी नोट छापे जाते रहेहैं; और

(ग) यदि हां, तो उस करेंसी का प्रतिशत क्या है, जिसके लिए प्रारक्षित निधि रखी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1966–67 म करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड ने लगभग 4.8 करोड़ रुपये के मूल्य के नोटों के दैनिक औसत के हिसाब से लगभग 1763 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट छापे।

(ख) 6.73 करोड़ रुपये के मूल्य के नोटों के दैनिक औसत के हिसाब से, मार्च, 1967 में 201.90 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट छापे गये।

(ग) किसी भी अवधि में छापे गये नोटों का स्टाक, शुरू में, करेंसी नोट प्रेस में या रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों और मुद्रा-तिजोरियों (करेंसी चेस्ट) में रखा जाता है और उनमें से बहुत से नोट फटे पुराने नोटों के बदले जारी किये जाते हैं। वास्तव में जारी किये गये नोटों के लिए ही प्रारक्षित निधि (रिजर्व) रखी जाती है। इनके लिए पूरी पूरी प्रारक्षित निधि रखी जाती है।

Interest Paid to Foreign Countries

3339. **SHRI HARDAYAL DEVGUN** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the total amount of interest paid by Government to the foreign countries during he last three years, year-wise ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : The total amount of interest paid by Government to the foreign countries/agencies during the last three years is as under :—

(Rs. crores.)

Year	Amount
1964-1965	80.95
1965-1966	84.84
1966-1967	124.37

(Figures given above represent the amounts actually paid at the rates of exchange prevailing from time to time, (*i.e.*) those paid upto 5-6-1966 at predevaluation rates and those paid thereafter at post devaluation rates).

AID RECEIVED FROM EAST AND WEST GERMANY

3340. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total aid received from the East and West Germany during the last 3 years, year-wise; and

(b) the aid likely to be received during the next three years ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The aid from the Federal Republic of Germany during the last three years is as follows :—

	Rs. crores
1964-1965	73.08
1965-1966	66.07
1966-1967	48.46

No aid has been received from East Germany.

(b) The foreign aid is received on an annual basis and it is not possible to indicate the aid likely to be received during the next three years.

BIFURCATION OF EYE AND E.N.T. DEPARTMENTS

3341. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the decisions of the Indian Medical Council, the Eye and E.N.T. Departments have to be bifurcated in all the Medical Colleges of the country;

(b) if so, the names of the Medical Colleges where these Departments have not so far been bifurcated; and

(c) the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The recommendations of the Medical Council of India on the subject of *standard* requirements for medical colleges indicate, *inter alia*, that the Departments of Eye and E.N.T. at the Under-graduate level should be bifurcated. However, no such specific directive has been issued by the Council in this behalf.

(b) and (c). In the background of the reply to part (a), this information has not been compiled.

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मेसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई

3342. श्री ओंकार सिंह : क्या वित्त मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8691 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मेसर्स मैकन्जीज लिमिटेड के बीच साझेदारी आरम्भ करने के समय हुये करार की शर्तों तथा निबन्धों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन कम्पनियों ने कुल कितने ठेके लिये हैं और इन्होंने सरकार को कितना आयकर दिया है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों को दी गई मजूरी के आंकड़े, जो आयकर प्राधिकारियों को बताये गये हैं, बढ़ाकर दिये गये हैं ;

(घ) मेसर्स मैकेन्जीज लि० को संचालकों के बारे में जानकारी प्राप्त न कर सकने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त कम्पनियों के बोर्डों के प्रत्येक सदस्य की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) साझेदारी करार में हस्ब मामूल धाराएं हैं जिनमें लाभ-विभाजन के अनुपात, साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी और साझेदारी में किये जाने वाले व्यवसाय का निर्देश है।

(ख) चार ठेके लिये गये थे। इन दो फर्मों द्वारा इन ठेकों के सम्बन्ध में दिये गये कर की रकम 1,25,200 रुपया है।

(ग) मजदूरी को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की ऐसी कोई बात अभी तक जानकारी में नहीं आई है।

(घ) यह कम्पनी बहुत पहले, अर्थात् 1907 में निगमित की गई थी। प्रवर्तकों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सूचना 20 साल से अधिक पुराने समय से सम्बन्ध रखती है जिसके रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

ALLOTMENT OF QUARTERS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WORKING IN DELHI CANTONMENT

3344. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether any representation has been received from the Delhi Cantonment Area Central Government Employees Association to allot them quarters in Delhi and New Delhi area; and

(b) if so, the result thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). The representation received from the Delhi Cantonment Area Central Government Employees Association is under consideration of the Government.

परिवार नियोजन योजनाएं

3346. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री शारदा नन्द :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य वासियों में और जनता के उन वर्गों में, जिनके धार्मिक प्रमुख परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं, परिवार नियोजन के बारे में प्रतिकूल भावनाओं तथा प्रभाव को दूर करने में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : अनुभव से पता चलता है कि देहातों में परिवार नियोजन के विरुद्ध न कोई व्यापक और न ही कोई संघटित विचारधारा है। जहां कहीं स्थायी अन्ध-विश्वास मौजूद होते हैं, वहां जोरदार प्रेरणा अभियान चला कर उन्हें दूर कर लिया जाता है। क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से प्रगट होता है कि परिवार नियोजन को अपनाने के मार्ग में धर्म कोई रुकावट नहीं है। कई सामाजिक और धार्मिक नेता स्पष्ट रूप से जिम्मेदार पितृत्व का पक्ष ले रहे हैं।

L.I.C. INVESTMENT IN SHARES

3347. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total investment made by the Life Insurance Corporation in shares during the last five years, year-wise; and

(b) the names of industrial concerns and companies in which the Life Insurance Corporation has purchased shares and the details of investment in shares ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a)

Year	Amount of investments
	(Rs. in Crores)
1-1-62 to 31-3-63	15.97
1963-64	9.67
1964-65	10.27
1965-66	23.92
1966-67	6.87

(b) It is not in public interest to disclose the holdings of the Life Insurance Corporation of India in the shares of individual companies.

बम्बई में सोने का तथा अवैध माल का पकड़ा जाना

3348. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त 1967 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में 73 लाख रुपये के मूल्य का अवैध माल पकड़ा गया है, जिसमें 33,000 तोले सोना भी था;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) ये माल और सोना किस स्थान से लाया गया था ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अगस्त 1967 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में 73 लाख रुपये मूल्य का कोई अवैध माल नहीं पकड़ा गया। यह अवश्य है कि 3 अगस्त 1967 को बम्बई से लगभग 60 मील दूर पनवेल-खोपोली मार्ग पर लगभग 35 लाख रुपये मूल्य का अवैध माल पकड़ा गया, जिसमें 33,000 तोले सोना भी शामिल है।

(ख) और (ग). पकड़े गये माल के सम्बन्ध में किसी ने दावा नहीं किया है। मामले की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है।

केन्द्र द्वारा कलकत्ता निगम को देय करों की बकाया राशि

3349. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न पदों के अन्तर्गत कलकत्ता निगम को कितनी बकाया राशि का भुगतान करना शेष है ; और

(ख) अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कलकत्ता निगम ने विभिन्न हिसाबों में 43·34 लाख रुपये की बकाया रकम की मांग की है। इनकी छानबीन की जा रही है और अधिक अदायगी आदि की रकमें घटाने के बाद इस रकम के काफी कम हो जाने की संभावना है।

(ख) सम्पत्तियों के मूल्यांकन की, तथा हिसाब सही तौर से जोड़ा गया है इसकी तस्दीक करने के लिए दावों की छानबीन करने के बाद ही अदायगी की जा सकती है। जिन मामलों में केवल आंशिक सेवाएं उपलब्ध की गई हैं उनमें ऐसे मामले भी हैं जिनमें सही रकम के बिल मिले नहीं हैं। फिर भी मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए सम्बन्धित विभागों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि यदि दावों की छानबीन में देरी लगने वाली हो तो अन्तरिम अदायगी कर दी जाय, और यह किया जा रहा है।

Electricity Requirements of Haryana State

3350. SHRI RANDHIR SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the annual electricity requirements of Haryana State,

(b) how much electricity Haryana State gets now annually as against Punjab;

(c) the agriculture and industries affected in Haryana State by the shortage of power; and

(d) the steps taken to remedy power shortage in future ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (d). The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Jamuna Water Dispute

3351. SHRI RANDHIR SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the dispute over the use of downstream water of river Jamuna at Okhla and at other places for irrigation purposes has been resolved between Haryana and U.P. Governments.

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) The Gurgaon Canal (Haryana State), as approved, is to take off from mile 5 of the Agra Canal (U.P. State). The waters for

Gurgaon Canal will be released in the river Yamuna through the Western Jamuna Canal escapes and are proposed to be let down the Agra Canal by remodelling it upto mile 5.

On account of the difficulties pointed out by U.P. Government in remodelling the Agra Canal, other suitable alternatives for feeding the Gurgaon Canal are being examined at a technical level between the officers of U.P., Haryana and Central Water and Power Commission. Final decision has not yet been made. As an interim arrangement applicable for 1967-68, the present requirement of Gurgaon Canal, which is likely to be about 10% of its full requirements, will be supplied through Agra Canal, after assessing the transmission losses in the Yamuna river.

(b) and (c). Do not arise.

PRICE OF GAS IN ASSAM AND GUJARAT

3352. SHRI R. K. AMIN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the prices fixed for the natural gas in Assam and Gujarat for one cubic metre of gass, and

(b) the reasons for differences between prices of gas fixed in Assam and Gujarat States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The prices of natural gas sold by Oil India Limited in Assam vary from Rs. 0.00877 per cubic metre to Rs. 0.05262 per cubic metre ex-field. The sale price of gas produced by Oil and Natural Gas Commission in Gujarat has been fixed by the Arbitrator at Rs. 0.05600 per cubic metre ex-field.

(b) The prices fixed in Assam are the result of negotiations and agreement between O.I.L., the producer, on the one hand, and the consumers, on the other. The price fixed in Gujarat for gas produced by the O.N.G.C. is the result of an arbitrator's award.

IRRIGATION AND POWER PROJECTS IN RAJASTHAN

3354. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several States are faced with serious deficit in their budgets and in Rajasthan alone the deficit during the current year is expected to be above Rs. 5 crores;

(b) whether it is also a fact that on account of paucity of funds, medium irrigation schemes and power generation projects are being neglected in Rajasthan; and

(c) if so, the manner in which Government propose to deal with the situation so that these projects do not suffer ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) It is a fact that several States are likely to have substantial deficits in their Budgets in the current year. Rajasthan is not expected to have a deficit as a result of the current year's transactions. However, as a result of previous commitments carried forward into the current year, the State Government may end this year with a negative cash balance which may exceed Rs. 5 crores.

(b) Since the resources available to the State Government are limited, it is a fact that the development programmes in all sectors have been affected. However, within the available resources, the question of neglect of any particular sector does not arise.

(c) It will not be possible for the Centre to provide additional assistance beyond what has already been agreed to for the State Plan. It is open to the State Government to provide larger outlays for particular projects within the State Plan, if in their opinion, such projects deserve a higher priority and if they can mobilise resources.

PRE-FABRICATED HOUSES

3356. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government propose to depute some engineers to U.S.S.R. to study the manufacture of pre-fabricated houses; and

(b) if so, whether Government propose to establish more pre-fabricated factories in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH : (a) No.

(b) Does not arise.

JAWAHAR JYOTI

3357. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the cost of carrying the Jawahar Jyoti from New Delhi to Tashkent and back;

(b) the names of persons carrying the Jawahar Jyoti and the expense for them with the manner in which the Jyoti will be taken;

(c) whether this is going to be an annual feature; and

(d) the other countries to which the Jawahar Jyoti will be taken and when and at what cost ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (d) The Jawahar Jyoti was not taken to Tashkent. The question of taking the Jawahar Jyoti to any other country does not arise.

NURSERIES MAINTAINED BY HORTICULTURE DEPARTMENT

3358. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of nurseries maintained by the Horticulture Department and the staff employed in them;

(b) whether Government have enquired that these nurseries are carrying on work commensurate with the expenditure incurred;

(c) whether it is a fact that in many nurseries major portion of the land attached is used for growing vegetables which are consumed by various officials; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) 3 nurseries and 54 employees.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Does not arise.

GOLD SEIZED IN GAUHATI

3359. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggled gold, bearing markings of a London firm, worth Rs. 20,000 was seized from a merchant at Gauhati in August, 1967 and also seized unaccounted gold weighing 60 tolas;

(b) whether it is also a fact that the gold was smuggled through Pakistan and that the merchant concerned had connections in Pakistan; and

(c) if so, whether any further facts have become available as a result of investigation and the action taken against him ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) On 25th August, 1967 100 tolas of gold bearing foreign markings valued at about Rs. 9,900/- at the international rate was seized from a merchant at Gauhati. On the same date Gold ornaments and coins weighing about 58 tolas were also seized from another merchant of Gauhati in the reasonable belief that they were liable to action under the Gold Control Rules.

(b) Investigations so far conducted in the matter do not indicate that the gold bearing foreign marking was smuggled from Pakistan or that the person concerned had connection in Pakistan.

(c) Does not arise.

HINDUSTAN ANTIBIOTICS

3360. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on account of non-payment of dues to their American collaborator by the 28th February, 1966,

the Hindustan Antibiotics had to pay an additional foreign exchange of Rs. 43,468; and

(b) if so, whether responsibility for this delay has been fixed and the action taken against the persons concerned ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) No, Sir, no additional foreign exchange payment was made.

(b) Does not arise.

MAP OF COLONIES IN DELHI

3361. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has neither prepared an up-to-date map of colonies in Delhi, both approved and unapproved, nor possess any data on the houses built in these colonies every year; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

PRICES OF URBAN LAND

3362. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether any technical study has been undertaken on urban land prices in India; and

(b) if so, whether Government propose to lay a copy thereof on the Table of the House ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) A survey of urban land values in selected cities was conducted by the Town and Country Planning Organisation in 1966.

(b) An article on the subject was published in 'Yojana' Annual Number, of 26th January, 1966. A copy is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See.* No. LT-1906/67].

DEFREEZING OF ACQUIRED LAND

3363. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to defreeze the land in Delhi because the Delhi Development Authority is unable to acquire, develop and dispose of land on large scale commensurate with the growing needs of the city of Delhi;

(b) whether it is a fact that the Delhi Development Authority lacks both in finance and competence to meet the situation of all round scarcity of making developed land available;

(c) if so, whether Government propose to have a joint venture of the Delhi Development Authority and the private companies to launch massive construction and renting of houses; and

(d) whether Government propose to appoint a committee to go into the working of the housing and land problems of Delhi and to recommend measures to tide over the housing difficulties for next 50 or 60 years to come ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) No.

COMPULSORY MEDICAL SERVICE IN RURAL AREAS

3364. SHRI SHRI CHAND GOEL : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no adequate arrangements for providing medical aid to the people in rural areas;

(b) wheher Government are contemplating a proposal to make service in rural areas compulsory for some years for the doctors in services; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Medical aid is being provided to people in the rural areas through 4,683 Primary Health Centres located in various States in the country. Besides, there are rural dispensaries of modern and indigenous medicine.

(b) and (c). A medical officer borne on a State cadre is liable to transfer anywhere in the State consistently with his status. This is a matter for the Sate Governments to regulate.

PRICES OF ESSENTIAL CONSUMER GOODS

3365. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the comparative prices prevalent in July, and October, 1967 with regard to the essential consumer goods; and

(b) the percentage increase or decrease in the prices in each case ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). Index numbers of wholesale prices of essential consumer goods at the end of July, 1967 and October, 1967, are tabulated in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1907/67]. Percent changes in these prices are also shown.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

3366. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the amount of assistance sanctioned by the Industrial Development Bank of India during the year ending the 30th June, 1967 has shown a decline;

(b) if so, the extent of decline over the sanctions made in the preceding two years;

(c) the reasons for the decline in assistance loans sanctioned;

(d) whether the Bank has any special scheme for assistance small scale industries; and

(e) if so, the details thereof and how much of the assistance sanctioned during each of the above three years were granted for small scale industries ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER & MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The amount of assistance sanctioned by the Industrial Development Bank of India in 1966-67 recorded some decline compared to the immediately preceding year 1965-66. The aggregate assistance sanctioned by the Development Bank in various forms (excluding guarantees) rose from Rs. 50.50 crores in 1964-65 to Rs. 70.10 crores in 1965-66 and decline to Rs. 64.20 crores in 1966-67.

(c) The overall assistance sanctioned was lower mainly because it was considered necessary, in the prevailing inflationary context and the limited resources available, to adopt a more selective approach in sanctioning assistance, so as to ensure the optimum use of the available funds, and partly due to the decrease in the number of applications for refinance and for direct assistance.

(d) and (e). No special scheme is operated by the Development Bank for assisting small scale industries. The Development Bank has, however, sanctioned refinance assistance in respect of loans to small scale industries of the order of Rs. 4.30 lakhs in 1964-65, Rs. 19.40 lakhs in 1965-66 and Rs. 25.45 lakhs in 1966-67. The Development Bank has also subscribed in a substantial measure to the shares and bonds of State Financial Corporations which cater to the needs of small-scale and medium sized industries.

Recently the Industrial Development Bank has liberalised its scheme of rediscounting bills arising out of sale of indigenous machinery, by abolishing the minimum amount of a transaction in the case of agricultural implements and reducing it from Rs. 50,000 to Rs. 10,000 in the case of other machinery. The maximum period of deferred payment has also been extended from 5 years to 7 years in deserving cases.

C.H.S. DOCTORS' AGITATION

3367. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY

PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a warning of fresh agitation from the C.G.H.S. doctors; and

(b) if so, what are their demands and the action thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No.

(b) Does not arise.

INCENTIVE TO GOVERNMENT EMPLOYEES FOR FAMILY PLANNING

3368. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Government have had under consideration a scheme to offer incentive increments to Government employees who accept the norms of Family Planning; and

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IS THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) to (c). A proposal to grant some increments to those Central Government employees in the lower income bracket, who undergo sterilization after specified number of children, is under consideration of the Government. The details are being worked out.

SHORTAGE IN RE. 1 BUNCH NOTES

3369. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that hundred rupees bundles of one and two rupees notes issued by the Reserve Bank of India are on occasions found to contain one note less than the required number;

(b) if so, whether Government will enquire into the causes of such shortage; and

(c) the steps Government propose to take in this regard ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). Instances of such shortage have been reported on rare occasions. A shortage or excess of one note in a bundle occasionally occurs due to error in bundling. However, a system of elaborate checks and counter-checks is in force at various stages in the Press and the issue offices of the Reserve Bank. Having regard to the large number of notes printed and issued, such occasions have been rare. Complaints brought to the notice of the Bank at the counter are looked into with a view to taking appropriate action against staff concerned.

कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन

3370. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बी०एच०सी०" और डी० डी०टी० कीटनाशी दवाइयों का, जो कृषि के लिये उपयोगी है, उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में घट गया है तथा इस वर्ष और घटने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि खड़िया का चूर्ण मिला कर डी०डी०टी० को अपमिश्रित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस अपमिश्रण को रोकने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं । बी०एच०सी० और डी०डी०टी० के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई बल्कि उत्पादन धीरे-धीरे क्रमशः 1964 में 6156 और 2660 से 1966 में

8277 और 2753 मीटरी टन तक बढ़ गया है । 1967 में 10,000 मीटरी टन बी० एच० सी० और 3200 मीटरी टन डी०डी० टी० के उत्पादन का अनुमान है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है और न ही कोई शिकायत मिली है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

HOLIDAY HOME IN SIMLA

3371. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is only one Holiday Home for the Central Government employees throughout India which is located at Simla, whereas the Departments like that of Railways have several Holiday Homes for their employees all over the country;

(b) whether it is also a fact that in the Holiday Home at Simla, Government have leased out half of the accommodation to a private hotelier thus curtailing the accommodation meant for the Central Government employees who wish to visit Simla for rest and recreation during summer season;

(c) whether it is further a fact that about 30 sets of the Holiday Home have been placed at the disposal of the Himachal Pradesh Government;

(d) if so, whether there is any proposal to terminate the lease and also to take back 30 sets from Himachal Pradesh Government to ease the position for the benefit of the Central Government employees; and

(e) if not, the reasons, therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) and (c). Grand Hotel consists of 141 suites out of which 28 suites were allotted to the Himachal Pradesh Government and some suites were being used as office accommodation. Remaining 99 suites were being used as Hotel which was open both to Government Officers and private persons.

With effect from 15th April, 1965, a portion consisting of 51 rooms out of these 99 rooms has been let out to a private hotelier for running a hotel and the remaining 48 suites have been converted into 'Holiday Home for Government Officials. M.Ps. etc. Accommodation from the 'Holiday Home' has not been leased out.

(d) and (e). Himachal Pradesh Government has already been asked to surrender 28 room in the Grand Hotel but they have not done so. The present period of the lease for the hotel portion expires on 14th April, 1968. The question of further leasing or otherwise is under consideration.

MEDICAL COLLEGE NEAR WARDHA

3372. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1201 on the 1st June, 1967 and state :

(a) whether the Kasturba Health Society Sewagram has since carried out the proposal to open a Medical College near Wardha;

(b) if not, the stage at which the proposal stands at present;

(c) whether the question of rendering financial help to the society has been finalised; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No.

(b) and (c). The Kasturba Health Society's request for financial assistance is under consideration in consultation with the Government of Maharashtra.

(d) Does not arise.

KORBA PROJECT

3373. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the

reply given to Unstarred Question No. 1185 on the 1st June, 1967 and state :

(a) whether the Fertilizer Corporation of India has since submitted the revised report for Korba Project; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) and (b). A Techno-economic Feasibility Study of a Coal-based plant in Madhya Pradesh prepared by the Fertilizer Corporation of India has been received and is presently under the scrutiny of Government.

MAJOR PROJECTS DURING FOURTH PLAN

3374. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the criteria for selection of additional major projects, for which Central assistance is to be given during the Fourth Plan period, have been finalised;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of the projects which have been thus selected for the Fourth Plan ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1908/67].

THERMAL PLANT AT COCHIN

3375. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 231 on the 1st June, 1967 and state :

(a) whether the Central Water and Power Commission have since examined the revised project report regarding Thermal Plant at Cochin forwarded by Kerala Government;

(b) whether a decision regarding the procurement of the generating plant and equipment has been taken; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) The revised report was examined by the Central Water and Power Commission and a Senior Officer of the Commission also visited the project site. The State Electricity Board has been requested to recast the report in the light of the observations of the Commission.

(b) and (c). Decision regarding the procurement of the generating plant & equipment for the project will be taken after the project is recast by the Board and approved by the Central Government.

REPAYMENT OF SOVIET LOANS

3376. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amounts paid to the USSR towards repayment of credits during the period from 1960-61 to 1966-67 year-wise; and

(b) the percentage of our projected exports which will be required to meet our repayment obligations to the USSR from 1967-68 to 1970-71, year-wise on the basis of the trade agreements negotiated recently with the USSR ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The amounts paid during 1960-61 to 1966-67 to the USSR towards interest and principal under the economic co-operation credit agreements are as follows :

(Rs. in crores)

	Principal	*Interest*	*Total*
1960-61	5.43	1.29	6.72
1961-62	5.40	1.21	6.61
1962-63	10.79	1.48	12.27
1963-64	7.86	2.94	10.80
1964-65	8.37	3.78	12.15
1965-66	4.77	5.14	9.91
1966-67	18.54	8.99	27.53

(b) Since repayments of Soviet Credits commence one year after completion of deliveries for each project, it will not be possible to make any accurate assessment of the repayments for credits as a whole, at any time. On current estimates, the payments towards principal and interest, as a percentage of the projected exports to the

USSR, during 1967—71 will be as follows:—

	Percentage
1967-68	28.1
1968-69	26.5
1969-70	23.7
1970-71	20.7

PROVIDENT FUND INVESTED IN GOVERNMENT SECURITIES

3378. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Provident Fund accumulation is invested in Government securities; and

(b) if so, the annual interest paid by Government thereon ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) Provident Fund moneys of Government employees are not invested separately but are treated as deposited with Govt. Moneys belonging to the Employees Provident Fund and the Coal Mines Provident Fund are, however, invested in Central Government securities including Small Savings Securities and State Government securities. No pattern of investment has been prescribed for other Provident Funds but for purposes of securing exemption from income-tax the balances in the Funds have to be invested in accordance with the provisions of the Income-Tax Rules.

(b) Interest is allowed on the balances of the Provident Fund of Government Employees on the broad assumption that the moneys are invested in Government of India securities. The interest rate which was 4.6% last year was raised to 4.8% this year and this rate applies not only to deposits made in the relevant year but to the entire outstanding balances representing deposits made in earlier years. So far as the Employees Provident Fund and the Coal Mines Provident Fund are concerned, interest is determined on the basis of the returns from the investments made. The rate of interest allowed by these two Funds during the current year is 5% and this applies not only to deposits made in this year but to the entire outstanding balances at the close of last year. The rate of interest for the other Provident Fund is determined each year by the Boards of Trustees who administer the Funds.

TRANSFER OF STERLING BALANCES BY PRAMODE PICTURES

3379. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government attention has been drawn towards the illegal transfer of sterling balances by Pramode Pictures from London to Tokyo;

(b) if so, whether the Reserve Bank of India objected to the deal on detection; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Enforcement Directorate received information that M/s. Pramode Films, Bombay had acquired foreign exchange for their location shooting expenses in Japan by remittances from some over-seas distributors.

(b) The required information is being collected from the Reserve Bank of India.

(c) The business and the residential premises of Shri Pramode Chakravarty, proprietor of M/s. Pramode Films, Bombay were searched on the 16th August, 1967 by the Enforcement Directorate and some documents were seized. The investigations are still in progress.

M/S. J. P. AND SONS

3380. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5491 on the the 13th July, 1967 and state:

(a) whether the enquiry being conducted in connection with the non-payment of income-tax by M/s. J.P. and Sons, Bombay has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

IMPORT OF MATERIALS FOR MANUFACTURE OF SPRINGS

3381. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the amount of licences given to those firms for importing the material of springs for motor vehicles who got order and rate contract for the supply of vehicle springs during the last 3 years;

(b) whether it is a fact that some of the firms did not complete the supply but utilized the import licences;

(c) if so, their names and action taken against such firms;

(d) whether it is a fact that some of these firms are still supplying the goods to Government and if so, the reasons therefor;

(e) the action which Government have taken against the officers who did not take any action against such firms; and

(f) whether it is further a fact that some indebtors made complaints to the Director General of Supplies and Disposals for late supply or non supply of springs but no action was taken on these complaints.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a). The Directorate General of Supplies and Disposals entered into rate contracts with five firms for the supply of springs for vehicles in 1965. According to the terms and conditions of these rate contracts, the firms were required to procure the raw materials for the manufacture of the springs under their own arrangements. No assistance for the import of these materials was provided by the D.G.S. & D.

(b) to (f). Do not arise inview of answer to part (a) of the Question.

SUPPLY OF SPRINGS FOR MOTOR VEHICLES

3382. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the rate on which the Director General of Supplies and Disposals purchased springs for motor vehicles during the last two years;

(b) the rate on which the Director General of Supplies and Disposals placed orders for the supply of springs for vehicles recently;

(c) whether it is a fact that the present rate is much less than the rate during the two years though the price of materials has gone up; and

(d) whether Government propose to make an inquiry to find out the reasons for the fall of rates ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) There are more than a hundred items of springs which the Directorate General of Supplies and Disposals have purchased in the last two years. The prices paid by them for some of the main items of springs ranged from Rs. 58.00 to Rs. 26.500 per unit.

(b) to (d). Tenders were recently opened for the various items of springs for different types of vehicles, but no orders have so far been placed. The rates quoted show a general down-ward trend in the prices. This down-ward trend can be attributed to the increased production capacity, easy position of imported raw materials owing to the liberalized imports, and keener competition. The primary function of the D.G.S. & D. is to purchase at the most economical prices. The question of the Government instituting an enquiry does not arise.

BANKING INDUSTRY IN BIHAR

3383. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the banking industry has not developed in Bihar;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how far and of what amount the agriculturists of Bihar have utilized the bank loans since the First Five Year Plan period ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) At the end of 1966, 16 commercial banks with 227 offices were operating in Bihar. There were

also 19605 cooperative credit societies at the end of June 1965 covering nearly 75% of the villages in Bihar. On the basis of these figures Bihar is not as underdeveloped as regards banking as some other States, although there is scope for further improvement.

(b) The number of banks functioning in any region largely depends upon the prospects for attracting large deposits and for the profitable deployment of such funds in trade, commerce, industry and agriculture.

(c) Information regarding the utilisation of commercial bank credit by agriculturists in Bihar is not available. A sum of Rs. 43.33 crores was disbursed by the cooperative credit system at the primary level to the agriculturists between the years 1951-52 and 1964-65.

HOUSING PLAN

3384. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the investments made on housing so far since the First Five Year Plan;

(b) the number of new houses constructed since the First Plan Period;

(c) the target fixed up to the end of the Third Plan and since the post-Third Plan period;

(d) the reasons for not achieving the target;

(e) whether Government have made any provision for the "trailor houses"; and

(f) if so, how many houses have been constructed and sold so far and the price of a single "trailor house" ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). Since the First Five Year Plan upto the end of 1966-67, the total investment from Plan as well as L.I.C. funds for implementation of the social housing schemes of the Ministry of Works, Housing and Supply, was of order of Rs. 284 crores and about 4.2 lakh houses were built under the schemes.

(c) The targets fixed upto the end of Third Five Year Plan period totalled about 6.43 lakh houses. No specific physical targets were fixed for the year 1966-67.

(d) The main reason is that the State Governments do not give sufficient priority to housing. Even the inadequate funds provided in their Annual Plans are not fully utilised. Besides, natural calamities and the successive hostilities with China & Pakistan have also retarded housing activities to a considerable extent.

(e) No.

(f) Does not arise.

COAL-BASED FERTILIZER PLANTS

3385. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up coal-based fertilizer plants besides Nephtha and ammonia-based plants;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the foreign collaboration, if any, sought for the coal-based fertilizer plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) The Fertilizer Corporation was asked to revise the earlier report for Korba on the basis of 600 tonnes of ammonia and 1000 tonnes of urea per day. The report has been received and it is under consideration.

(b) Effective and economic utilization of the coal production capacity that has been built up in the Korba area.

(c) No, Sir.

SETTLEMENT PETITIONS UNDER THE INCOME-TAX ACT, 1961

3386. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of settlement petitions filed under section 271(4A) of the Income-tax Act, 1961 since last two years before the Commissioners of Income-tax, West Bengal, month-wise along with the number of petitions disposed and pending finalisation.

(b) the reasons for the delay in disposal of these cases; and

(c) the steps Government propose to take to expedite the early disposal of all pending petitions ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Steps have been taken to expedite the disposal of all arrear assessments before 31-3-1969. This will result in automatic disposal of the petitions under section 271(4A) as they pertain to arrear assessments.

उर्वरक कारखाने

3387. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी और हालैंड की दो फर्मों ने भारत में तीन उर्वरक कारखानें स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) मार्च, 1967 में लन्दन की ब्रिटिश इंडियन डीवेलपमेंट कारपोरेशन के एक डाइरेक्टर मिस्टर थामस गेस्ट ने पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को एक सामान्य प्रस्ताव भेजा था कि जर्मन, डच्च और ब्रिटिश फर्मों का एक कोंसोरटियम (Consortium) भारत सरकार के सहयोग से उर्वरक कारखानें स्थापित करने की इच्छुक है। प्रस्ताव में सरकार की सांझेदारी के इच्छुक उपक्रमियों द्वारा हमेशा भेजी जाने वाली सूचना उपलब्ध नहीं थी । और सूचना मंगाई गई थी, जिसकी अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास योजनाएं

3388. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये कितनी धनराशि मजूर की गई है ;

(ख) उक्त अवधि में राज्य सरकार ने इस कार्य पर वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ग) वर्ष 1967-68 में इस काम हेतु राज्य सरकार के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिए 1.60 लाख रुपए नियत किये गये थे ।

(ख) राज्य सरकार के द्वारा सूचित किये गये पहले तीन तिमाही के वास्तविक खर्चे तथा 1966-67 के अन्तिम तिमाही के खर्चे के पूर्व अनुमान के आधार पर 1.13 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी । राज्य सरकार ने वर्ष का वास्तविक खर्चा सूचित नहीं किया है ।

(ग) 2.75 लाख रुपये नियत किये गये हैं ।

मध्य प्रदेश में नगरीय विकास

3389. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय विकास के लिये मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि नियत की गई थी ; और

(ख) इस धन-राशि से कौन-कौन से नगरों तथा कस्बों का विकास किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). भूपाल, जबलपुर, भिलाई तथा भिलाई क्षेत्र के शहरों के लिए सर्वांगीण विकास आयोजनायें (प्लान्स) बनाने के लिए मध्य प्रदेश को 16.50 लाख रुपये की राशि नियत की थी। राज्य सरकार ने केवल 6.49 लाख रुपये खर्च किये। राज्य सरकार ने भूपाल के लिए एक अन्तरिम विकास आयोजना तैयार की है तथा अनुमोदित की है, जबकि अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूपाल के लिए एक सर्वांगीण विकास आयोजना बनाई जा रही है।

PRODUCTION COST OF FERTILIZERS

3390. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the production cost of fertilizers manufactured from coal, naphtha and ammonia separately;

(b) the quantum of foreign exchange required separately for each unit;

(c) whether it has been finally decided to have coal-based fertilizer plants; and

(d) if so, the reasons for not setting up coal based fertilizers plant at Kesha or in Pench Valley or at Gotitoria in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The cost of production varies with the type of fertilizers manufactured, the product-mix the size of the plant, its location, cost of raw materials and utilities. Several assumptions that would rarely be applicable in practice have to be made in arriving at comparable cost figures for the three types of plants, *viz.*, coal-based, naphtha based and ammonia based. As a generalisation, however it can be stated that coal-based fertilizers would cost slightly more to produce than in the other two cases.

(b) We have no recent experience of a coal-based plant. The foreign exchange component of the naphtha-based plants at Durgapur and Cochin with the capacity of 1000 tonnes of urea per day is Rs. 16.4 crores and Rs. 17.2 crores respectively.

(c) and (d) No, Sir. A Techno-Economic Feasibility study of a coal-based plant in Madhya Pradesh recently prepared by the Fertilizer Corporation of India is under scrutiny by the Government.

RECOVERY OF CENTRAL TAXES

3391. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of Central taxes outstanding for recovery on the 31st March, 1967;

(b) how many persons, Hindu undivided families, firms and Corporatons are to pay over one crore of rupees each of the above dues and since when the amounts are outstanding against them; and

(c) the names of top most ten defaulters with amounts outstanding against each?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ASSISTANCE FOR MAJOR IRRIGATION PROJECTS IN MADHYA PRADESH

3392. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government propose to give cent per cent assistance to Madhya Pradesh for the construction of major irrigation projects;

(b) if so, the amount proposed to be given; and

(c) the names of the projects for which it will be given ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) Cent per cent earmarked Central assistance is already being given for the Chambal Project. It has been decided to extend this practice to Bagh project also. The case of Tawa is under consideration.

(b) and (c). The amount proposed to be given during the current year is yet to be decided.

FACT EMPLOYEES' ASSOCIATION

3393. SHRI A. SREEDHARAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government had received any memorandum from the FACT Employees' Association in July, 1966 containing charges against the management of the Fertilizers and Chemicals Travancor Ltd.;

(b) whether Government have enquired into these charges and, if so, the findings thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) to (c). Yes, Sir. A memorandum was received from the FACT Employees' Association in July, 1966. The facts were ascertained and it was found that there was no substance in the allegations made therein.

REVISION OF SCALES OF PAY FOR SUPERVISORY STAFF OF STATE BANK OF INDIA

3394. SHRI M. S. MURTI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that supervisory staff in the State Bank of India get less emoluments than the clerical staff having the same period of service; and

(b) if so, whether Government propose to revise the scales of pay of the supervisory staff ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The State Bank of India has recently decided that if an employee's total emoluments, comprising basic pay, dearness allowance, house allowance and city compensatory allowance, if any, on or after promotion as a supervising official are, at any time, less than the total emoluments he would have drawn as a clerk/cashier had he continued to remain so, he will be paid an adjusting allowance equal to the difference between the two emoluments. This decision has retrospective effect from the 1st January, 1967.

M/S. BEHARILAL RAM CHARAN, KANPUR

3395. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the action taken or proposed to be taken against the partners of M/s. Beharilal Ram Charan of Kanpur for filing false affidavits in 1957 and 1961 to secure the write off of tax arrears;

(b) the action taken against the officers responsible for the wrong write-off of Rs. 30.41 lakhs; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to realise the amount from M/s. Beharilal Ram Charan and its partners ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The question whether the affidavits filed by partners of Beharilal Ram Charan are false will be decided in a civil suit filed by the Department for recovery of part of the demand written off. The question of taking action for false affidavits will be taken up after the civil suit is decided.

(b) The write off was obtained by fraud and misrepresentation by the assessees and the question of taking action against officers does not arise.

(c) A civil suit has been filed for recovery of Rs. 13.16 lakhs for which recovery proceedings had not been started and which could not be recovered under the provisions of the Income-tax Act. The suit is pending. For the balance of Rs. 17.25 lakhs for which recovery proceedings had been started under the Income-tax Act, the recovery is being pursued. The assessee has filed a writ before the Allahabad High Court and the writ is pending.

M/S. LAKSHMIRATAN COTTON MILLS, KANPUR

3396. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of advance given by the State Bank of India outstanding against M/s. Lakshmiratan Cotton Mills, Kanpur on the 6th September, 1966, when the mill closed down;

(b) the amount due from the Company to the State Bank of India at present; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to realise the dues ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). Section 44(1) of the State Bank of India Act, 1955 precludes the State Bank from disclosing information relating to the affairs of its individual constituents, as it would be against the practice and usage customary among bankers. As such the information sought for cannot be disclosed.

(c) After the closure of the Mills in September, 1966, the State Bank has obtained additional collateral security to cover the amounts due to the Bank from the Mills. The Company has also agreed to pay the value of stocks pledged with the Bank before they are cleared for processing and sale. It is expected that the outstanding amounts will be progressively reduced and ultimately liquidated.

Tawa Project

3397. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8795 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether the amount of assistance to be given for Tawa Project has since been finalised;

(b) if so, the extent of assistance to be given in 1968-69; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the time by which it would be taken ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) to (c). The question of giving earmarked loan assistance for the Tawa Project is under consideration. It is expected to be finalised shortly.

Prices of Natural Gas

3398. SHRI PASHABHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) the comparative well-head production costs and selling prices for natural gas from oil wells in Assam and Gujarat;

(b) whether Government propose to create zones for natural gas and oil and restrict its distribution on the same lines as the food zones; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) Natural gas in commercial quantities is being produced in Assam by Oil India Limited and in Gujarat by the Oil and Natural Gas Commission. Production costs vary from place to place depending on the geological formation of the structure, the nature of the gas (*i.e.* whether associated or free), the quantity of gas produced and the period of depreciation and amortisation. As these factors are not identical or comparable in the two cases, it is not possible to give comparative figures of production costs in Assam and Gujarat.

The price of natural gas sold by Oil India Ltd. in Assam varies from Rs. 8.77 per 1000 cubic metres to Rs. 52.62 per 1000 cubic metres ex-field. The price of gas produced by the Oil & Natural Gas Commission in Gujarat has been fixed by the Arbitrator at Rs. 56.00 per 1000 cubic metres ex-field.

(b) No, Sir.

(c) The areas in which natural gas can be economically transported and distributed depend upon the quantity produced, the nature and extent of the demand and the availability of alternative fuels or feedstocks. The total effect of these factors is to limit the utilisation to areas of economic supply. In the case of crude oil, however, the location of the refineries is the actor that determines its distribution and the diverse means of transportation available give greater flexibility to areas of utilisation.

Petro-Chemical Complex in Assam

3399. SHRI MAYAVAN :
SHRI DHIRESWAR KALITA :
SHRI SARJOO PANDEY :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Japan has agreed to offer aid for setting up a petrochemical complex in Assam;

(b) if so, the aid offered by Japan ;

(c) when the work on the project is likely to start.

(d) the total expenditure involved in the project; and

(e) when the project is likely to start production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) No, Sir. No such offer has been received by the Government of India.

(b) to (e). Do not arise.

नागार्जुन सागर पर स्लुइस द्वार

3400. **श्री बलराज मधोक** : क्या सिंचाई व बिजली मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर बांध में अभी भी स्लुइस द्वार लगाए जाने हैं और कि इन के न होने के कारण बांध की पूर्ण सिंचाई शक्यता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस काम को थोड़ी सी धन राशि से ही पूर्ण किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० एल० राव) : (क) जी हां, दवारों को अभी लगाया जाना है । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि स्वीकृत समस्त सिंचाई शक्यता के विकास के लिये द्वार आवश्यक हैं ।

(ख) इन द्वारों पर लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) द्वारों को लगाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए आन्ध्र प्रदेश की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

बम्बई में चांदी का बरामद किया जाना

3401. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1967 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में समुद्र तल से 7 लाख रुपये के मूल्य की चांदी बरामद की गई थी; और

(ख) यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । 9 नवम्बर, 1967 को बम्बई के माहिम बन्दर पर समुद्रतल से लगभग 7.78 लाख रुपये के मूल्य की चांदी की सिल्लियां बरामद की गई थीं ।

(ख) एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है । एक मोटर-लारी भी पकड़ी गई है । आगे जांच पड़ताल चल रही है ।

Losses Suffered by Barauni and Gauhati Refineries

3402. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have compensated the Indian Oil Corporation for the losses suffered due to the delay in commissioning of the Barauni and Gauhati Refineries and if so, to what extent;

(b) whether this amount is sought to be recovered; and

(c) if so, how ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

आसाम तथा उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

3403. **श्री निहाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसाम तथा उत्तर प्रदेश में कितने गांवों को विद्युतीकरण के लिये चुना है ;

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) वर्ष 1967-68 में केन्द्र ने इन राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) भारत सरकार ने असम और उत्तर प्रदेश समेत राज्य सरकारों को सूचित किया था कि 1966-67 से ग्राम विद्युतन स्कीमों में सिंचाई पम्पों को कनक्शन देने पर बल देना चाहिये ताकि कृषि-उत्पादन को बढ़ाया जा सके । दोनों राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए योजनाओं के मसौदे के अनुसार चौथी योजना में असम में 490 बस्तियों को और उत्तर प्रदेश में 500 बस्तियों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, किन्तु चूंकि अभी चौथी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिये कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । 31 मार्च, 1967 तक असम में 89 ग्रामों को और उत्तर प्रदेश में 9883 ग्रामों को बिजली दी गई । 1967 से 1969 तक की अवधि में असम में 116 ग्रामों और उत्तर प्रदेश में 160 ग्रामों को बिजली देना प्रस्तावित है । 1967-68 में ग्राम विद्युतीकरण के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को 750 लाख रुपये तथा असम को 60 लाख रुपये दी गई है ।

HIGH PRICES OF BUILDING MATERIALS

3404. SHRI DHIRESWAR KALITA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that shortage and high price of building materials are hampering the progress of housing programmes; and

(b) if so, the steps taken by Government to encourage the production of cheap building materials in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) The National Buildings Organisation under my Ministry advises on establishment of building materials industries in the country to manufacture newer or cheaper building materials, use of which effect economy and accelerate the pace of construction. Its efforts have resulted in the establishment of five mechanised brick plants at Delhi, Calcutta, Madras, Assam and Pampore (Kashmir), two lime hydrating plants at Katni and Monda, eight particle board plants at Bhandup (Maharashtra), Cannanore, Sitapur, Dandeli, Rampur, Itarsi, Calcutta and Mysore, and three hard board plants at Balliapatam (Kerala), Bhandup and Gauhati and ninety seasoning and preservation plants. Also, two cellular concrete plants at Ennore, Madras and Bandel (West Bengal) and four asphaltic corrugated sheet plants at Vishakhapatam, Madurai, Madras and Bombay are at various stages of implementation.

In addition, various State Governments and other agencies have under consideration establishment of ten brick plants in Gujarat, Mysore, Madras (2 plants), West Bengal (2 plants), Assam, Andhra Pradesh, Tripura and Himachal Pradesh, five sand-lime brick plants in M.P., Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan and Gujarat, two light-weight aggregate plants at Calcutta and Tripura.

Also the National Buildings Organisation, as promoter of the results of research from various research institutes in the country to the field, has assisted in improving the existing practices in brick and lime manufacture as well as in use of lime-surkhi mixtures and industrial wastes-fly ash to economise the use of scarce and costly material, cement in construction.

हिन्दी प्रकाशनों का मुद्रण

3405. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी मुद्रणालयों में विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सम्बद्ध कार्यालयों के हिन्दी प्रकाशनों तथा वाद-विवाद के अनुदित संस्करण तथा हिन्दी के अन्य संसदीय पत्रों के समय पर मुद्रण की व्यवस्था है;

(ख) क्या उत्तरोत्तर हिन्दी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकारी मुद्रणालयों का विस्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) बढ़ती हुई मांग से वर्तमान हिन्दी मुद्रण क्षमता कम पड़ गयी है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार मुद्रणालय फ़रीदाबाद में दूसरी पारी आरंभ होने की शीघ्र संभावना है, जिसमें हिन्दी मुद्रण के लिए सज्जित छः मोनो मशीनों का उपयोग होगा। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के आधार पर, पूर्व परिकल्पित मान से अधिक मान पर रिंग रोड नयी दिल्ली के नये भारत सरकार मुद्रणालय में हिन्दी नयी मुद्रण मशीनें स्थापित की जायेंगी। भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों में भी इसी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

EXPORT OF SYNTHETIC DRUGS AND SURGICAL INSTRUMENTS

3406. SHRI S. C. BESRA :
SHRI MARANDI :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had sponsored four members' delegation for West Asia to prospect the market for synthetic drugs antibiotics and surgical instruments;

(b) if so, the success achieved by the delegation; and

(c) the number of countries visited by the delegation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) The Government had approved the proposal of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. to send a three members Trade Delegation to Middle East, and East African countries to explore the possibilities of export of surgical instruments and other products of the Company to those countries.

(b) The delegation found that there was a good market for surgical instruments, having regard to the quality and prices of the products of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. compared to other competitors in the field. The delegation has quoted for three tenders and Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. have received the notice for three more tenders. They also obtained on the spot orders for small supplies.

(c) 10 countries.

PETROLEUM AND OIL PRODUCTS

3407. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the number and names of places where searches and prospecting for petroleum are being carried on and the amount spent annually for the purpose;

(b) the chances of getting oil at those places; and

(c) the total annual consumption of petroleum and its products in India, the quantity being obtained locally, the quantity being imported and Centres from where imported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) Geological and geophysical surveys in various parts of Gujarat, Jammu & Kashmir, Bihar, Assam, Tripura, Madras, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan and Gulf of Cambay and NEFA are being carried out.

Details regarding drilling activities in individual oil fields/structures are restricted information under the Defence of India Rules, 1962.

The expenditure incurred on prospecting for petroleum during 1966-67 was Rs. 25.79 crores.

(b) Oil has already been discovered in commercial quantities in Gujarat and

Assam. In respect of the other areas, it is too early to come to any conclusion about the possibility of finding oil/gas in commercial quantities.

(c) The total consumption of petroleum products during 1966 was 13 million tonnes including 2 million tonnes imported from the USSR, Yogoslavia, Rumania, Iran and the U.S.A. This required the refining of 4.56 million tonnes of indigenous crude oil and 7.46 million tonnes of crude oil imported from Saudi Arabia, Iran and Kuwait.

SENIOR MANAGEMENT POSTS IN PUBLIC UNDERTAKINGS

3408. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to eliminate senior management posts in the public undertakings in the light of the recommendations of the Menon Committee on Public Undertakings;

(b) the number of officers *vis-a-vis* the staff and workers in the different public undertakings at present and the percentage the former bears to the latter in each case; and

(c) the average percentage of the number of officers in regard to the number of staff and workers in Government undertakings taken together ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Menon Committee has not made any reference to the elimination of senior management posts. Presumably, the Hon'ble Member is referring to the recommendations made by that Committee on the question of appointment of senior civil servants to Public Sector Undertakings. According to the present policy, Secretaries to the Government of India are not appointed to or continued in the posts of Chairman/Chief Executives, or on the Boards of Public Enterprises except for very special reasons, the appointment being confined to the initial stages of an undertaking's functioning (or) to some cases of point ventures where foreign collaborators are involved, (or) where important problems of planning and organisation arise.

(b) and (c). The information asked for is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

FINANCING OF AGRICULTURAL PROGRAMME BY WORLD BANK

3409. SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : Will he Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some projects for intensive agricultural development programme are proposed to be financed by the World Bank.

(b) if so, how many projects are proposed to be chosen for being financed by the World Bank; and

(c) the location of the projects and the *criteria* on which they have been chosen ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) One project is now under consideration.

(c) A proposal for intensive agriculture centred around tubewells and other groundwater facilities in two districts (Varanasi and Etah) of Uttar Pradesh is presently under consideration of the International Development Association, which is an affiliate of the World Bank. The selection of the two districts for the purposes of the scheme has been made on technical and economic considerations, on the basis of their providing a representative cross-section of a wide variety of problems, the experience in tackling which will be useful for the agricultural development in the rest of the U.P. and elsewhere. Such problems pertain to development and operation of tubewells in the private and State sectors, the problems of drilling in various types of rock conditions, relationship of different types of credit structures, *viz.*, cooperative, governmental and commercial banking, problems of soil conditions and salinity etc.

HOARDING OF FOREIGN EXCHANGE BY RAJ KAPOOR, A FILM ACTOR OF BOMBAY

3410. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Raj Kapoor, proprietor, R. K. Films and Studios, Bombay has been found hoarding foreign exchange to the tune of Rs. 27 lakhs;

(b) if so, whether it is also a fact that he has been fined for the offence and he is paying the fine in instalments; and

(c) the number of instalments which have yet to be recovered from him ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b) As a result of the investigations conducted by the Enforcement Directorate in 1964, Shri Raj Kapoor was found to have retained, in contravention of the provisions of Sec. 4(3) of the Foreign Exchange Regulation Act, foreign exchange to the tune of about Rs. 26,000, which was seized on 24th August, 1964. On adjudication, a penalty of Rs. 3,000/- was imposed on Shri Raj Kapoor by the Director of Enforcement in addition to the confiscation of the seized foreign exchange. The penalty imposed was paid in full on 22nd January, 1965.

(c) Does not arise.

INCOME TAX AND WEALTH TAX DUE FROM FILM PRODUCERS/ACTORS

3411. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the annual income-tax and wealth tax assessment during the three years ending March, 1967;

(b) the amount of tax arrears due from the following film people; (i) Shri Manoj Kumar, (ii) Kumari Waheeda Rehman, (iii) Producer Director Shri B. R. Chopra, (iv) Shri Shammi Kapoor, (v) Producer Director Shri Raj Kapoor, (vi) Music Directors Shanker-Jaikishan and (vii) Kumari Rajshri;

(c) the steps taken to recover the tax arrears from each of them; and

(d) the amount of penalties levied on them and the value of the property attached in each case ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

परिवार नियोजन के साधन

3412. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के साधनों का कालेजों में पढ़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों और अन्य अविवाहित व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस से जनता का नैतिक चरित्र गिर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे नियम बनाने का है कि उपकरण केवल विवाहित व्यक्तियों को ही दिये जाएं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । वर्तमान नियमों में यह व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है कि परिवार नियोजन उपकरण केवल विवाहित व्यक्तियों को ही दिये जाएंगे ।

नोटों का मुद्रण

3413. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित नोटों पर राष्ट्रीय चिन्ह तीन अंकित है और उस पर "सत्यमेव जयते" शब्द नहीं छापा गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस गलती को ठीक करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) नोटों पर छापे जाने के लिए, अशोक स्तम्भ के शीर्ष भाग का नमूना, भारत के स्वतन्त्र होने से पहले, नोटों पर छापे जाने वाले राजा के चित्र के स्थान पर अपनाया गया था । यह निर्णय तब किया गया था जब आदर्श वाक्य (मोटो) के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया गया था । फिर भी, इस विषय पर और विचार किया जायेगा ।

INCOME-TAX COLLECTION FROM MANIPUR

3414. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total Income-tax collection from Manipur during the years 1966-67 and 1967-68, so far;

(b) the Income-tax arrear accumulation so far; and

(c) the steps taken to realise them ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) :

	1966-67	1967-68 (So far)
(a)	Rs. 7,61,000	Rs. 3,24,000

(b) Rs. 10 lakhs.

(c) Such steps as are available in law are being taken on the facts and circumstances of each case.

BALI NAGAR, DELHI

3415. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration have sanctioned loan assistance to some of the plot holders in Bali Nagar, Najafgarh Road, Delhi;

(b) whether some of the plot holders in Bali Nagar have been refused by the Delhi Administration the issue of 'No Objection Certificates' required by them in connection with loan assistance from the Life Insurance Corporation; and

(c) if so. the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) and (c). Since some complaints had been received against the colonizers of Bali Nagar Colony, 'No Objection Certificates' asked for by the Life Insurance Corporation were in certain cases refused temporarily. These certificates have since been issued communicating the fact of the complaints also so that the L.I.C. may take their own decision in the matter.

OIL EXPLORATION IN U.A.R.

3416. SHRI D. C. SHARMA :
SHRI R. K. AMIN :
SHRI HIMATSINGKA :
SHRI R. BARUA :
SHRI BHOGENDRA JHA :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is proposed to participate in Oil exploration in U.A.R. territory near the Red Sea by India.

(b) if so, the details thereof; and

(c) the stages at which the matter stands at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) No such proposal is under consideration at present

(b) and (c). Do not arise.

SAFDARJANG SCHOOL OF NURSING

3417. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Safdarjang School of Nursing which was started in 1961 for diploma on public health and public nursing is still without a proper building;

(b) whether it is also a fact that there are no hostel facilities for the students and they have been putting up in rented houses which apart from creating transport difficulties, affect the training of the students; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY : (a) Class-room facilities for the School of Nursing at the Safdarjang Hospital are satisfactory.

(b) The student nurses have been accommodated in rented building and are provided transport.

(c) It is proposed to build a hostel when funds become available.

ANDAMAN P.W.D. STORES

3419. SHRI K. R. GANESH : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether verification of the Andaman P.W.D. Stores have been fully conducted;

(b) whether partial verifications conducted by two S.D.O.s of the Andaman P.W.D. have revealed vast shortages and fraud; and

(c) whether Government propose to lay these verification reports on the Table of the House ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) Verification during the years 1961-62 and 1964-65 has revealed excesses and shortages of stores. The 1966-67 verification has just been completed and the figures are under scrutiny. Excesses and shortages are due to wrong adjustments in accounting. Action has been taken to reconcile the discrepancies.

(c) No. The verification reports cover 6,000 items on 200 sheets. It is felt that no useful purpose will be served by placing the mass of details on the Table of the House.

SULPHUR FOR BIHAR STATE SUPERPHOSPHATE FACTORY

3420. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar State Superphosphate factory situated at Sindri has not been allotted the quota for sulphur needed by it in the current year;

(b) if so, whether it purchased sulphur from a Bombay firm named Dipton at a price of Rs. 700 per ton;

(c) the controlled rate of sale price of sulphur and the firms who were given licence for the import of this community; and

(d) the measures taken to see that this commodity does not find its way in the black market ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) Yes, the Bihar State Superphosphate Factory, Sindri, has been allocated 50% of its requirements on the basis of equitable distribution of the available sulphur.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) In the case of sulphur imported from traditional sources, the price is fixed by the Chief Controller of Imports and Exports and has ranged from Rs. 455 to Rs. 525 per tonne. Sulphur is also imported from non-traditional sources and no price is fixed in respect of this sulphur.

The names of the licence holders for import of sulphur are indicated in the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences published by the Chief Controller of Imports and Exports, a copy of which is available in the Parliament library.

(d) Distribution of sulphur imported from traditional sources is controlled by DGTD. It has not been considered advisable to bring under controlled distribution the sulphur imported from non-traditional sources.

STERILIZATION OPERATIONS

3421. SHRI BENI SHANKAR SHARMA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state the number of operations done for sterilization of males and females belonging to muslims, scheduled castes and other Hindus, separately, since the beginning of this campaign, year-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : Two Statements, No. I—showing the number of persons sterilised since 1962 and inserted with loop since 1965 when loop programme was started and No. II—showing the available statistical data in respect of vasectomies and tubectomies for the period ending December, 1965, are laid on the Table of the House. [*Placed in*

Library. See No. LT-1909/67] Separate figures for vasectomy and tubectomy thereafter are not available. Statistical-data community-wise etc. is not maintained.

DANGEROUS AND OFFENSIVE TRADES

3422. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trades of Flour Mills, Cotton-cording Mills, Oil Mills and Printing Presses come under the category of "Dangerous and Offensive Trades".

(b) the main conditions for the grant of licences with annual licence fees for the aforesaid different trades, and the sanctioning authority in the N.D.M.C. area of New Delhi;

(c) whether the rules or bye-laws pertaining to the grant and renewals of such licences have been amended/changed during the last five years; and

(d) if so, what are the amendments and the total number of licences granted and renewed separately for the above trades, during the last five years in New Delhi area ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes. They are covered by the definition of dangerous or offensive trades as contained in Section 121 of the Punjab Municipalities Act which is applicable to N.D.M.C.

(b) They should be neither hazardous nor dangerous to residents of the locality. They should fulfil conditions of the Delhi Master Plan.

Fees :—	1. Flour Mills	Rs. 50/-
	2. Cotton-cording	Rs. 50/-
	3. Oil Mills	Rs. 50/-
	4. Printing Presses	Rs. 20/-

Sanctioning authority in New Delhi area is the N.D.M.C.

(c) No amendments have been made in the rules. However, under the provisions of the Delhi Master Plan various trades are allowed in approved areas only and this the N.D.M.C. has to keep in view while sanctioning licences.

(d) As given in (c) above. Total number of licences granted/renewed during the past five years is as under :—

1. Flour Mills	..	2
2. Cotton-cording Mills	..	1
3. Oil Mills	..	3
4. Printing Presses	..	17

MEDICAL AID TO EMPLOYEES OF KOLAR GOLD FIELD:

3423. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the facilities of medical aid to the employees and their dependents in the Kolar Gold Field Mines are not being provided; and

(b) the reasons for not opening the Medical Ward of the new building for providing these facilities ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) facilities of free medical aid, both to the employees and their dependents, are provided by the Kolar Gold Mining Undertakings.

(b) The new Medical Ward, for in-patients, was commissioned on 25-6-1967. If, however, the Honorable Member is referring to the Out Patients Blocks, equipping of the Block is in progress and it expected to be commissioned in a coulple of months.

KOLAR GOLD FIELDS

3424. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is general dissatisfaction among labourers of the Kolar Gold Field Mines;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the remedial measures taken to remove the same ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). Government is not aware of any general dissatisfaction. The Workmen's Unions/Associa-

tions bring up now and then certain matters affecting their terms and conditions of service. These are examined and appropriate action taken on merits. It has been reported recently that some Labour Unions are exercised about the question of bonus for the period 1-12-1962 to 31-3-1964. This matter was referred to adjudication of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in 1965 and is pending before the Tribunal.

KOLAR GOLD MINES

3425. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Kolar Gold Mines are working satisfactorily;

(b) if so, what is the improvement in production; and

(c) if not, what is the remedy to the conditions in the Mines ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). Production of gold in the Kolar Gold Mining Undertakings has been adversely affected from 1965-66 onwards owing mainly to several natural calamities and adverse mining conditions and the decline in the grade of ore. The average grade of ore milled was 7 grammes per metric tonne in 1966-67 as compared to 7.64 grammes per metric tonne in 1961-62. There was a shortage in the tonnage of ore milled due to adverse mining conditions caused by natural calamities etc., the more important of which are enumerated below :—

(i) Major rockbursts took place on 26-11-1962 in the Champion Reef Mine, affecting the whole of Glen Ore Shoot and the Southern Ore body of the mine—these Sections were contributing to about 40 to 50 per cent of the gold produced in this mine. An outbreak of a major fire occurred in the Northern Folds Section of the Champion Reef Mine resulting in sealing of the area from July, 1965 to February, 1966. There were 3 short fires again in 1966-67 in this mine. Further, due to unprecedented rain during September-November, 1966 parts of the mines were flooded. In December, 1966 due to ground movement, the sub auxiliary shaft and the associated levels were damaged by a series of rockbursts. The effect of all these natural calamities in the Champion Reef Mine has been to cause a fall in the production of ore.

(ii) The Mysore Mine is a very old mine with limited reserves and mining of ore in this has had to be restricted on account of various technical considerations.

(iii) The Nundydroog Mine, which has large deposits of ore but of comparatively low grade, suffered a setback in production of ore as during 1965-66 there was an accident to No. 2 Auxiliary Shaft in the mine, and during 1966-67 the unprecedented rains resulted in flooding of parts of the mine.

In order to augment production in the Kolar Gold Mining Undertakings, an expert committee was appointed early this year to review and recommended measures to be taken for the reopening of the Northern Folds of the Champion Reef Mine. The committee has recently submitted its report and the recommendations are under examination by the Inspectorate of Mines Safety. Production at Kolar Gold Mining Undertakings is expected to improve when these recommendations are implemented. Besides this, efforts are also being made to increase the output at the Nundydroog Mine by implementing a scheme for expansion of ore production at this mine.

SANITATION IN LABOUR AREAS OF KOLAR GOLD FIELDS

3426. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sanitation in the Labour areas of the Kolar Gold Fields has worsened;

(b) whether it is also a fact that the sanitation Department of individual mines has been merged into a single separate Department which is to be disadvantage of the labour classes; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) and (c). A Central Estate Department has been formed merging also all the Sanitary Departments of the Mines with a view to economy and efficiency. This has not resulted in any disadvantage to the labour classes.

FLOODS CONTROL AND FLOOD CONTROL-*cum*-IRRIGATION SCHEMES IN MYSORE

3427. SHRI S. A. AGADI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether any Flood Control and Flood Control-*cum*-Irrigation Schemes have been submitted by the Government of Mysore during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68;

(b) if so, the estimates of each one of the schemes;

(c) the schemes which have been approved; and

(d) if any of them are pending, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (d). One scheme, *viz.*, the Manchanable flood control-*cum*-irrigation scheme, which envisages the construction of a dam across the Arkavathi river near Manchanable, about 13 miles from the Ramnagaram Town in Bangalore district, was received from the Mysore Government in September, 1966. The scheme is estimated to cost Rs. 316.78 lakhs and is under examination. The State Government have been requested to carry out certain further investigations so as to make the project as economical as possible and to enable its execution in stages.

FOREIGN AID FOR UPPER KRISHNA PROJECT

3428. SHRI S. A. AGADI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal to seek foreign aid for the Upper Krishna Project in Mysore State;

(b) if so, the names of countries approached with the extent of aid in machinery, finance and technical know-how; and

(c) the stage at which the matter stands at present ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) No specific proposal for seeking foreign aid for the Upper Krishna Project in Mysore State is under consideration.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

अर्द्ध अहर्व विकसित बस्तियों का संघ दिल्ली

3429. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैर-मंजूर शुदा बस्तियों के निवासियों ने अपने हितों की रक्षा के लिये 'अर्द्ध विकसित बस्ती संघ' के नाम से एक संगठन स्थापित किया है;

(ख) क्या उक्त संगठन ने राजधानी में मकानों की समस्या को हल करने के लिये गैर-मंजूर शुदा बस्तियों को नियमित करार देने के लिये दिल्ली प्रशासन पर जोर दिया है;

(ग) क्या इस प्रकार की प्रार्थना सरकार से भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). सरकार को ऐसी किसी यूनियन का पता नहीं। अनधिकृत बस्तियों के नियमितीकरण संबंध में सरकार की नीति लोक सभा में 22 जून, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3330 में स्पष्ट की जा चुकी है।

EXPENDITURE INCURRED BY MINISTRIES

3430. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that expenditure provided under the Budget during 1966-67 was evenly incurred during the whole year;

(b) whether Government propose to lay a statement on the Table showing the expenditure incurred by each Ministry during the April/June, July/September, October/December and January/March quarters; and

(c) the reasons for the uneven distribution of expenditure under various Ministries ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir. Government expenditure being of different types cannot be expected to be incurred evenly during the year. Government receipts are also likewise not realised evenly during the year.

(b) A statement of this type will take considerable time to prepare and further, it will be difficult to relate to the various quarters the numerous book adjustments which take place between the different Ministries towards the close of the year.

(c) Government expenditure consists not only of salaries of employees and other standing charges, but also of expenditure on purchase of plant and machinery, civil works, payment of grants and loans to States and other parties, payment of interest on and repayment of loans, etc. While by large the expenditure of the first type *i.e.* on salaries and other standing charges is distributed evenly, the expenditure of the other type, depending as it does on supply schedule, construction programme, requirements of parties to whom loans and grants are given, terms and conditions of borrowings, etc. will not be evenly distributed over the year. Further, a considerable part of the construction expenditure takes place in the fair season most of which falls on the latter half of the year.

Foreign Markets for Products of Indian Oil Corporation

3431. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation has been exploring possibilities of expanding foreign markets for its products rendered surplus by the industrial recession; and

(b) if so, the extent to which its efforts have been successful ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). The Indian Oil Corporation Limited handles the distribution of the products of its own refineries and that of the public sector refinery at Cochin. The products of its refineries, which are situated inland, are consumed within the country. Such of the products as are surplus to our requirements are being exported by the Indian Oil Corporation. The only products rendered surplus due to the demand not coming up to expectations is high speed diesel oil. The total quantity of this product exported by the Indian Oil Corporation during the period April-September, 1967, is 1,39,000 Kls.

Hydel Potential in Assam

3432. SHRI R. BARUA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether 30 per cent of India's total hydel potential is concentrated in Assam; and

(b) if so, why it is not being exploited ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) The firm hydro power potential within the State of Assam has been estimated at 2.57 million kw at 60% load factor, which is about 6% of the country's total hydro potential. However, the North Eastern Region, including Assam, NEFA and Manipur has an estimated potential of about 12.5 million kw as 60% load factor which is about 30% of the country's hydro potential.

(b) This is due partly to the slow growth of demand in Assam and partly to development of Thermal power by utilisation of natural gas available in Assam.

Water Pollution Control

3433. SHRI R. BARUA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any plan for Water Pollution control due to rapid industrialisation and due to the discharge of sewage and sullage into natural bodies of water; and

(b) if so, the broad details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) and (b). The Government of India have circulated to the State Governments a draft Bill to provide for the prevention of water pollu-

tion and the maintaining or restoring of wholesomeness of water, and with a view to carrying out the purposes aforesaid, establishment of Water Pollution prevention Boards.

The Bill envisages the setting up of Water Pollution Control Boards in the States and also a Central Water Pollution Control Board to co-ordinate the work of the State Boards, provide technical assistance and guidance, and organise training of persons etc.

सुपर बाजार से खाद्य पदार्थों के नमूने

3434. **श्री रामगोपाल शालवाले :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार समेत इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्टोरों से खाद्य पदार्थों के नमूने न लेने के लिये हिदायतें जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो 15 जुलाई, 1966 से 30 सितम्बर, 1967 तक और 1 अक्तूबर 1967 से 21 नवम्बर 1967 तक की अवधियों में स्वास्थ्य विभाग ने सुपर बाजार से खाद्य पदार्थों के कितने नमूने लिये थे;

(घ) कितने नमूनों के परीक्षण परिणाम घोषित किए जा चुके हैं तथा कितने नमूने स्वीकार किये गये हैं और कितने नमूने अस्वीकार किये गये हैं; और

(ङ) सुपर बाजार प्रबन्ध के विरुद्ध कितने मामले न्यायलयों में निर्णय के लिये पड़े हुए हैं तथा कितने मामलों में सजा दी गई अथवा जुर्माना किया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुपर बाजार से लिए गये खाद्य पदार्थों के नमूनों की संख्या इस प्रकार है :

(1) 15-7-1966 से 30-9-67 तक	कोई नहीं
(2) 1-10-1966 से 21-11-67 तक	6
(घ) घोषित परिणाम	6
स्वीकृत तथा मानकों के अनुरूप पाये गये	5
अस्वीकृत	1
(ङ) न्यायालयों में निर्णय के लिये पड़े हुये मामले	1
सजा दिये गये अथवा जुर्माना किये गये मामले	कोई नहीं

ASHOKA HOTEL

3435. SHRI K. M. KAUSHIK : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item that appeared in the *Times of India* of the 20th November, 1967 that no hotel in the country where he (Mr. R. H. Pick, an American guest of Tourist Department) stayed was quite as bad as the one run by the Government in Chanakyapuri;

(b) the steps taken to find out the reasons for the dissatisfaction expressed by the American guest;

(c) whether there is a complaint book kept in the said hotel enabling the customers to record their complaints; and

(d) whether Government propose to contact the said American guest to know the nature of his complaints so that the mistakes, if any, could be rectified ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) to (d). Every residential room in the hotel has a form in which the guest is requested to give his comments on Food Quality, Dining Hall Service, Service in the Room, Courtesy of the Hotel Staff and General Standard/Amenities in the hotel. He is also invited to give special remarks for the attention of the management of the hotel. Mr. Pick did not fill up this form.

Specific complaints are attended to promptly and on occasion the matter is taken up with the guest himself. It is difficult to handle such sweeping generalisations as have been made in the present instance. However, efforts are being made by the Company to get in touch with this particular guest.

PHARMACY COUNCILS

3436. SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pharmacy Councils have been formed in all the States;

(b) if so, the date from which such a Council was functioning in Orissa, the date of expiry of the term of the first Council and whether a Council for the second term was notified and election of the President and Vice-President was held;

(c) whether the attention of Government has been drawn to a resolution by the Orissa State Branch of the Indian Pharmaceutical Association alleging that the old Council is still functioning and the charge has not been handed over to the new Council; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) No.

(b) The Orissa State Pharmacy Council was formed with effect from the 30th December, 1950. Under Section 25 of the Pharmacy Act, 1948, a nominated or elected member of a State Council shall hold office for a term of five years from the date of his nomination or election or until his successor has been duly nominated or elected whichever is longer. Information whether the Council was notified for the second term and election of President and Vice-President held, is being obtained.

(c) Yes.

(d) It is provided in Section 24 of the Pharmacy Act, 1948, that any dispute regarding election to the State Council shall be referred to the State Government whose decision in the matter shall be final.

INCLUSION OF BAITE TRIBE OF MANIPUR IN SCHEDULED TRIBES

3437. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Baite tribe of Manipur is not included in the list of Scheduled Tribes of Manipur while the Baites of Assam have been included in the list of Scheduled Tribes in Assam;

(b) whether Government have received any representation in this regard; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) No community called Baite is scheduled either in Manipur or in Assam as a Scheduled Tribe.

(b) Yes.

(c) Government's decisions in the matter of revision of lists are incorporated in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill introduced in the House, on 12th August 1967.

GANDAK PROJECT

3438. SHRI BISHWANATH ROY : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether as a result of the devastating floods in the river Gandak during the last rainy season, any danger has been created to the Gandak Project itself; and

(b) if so, the steps taken in the matter ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). No danger has been created to the Gandak Project owing to the floods which occurred during the last rainy season. However, during the last few years, the Gandak river has shown a tendency to move westwards and a portion of the Chitauni Embankment in U.P. was erorded last year, posing a danger to the present alignment of the Western Gandak Canal. Adequate river training measures near the Embankment have helped hold the river away from the Canal alignment. Further steps to strengthen these measures are in progress.

PIPELINE SCHEME FOR RAJASTHAN

3439. SHRI AMRIT NAHATA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have received any blue print for a Pipeline scheme to harness the waters of the North Indian rivers to irrigate the desert lands of Rajasthan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) No.

(b) Does not arise.

DEMONETISATION

3440. SHRI AMRIT NAHATA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government are contemplating to demonetise the currency as a deflationary measure which will help in creating the climate of non-inflation and psychology of confidence in the country ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : No, Sir. Government seeks to create a climate of price stability and a psychology of confidence by stimulating agricultural and industrial production and taking other suitable measures to raise availability and regulate distribution of essential commodities. The level of total demand is restrained through budgetary and monetary policies.

CURRENCY CIRCULATED BY CHINESE

3441. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that fake Indian currency is being inflicted and circulated by the Chinese in the Tibetan border, West Bengal, Nagaland and Kerala; and

(b) the steps being taken to find out and curb the same ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Government have no information to support that currency notes of Chinese origin are in circulation in these areas.

(b) Does not arise.

DEVALUATION OF £ STERLING

3442. SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI B. N. SHASTRI :

Will the the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any assessment of the effect of the devaluation of the £ Sterling on Indian economy has been made; and

(b) if so, the measures being taken to remedy it ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government is keeping a watch on developments and such measures as may become necessary to safeguard and promote our interests will be taken.

FOURTH PLAN FERTILIZER PROGRAMME

3443. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the report of the world Bank Team which visited New Delhi for talks on India's Fourth Plan Fertilizer Programme and the possible Bank assistance therefor has been considered;

(b) if so, the recommendations made by the team and accepted; and

(c) the assistance which the World Bank proposes to give ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) A world Bank Team was in India from the 14th to 23rd July, 1967. The Team reviewed with the Government the estimates of fertilizer production during the Fourth Plan period and also discussed the ways in which the IFC/World Bank could help in expediting the implementation of approved projects in the private sector. The team has not submitted any formal report on the subject.

(b) Does not arise.

(c) The Bank has not made any decision as to the quantum of assistance that would be made available for fertilizer projects in India. The IFC/Bank considers each project on merit and relate the quantum of assistance to specific projects. The IFC has already concluded arrangements for an investment of $ 11.5 million in Kanpur Fertilizer Project.

CRUDE OIL FROM IRAN

3444. SHRI D. C. SHARMA :
SHRI S. S. KOTHARI :
SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI HIMATSINGKA :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether India is likely to get supply of crude oil from Iran as a result of off-shore drilling it had undertaken in Iran in collaboration with U.S. and Iranian firms; and

(b) if so, what are the prospects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). Exploration for oil in the off-shore areas of Iran is still going on and it is premature to come to any definite conclusion about oil becoming available from that source in commercial quantities.

COMPLAINTS INVESTIGATION SYSTEM BY COMMISSIONER OF SCHEDULED CASTES AND TRIBES

3445. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Head and Regional Offices of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been receiving year after year an increasing number of complaints of various categories from the concerned people;

(b) if so, the procedure followed to investigate into such complaints;

(c) whether the Commissioner has pointed out long delays stereotyped replies and even non-action in the disposal of cases by the concerned authorities;

(d) whether in his latest 15th Report, he has demanded his right to access to official documents to effectively exercise his constitutional powers to investigate into the complaints;

(e) whether in the current scheme of reorganisation of the Commissioner's offices, any steps have been taken to develop a complaint investigation system along with a compliance reporting system as the two most important devices for proper functioning of this organisation; and

(f) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) Yes. Following is the number of complaints received :

1963-64	..	1,257
1964-65	..	2,153
1965-66	..	3,051

(b) The complaints received are generally sent to the authorities concerned for gathering the facts which, on receipt, are examined in the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In a limited number of selected cases, on the spot enquiries are also made by the officers of the Commissioner's organisation.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) Yes. Five Research and Investigating Units have been created.

(f) Does not arise.

ROAD ROLLERS

3446. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the road rollers recently requisitioned by the P.W.D., Manipur are defective.

(b) if so, the number of road rollers purchased, the firm supplying them and the total expenses incurred by Government in purchasing them; and

(c) whether Government proposes to make an enquiry into the deal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Government are not aware of any requisitioning of Road-Rollers by the P.W.D., Manipur. However, two contracts were placed on behalf of P.W.D. Imphal during February/May, 1967 for a total number of 9 Road Rollers on M/s. Garden Reach Workshops (a Govt. of India Undertaking). The consignee reported some manufacturing defects in the Road Rollers supplied by M/s. Garden Reach Workshops.

(b) The total number of Road Rollers is nine. The suppliers are M/s. Garden Reach Workshops. Value of each Road Rollers is Rs. 51,000.

(c) No, Sir. The matter has been taken up with the manufacturers who under the

Conditions of the Contract, are responsible for remedying the defects at their cost for a period of twelve months from the date of supply.

BURMA RETURNED PENSIONERS

3447. SHRI NAMBIAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Burma-returned pensioners in the Madras State are not paid pensions at revised rates after devaluation;

(b) whether the Accountant General, Burma had authorised his counterpart in India to make payments on behalf of the Burmese Government at their official rate of exchange.

(c) whether the revised rate of exchange is being followed by other Accountant Generals excepting Madras; and

(d) if so, the steps taken to regularise payments and remove hardships to the pensioners ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (d). Soon after the devaluation of the 'Rupee' with effect from the 6th June, 1966, the Accountant-General, Burma, advised all the Accountants-General in India that the conversion rate for Burmese 'Kyats' would be, one Indian rupee=0.6349 Burmese 'Kyat', and that all pension payments made by the latter on or after the 6th June 1966 on behalf of the Government of the Union of Burma should be regulated at the new rate of conversion. Since the communication from the Accountant General, Burma, did not refer to the rate of conversion for pensions expressed in 'Rupees', a reference was made to the Government of the Union of Burma enquiring whether for purposes of conversion into Indian rupees, the new rate of exchange as for 'Kyats', would be applicable to pension payments authorised in 'Rupees'. Pending receipt of advice from the Government of Burma, the Burma pensions expressed in 'Rupees', have to be paid at the rate of exchange obtaining prior to devaluation. Where payments had, however, been made in respect of such pensions at the enhanced rate, instructions have been issued to make subsequent payments at the old rate unless the Government of Burma advise that these be paid at the higher rate.

DEFECTIVE PROCUREMENT OF ROCK PHOSPHATE AND SULPHUR BY S.T.C.

3448. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fertilizers Association has submitted a memorandum to his Ministry that phosphate procurement by the State Trading Corporation is defective and retarding the progressive production of fertilizers;

(b) whether it is also a fact that defective procurement of rock phosphate and sulphur by the State Trading Corporation is responsible for 67 per cent of high manufacturing cost of fertilizers; and

(c) if so, whether Government propose to revise its procurement policy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

INVESTMENT OF EXTRA INCOME OF RURAL AREAS

3449. SHRI R. BARUA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether, in the light of bumper crop during this year and consequent rise in purchasing power in rural areas, any steps are contemplated to divert the extra money to fruitful investment; and

(b) if so, how far the State Governments have shown their willingness to mop up the extra income and divert the same for national capital ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). A variety of saving media exist through which people both in urban and rural areas can voluntarily invest their savings. Further in view of the better crop-prospects this year, the National Savings Organisation has recently requested the State Governments to undertake special drives for tapping rural savings with the active cooperation of Panchayats. As for the taxation of rural savings, the subject falls essentially within the purview of the State Governments. This matter was however discussed at the re-

cently held meeting of the National Development Council and some suggestions were put forward on the methods of raising additional resources from the rural sector.

DISAFFILIATION OF NURSING COLLEGE BY DELHI UNIVERSITY

3450. SHRI R. BARUA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi University propose to disaffiliate the Nursing College; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संस्था

3451. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 सितम्बर, 1967 को उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संस्था ने अपनी मांगों के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क संघ से तारीख 9 सितम्बर, 1967 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ नहीं लगता । यह अवश्य है कि इसके पहले इस संघ से तारीख 28-4-1967 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ।

(ख) संघ की मुख्य-मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं :—

(i) चालू किस्म की जांच की आवृत्ति घटा कर जांच वास्तव में प्रभावकारी ढंग से की जाय । बुलेटिन, आदेश, व्यापार-नोटिस आदि सामग्री सब निरीक्षकों को दी जानी चाहिये ।

(ii) कर्मचारियों को अव्यवहार्य कार्य-प्रणाली को न अपनाने के कारण दिये जाने वाले आरोप-पत्रों को देना तथा किसी अभिकथित गुनाह करने के तीन-तीन साल बाद कर्मचारियों को आरोप-पत्र देना बन्द कर दिया जाना चाहिए । तीन तीन साल बाद आरोप-पत्र तभी दिया जाना चाहिये जब मामले में आरोप बहुत ही संगीन किस्म का हो ।

(iii) कर्मचारियों का चक्रावर्तन किस्म के स्थानान्तरण बन्द कर दिये जाने चाहिए ।

(iv) जिन व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया जाना हो उन्हें उसकी सूचना काफी पहले से दी जानी चाहिए तथा इस बात की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को उनकी अपनी पसंदगी की जगह तैनात किया जाय ।

(v) तृतीय श्रेणी के कार्यकारी संवर्ग की पदोन्नति की संभावनाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में जो भी असंगतियां हों उन्हें दूर किया जाना चाहिए ।

(ग) सुझावों पर विचार हो रहा है ।

JHUGGIS IN TEES JANUARY MARG, NEW DELHI

3452. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether any assurance was given by Land and Development Officer that *jhuggis* of *dhobis* on Tees January Marg, New Delhi would not be demolished;

(b) if so, the reasons as to why jhuggis have been demolished;

(c) whether it is a fact that a meeting regarding the rehabilitation of these dhobis was held in Vikas Bhavan, New Delhi on the 25th April, 1967; and

(d) if so, the action taken to implement the decision taken at that meeting ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No.

(b) The Jhuggis were demolished in order to remove unauthorised squatters from the Government land.

(c) No.

(d) Does not arise.

TRANSFER OF CERTAIN HEAD-WORKS TO PUNJAB

3453. SHRI DEVINDER SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the erstwhile Punjab Chief Minister approached him for transferring certain head-works situated in Punjab to the State; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) Under the Punjab Reorganisation Act, the control of Ferozepore, Harike and Rupar Head-works was to be taken over by the Bhakra Management Board. The Chief Minister Punjab has however approached the Central Government not to take over these headworks. The matter is receiving attention.

(b) The matter is receiving attention.

आयुर्वेदिक गर्भनिरोधक औषधियां

3454. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आयुर्वेदिक गर्भनिरोधक औषधियों का पता लगाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) लूप का प्रयोग करने से अब तक कुल कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन पर वैद्यों और हकीमों का एक सेमिनार नई दिल्ली में 18 और 19 जुलाई, 1967 को हुआ था । सेमिनार की सिफारिश के अनुसार स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर आधारित गर्भ-निरोधक नुस्खों से सम्बन्धित सूचना, जहां तक सम्भव हो सका है, एकत्र कर ली गई है । वैद्यों और हकीमों ने कई नुस्खे भेजे जिनकी एक विशेषज्ञ समिति ने जांच की । यह समिति इसी उद्देश्य से बनाई गई थी । 56 नुस्खों का क्लीनीकल मूल्यांकन के लिए भेजने की सिफारिश की गई है । इस के बाद इन पर आगे और अनुसन्धान किए जाएंगे ।

(ख) लूप के प्रयोग के कारण अभी तक किसी मृत्यु के समाचार नहीं मिले हैं ।

'लूप' के असफल मामले

3455. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कुल लूप लगवाने वाले मामलों में से औसतन कितने मामले असफल हुए हैं;

(ख) प्रत्येक स्त्री के लूप लगाने और प्रत्येक व्यक्ति के आपरेशन पर क्या खर्च होता है; और

(ग) देश में असफल लूप लगाने और आपरेशनों के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) ऐसे मामलों की कुल संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनमें लूप सफल नहीं हुआ है । लूप लगे होने की अवस्था में गर्भ धारण की दर 0.8 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत तक है । लूप पहनी हुई और देश के विभिन्न भागों के 19 केन्द्रों पर आई हुई 20,695 महिलाओं से प्राप्त आंकड़ों

के विश्लेषण से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि 12 और 24 माह बाद लूप निकालने की दर क्रमशः 23 और 40 प्रतिशत थी। लगभग 50 प्रतिशत लूप पहनी हुई महिलाओं को किसी प्रकार की भी शिकायत नहीं थी। 24.5 प्रतिशत शिकायतें रक्त-स्राव के कारण थीं। दूसरे नम्बर पर मनोविज्ञान सम्बन्धी शिकायतें थीं जो लगभग 16 प्रतिशत थीं। अनेक महिलाओं ने इन मामूली शिकायतों के बावजूद लूप नहीं निकलवाया।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों को लूप, वेसेक्टामी और ट्यूबेक्टामी के प्रत्येक केस के लिए 11, 30 और 40 रुपये की दर से भुगतान करती है। इस भुगतान में सम्बन्धित व्यक्ति के काम की क्षतिपूर्ति, प्रेरणा देने वाले, डाक्टर, दवाई के मूल्य, मरहमपट्टी आदि का खर्च आ जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन का पैसा भी दिया जाता है। प्रति महिला लूप पहनाने और प्रति व्यक्ति नसबन्दी आपरेशन करने पर कुल कितना खर्च होता है, इसका विशेषरूप से हिसाब नहीं किया गया है।

(ग) लूप पहनने या नसबन्दी कराने के कारण मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

तीसरा वेतन आयोग

3456. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे वेतन आयोग की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार अब तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दूसरा वेतन आयोग अगस्त, 1957 में नियुक्त किया गया था इसकी नियुक्ति की आवश्यकता इसलिये प्रतीत हुई थी कि सरकार उस समय इस निर्णय पर पहुंची थी कि पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद हुए परिवर्तनों की दृष्टि से तथा देश की आर्थिक स्थिति और विकास योजनाओं के प्रभावों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की शर्तों की जांच जरूरी हो गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय वेतन आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं समझी गई है :—

(I) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें अभी 1960 में ही तो कार्यान्वित की गई थीं और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के जीवन-निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि की पूर्ति करने के लिए मंहगाई भत्ते में समय-समय पर यथोचित समायोजन किये जा रहे हैं;

(II) मितव्ययिता की दृष्टि से वर्तमान नीति यह है कि किसी भी स्तर के वेतनमानों का संशोधन न किया जाय।

(III) राज्य सरकार के कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

Allotment of Accommodation on Transfer of Government Employees

3457. **SHRI S. M. JOSHI** : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Government servant who is employed in any Government Department is entitled to get a Government residential accommodation on his turn;

(b) whether it is a fact that a Government servant on his transfer on deputation from one department of the Ministry to another Department of another Ministry who is in occupation of Government residential accommodation continues to reside in the allotted accommodation;

(c) whether it is a fact that such employees who are transferred on deputation to semi-Government Departments or autonomous bodies continue to reside in the same accommodation but are deprived of the accommodation immediately on their permanent absorption in such bodies; and

(d) if so, the facilities Government propose to give to the persons who have to lose the accommodation on permanent absorption in the autonomous bodies ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). Government servants working in eligible offices are entitled for allotment of residential accommodation from the general pool on their turn. Such Government servants on transfer from one eligible office to another eligible office at the same station can retain the general pool accommodation in their occupation.

(c) Yes.

(d) The Government servants who go on deputation to semi-Government Departments/autonomous Bodies on their permanent absorption in such organisations no longer remain Government servants and it is the responsibility of the organisation concerned to provide them alternative accommodation.

MENTAL HOSPITAL IN MANIPUR

3458. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any allotment of fund in the current Annual Plan of Manipur for the setting up of a mental hospital;

(b) if so, the progress made in setting up the hospital; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Subject to the availability of funds, it is proposed to set up two Psychiatric Clinics in 1968-69 which, it is considered would meet the requirements for the time being.

DIGBOI OIL FIELD

3459. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Digboi Oilfield is going to dry in the near future; and

(b) if so, its impact on the oil resources ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) and (b). No, Sir. But as the field is 76 years old, production of crude therein is declining steadily. The Assam Oil Company, is, however, examining the technical and economic feasibility of adopting techniques to arrest this downward trend as far as possible.

NEW OIL BEARING AREAS IN LAKHIMPUR

3460. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new oil bearing areas in Lakhmipur District in Assam and N.E.F.A. regions are being explored; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) and (b). Oil India Limited are conducting exploration in the Dum Duma and Ningru areas and have drilled some test wells. Further exploratory drilling is necessary before the prospects can be assessed.

OPENING OF HOTELS ABROAD BY INDIANS

3461. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 212 on the 23rd November, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that there is a great demand of Indian *tanduri chicken* and *Jalebi* etc. abroad; and

(b) the reason for not providing special assistance for running this kind of business or starting some hotels abroad ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Some Indian dishes were popular in restaurants opened in Exhibitions such as Expo. '67. Apart from this, Government has not come across any clear evidence of great demand abroad.

(b) The number of requests received from Indian parties for opening hotels and restaurants abroad has been very small and the question of providing special assistance has not arisen.

10, JANPATH, NEW DELHI

3462. SHRI M. L. SONDHI :
SHRI HIMATSINGKA :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state .

(a) whether it is a fact that bungalow No. 10, Janpath, New Delhi has been lying unused for the last two years;

(b) if so, the total loss of rent during the above period and whether it has been maintained properly;

(c) the number of persons to whom this bungalow was allotted and the reasons for their refusal; and

(d) the manner in which Government propose to use this bungalow ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No. The bungalow remained vacant from 23rd March, 1966 to 23rd June, 1966 after vacation by the family of late Shri Lal Bahadur Shastri and thereafter it was allotted to a Government office who vacated it on 22nd May, 1967, and since then it is vacant.

(b) The monthly rent of the bungalow under F. R. 45-A is Rs. 1380.85 per month. The bungalow is maintained by the C.P.W.D.

(c) and (d). The question for the allotment of this bungalow is still under consideration and the decision is likely to be taken in the very near future.

DEMAND FOR SMALL SIZE PLOTS IN DELHI

3463. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for big and medium size plots is decreasing as only 3,000 applications were received for 1,600 such plots, whereas 23,000 applications were received for 300 small size plots situated at Pankha Road and Wazirabad in Delhi; and

(b) if so, the action taken by Government to increase the number of small size plots ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes. The Delhi Development Authority have received 3,152 applications for 1,600 plots for the Middle Income Group in Pankha Road and Wazirpur Residential Schemes and 13,334 applications for 300 plots for the Low Income Group in Wazirpur Residential Scheme.

(b) The Delhi Development Authority are examining a proposal to provide more plots for the Low Income Group.

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को ऋण

3464. **श्री रमेशचन्द्र व्यास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने अगस्त, 1966 में पीने के पानी की कुछ अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने और ग्रामों में बिजली देने के लिये चार करोड़ रुपये के ऋण देने के लिये जीवन बीमा निगम को आवेदन किया था और निगम ऋण देने के लिये सहमत हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम ने अभी तक यह ऋण राज्य सरकार को नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस ऋण को शीघ्र राज्य सरकार को दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राजस्थान सरकार ने अगस्त 1966 में राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं को उनकी जल-पूर्ति योजनाओं के निमित्त देने के लिए जीवन बीमा निगम से कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, तथा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने नवम्बर 1966 में "कोटा के परमाणु बिजली केन्द्र से जयपुर तक प्रेषण-लाइन बनाने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये" 2 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था ।

(ख) से (घ) . जल-पूर्ति योजनाओं के लिये ऋण दिसम्बर 1966 में मंजूर किया गया था तथा उसमें शर्त यह थी कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने

के बाद, ऋण की रकम बाद से बाद 31 मार्च 1967 तक ले ली जानी चाहिये। आवश्यक औपचारिकतायें समय से पूरी नहीं की जा सकीं और इसलिये उक्त ऋण की मंजूरी वित्तीय वर्ष 1966-67 के अन्त में खतम हो गई। इस सम्बन्ध में निगम तथा राजस्थान सरकार के बीच अभी भी पत्र-व्यवहार चल रहा है।

राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मांगे गये ऋण के बारे में जीवन बीमा निगम ने अक्तूबर 1967 में बोर्ड को सूचित किया था कि वह 1 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करेगा; बोर्ड द्वारा ऋण लेना स्वीकार किये जाने तथा तत्सम्बन्धी शर्तों का पालन किये जाने का अभी भी इन्तजार किया जा रहा है।

SHORTAGE OF NAPHTHA

3465. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 216 on the 23rd November, 1967 and state :

(a) the production of Naphtha in oil refineries, refinery-wise, in the country and its estimated consumption in various industries, separately; and

(b) whether it is a fact that there is likely to be shortage of Naphtha for all the Naphtha-based industries except the fertilizer industry by 1970-71 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Figures of production refinery-wise or totals of individual products and consumption thereof cannot be disclosed under the Defence of India Rules, 1962.

(b) No, Sir.

ARBITRATION TO SETTLE GAS PRICE IN GUJARAT

3465-A. SHRI R. K. AMIN : Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. V. K. R. V. Rao acted as an arbitrator for the determination of Gas prices for the Governments of India and Gujarat;

(b) whether he gave the award when he was already working as a Cabinet Minister and hence was a party to the dispute; and

(c) if so how far it is in consistent with the conventions evolved for the appointment of an arbitrator ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) to (c). The dispute regarding price of natural gas production from the oilfields located in Gujarat was between the Government of Gujarat and the Oil and Natural Gas Commission. Prof. V. K. R. V. Rao was appointed as Arbitrator in February, 1964, in his personal capacity. Because of this fact, and as the Government of India was not a party to the dispute, in any case, his acting as Arbitrator involved no violation of any conventions. However, immediately on the assumption of the office of Union Minister of Transport and shipping the Arbitrator had ascertained, that his continuance as arbitrator was acceptable to both the parties.

मध्य प्रदेश में सत्यारा बांध के निर्माण की योजना

3465-B. **श्री लाखन लाल गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में सत्यारा बांध का निर्माण करने की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बांध का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है और उस पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) उस बांध का निर्माण हो जाने के परिणामस्वरूप वहां जमा होने वाले जल का किस तरीके से उपयोग किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, इस स्कीम पर विचार हो रहा है ।

(ग) सत्यारा योजना भिलाई इस्पात कारखाने के प्रस्तावित विस्तार के निमित्त अपेक्षित पानी की सप्लाई करने के लिये बनाई गई है । फालतू पानी को महानदी नहरों के अन्तर्गत सिंचाई के लिये प्रयोग में लाया जाएगा ।

ESSO AND BURMAH-SHELL OIL REFINERIES

3465-C. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ESSO and Burmah Shell started production 31 to 38 months after signing the contracts at Rs. 70 and Rs. 80 per ton capacity respectively;

(b) whether it is also a fact that the Barauni and Koyali oil refineries built by the U.S.S.R. started production 59 and 54 months after signing the contracts at a cost of Rs. 205 and Rs. 155 per ton;

(c) whether any other foreign Company offered to build oil refinery in Madras with investment cost of not more than Rs. 50 per ton giving a time-limit of 30 months for starting production after signing the contract; and

(d) if so, the reasons for accepting this contract at a higher cost of production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) ESSO and Burmah-Shell refineries started production 32 months and 37½ months after signing the contracts at Rs. 101 and Rs. 107 per tonne capacity respectively.

(b) Barauni and Koyali refineries started production 36 months and 27 months after signing the contracts at Rs. 205 and Rs. 155 per tonne respectively; these costs, however, cover facilities and services of a more comprehensive scope, such as a power station, own water supply scheme, etc.

(c) Yes, Sir. An offer was made by Phillips Petroleum Company, U.S.A., for building a 2.5 million-tonne oil refinery in South India on a fixed-sum basis, which was accepted. This fixed-sum contract, however, did not cover items like import duties, rail-road facilities, power and water supply, land, marine loading/unloading, etc. The total cost of complete refinery comes to Rs. 29 crores (including effect of devaluation).

(d) The offer referred to in (c) for a refinery in South India was made in 1962 and completed at a cost of Rs. 116 per tonne as compared to Rs. 101 to Rs. 107 per tonne incurred by ESSO and Burmah-Shell refineries respectively.

CASTRATION IN FAMILY PLANNING PROGRAMMES

3465-D. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether castration is included in Family Planning Programmes; and

(b) if so, how many persons, both male and female, have been castrated State-wise, so far since the commencement of the First Five-Year Plan; and

(c) its effect on the human system?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

ANTIBIOTICS PROJECT, RISHIKESH

3465-E. SHRI K. HALDAR: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the Central Bureau of Investigation recently raided a firm in Bombay and unearthed a plan of sabotage of the Rishikesh Antibiotics Project by International Chemical Cartels;

(b) whether any documents which relate to the project have been seized in this raid; and

(c) if so, the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) and (b). The Central Bureau of Investigation searched the promises of three firms in Bombay who were connected with the construction of the antibiotics project, Rishikesh, and seized some documents relating to their transactions with that project. These documents do not indicate any plan of sabotage of the antibiotics project by international chemical cartels.

(c) Since there is no indication of any plan of sabotage, the question of further steps being taken by Government does not arise.

ENCROACHMENTS BY ALLOTTEES

3465-F. SHRI RAMESH CHANDRA VYAS : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain allottees of Government Quarters in G-I Blocks of Sarojini Nagar, New Delhi and Dev Nagar (Karol Bagh) have made encroachments on the Bajri paths in front of their quarters and if so, the action proposed to be taken against them;

(b) whether Government are aware that certain allottees of these quarters who happen to be employed in the C.P.W.D. have had extensive repairs done and kitchen gardens put up with the material acquired from Government stores, etc.; and

(c) if so, the action proposed to be taken against them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

SUN-LIGHT COLONY, MOTI BAGH, NEW DELHI

3465-G. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the piece of land belonging to the Sun-light Colony situated on the Ring Road near Moti Bagh, New Delhi was acquired by the authorities in 1951 and that a case pending in the High Court was decided as late as the 25th January, 1966 in favour of the plot holders;

(b) if so, whether possession has been given to the plot holders of the colony; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) and (c). No. It is proposed to file an appeal in the Supreme Court against the decision of the High Court.

PROHIBITION

3465-H. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the centrally administered areas are scrapping or propose to scrap prohibition;

(b) if so, whether they are not acting against Article 15 of the Constitution; and

(c) the action being taken by Government to uphold the Constitution ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

INCOME-TAX FILES OF BIRLAS

3465-I. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Income-tax files of Birlas have reached Delhi from Calcutta to assess the extent of evasion of Income-tax; and

(b) if so, the findings thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The matter has been entrusted to the Director of Inspection (Investigation) for investigation in all its aspects. Where considered necessary, the files have been called for and examined at Delhi. In other cases, the Director of Inspection (Investigation) is having the files examined at the places where the assessments are made. The investigations are in progress.

'P' FORM FOR FORMER RAILWAY MINISTER

3465-J. SHRI GEORGE FERNANDES : SHRI V. KRISHNAMOORTHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the former Railway Minister, Shri S. K. Patil went abroad in July, 1967, for about a month on a 'P' form for medical treatment;

(b) whether he had sought any foreign exchange; and

(c) whether he fulfilled the conditions laid down for the purpose.?

THE DEPUTY PRIME MINISTER & MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (c). Yes, Sir. On being satisfied about the need for a medical check up, the Reserve Bank gave 'P' form clearance.

(b) No, Sir.

CORRECTION OF ANSWER TO U.S.Q. NO. 753, DATED 16-11-1967

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : I had given a reply in the negative to Unstarred Question No. 753 on the 16th November, 1967, regarding compulsory rural service for doctors. I would like to amplify that while there was no resolution by the Conference of Deans and Principals of Medical Colleges to introduce compulsory rural service for doctors and students, a resolution was adopted by the Conference recommending compulsory training for the interns in rural areas in Maternal and Child Health and Family Planning for a limited period of one year. A copy of the full resolution is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1910/67]

2. The recommendations are under consideration.

12.15 HRS.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED RUSSIAN INTERFERENCE WITH THE LAST GENERAL ELECTIONS IN INDIA

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

Reported Russian interference with the last General Elections in India.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Speaker Sir, Government have seen press reports regarding the alleged interference by Russians in the last General Elections. Efforts are being made to obtain the full text of the statements made by Mr. Y. N. Loginov. Pending their receipt and examination, it is not possible for Government to say anything in the matter. Honourable Members are, however, aware that objectionable aspects of the broadcasts made by "Radio Peace and Progress" have been brought to the notice of the appropriate Soviet authorities by the Government of India.

SHRI D. N. PATODIA : The answer is so evasive that it is necessary for me to bring some facts to the notice of the hon. Minister before he can give a suitable reply.

The Russian agencies, through various methods, have been systematically indulging into the election campaign of India as if they are fighting their own elections. According to the *Hindustan Times* of 4th December as referred by the hon. Minister, certain very serious insinuations have been made. Now I want to know whether, in respect of this gentleman, Mr. Yuri Modin, the Government of India had sufficient information available with them and the Russian Embassy was already asked to see that Mr. Yuri Modin was deported back from India.

Regarding the various interference of the Soviet Embassy into the election campaign of India, there have been several facts which have already come to the notice of the Government of India, and for the sake of illustration, I will quote only one and it is this.

Another report through the broadcast of June 7 "Radio Peace and Progress" com-

pared Mr. Menon to Mahatma Gandhi of India on the one hand. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : What an imagination !

SHRI D. N. PATODIA : ....and on the other hand, Mr. Morarji Desai, who happens to be one of our national leaders was described as the mouth-piece of reactionary forces in the Congress and it partly hinted in the broadcast of Mr. Desai's failure to stop the murder of Mahatma Gandhi in 1948 when he was the Home Minister... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : It is all wrong.

SHRI D. N. PATODIA : In this respect it has been very seriously alleged that there have been various sources of financing the election campaign in India and in that process, it has come to the notice of the Government of India that one firm by name Nav Bharat Enterprises, 22 Ring Road Lajpat Nagar, New Delhi, had been systematically financing. This firm happens to be a contractor and does the import and export business of the Russian Government....

MR. SPEAKER : He may put his question.

SHRI D. N. PATODIA : What I will try to explain now is that the Russian propaganda did not stop with the completion of the elections in India; they are continuing the same propaganda and they are preparing for the next elections in India. To that extent. I want to advise.... (*Interruptions*)

SHRI NAMBIAR (Tiruchirapalli) : Is he giving information or seeking information ?

SHRI D. N. PATODIA : I am giving information to seek information.

This particular aspect of the propaganda has now been taken over by the Russian Embassy systematically and it has been reported that one Mr. Vitali Jourkins, Councillor of the Soviet Embassy, whose name has been included in the official diplomats' list, is now the liaison between Moscow and the Communist Party of India and he sends regular messages to "Radio Peace and Progress"....

AN HON. MEMBER : Shame, shame.

SHRI D. N. PATODIA : ....and I have been told that this is an information which is in the knowledge of the Home Ministry and they are watching his activities.

The other method which they have now adopted is that they are preparing for the next elections. They have openly condemned the dismissal of the West Bengal Government in the "Radio Peace and Progress" programme..(*Interruptions*) They have also openly condemned this in the 'Radio Peace and Progress and they have suggested that whatever has happened in West Bengal is reactionary and is not proper. I think that explains the Communist Party's demand for mid-term elections in West Bengal because they want to link up mid-term elections with Soviet propaganda and Soviet assistance. (*Interruptions*)

SHRI NAMBIAR : Nobody can give a speech.

SHRI D. N. PATODIA : Now my question is : whether the Government of India has made proper investigations into all the facts that I have mentioned and what is the result of those investigations ? That is No. 1.

No. 2—Novosti which has been associating itself with these activities about which sufficient proof is there and with which PIB has entered into an agreement recently . . . (*Interruptions*). Is the Government of India prepared to revoke that agreement ? No. 3—Is the Government prepared to disband all such associations which have been associating themselves with these activities ? No. 4 is : whether the Government of India is prepared to appoint a Parliamentary Committee to go into all these investigations ? (*Interruptions*)

SHRI NAMBIAR : He must be made the Chairman of that Committee.

SHRI D. N. PATODIA : I accept it. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BASU *rose*—

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Basu let us hear the Home Minister now.

MR. Y. B. CHAVAN : Sir, as far as these 'Peace and Progress Radio' broadcasts are concerned, certainly we have taken up this matter with the appropriate Soviet authorities and some questions were put in

[SHRI Y. B. CHAVAN]

this hon. House and information was given that they have agreed to consider these matters. Naturally, if any foreign broadcast propaganda casts any reflection on the national leaders of our country, we have to protest against such matters.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): They have been doing that.

SHRI Y. B. CHAVAN: My only point is: whose activities we are watching, I do not think I can disclose that information here. It should not.

I would only make one point Sir. It is expected that the friendly countries should not interfere in any of our political activities and it is their claim too that they are not doing that. But, certainly, we would wish them not interfere. But, at the same time, I think we should not allow our country to become a fighting ground for any cold war propaganda of any of the foreign countries. They possibly might do that. Despite our wishes about it, they possibly might do it. It will be the duty of all political parties in this country not to get influenced by this Matter. Ultimately we have to strengthen our base in this matter and we will have to fight our political lives on the merits and demerits of our own political views.

SHRI D. N PATODIA: But we are permitting it without any objection.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अभी तक देश के घरेलू मामलों में अमरीकी हस्तक्षेप की चर्चा होती थी। अब सोवियत हस्तक्षेप के कुछ प्रमाण सामनें आ रहें हैं। सारा सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि एक स्वतंत्र और प्रभुतासम्पन्न देश के नाते हम इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाशत नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी देश की तरफ़ से हो। लेकिन मुझे गृह मंत्री का वक्तव्य सुन कर बड़ी निराशा और आश्चर्य हुआ है। इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में जो खबर छपी है, उन्होंनें उस का हवाला तो दिया है, लेकिन यह बताने का कष्ट नहीं किया कि वह खबर सही है या ग़लत। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है:

"Mr. Loginov has described how a high-ranking K.G.B. officer, whose real name was Mr Lyudin was sent last year as a political counsellor in the Soviet Embassy in Delhi where, under the assumed name of Mr. Yuri Modin, he organized Soviet Union's 'election campaign'."

क्या गृह मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि मि० माडिन के नाम से सोवियत एम्बेसी में कोई कांसेलर थे? मेरे पास भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका है, जिस में राजदूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम हैं। इस के पृष्ठ 93 पर "यूनियन आफ़ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक्स" के नीचे दिया हुआ है: "कांसेलर: म० यूरी आई० माडिन, फ्लैट नम्बर 16, हाउस नम्बर 4, रेजिडैंशल बिल्डिंग्ज आफ़ दि यू० एस० एस० आर० एम्बेसी, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली-21"।

आरोप यह लगाया जा रहा है कि मि० माडिन के० जी० बी० के एक ऊंचे अफ़सर थे। यह चुनाव के दिनों में दिल्ली में आए, गर्मी से ले कर वसन्त के बीच में रहे और उन्हों ने यहां ऐसे काम किये, जिन से हमारा चुनाव प्रभावित हो।

क्या गृह मंत्री के ध्यान में यह बात भी आई है कि मि० माडिन के नाम को ले कर कुछ जाली पत्रों की चर्चा हो रही है। यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं गृह मंत्री से चाहता हूं कि वह बिल्कुल ठोस जानकारी के आधार पर स्पष्ट और दो-टूक उत्तर दें। क्या उन के ध्यान में यह बात आई है कि मि० माडिन के नाम को ले कर कुछ जाली पत्रों की चर्चा हो रही है? एक जाली पत्र बम्बई में अमरीका के कान्सुलेट के कोंसेलर-जनेरल की ओर से अमरीकी एम्बेसेडर को लिखा गया। एक पत्र ब्रिटिश हाई कमिश्नर के नाम से लिखा गया जिस में श्री पाटिल से ले कर, और कांग्रेस नेताओं को ले कर, गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। क्या गृह मंत्रालय ने इस बात

की जांच की है कि यह जाली पत्र लिखने वाला कौन था ।

गृह मंत्री ने कहा है कि हम एलेज्ड इन्टर-फ़ीयरेंस की जांच कर रहे हैं । यह "एलेज्ड" क्या है ? यह जो "रेडियो पीस एंड प्राग्रेस" प्रोग्राम चल रहा है, वह सोवियत भूमि से चल रहा है । क्या कोई इस से इन्कार कर सकता है ? कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता है ।

MR. SPEAKER : But the hon. Minister has said that Government have already protested and written to that Government.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब सरकार विरोध कर रही है, तो फ़िर "तथा-कथित हस्तक्षेप" की बात कहने का क्या मतलब है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं ने उस के बारे में नहीं कहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय किसी और प्रमाण में न भी जायें, तो भी यह जो "रेडियो पीस एंड प्राग्रेस" कार्यक्रम चल रहा है, वह भारत के घरेलू मामलों में खुला हस्तक्षेप है और सहअस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ़ है । भारत सरकार विरोधपत्र देने के बजाय रूस को यह क्यों नहीं कहती कि अगर यह प्रोग्राम बन्द नहीं किया गया, तो यह एक अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझी जायगी और इस से हमार और रूस के सम्बन्धों को धक्का लगेगा ?

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सोवियत रूस से मित्रता चाहते हैं और सोवियत रूस हमारी जो सहायता कर रहा है, उस के लिए हम आभारी हैं, मगर वह हमारे स्वाभिमान, हमारी स्वतंत्रता और हमारी प्रभुसत्ता पर आघात नहीं कर सकता । न हम रूस को यह काम करनें देंगे और न अमरीका को ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I entirely agree with the hon. Member about the sentiment that he has expressed in the last part of his statement. I did not say about the alleged interference as far as the radio was concerned. I have said that we have taken up this matter with them but about the other matters naturally, when I have not got the text of the statement with me, I just cannot say anything about it.

It is a fact that an officer of the name of Mr. Yuri I Modin, mentioned in the news items etc. was an officer who was designated as a counsellor, and he was in India between 12th July, 1966 and 22nd April, 1967. That is a fact. But that fact would not authorise me to say whether what is alleged is right or wrong. This fact is true and we know about it.

Certain other allegations also are made, but unless we come to any conclusion with proper evidence, I think it would be very unfair, in view of our relationship with other countries, friendly countries, both America and Soviet Russia, to make any authoritative statement on the floor of the House. That is my main difficulty.

SHRI D. N. PATODIA : On a point of order....

MR. SPEAKER : There is no point of order now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब कहां दिया गया है ? क्या भारत सरकार सोवियत रूस से यह कहने के लिये तैयार है कि यह हस्तक्षेप बन्द होना चाहिए, नहीं तो यह अनफ़्रेंडली एक्ट समझा जायेगा ?

MR. SPEAKER : The hon. Minister has already said that it should stop whether it be from America or from Russia.

SHRI RANGA (Srikakulam) : It is an omnibus answer which he has given.

But the hon. Member had asked a specific question.

MR. SPEAKER : He has already said that it should stop whether it be from America or from Russia.

SHRI Y. B. CHAVAN : I did say that.

SHRI D. N. PATODIA : Information is being concealed.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Is the hon. Minister prepared to say that it is an unfriendly act ? Let him stand up and say it.

SHRI D. N. PATODIA : Information is being concealed. The news item was published on the 4th and today is the 7th, and already about three days have elapsed, and yet information has not been collected. How does the hon. Minister explain it ?

श्री य० द० शर्मा : (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, ...

SHRI HEM BARUA : I do not want to put any question, but I just want to have a clarification from you. We had tabled a calling attention-notice.....

MR. SPEAKER : Let this calling attention-notice be over first.

SHRI HEM BARUA : We had tabled a calling-attention-notice about the involvement of Mr. Modin, but you had disallowed that. But now this question has cropped up....

MR. SPEAKER : Let this be over now. The hon. Member can write to me or meet me later on in regard to whatever calling-attention-notice he wants me to take up. Several notices are received, and do reject some and allow some others. Unfortunately, I am in that position....

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : May I seek a clarification ?....

MR. SPEAKER : Let this be over first.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I do not want to put any question, but I only want to have a clarification. Was that not the election period ? Is it the normal rule to allow such things to go on during that period ?....

SHRI Y. B. CHAVAN *rose*—

MR. SPEAKER : The Home Minister shall not answer this question. I want to be very strict.

श्री य० द० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह जो प्रचार रूस द्वारा चल रहा है और भारत सरकार ने जिस प्रचार के लिए कुछ आपत्ति उठाई है क्या वह निश्चित रूप में उस प्रचार को अमैत्रीपूर्ण मानते हैं ? क्या वह अपनी नीति के अन्दर उस प्रचार को अमैत्रीपूर्ण समझते हैं हमारे देश के लिए और इस देश की आंतरिक शांति और चुनाव आदि व्यवस्थाओं के अन्दर सीधे तौर पर इसे हस्तक्षेप मानते हैं ?

(2) यह जो इस प्रकार की चीजें हैं जिन के प्रमाण अभी माननीय सदस्यों ने यहां दिए और इस के अतिरिक्त अभी-अभी हमारे देश के पी० आई० बी० ने रूस की एक एजेंसी के साथ वहां के साहित्य के प्रचार का एक समझौता किया है और इस के साथ-साथ जो अभी-अभी रूस की क्रांतिकी पचासवीं वर्षगांठ के ऊपर प्रधान मंत्री महोदया वहां पधारीं, इन सारी बातों से क्या देश के लोग यह समझने के लिए मजबूर नहीं हैं कि हमारी सरकार की कमजोरियों के कारण या उस की इच्छाओं के कारण यह सब हो रहा है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : As I said, about this radio broadcast, we have taken up the matter with the Soviet authorities. And when they have said that it is being considered by them, it would be rash on my part to come to any conclusion as to whether it is a friendly or unfriendly act. The matter is now between the two friendly countries.

It is absolutely wrong to say that because of the weakness of the Government of India, these people are doing this....

SHRI D. N. PATODIA : Are they considering the objection ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would still make an appeal. Possibly other countries might be trying to influence our politics, but it is we who will have to be very cautious about it and not allow cold war propaganda to be taken notice of.

SHRI D. N. PATODIA : Are they considering it ?

श्री य० द० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय यदि इस सदन के सामने अपनी सरकार की किसी स्थिति को स्पष्ट नहीं रखना चाहते, दूसरे देशों से इस का सम्बन्ध नहीं है, हमारी सरकार इस प्रचार को किस रूप में ले रही है यह अगर इस महान सदन को नहीं बताते तो मैं समझता हूं कि देश के साथ धोखा करते हैं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Any attempt to interfere in our politics is something very undesirable. I have no doubt in my mind about that.

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो 4 तारीख के अखबार की ही बात चल रही थी, मेरे हाथ में यह 14 अक्तूबर का करेंट है जिस में लिखा हुआ है—होम मिनिस्ट्री सिट्स आन इट्स बिगेस्ट स्टोरी—इस की तरफ क्या मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट हुआ है ? उस में यह भी दिया गया है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपये रूस ने हिन्दुस्तान में भेजे हैं चुनाव के लिये । क्या इस ओर आप का ध्यान आकृष्ट हुआ या नहीं ? यदि हुआ है तो क्या इस की कोई जांच की गई है ?

दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या जिस रास्ते यह रुपये भेजे जाते हैं उस के बारे में आप ने कोई जांच की है ? मैं दो रास्तों का पता आप को बताता हूं । उस के बारे में क्या आप जांच करेंगे ? एक तो चीन से और रूस से बहुत बड़ा साहित्य अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में हिन्दुस्तान में आता है और रुपयों में बेचा जाता है । क्या इस का कोई हिसाब है कि कितने रुपयों की कितनी किताबें आईं कितनी बिकीं, कितना रूपया यहां बिक्री में मिला और कमीशन काट कर कितना रुपया रूस गया या कितना यहीं रह गया ? अगर सारा या कुछ अंश यहीं रह गया तो क्या चीन और रूस के समर्थक दलों को वह दिया गया या उस का क्या हुआ ? इसी प्रकार रूस की प्रभाव परिधि में पड़ने वाले देश जैसे कि पूर्वी जर्मनी, हंग्री, पोलैंड, बागेरिया इत्यादि हैं, उन से सोने की दर से नहीं पाउंड और डालर के हिसाब से नहीं बल्कि रुपयों के हिसाब से इस देश में बहुत सा माल आयात होता है । वह यहां से जो माल खरीद करते हैं वह भी रुपये में लिया जाता है । क्या इस की जांच हुई है कि जितने का माल आता है उतना रुपया या उतने ही का माल वहां जाता है ? माल के रूप में या नकद के रूप में क्या उतना ही वहां जाता है या नहीं ? यह दो रास्ते बहुत स्पष्ट हैं कि जिन से पता चल सके कि कैसे रूस से रुपये यहां आये और बांटे गए ।

इस के बाद फिर सवाल उठता है कि जब कि यंग इंडिया में इस के बारे में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं करेंट और यंग इंडिया की प्रतियां आपके पास पेश करूंगा, उस में पूरा हिसाब दिया हुआ है पार्टियों के हिसाब से । तो उस के ऊपर क्या आप कृपा कर के जांच पड़ताल करेंगे ?

दूसरी बात—क्या चुनाव के दिनों में विदेशी पर्यटक चाहे वह रूस के हों, चीन के हों या दूसरे साम्यावादी देशों के हों, वह उन-उन स्थानों में घूमते रहे हैं जिन के नाम पर्यटक स्थानों के लिहाज से ऊंचे नहीं रहे हैं बल्कि वे स्थान केवल चुनाव के लिहाज से ऊंचे रहे हैं?

इस के बाद क्या सरकार को पता है·· (**व्यवधान**)··मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । जिस समाचार की आप खोज में हैं जो उनमें उनके नाम दिए गये हैं जिन्हें रूस से पैसे मिले हैं । क्या वे नाम जब आप को मिल जायें विदेशी पत्रों से तो क्या आप कृपा कर के उन नामों को सदन के पटल पर रखेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. member has invited my attention to some article which appeared in the *Current*, *Young India* and some other papers. I think the article which was published by *Young India* most probably was reproduced by *Current*. I can say that this entire question of the use of foreign money in the last general election was a matter of some enquiry by the Intelligence Bureau, about which I had made a statement in the last session that that report is under the examination of the Government. So, the allegations or the reports about the use of money from the Russian side, about the use of money from the American side, in our political life were made, and that matter necessarily requires to be gone into carefully.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : कितने साल एग्जामिनेशन चलेगा ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जितना वक्त आवश्यक है उतना अवश्य लगेगा । वक्त कहना मेरे लिये मुश्किल है ।

I would certainly say that we in the Home Ministry naturally do get information, and we certainly try to find out their *modus operandi*, keep a watch on this matter, and if possible to lay our hands on them, but it is very difficult for me to say whether "A" or "B" did or which *modus operandi* they are using. If I disclose whatever information I have, our further efforts will be frustrated, because we are trying to pursue the matter.

SHRI N. K. SOMANI (Nagpur) : It is very unfortunate that the Prime Minister of our country has reduced the status of New Delhi as an extended suburb of Moscow. Otherwise I do not know how we can accept the fact of our Prime Minister associating herself with the distribution of prizes to Indian citizens at the behest of *Pravda*. I put it to you that we have 56 Ministers in this Cabinet, and any one of the Deputy Ministers could have very well done this function. Actions and policies like this embolden the Soviet authorities to arrogate to themselves the power of running the internal affairs of this country. If by leaders and in this Parliament a lot of serious allegations have been made in respect of Yuri Modin, I would like to ask the Home Minister how long he would take to complete the enquiry in respect of Radio Peace and Progress and pronounce a judgment. I am also surprised at the answer that he gave in respect of Radio Peace and Progress talks. I know that before the last election the monitoring unit of All India Radio at Simla had sent in a report about the objectionable pronouncements of this radio. Now, several months have passed after that, and why is the Government still saying that we are holding an enquiry? And on top of it, we have reduced our PIB to a *chamcha* of Moscow. And it is all going to be one-way traffic, because I am sure that whatever literature and material and propaganda stuff goes from India will be censured and would not be distributed. there. I would like to have a specific answer to this question.

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member has not asked any question. But he has made a rather irresponsible statement, saying.... (*Interruption*).

SHRI RANGA : What is this, Sir? The hon. Member has asked questions; why should the Minister say he has not asked any question?

SHRI Y. B. CHAVAN : Instead of giving any information or asking me any question, I must say with all the emphasis at my command that he made an irresponsible statement that New Delhi has become a suburb of Moscow. It is not so. Sometimes some people who want India to be a suburb of Washington possibly think that way. (*Interruption*). We do not want to be a suburb of either Washington or Moscow. We have our independent policy and we would like to follow it with determination.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काम रोको प्रस्ताव है—दिल्ली में गिरफ्तारियों के बारे में .....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to raise a point of order. Please permit me to raise it.

MR. SPEAKER : On what?

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 260 की ओर दिलाना चाहता हूं । दिल्ली में कल पुलिस ने बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की है, उन को मारा है ..... (व्यवधान) .....

MR. SPEAKER : I am not obliged to hear new points. Somebody wants to raise something about Delhi arrests, somebody wants to raise something about Hyderabad and so on. How can I allow all these now?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Central Government is responsible for solving the genuine difficulties of the people.

MR. SPEAKER : Order, order. It is not possible to see to all those things now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आप जानते हैं .....

MR. SPEAKER : All sorts of things cannot be raised now on the floor of the House. You should tell me inside the Chamber so that I could permit you, if it is an urgent matter, to raise it here. But you should not raise like this. I am proceeding to the next item of business.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा आप कल इजाज़त दीजिये ।

12.43 HRS.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF INDIAN OIL CORPORATION LIMITED AND REVIEW BY GOVERNMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Bombay for the year 1966-67 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(2) Review by the Government on the working of the above Corporation.

[*Placed in Library. See* No. LT-1898/67].

ANNUAL REPORT OF THE DAMODAR VALLEY CORPRATION

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[*Placed in Library, See* No. LT-1899/67].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : I beg to re-lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

(i) G.S.R. 1082 published in Gazette of India dated the 22nd July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(ii) G.S.R. 1112 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(iii) The Indian Police Service (Uniform) Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1113 in Gazette of India dated the 29th July, 1967.

(iv) G.S.R. 1114 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(v) G.S.R. 1117 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(vi) The Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Thirteenth Amendment Regulations, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1119 in Gazette of India dated the 29th July, 1967.

(vii) The Indian Police Service (Appointment by Promotion) Twelfth Amendment Regulations, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1120 in Gazette of India dated the 29th July, 1967.

[*Placed in Library. See* No. LT-1374/67].

12.44 Hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 366 *RE.* BONUS FOR EMPLOYEES OF ASHOKA HOTEL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : In reply to Supplementary questions to Starred Question No. 366 answered on the 30th November, 1967, regarding bonuses for employees of Ashoka, Janpath, Ranjit and Lodhi Hotels, I informed the Lok Sabha that in Hotel Janpath a bonus of 10% was given, whereas in Ranjit and Lodi Hotels, only 4% bonus was given. The factual position is that in all the three hotels, namely, Janpath, Ranjit and Lodhi, a 10% bonus was given since all the employees were under the Janpath Hotels Limited which controls all the three hotels.

MR. SPEAKER : The Home Minister.

12.44½ Hrs.

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION *RE.* OFFICIAL LANGUAGES

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, I beg to move : (*Interruption*).

SHRI RAM SEWAK YADAV : ***

MR. SPEAKER : Nothing will be taken down.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Nothing will be taken down. (*Interruption*). Order, order. Points of order are being raised now. When the Bill was introduced the other day, points of order were raised. I permitted them and the points of order were discussed, in regard to this Bill. The legality and the constitutionality of the Bill were discussed. Now, today, to raise points of order again is not proper. I am not going to allow it, because on that day, I had allowed everybody to speak.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, आप मेरी बात सुनिये .....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप पहले इनकी बात सुनिये । आप पहले ही मना कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER : Mr. Limaye has written to me already. He cannot spring a surprise on me like that. He has written to me. (*Interruption*). have allowed all of you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : You did not allow me. I was not even present then. Hon. Members are within their right to make points of order.

MR. SPEAKER : I have allowed all the Members, individually.

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, कोई नया प्वाइन्ट भी हो सकता है । अगर आज मैं एक प्वाइन्ट उठाता हूं, कल दूसरा भी उठा सकता हूं—यह मेरा अधिकार है, आपको रोकना नहीं चाहिये, यह रूल्ज के मुताबिक है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा यह कहना है कि जैसा अभी आपने कहा कि जिस दिन यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन इस बिल में अगर कोई असंवैधानिक बातें थीं तो उस दिन उन पर विचार कर लिया गया था और उनके आधार पर यह निर्णय कर लिया था कि इस बिल को विचार के लिये प्रस्तुत किया जाय, लिहाजा अब उस विषय पर कोई बात नहीं सुनी जा सकती । शायद आप यही बात कहना चाहते थे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में कोई असंवैधानिक बाधा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस बिल के साथ गृह मंत्री जी ने जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में क्या असंवैधानिकता है, उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता

*** Not recorded.

हूं । इस सदन की यह परम्परा है कि दो तरह के संकल्प यहां आते हैं—एक वे होते हैं जो गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से आते हैं और दूसरे वे होते हैं जो सरकारी पक्ष की ओर से आते हैं—इस तरह से जो सरकारी पक्ष की ओर से आते हैं और दूसरे जो गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से आते हैं—उनमें अन्तर होता है । इस संकल्प में दो शब्द इस प्रकार के हैं जिनसे संविधान की जो शपथ आपने ली है और जो शपथ इस सदन के 550 सदस्यों ने ली है—उसको दृष्टि में रखते हुए, आपका भी कर्त्तव्य है और हमारा भी कर्त्तव्य है कि इस संविधान की पवित्रता की रक्षा करें । अगर इस संकल्प में कोई इस प्रकार का शब्द है जिससे संविधान की मूल भावनाओं को आघात पहुंचता है या जो उसके विपरीत हैं, तो मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि इस प्रकार का संकल्प इस सदन में प्रस्तुत हो सकता है या नहीं ?

पहली बात तो यह है कि इस संविधान की धारा 383 को आप पढ़ें, जिसके अन्तर्गत यह निश्चय कर दिया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है । अब इस संकल्प की पहली पंक्ति में यह है (अगर इसका हिन्दी अनुवाद सही है तो) संविधान के अनुच्छेद 383 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिन्दी होगी । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुसार और 1965 के राज-भाषा संशोधन विधेयक के अनुसार भी सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि संघ की राज-भाषा हिन्दी है । जब सरकार इसको स्वीकार कर चुकी है और संविधान के अन्तर्गत यह है तो इस संकल्प में ये शब्द नहीं आ सकते कि राज-भाषा हिन्दी होगी । इसका अभिप्राय यह है कि सरकार नये सिरे से इस चेप्टर को फिर खोलने जा रही है, जो कि असंवैधानिक है ।

दूसरी बात यह है कि इसी संकल्प में एक स्थान पर यह लिखा है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के सम्बन्ध में देश के किसी भाग के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा । वहीं पर एक शब्द यह लिखा गया है—आप अन्तिम पैरे से ऊपर पढ़ें । यदि यह हिन्दी अनुवाद सही है तो—कि उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी का ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित नहीं होगा । जब संविधान के अनुसार हिन्दी इस देश की राजभाषा हो गई है और सह-भाषा के रूप में ही केवल अंग्रेजी है तो आज गृह-मंत्री या प्रधान मंत्री या कोई भी सरकार पहले संविधान में संशोधन करे । संविधान में संशोधन करके इस बात को कहे कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी प्रमुख भाषा है । लेकिन जब तक ऐसा संशोधन नहीं होता है और 1965 के बाद से अंग्रेजी प्रमुख भाषा नहीं है । इस देश की राजभाषा केवल हिन्दी ही है, तो कोई भी संकल्प सरकार की ओर से इस प्रकार का नहीं आ सकता जिसमें यह हो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये हिन्दी को अनिवार्यता नहीं होगी । इन दोनों प्रश्नों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दोनों बातें असंवैधानिक हैं, संविधान की धाराओं के विपरीत हैं ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि नेहरू जी के आश्वासन के आधार पर ऐसा करना पड़ रहा है । इस समय विस्तार से तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि नेहरू जी की अपेक्षा संविधान बड़ा है, नहरू जी संविधान से बड़े नहीं हैं ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि यह जो विधेयक प्रस्तुत है—इस विधेयक को हम संवैधानिक मानते हैं या असंवैधानिक मानते हैं, इस पर जब चर्चा चलेगी, तब इस को उठाया जा सकता है तथा मैं यह भी जानता हूं कि माननीय प्रकाशवीर शास्त्री ने जो इस पर आपत्ति

[श्री राम सेवक यादव]

उठाई है, इसके लिये भी आप यही तर्क देंगे कि इस पर चर्चा होने वाली है । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे यह विधेयक हो या जो प्रस्ताव माननीय गृह-मंत्री जी ने रखा है, दोनों संविधान की व्यवस्था, मंशा, सब के विपरीत हैं, उस की मंशा और व्यवस्था के खिलाफ हैं । इस में सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की मंशा का सहारा लिया गया है और मैं साफ कहना चाहूंगा, इस सदन में आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि क्या किसी व्यक्ति विशेष की मंशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ी हो सकती है और जब कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था हो । राष्ट्रपिता ने कहा था—अगर मेरे हाथ में तानाशाही के अधिकार हों, तो मैं एक क्षण में अंग्रेजी को खत्म कर दूं ।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने इस विधेयक द्वारा राजभाषा पद पर अंग्रेजी को कायम रखने का प्रयास किया है और हम देख रहे हैं कि सरकार के इस कुप्रयास का हर जगह किस तरह विरोध हो रहा है और आम जनता में इस को लेकर किस कदर एक व्यापक असन्तोष की लहर फैल रही है और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो घटनाएं घट रही हैं उस के लिये यह केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है चाहे वह घटनाएं बिहार में घट रही हों या उत्तर-प्रदेश में घट रही हों या और कहीं घट रही हों..... (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Is the hon. Member making a speech ? Mahatma Gandhi does not come in the point of order.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं किसी के बोलने में कोई बाधा नहीं डालूंगा हां वे लोग जिनकी कि मातृभाषा हिन्दी है वे यदि अंग्रेजी में बोलते हैं तो बात और है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो लोग कह रहे हैं कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि ऐसी न तो हमारी मंशा है और न इरादा है । हम किसी के ऊपर हिन्दी लादना नहीं चाहते । साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश की एकता का प्रश्न उठाया जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश की एकता के लिए अंग्रेजी के बनाये रखने की बात होगी.....

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : Sir, it is not a question of one man. It is a question of unity of India. If you want us in the Indian Union you will have to give us our due rights. You cannot ride over us. You cannot be imperialists over us. We would not allow it. We are not here by anybody's courtesy. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Order, order. It is a point where tempers will rise high. Still, when you have an opportunity to discuss, everybody must be given an opportunity to express his views.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : आप यह राजभाषा (संशोधन) विधेयक वापिस करवा दें तो सब ठीक हो जायेगा वरना गड़बड़ी और भी बढ़नें वाली है ।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : This point of order was raised and discussed the other day. Every day the same point is raised.

Every day we cannot allow it. There is a limit to everything.

MR. SPEAKER : A point of order has been raised. Ample time has been given for this Bill. It is not that all the 522 Members will speak on this. Twelve hours have been allotted for this Bill. Again the Business Advisory Committee is meeting today at 4.45 P.M. We will be discussing again about the time and all that. Therefore, if one section tries to disturb the other section it leads us nowhere. Shri Prakash Vir Shastri has raised a point of order. Whether Shri Yadav is supporting it or opposing it I do not yet know. He is still on Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai and others. When he comes to the point of order we will know. I would

now request him to come to the point of order. Let us quietly hear him. Let not anybody disturb when others are speaking. Everybody has to place his point of view.

श्री रामसेवक यादव : हमें डर है कि कभी यह भी कहा जायेगा कि विदेशी हुकूमत करो तभी देश एक रहेगा । मैं यह कह रहा हूं कि सारे देश में इस प्रश्न को लेकर जो भाषा सम्बन्धी चीज आज से बहुत पहले सन् 50 में तय हो गई थी, संविधान में वह स्पष्ट तौर पर लिख दी गई थी आज इस विधेयक को लाकर उस में सरकार आग लगा रही है । यह जो व्यापक असन्तोष सर्वत्र फैल रहा है उस के लिये केन्द्र जिम्मेदार है । यह जो भाषा विधेयक भारत सरकार के गृह मंत्री ने रखा है उस को लेकर सारी दिल्ली की जनता में विक्षोभ है, एक असन्तोष है । कल दिल्ली में सब जगह हड़ताल थी और कल जनता के चुने हुए नुमायन्दों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है । इसलिये पहले तो यह जो सारे वातावरण को आग लग गई है उस पर सारे कामकाज को रोक कर बहस होनी चाहिये । उस के बाद इस बात पर विचार किया जा सकता है कि विधेयक पर विचार हो सकता है या नहीं लेकिन पहले उस हमारे कामरोको प्रस्ताव पर चर्चा की जाये ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : शास्त्री जी ने जिन दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया है उन दोनों के विषय में मैंने संशोधन दिये हैं और मैं आशा करती हूं कि उन को वह मंजूर करेंगे ।

श्री मधु लिमये : अभी संशोधनों का सवाल नहीं है बल्कि व्यवस्था का सवाल है ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अभी सुचेता जी ने कहा कि उन्होंने संकल्प के सम्बन्ध में दो सुझाव भेजे हैं । मेरा आप से निवेदन है कि प्रकाशवीर शास्त्री जी के मतानुसार कि जिस मत का मैं समर्थन करता हूं, यानी संकल्प ही गैर-कानूनी है । अगर संकल्प गैर-कानूनी है तो उस में सुधार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । आप को पता है कि उस संकल्प के आरम्भ में जो कुछ कहा गया है और उस के बाद जो कुछ कहा गया है वह दोनों बातें ऐसी हैं कि जिससे संकल्प गैर-कानूनी, अनकांस्टीट्यूशनल, संविधान के विरुद्ध सिद्ध होता है । इस लिये मेरा निवेदन है कि जब संकल्प ही गैर-कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है तब सुधार का प्रश्न कहां से उपस्थित होता है ।

मैंने, जब विधेयक आया, उस समय भी यही बात कही थी और आज मैं फिर कहता हूं । कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जिनसे केवल दिल्ली में ही नहीं वरन् सारे देश में एक क्षोभ हो गया है । उत्तर प्रदेश में देखिये, दिल्ली में देखिये, सब जगह देखिये इस तरह की घटनायें घट रही हैं और असन्तोष भड़क रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इस गैर-कानूनी विधेयक के संकल्प को वापिस ले लेना चाहिये ।

MR. SPEAKER : You are the senior-most Member of this House. Yet, you are making a speech on a point of order. Will you kindly sit down. You should set an example to other Members.

SHRI A. K. SEN (Calcutta North West): On this point of order may I make a few submissions ? When the whole Constitution was adopted on the 26th January, 1950; article 343 read that as from the date of 26th January, 1950 the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. If it had been drafted in any other way, say, instead of the word "shall" the word "is" was there, it would have meant that on that day it may be Hindi in Devanagari script but in future it might be something else. So, those who are raising this point of order do not know that they are destroying their own argument. Then, in future it would be open to anybody to change it.... (*interruptions*). They do not know what they are saying.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : बिलकुल गलत बोल रहे हैं ।

श्री य० द० शर्मा : यह बड़े खेद का विषय है कि कानून के पंडित भाषा को तोड़-मरोड़ कर इस तरह का अर्थ कर रहे हैं और उन्हें इस के लिये लज्जा आनी चाहिये.....

SHRI A. K. SEN : Those who drafted the Constitution were able lawyers.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I am speaking on the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri. The Resolution reads like this :

"जबकि संविधान के अनुच्छद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी ।"

13 HRS.

After notice of it was given, I saw some notice of amendment to the effect that for "shall" read "is". This amendment was given notice of by Shrimati Sucheta Kripalani and others. I would only request, let us not quibble on this. Shri Asoke Sen has quoted something; he wanted to prove that the word "shall" is the proper word used, though it says that the language is Hindi. Just to cut short all this, I would suggest that Shri Chavan should accept this amendment and he should move the amended motion. He should say : **भाषा हिन्दी है न कि होगी ।**

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : In continuation of what Shri Asoke Sen said, the word "shall" is a mandatory word. When you say, "Thou shall not kill", it means, you will not kill either today or tomorrow. The word "shall" is not for the future; the future is "will". "You will do this" is for the future; "You shall do this" is a mandatory word.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : I rise to support the point of order of Shri Prakash Vir Shastri. In the Constitution the word "shall" has been used. In the English language the word "shall" has a certain connotation. The word "shall" was used when the Constitution was framed and it was said that after 15 years this will come into force; therefore, the words "shall be" were put there. But now the 15 years are over and officially Hindi has become the official language of the country. Therefore when a Resolution is brought forward in 1967 the words "shall be" cannot be used; the word should be "is". We are referring to the Resolution in Hindi, not in the English language. The phraseology and connotation of a particular word in the English language do not apply to Hindi. When a Resolution is given in Hindi, the proper word should be used.

The second point that Shri Prakash Vir Shastri has raised is about the words that anyone entering the service need not have compulsory knowledge of Hindi. When Hindi is the official language, how can a man enter the service of the country without the knowledge of Hindi ? Therefore, this also is unconstitutional.

On both these counts the point of order of Shri Prakash Vir Shastri should be upheld.

SHRI A. K. SEN : The real difficulty is.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why should he speak again ?

SHRI A. K. SEN : ..... because of wrong translation of the English word "shall" in Hindi. It should have been translated as "rahegi" instead of "hogi". "Rahegi" would have been the proper translation.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस में मुझे काफी वजन नजर आता है । यह बात सही है कि प्रस्ताव में जो यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि हिन्दी भाषा होगी वह हमारे संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है । इसी प्रकार श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी वह भी हमारे संविधान की आत्मा के विरुद्ध है । लेकिन ये दोनों बातें पूरे प्रस्ताव के दो छोटे-से अंश हैं इसलिये जब हम इस प्रस्ताव पर विचार करें उस वक्त यदि श्री प्रकाशवीर शास्त्री कहें कि इनमें ये संशोधन किये जायें क्योंकि ये अंश संविधान के खिलाफ हैं तो मेरा विश्वास है कि सरकार को उन संशोधनों को स्वीकार करना

पड़ेगा और हम उनका समर्थन करेंगे । लेकिन चूंकि ये दो भाग संविधान की आत्मा के खिलाफ हैं इस आधार पर यदि यह कहा जाये कि पूरा का पूरा संकल्प जो है उस पर विचार ही न करें, और यह सदन या सदन के अधिकारों की परिधि के बाहर है तो इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं । इसलिये मैं उन से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव पर बहस को वह चलने दें ।

MR. SPEAKER : Now we are adjourning for lunch and at 2 o'clock we will begin the discussion on the Bill and the Resolution and the technicalities also.

13.05 hrs:

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION *RE.* OFFICIAL LANGUAGES—*Contd.*

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I want to raise a point of order.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY SPEAKER : All of you please resume your seats. I will permit everyone.... (*Interruptions*) Please resume your seats. Let us follow the procedure.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. I was in the House when the points of order were being raised. I am following a procedure under Rule 376 that we are following here. If I have followed correctly, the Home Minister just referred to the Bill. The Resolution was not placed before the House and before that some points of order were raised on the Resolution. (*Interruptions*).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस में लिखा है कि बिल और रेजोल्यूशन एक साथ लिये जायेंगे ।

SHRI MANOHARAN *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may please resume his seat. He is quite meticulous about procedures. He may resume his seat. Let the Home Minister move the Resolution and before he makes a speech or I say that the discussion might start, I will permit the hon. Member. Let the Home Minister first move the Resolution because, as it is, there is nothing before the House.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को बुलाने से पहले मेरा निवेदन सुन लें । मेरा काम रोको प्रस्ताव है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not fair. All the hon. members may please resume their seats. Let the Home Minister move his Resolution first.

SHRI MANOHARAN (Madras North) : I have nothing to do with the Bill..... (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : All the hon. members may please sit down. Let the Home Minister move his Resolution first...

SHRI MANOHARAN : I have nothing to do with the Bill. Please allow me to speak. . . .

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने सब से पहले पायंट आफ़ आर्डर उठाया था । आप मुझे पायंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will permit him later. Let him move the Resolution.

SHRI MANOHARAN : I have nothing to do with the Bill. I just want to draw the attention of the hon. Home Minister to this fact. I have just now received information that the Madrasi Schools in Delhi have been raided by the student population in Delhi..

AN HON. MEMBER : Bengali Schools also.

SHRI MANOHARAN : Yes, Bengali Schools also, and certain students of South Indian origin have been attacked here....

श्री मधु लिमये : बहुत बुरा हुआ ।

SHRI MANOHARAN : I can prove this.

Three days back, three MLAs from Madras came to attend a Co-operative Conference in Delhi and they wanted to go to Agra; on the way, these people were beaten down and the name-plate was removed. I am told that the next target of attack is the Members of Parliament representing South India....(*Interruption*). The Home Minister may give us protection....(*Interruption*) I cannot understand this. This is the position.

श्री मधु लिमये : पहले हम मार खायेंगे । मानीय सदस्य न घबरायें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह ग़लत बात है । किसी ने ऐसा नहीं किया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Manoharan has related certain incidents and the Home Minister will take note of them. He may now move his Motions.

SHRI NAMBIAR : I have seen the boy beaten. A boy living in my house came back beaten from the school....

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Home Minister may move his Motions.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I move :

"That the Bill to amend the Official Languages Act, 1963, be taken into consideration."

I also move the following Resolution :—

('WHEREAS under the article 343 of the Constitution Hindi shall be the official language of the Union, and under article 351 thereof it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India;

This House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi, and its progressive use for the various official purposes of the Union, and an annual report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both Houses of Parliament, and sent to all State Governments;

2. WHEREAS the Eighth Schedule to the Constitution specifies 14 major languages of India besides Hindi and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measudes should be taken for the full development of these languages;

This House resolves that a programme shall be prepared and implemented by the Government of India, in collaboration with the State Governments, for the coordinated development of all these languages, alongside Hindi so that they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge.

3. WHEREAS it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula evolved by the Government of India in consultation with the State Governments;"

"This House resolves that arrangements should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking areas, and of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi-speaking areas;

4. And, whereas, it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;

This House resolves—

(a) that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential for the satisfactory

performance of the duties of the service or post; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative native media for the All India and higher Central Services examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing."

SHRI KANWAR LAL GUPTA : On a point of order, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him conclude.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, the Bill relates. . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is making a speech, Sir.

SHRI Y. B. CHAVAN : I would certainly like to make a few observations.

SHRI KANWAR LAL GUPTA *rose*—

MR. DEPUTY SPEAKER : He is not making a major speech. He is just explaining.

SHRI KANWAR LAL GUPTA AND SHRI NATH PAI *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has resumed his seat. Mr. Gupta, I will permit you. But let us have some order while disposing points of order. No. 1, according the Rule 376, certain specific procedure is there. That must be followed while raising a point of order. I will permit one Member from each Group. If it is repetitive, then, of course, I will have to stop there; otherwise, points of order will be endless.

I will call Mr. Gupta first, and later on call Mr. Nath Pai.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, आप का धन्यवाद है.....

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga) : Has the Home Minister finished his speech ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will make his speech later on, but when he has moved the resolution, they have a right to raise a point of order.

L93LSS/67

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक देश की भाषा का सवाल है.....

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकाशवीर शास्त्री का प्वाइंट आफ आर्डर खत्म हो गया ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, this is a point of disorder.

इनको रोकिए

SHRI SHEO NARAIN : Who are you ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sheo Narain, please resume your seat.

SHRI SHEO NARAIN : Sir, I have a right to speak.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, भाषा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था विधान में की गई है वह आर्टिकिल 343 के तहत की गई है और 343 में यह लिखा है :

'The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.'

इसके आगे एक प्राविजो है जिस में लिखा है :

"Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement".

तो यह दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, उसमें यह लिखी गई है कि जब यह विधान बनेगा उसके बाद 15 साल तक अंग्रेजी भी लागू रहेगी और उसके इसके आगे एक तीसरा है : ?

"Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of the English language..... for such purposes as may be specified in the law".

इसमें यह कहा गया है कि 15 साल के बाद भी पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है जिसमें यह कहते हैं कि अंग्रेजी भी कुछ कामों के लिए रह सकती है । इसका

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मतलब यह है कि १५ साल तो बीत गए। अब उसके बाद हिन्दी के ऊपर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। आर्टिकिल में कहा गया है कि अंग्रेजी भी चाहें तो अंग्रेजी भी आ सकती है, कुछ कामों के लिए आ सकती है, यह विधान में है। और दूसरी चीज विधान में यह है कि आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा बनेगी।

उसके बाद आर्टिकिल 344 में यह कहा है कि राष्ट्रपति 5 साल के बाद एक कमीशन बनाएगा। मैं आप की आज्ञा से उसे पढ़ देना चाता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I know that. The hon. Member's point of order now can refer only to that article or section which is referred to in this resolution.

श्री कंवर लाल गप्त : आप मुझे थोड़ा टाइम दें।

आर्टिकिल 344 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पांच साल के बाद एक कमीशन बनाएगा। उसके बाद दस साल के बाद एक कमीशन बनाएगा। लेकिन एक ही कमीशन बना और इन्होंने विधान को वायलेशन किया। दूसरा कमीशन नहीं बनाया। इसके बाद कमीशन की जो रिपोर्ट आई वह यह है कि यह सदन और दूसरा सदन मिलकर एक कमेटी बनाएगा और उस की सिफारिश होगी। उसके बाद राष्ट्रपति किस प्रकार से आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी आ सकती है 15 साल के बाद या 15 साल तक वह क्या हिदायतें राष्ट्रपति देगा यह आर्टिकिल 344(6) में लिखा हुआ है।

अब इसका मतलब यह है कि विधान बनाने वालों की नीयत यह साफ थी लेटर ऐंड स्पिरिट दोनों में कि आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी आनी चाहिए। पांच साल में आये दस साल में आये। ज्यादा से ज्यादा 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी भी 15 साल के बाद कुछ कामों के लिए हो सकती है। मगर अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है और जो प्रस्ताव रखा गया है यह विधान की स्पिरिट के खिलाफ तो है ही साथ ही यह जो 344 (6) में पावर्स दी हुई हैं राष्ट्रपति को उसके ऊपर भी पाबन्दी लगाता है। मैं बताता हूं किस तरह से पाबन्दी लगाता है। पहला बिल भी जो पास हुआ 1963 में भी और इसमें भी जो प्राविजो रखा गया है आखिर में देखिए तीसरा क्लाज है :

'To sub-section 4 of section 4 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the directions so issued shall not be inconsistent with the provision of section 3".

और सेक्शन 3 में अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है कि अंग्रेजी अभी सब परपजेज के लिए होगी। सेक्शन 3 मैं पढ़े देता हूं।

"Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi :

(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament".

इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बिल मंत्री जी ने रखा है उसका कहना यह है कि कोई ऐसी डाइरेक्शन ईश्यू नहीं की जायेगी जिस से कि अंग्रेजी के ऊपर कोई पाबन्दी लगे। यह एक चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के अन्दर अंग्रेजी रख दिया। एक तो यह है कि सभी चीजों के लिए अंग्रेजी रख दिया। कुछ स्पेसिफिक परपज होना चाहिए। वह स्पेसिफिक परपज इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा कि सब चीजों के लिये है यह विधान के खिलाफ है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : His point of order is concerning the resolution and not the Bill.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am finishing in two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him clinch the issue and finish.

श्री कंवर लाल गुप्त : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह साफ तौर से कहा गया है—अंग्रेजी अगर लायी जाये कुछ कामों के लिये तो विधान के अनुसार होगा—लेकिन इस में हिन्दी के लिये पाबन्दी लगाई गई है जो 1965 के बाद इस विधान के मुताबिक हिन्दी पर किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं लग सकती और पाबन्दी इस में लगाई गई है एक राष्ट्रपति के ऊपर और दूसरी पाबन्दी लगाई गई है कि हिन्दी में अगर कोई आदमी पत्र लिखेगा तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देगा । अध्यक्ष महोदय, 1965 के बाद अगर कोई आदमी हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे यूनियन के किसी दफ्तर के साथ तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी लगाना कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ होगा और इस के अन्दर यह स्पष्ट लिखा है कि 1965 के बाद भी जो उस को अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देना पड़ेगा । तो अंग्रेजी में कोई पत्र लिखे उस पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये यह तो मैं मान सकता हूं, इस में हो सकता है । लेकिन जो हिन्दी में लिखेगा, उस पर अंग्रेजी में भी देने की पाबन्दी होगी, यह संविधान के खिलाफ़ है ।.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his point of order.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : This very point was argued that day. This is repetition.

श्री कंवरलाल गुप्त : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि रेक्रूटमेन्ट के लिये, यूनियन सर्विस के लिये हिन्दी जरूरी नहीं होगी, अंग्रेजी जरूरी होगी—यह भी विधान की स्प्रिट के खिलाफ़ बात है—हिन्दी पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी लगाना, विधान के खिलाफ़ होगा । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव और यह बिल दोनों मेरे ख्याल से संविधान के खिलाफ़ हैं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि कौन से सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं । यदि हम यह समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो सवाल माननीय शास्त्री जी ने उठाया है—उस पर तो आपने अभी कोई निर्णय नहीं दिया । श्री कंवर लाल जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसके महत्व को जानता हूं, मगर जब तक एक सवाल का फैसला नहीं हो जाता, आप उस पर अपना फैसला नहीं दे देते, तब तक दूसरा सवाल नहीं उठाया जा सकता—मेरा अनुरोध है कि आप उस को अपने ध्यान में रखने की कोशिश कीजिये ।

अब जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है जोकि शास्त्री जी ने उठाया है—मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं न उस का समर्थन करना चाहता हूं और न विरोध करना चाहता हूं, परन्तु थोड़ा-कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । मैं उसके गुण व दोषों की चर्चा करना चाहता हूं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : प्रकाश तो वे स्वयं हैं।

श्री नाथ पाई : मगर फिर भी कुछ अन्धेरा है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : कुछ अन्धेरा आप को दिखता है ।

श्री नाथ पाई : हां, इसीलिए इस पर रोशनी डालना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When a point of order has been raised, he can either support it, sponsor it or oppose it. There is no neutral position which can be adopted so far as procedure is concerned.

SHRI CHANDRA JEET YADAV (Azamgarh) : It will help the chair.

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बात आपके सामने रखी है, उस पर जैसा मेरे अन्य साथियों नें कहा है, मुझे भी कुछ मोह हो रहा है कि वे भी उस पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, मगर मैं इस मोह को टालना चाहता हूं । अब जहां तक हिन्दी का सवाल है, हमारी राय जाहिर है—इस देश में रानी की हैसियत पर सिर्फ हिन्दी रहेगी, दूसरी भाषाएं नहीं रहेंगी । अंग्रेजी रहेगी तो दासी के रूप में रहेगी, रानी के रूप में नहीं रहेगी और यह फैसला तो हो चुका है । मैं यह जानता हूं कि कई लोग रानी से दासी को ज्यादा पसन्द करते हैं · · · · · ·

श्री रामसेवक यादव : समाजवाद में दासी नहीं होती है ।

श्री नाथ पाई : हमारी पसन्दी की मोहर हमारे स्वाधीनता संग्राम के काल में ही लग गई थी । हिन्दी का आज का जो हमारे जीवन में स्थान है, वह कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है, हमारे लोगों के प्रेम और मोहब्बत के द्वारा बनाया गया है और वह नहीं भुलाया जा सकता है ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : What do you prefer ?

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी के साथ इस देश में हमारी जो अन्य भाषाएं हैं, जिनको प्रादेशिक भाषायें कहा जाता है, मगर जो प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय भाषायें हैं, ये भाषायें और हिन्दी—ये रानी के पद पर रहेगी, अंग्रेजी रहेगी तो नौकरानी के रूप में, इन भाषाओं की सेवा और खिदमत के लिये रहेगी । मुझे आशा है कि अब तो आप इससे सहमत हो जायेंगे ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : Not all India. We do not accept it.

श्री नाथ पाई : अभी शास्त्री जी ने जो बात उठाई है—चूंकि कोई गलतफहमी न हो जाय, इस लिये मैंने इस बात का जिक्र किया—उन्होंने "शल रिमेन" की तरफ़ ध्यान खींचा है । मैं बड़ी नम्रता से उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि "शल रिमेन" हिन्दी के हक में है । अंग्रेज के "शल" का अर्थ आज्ञा है, जिस का उलंघन नहीं किया जा सकता है, यह आज्ञा है, शिरोधार्य है, वाध्य है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, सदा के लिये रहेगी—यह इसका अर्थ है ।

अंग्रेजी के "शल" में जितनी सामर्थ्य है, वे कृपया इस को समझें—इस का अर्थ है, कि यह हमेशा के लिये रहेगी । मगर यह ठीक है कि हिन्दी में जो उस का अनुवाद "होगी" किया गया है, उस में उतनी ताकत नहीं है, इस लिये मेरा सुझाव है कि हिन्दी में "सदा के लिये रहेगी" होना चाहिये । मैं आप जैसा पंडित तो नहीं हूं, परन्तु मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हिन्दी में इस का अनुवाद "सदा के लिये रहेगी" होना चाहिये · · · · · · · ·

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : "सदा के लिये रहेगी" हो तो मैं उस को स्वीकार करता हूं ।

श्री नाथ पाई : यदि हम इस चीज को मान लें, तो इस व्यवस्था के सवाल पर आप कुछ निर्णय ले सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे विचार प्रकट करने के लिये मौका दिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : A point of order was originally raised by Shri Prakash Vir Shastri. That is in my mind, it has not been disposed of, but some members were on their legs already when we adjourned.

Shri Nath Pai has tried to interpret "shall". I will keep that in mind, but I may submit to the House that ultimately, whether it is right or wrong I am stating a fact, the Constitution of this land is in English, and we will have to interpret it as it is in English. Unfortunately it is so, but it is there. I have to interpret that Constitution which is accepted by the Constituent Assembly and finally accepted by the people.

I have followed what Mr. Nath Pai has tried to explain in very lucid Hindi.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : My point of order is that these two things cannot be discussed together. There is the Bill and there is a resolution. The Bill has got its amendments, and the Bill has to be discussed as per the procedure laid down by the Speaker under rule 75, which says :

> (1) On the day on which any motion referred to in rule 74 is made.. the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.
>
> (2) At this stage no amendments to the Bill may be moved."

With regard to the resolution, the procedure is quite different. It is governed by rule 173. On the question whether this resolution is in order, constitutional or unconstitutional, I am prepared to agree with my Hindi propagandists.... (*Interruptions*). —they are propagandists—that this resolution is out of order. My point is that this resolution is out of order not only because of the objection raised by Shri Prakash Vir Shastri, because rule 173 says :

> "In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely :—
>
> (i) it shall be clearly and precisely expressed;
>
> (ii) it shall raise substantially one definite issue;
>
> (iii) it shall not contain arguments, inferences...."

But this resolution contains four parts. The first part speaks about the propagation of Hindi, the second part about the development of the 14 languages, the third part about the three language formula and the fourth part about examinations to be held by UPSC. These are four different subjects and there are arguments also in the resolution. For instance, in the first part, the argument is this :

> "WHEREAS under article 343 of the Constitution Hindi shall be the official language of the Unionand under article 351 thereof it is the duty of the Union.".

"The House, therefore, resolves." It first gives the argument and then gives the resolution. It goes on repeating in all the four items. Therefore, even under rule 173 the resolution is not admissible. Granting that, for argument's sake, you are pleased to admit the resolution, even then it cannot be discussed along with the Bill, because rule 177 says clearly that after a resolution has been moved, any Member may, "subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to the resolution." There are amendments to the resolution. Any number of amendments are there. There are amendments to the Bill. And there are motions to refer the Bill to a Select Committee. So many things are there.

Now, what happens ? If you allow the Bill to be moved today—as it is being moved—and when the amendments are there, and along with it, the resolution is also moved for which also there are many amendments, what are we to discuss and how can we discuss both ? Under rule 75, the preliminary discussion of a Bill can only be on general terms and not beyond that. Now, if the resolution is also discussed along with the Bill, the resolution is such a big one comprising so many facts—those who discuss the Bill will refer to this point also which is against rule 75. Therefore, these two things cannot go together. I do not find anywhere whether this was the practice. I searched and searched and found nothing to substantiate this procedure, that the Bill and the resolution could go together. I can only request you to see that the Bill be discussed first and the resolution be discussed next; if the resolution is admissible, it may be taken up. If it is not admissible, you can amend or change or do whatever you can. I am not going into the merit of the question at issue, the language question. Though my friends have done it, I am not going into that. I shall reserve my right to discuss it when the question comes up.

Therefore, I say that these two things cannot be discussed together. Kindly dislodge the resolution from the Bill and let the Bill be taken up and discussed as it is introduced. That is my humble submission.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हाउस लंच के लिए उठ रहा था तो मैं खड़ा हो रहा था इसलिए मेरी बात आप सुन लिजीये ।

[श्री शिव नारायण]

केवल एक लफ्ज का झगड़ा है। कांस्टीट्यूशन में 26 जनवरी सन् 1950 को लिखा गया :

"The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script."

मानें कि हमेशा रहेगी, शाश्वत तक रहेगी लेकिन यह जो शब्द "होगी" है इस से संदेह उत्पन्न होता है और मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि यह शब्द "होगी" एक संदेहात्मक शब्द है और उस से एक संशय पैदा होता है। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आप के महकमे में आप के डिपार्टमेंट के लोगों में कितनी बड़ी काबिलियत है कि यह शब्द "होगी" रख कर सब को धोखे और डार्कनैस में रखना चाहते हैं। यह शब्द "होगी" ग़लत है, संदेहात्मक है और होगी के बजाय शब्द "रहेगा, रहेगी" रखना चाहिये जो कि शाश्वत शब्द हैं। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूं और साथ ही सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन का ट्रान्सलेशन डिपार्टमैंट कितना निकमा है और इस तरह का "होगी" शब्द रख कर वह सब को धोखा देते हैं और लोगों को डार्कनैस में रखते हैं इसलिये मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूं कि यह शब्द "होगी" को वह वापस ले लें और शब्द "रही है और रहेगी" रक्खा जाये।

SHRI AMIYANATH BOSE (Arambagh) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, under rule 173 of the Rules of Procedure, it is stated that for a resolution to be admissible, one of the conditions to be fulfilled is that "it shall be clearly and precisely expressed." If you come to the operative part of the resolution, you will find that this is how it reads. I am reading clause 4(a) of the resolution :

> "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts...."

Up to this, it is clear and it is precisely expressed. Let me proceed further.

> "excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential"—by whom ?—"for the satisfactory performance of the duties of the service or post."

I submit that in the way it has been framed, it is so ambiguous. Firstly, there is no definition anywhere in the resolution as to what "special services" or "special posts" are. There is no definition as to who should be satisfied that special knowledge of Hindi is required for a particular service or post. Therefore, this is not an admissible resolution.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians) : So far as the consideration stage—general discussion—is concerned it may be permissible to join the discussion of the resolution with the amending Bill. But I am quite clear very respectfully in my own mind that there is no possible way of joining the discussion on the amendments of the resolution with the discussion on the amendments to the Bill. You will have to separate the two.

एक माननीय सदस्य : इन की राय की कोई क़ीमत नहीं है.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are not following what he says.

SHRI FRANK ANTHONY : That is the trouble.

एक माननीय सदस्य : उन को ही पता नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं।

SHRI FRANK ANTHONY : So far as the resolution is concerned, one particular part of it to my mind is *ex-facie* unconstitutional, *i.e.*, the part dealing with the proposal to implement the three language formula. I will read it :

> "Whereas it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula ...." etc.

Secondary and higher secondary education is a State subject. You cannot purport to arrogate to yourself the power to tell any State whether it should have a two or three-language formula *ex-facie* it is beyond the jurisdiction of this House to come to any purported decision on the three-

language formula with regard to secondary and higher secondary stage. That part of the resolution would be *ex-facie* untenable and outside the jurisdiction of the House.

SHRI NATH PAI : How many points of order are we considering, Sir ? There is first Mr. Prakash Vir Shastri's point of order which is undisposed of. Then there is Mr. K. L. Gupta's point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I suggest is, first let us dispose of Mr. Shastri's and Mr. Gupta's points of order, because they are more or less similar.

SHRI NATH PAI : The point raised by Shri Anandan Nambiar is *prima facie* a substantial one. That brings us into the problem of procedure to be followed. Today's agenda says that both the Bill and their resolution are to be discussed together. That is perhaps a practical arrangement because the arguments are likely to be repetitive and overlapping, the substance of the resolution and of the Bill more or less converging on the same subject. But the point of order raised by Mr. Nambiar, which draws attention to the rules of procedure here as to how a Bill is to be disposed of and how a resolution is to be disposed of, is a meaningful point. But before we dispose of that, I would like to know what is your guidance and ruling regarding the limited point first raised by Mr. Prakash Vir Shastri. We are getting into a mess.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has partially supported Shri Nambiar, in the first part of his observations, and in the second part he has raised a new point of order.

SHRI NATH PAI : Sir, I have unlimited regard for your ability to grasp so many points at a time, but mine is a limited one and I am getting confused. Will you help me, Sir, by just disposing of one point at a time ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you for this compliment. When I permitted several hon. Members here, on this side and that side, I felt they were either supporting or disapproving the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri. I fully realise that there are now three distinct points of order. I do not think the point raised by Shri Shastri and the point raised by Shri Gupta are two distinct ones. There was a second point of order raised by Shri Nambiar and the third one was raised by Shri Frank Anthony. I want to dispose them of one by one. Let us take the first one, the point raised by Shri Shastri and Shri Gupta. I will now allow only those who want to speak on this point. Does Shri Vikramchand Mahajan want to say something on this point ?

SHRI VIKRAMCHAND MAHAJAN (Chamba) : Yes, Sir, a point of order has been raised that the Bill and the Resolution cannot be discussed together. My submission is that they can be discussed together.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not on that point now. Shri Prakash Vir Shastri has raised a point of order concerning some sort of contradiction between the article of the Constitution and the Resolution. The hon. Member may confine his remarks to that.

SHRI VIKRAMCHAND MAHAJAN : Sir, my point of order is that the Bill and the resolution can be discussed together.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his seat. That is not the question before us. I have said specifically that I want to dispose of the first point of order about contradiction between the Constitution and the Resolution.

श्री मधु लिमये : मेरी प्रार्थना है कि एक-एक करके आप खत्म करें । इनकी और शास्त्री जी की आपत्ति वैधानिक है । उसका पहले फैसला हो । बाद में प्रक्रिया के बारे में हो ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall call him later on.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : 'Later on' means when ? Last time twice I got up but I was not permitted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will get his opportunity. I cannot say when. After some time I will call him.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे आप क्षमा करें अगर मैं यह कहूं कि जो शोर मचाता है उसको सुना जाता है । मैं कभी शोर नहीं

मचाता हूं । मैं खड़ा हो रहा हूं और आप देखते ही नहीं हैं .....

MR. DEPUTY-SPEAKER : From your group also *shor machathe hain.* He is not one of them. I am now disposing of the first one. I put him a specific question whether he is supporting or elaborating the point of order raised by Shri Shastri and Shri Gupta.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आप मुझे आश्वासन दें कि दोनों के बाद आप मुझे समय देंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am now confining to the first point of order wherein it was pleaded that some portions of the resolution contravenes some article of the Constitution.

SHRI MANOHARAN : Please give your ruling and dispose it of.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri in substance means that only because this part of the Resolution says that, in its Hindi translation "*hogi*" therefore it contravenes the very article of the Constitution. I entirely agree with Shri A. K. Sen and Shri Nath Pai as far as the English part of it is concerned, because 'shall be' really speaking means a continuous process. It is a thing which will stay there permanently, that is the connotation of the word. A difficulty was raised about translation. I have no objection in accepting the amendment. But I would like to make one point clear. Some people did say that it was a careless translation. I may say for the information of the House that if they see the Hindi translation of the Constitution itself, which was done under the Resolution of the Constituent Assembly under the Chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, there article 343 is translated in Hindi as :

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।

श्री नाथपाई : होगी के बजाय रहेगी ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not opposing the suggestion that is made here. The point I am making out here is that when this translation in Hindi of this Resolution was made, it was not carelessly made; it was based on something. Now, if you think that some of the Hindi words in the original translation are imprecise and that now in Hindi the precise connotation will have to be used..... (*interruptions*) So, I am prepared to accept the suggestion made by hon. friend.

होगी के बजाय रहेगी, सदा के लिये रहेगी ।

I have no objection for that. Therefore, my main point is that the point of order that the Resolution is against the Constitution is not valid. That is the first thing. Secondly, some hon. Members raised the point whether the two resolutions can be discussed together etc.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That we will take up later. One point he raised in continuation of the point on translation was that the Resolution contravenes some section of the Bill.

SHRI Y. B. CHAVAN : About the Bill itself. I would say that the same point of order was raised by the hon. Member, Shri Limaye, when the Bill was being introduced. That point was discussed at that stage and I think a ruling came from you that it is not a valid point of order. Because, really speaking, the Constitution says that it should be specifically indicated as to for what purposes English should be used. Here we have specifically stated for what all purposes it would be used. So, it satisfies the provisions of the Constitution.

श्री कंवरलाल गुप्त : आप हिन्दी पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पूर्व इसके कि आप व्यवस्था दें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । गृह मंत्री जी ने कहा और श्री नाथ पाई ने भी कहा कि शब्द अगर हिन्दी में इस प्रकार रहें कि सदा रहेगी तो मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं होगी । उसका अनुवाद इस प्रकार का कर लिया जाये । दूसरी आपत्ति यह थी कि शायद व्यवस्था देने के पहले आप भूल रहे हैं और गृह मंत्री जी भी शायद उस बात को भूल गए कि हिन्दी प्रमुख भाषा होने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में जो आपने कहा है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी, क्या यह संविधान की

भावनाओं के विपरीत नहीं है ? आपको व्यवस्था इन दोनों प्रश्न पर देनी है और गृह मंत्री को भी स्पष्टीकरण इन दोनों पर देना है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Certainly, I will answer it. I thought only one point of order should be answered.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I said only one procedure.

SHRI Y. B. CHAVAN : What is proposed to be done in that stage is, really speaking, a matter of procedure. At what stage Hindi should be compulsory ? The very purpose of the Bill and the Resolution is to facilitate the growth of Hindi and acceptance of Hindi by non-Hindi people. Really speaking, that is the basic concept of it. What is done is, they will have to learn Hindi, even after they are recruited, within a year or so; they will have to take some Hindi examination. Really speaking, we are facilitating them to appear for the examination. It is only at that stage that Hindi is not made compulsory. It is absolutely a procedural matter for the holding of the examination. There is no restriction.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप इसको यों कर लें कि यदि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी तो अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं होगी । अगर यों कर लें तो भी कुछ समाधान हो सकता है । हिन्दी प्रमुख राज भाषा बन चुकी है, वह तो अनिवार्य नहीं होगी और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी अनिवार्य होगी ?

SHRI Y. B. CHAVAN : No, I can assure the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that this question of accepting amendments to the Resolution will certainly be examined and considered when we reach that stage. I am not opposing that at this stage. But his fundamental point was that it is against the Constitution and, therefore, it is out of order. I am opposing only that part.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad) : The language fanatics have said that Hindi is a primitive language. What right have they to say that ? Every Indian language is a national language and no language is primitive. This anglophile wants to say that Hindi is a primitive language. He is primitive.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : I will say it. It is a primitive language. It has no capacity.....(*Interruption*).

श्री मधु लिमये : यह गुलाम मनोवृत्ति के आदमी हैं । गुलाम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : श्री सिन्हा ने इन को अंग्रेजी में "प्रिमिटिव" कहा है, इस लिए इन को बुरा नहीं मानना चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : While hon. Members are within their rights to say anything about a particular clause of the Bill or the Resolution, they should not use language regarding other, sister languages, because all are national languages, which is derogatory.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसी ने भी मलयालम या तामिल या बंगला के बारे में नहीं कहा है । यह गुलामों की मनोवृत्ति व्यक्त कर रहे हैं ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : I come from Dravidian stock.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको क्यों रोक रहे हैं ? वह गुलाम है और वह इस बात को दिखा रहे हैं । किसी ने भी मलयालम या तामिल के बारे में नहीं कहा है । वह गुलाम मनोवृत्ति के आदमी हैं । आप उनको छोड़ दीजिये ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : He is talking rot.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Derogatory language should not be used. He has used it. I am warning him.

So far as the point of order raised by Shri Shastri is concerned, I made a casual observation. I will have to make it very clear. Shri Nath Pai has made it clear, that is, regarding the translation part of it. As I said, the law of the land or the Constitution is in English today and though it was translated then it is not an authoritative translation. As the Home Minister has said, if there is any objection so far as the translation is concerned, it is for the Home Minister to see how to accommodate your point of view while placing that particular

[Mr. Deputy Speaker]

clause before the House. Therefore, there is nothing left so far as your point of order is concerned.

So far as Shri Gupta's point of order is concerned, when the Bill was first introduced a ruling was given at that stage. But he has made an additional point there, that it contravenes the spirit. I have gone through the Bill and the Resolution. He read out certain sections. I do not want to repeat them. I may tell him very plainly that it must be admitted that if at all it is something for which the whole House has to take the responsibility. When the Resolution says, "shall"—if you read all the sections—there is a certain obligatory responsibility taken by the Government to implement it. You referred to 15 years and all that. The House was perhaps not vigilant. You cannot blame the Government. We were here or your predecessors were there. So, if it is not implemented, certainly language is a thing where "Let there be light and lo and behold there was light" that sort of a miracle does not happen. His Resolution is a determination to give effect to this. Therefore I feel that your point of order also is not valid. You are pointing out a failure. If there is a failure, it is of all of us. Therefore it is not valid.

So far as the procedure is concerned, Shri Nambiar has raised a point of order.

SHRI NAMBIAR : I have raised two specific points. One is that the Resolution is out of order and the other is that these two things cannot be discussed together.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : On a point of clarification. In the course of your ruling you have said that there is no authoritative version of the Constitution in Hindi. I want to know from you whether after 17 years of having our Constitution there is any authoritative version or Hindi translation of our Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So far as I know, there is a translation which is an approved one but not, in that sense, authoritative that can be quoted. That is not there, so far as I know.

SHRI SAMAR GUHA : But here are the people who want to throw out English when even after 17 years, they could not have an authoritative version of the Constitution in Hindi. ....(*Interruptions*).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह के शब्द कह कर बड़ी ग़लतफ़हमी पैदा कर रहे हैं। आपको शायद स्मरण हो कि इसी संविधान में भाषा के सम्बन्ध में जो अनुच्छेद है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1947 से पहले जिन कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था, उनमें 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। 1947 से पहले स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था, इस लिये 1947 के बाद यह संविधान बनाया गया और उसका जो हिन्दी अनुवाद किया गया, वह अधिकृत अनुवाद है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिन्दी अनुवाद पर ही अपने हस्ताक्षर किये थे। उसकी प्रामाणिकता के बारे में सन्देह पैदा करके आप देश को ग़लतफ़हमी में न डालें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He asked, in terms of law, can it be contended that it is an authoritative translation ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यह विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है।

श्री रामगोपाल शालवाले (चांदनी चौक) : आप इन शब्दों को वापस लीजिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the hon. Home Minister clarify the position.

SHRI Y. B. CHAVAN : For me, it is very clear that the translation was done by the resolution of the Constituent Assembly—the President was the Chairman of the Committee—and, I think, it is an authorised version.

श्री ओ० प्र० त्यागी (मुरादाबाद) : आप ने कहा है कि हिन्दी का वर्शन अधिकृत नहीं है। उस का क्या हुआ ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, so far as the point of order raised by Mr. Nambiar is concerned....(*Interruptions*)

SHRI SAMAR GUHA : On a point of information. Is it not a fact that there have been six Hindi translations of our Constitution but none of the Hindi versions has been accepted as an authoritative one ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Home Minister has clarified the position and the House has accepted it. There is no question of that.... (*Interruptions*) Whatever the hon. Home Minister has said regarding the Hindi version stands and it is accepted by the House.

SHRI HIREN MUKERJEE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, I am on Mr. Nambiar's point of order.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli) : May I know whether the Hindi version of the Constitution has been signed by all the Members of the Constituent Assembly ?

SHRI HIREN MUKHERJEE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not the question. Shri Mukerjee.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जोशी, कितनी देर से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप ने उनको अवसर न दे कर श्री मुकर्जी को बुला लिया है । आप यह क्या कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has something to say on the statement of the Home Minister. Therefore, I have called Shri Mukherjee.

SHRI J. H. PATEL (Shimoga) : *spoke a few words in Kannada* (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : What the Home Minister has stated has been accepted by the House and that stands.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : You are pleased to say earlier that the only authoritative text of the Constitution in the sense that it can be interpreted by the Supreme Court or by any High Court in this country is the Constitution, rightly or wrongly, happily or unhappily, as it is formulated in English.

DR. GOVIND DAS : No.

SHRI H. N. MUKERJEE : You were pleased to say that we do have a translation in Hindi of the Constitution, but for purposes of judicial interpretation of the articles of the Constitution, what is acceptable to the court is the English version, rightly or wrongly, happily or unhappily.. (*Interruption*) That is a different problem. Now you have also been pleased to observe, after the Home Minister's intervention, that this is an authoritative statement. I do not understand this. An authoritative text of the Hindi translation, if it is really authoritative, cannot be altered with impunity, as the Home Minister suggested that it could be, by the words "Sadha ke liye rahegi" instead of "Hogi". It was an authoritative text, it could not be altered authoritatively by a pronouncement *ex-cathedra* of the Home Minister.

Therefore, quite apart from the merits of the matter, it may be a matter of shame for us that we have to have our Constitution in the English language, but the fact of the matter is that the law of the country being as it is, the only text of the Constitution which is authoritatively acceptable to the judicial authorities for interpretation is unfortunately the English text. Since changes in the Hindi translation are suggested perhaps very intelligently by Mr. Prakash Vir Shastri and accepted with alacrity by Mr. Chavan, since changes in the authoritative text can be accepted and offered just like that, it cannot be the authoritative text. Therefore, as far as the authoritative text is concerned, let us not forget the law of the land; rightly or wrongly, the only text is the English one.

15.00 Hrs.

SHRI NATH PAI : I first want to know what is the point that we are discussing....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Mukerjee has raised a point of objection.

श्री नाथ पाई : मैं आपकी इजाजत चाहता हूं । यह आप का प्रथम कर्त्तव्य है,

It is your duty first to bring the point of order and then allow. I think, you once disposed it of when the question was raised होगी या रहेगी, यह तो काम खत्म हो गया । इसके बाद सवाल आया कि जो हिन्दी अनुवाद है वह प्रमाणित है या नहीं, इस पर

[श्री नाथ पाई]

यह कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वह पहले अंग्रेजी भाषा में आया, फिर उसका जो अनुवाद उपलब्ध है वह प्रमाणित है, यह हमारा दावा है। यह बात बदली नहीं जा सकती ।.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said that it stands. The only thing that he has raised is a point of objection. He has already explained it.... (*Interruptions*)

SHRI NATH PAI : First I want to know a very simple thing from you, Sir. What is the question before the House now ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nambiar's point of order.

SHRI NATH PAI : It is you who are drifting from the point of order. There were three different points of order and you tried to give a ruling on the first point about the word 'shall'; instead of 'Hogi', I had suggested 'Rahegi' and the Home Minister agreed. I thought that that particular part ended there. Now we have come to another point raised by Mr. Mukerjee about the authenticity of the translation and your *ex-cathedra* remark. It is true that our Constitution was drafted in English. But where is the corollary to it, that the Hindi translation is an authoritative translation ? Now let us not get confused. The Constitution as adopted was in English. (*Interruption*)

SHRI MANOHARAN : That is not authoritative.

SHRI NATH PAI : You do not understand, Mr. Manoharan. Under the Constitution . . .

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, I may clarify...

SHRI NATH PAI : Are you improving or confusing ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सवाल यह है कि बात दूसरी तरफ क्यों जा रही है ? इस वक्त यह बहस कांस्टीट्यूशन पर तो है नहीं । जो भी कांस्टीट्यूशन की बात उठी थी वह अब खत्म हो गई । कांस्टीट्यूशन को कोई बदल नहीं रहा है चाहे जिस भाषा में भी है । इसलिए उस पर अब बहस करने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी में है या हिन्दी में है..... (**व्यवधान**)..... यही मैं कह रही हूं। माननीय सदस्यों से मैं विनती करती हूं कि अब इस बात को छोड़ दें। अब हम अगली बात जो कुछ भी है उस पर चलें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When he explained the position, I have accepted it. Mr. Nambiar.

SHRI J. B. KRIPALANI—*rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nambiar.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : As a person who was present all the time when the Constitution was being made, I can say that after we framed the Constitution in English, we said that an authoritative translation of it must be produced and it was produced. Now to say that it was not an authoritative version of the Constitution is altogether wrong. It is authoritative.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is accepted.

डा० गोविन्द दास : उपाध्यक्ष जी, मैं स्वयं संविधान सभा का एक सदस्य था । यह प्रश्न जब एक दफा हमारे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया तो फिर हीरेन्द्र मुखर्जी साहब को उठाने की क्या आवश्यकता थी। राजेन्द्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे और हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे उन्होंने यही कहा था । जो हिन्दी का हमारा संविधान है वह ऐसे ही मुकम्मिल है जैसे अंग्रेजी का है । इस मामले को अब समाप्त करें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have accepted that. (*Interruptions*)

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : You have said by way of your ruling that the Hindi version of the Constitution is not an authoritative version.

SHRI J. H. PATEL *spoke in Kannada.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot follow your language. (*Interruptions*)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR *spoke in Malayalam.*

SHRI J. H. PATEL—*rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Either you speak in Hindi or English.

श्री मधु लिमये : हम उसका अनुवाद करेंगे । ..... (**व्यवधान**) .....

SHRI RAM SEWAK YADAV, SHRI RABI RAY AND SHRI J. H. PATEL—*rose*

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय अनुवाद हो जायेगा । इनको अपनी मातृभाषा में बोलने का हक है । जार्ज फर्नेन्डीज उसका अनुवाद कर देंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Last time I have permitted.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह तय हो चुका है कि हर एक को यहां अपनी भाषा में बोलने की आजादी होनी चाहिये ।

SHRI J. H. PATEL *spoke in Kannada.*

SHRI N. SREEKANTAN NAIR *spoke in Malayalam.* (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Can you follow him and communicate to me what he says ? Do you realise how much time will it take ?

श्री मधु लिमये : उसका अनुवाद हो जाएगा ···· (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER : On procedural matters that was never permitted, only speeches I have permitted.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न का अनुवाद हुआ है इसी सदन में । जब अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर थे तो पूरक प्रश्न का अनुवाद हुआ है और उसका उत्तर दिया गया है ।

SHRI J. H. PATEL :* Though our Constitution has given us equality of status and opportunity as well as libert 'yof thought and expression, I now find that in the Lok Sabha itself, we do not have the freedom of speech and thought. I would like to speak on a point of order relating to the Official Languages (Amendment) Bill. The Constitution provides Hindi as our official language. English was to continue for a period of 15 years *i.e.* till 1965. The enactment of Official Languages Act in 1963 was a method of perpetuate the use of English as an official language on one pretext or the other, not only in Delhi but in all the States. The present Bill is another device to continue English as official language. This is against the provisions of the Constitution.

My next point is regarding the resolution accompanying the Bill. Introduction of the resolution on the same topic as that of the Bill simultaneously is against the provisions of rules. The resolution should be withdrawn. Only the Bill should be discussed in the House after preliminary consultation with the leaders of all the opposition parties of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot translate it; let some Member translate it for me.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, पटेल साहब यह कह रहे हैं कि हमें हमारी भाषा बोलनें की आजादी है, उस आजादी को आप हमें बोलनें की इजाजत न दे कर छीन रहे हैं, यह अधिकार हमें सविधान ने दिया है ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I had called Shri Madhu Limaye. I had not called Shri J. H. Patel at all but he got up in between. I am not going to follow the procedure that Shri George Fernandes has suggested. I have called only Shri Madhu Limaye. (*Interruptions*).

Now, I shall give my ruling on the point of order raised by Shri Nambiar. Rule 174 reads thus :

> The Speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules . . .

So, so far as the admissibility question is concerned, the Speaker has admitted both the things, the discussion on the Bill and also the discussion on the resolution. As some hon. Member pointed out rightly, to save time, a common discussion has been permitted. But in order to facilitate the debate and to have a full-throated debate,

*Tanslation of the speech delivered in Kannada.

[Mr. Deputy-Speaker]

the question of amendment was raised. After the general discussion, the amendments can be moved.

SHRI HEM BARUA: What is full-throated discussion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I said so because Members wanted to waste time by raising points of order etc.

So, so far as the point of order raised by Shri Nambiar is concerned, I have overruled it. We shall carry on the debate now.

SHRI J. H. PATEL *spoke a few words in Kannada.*

SHRI AMIYANATH BOSE: On a point of order.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let not these things be taken down. Now, let the Home Minister speak. (*Interruptions*)**

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, वह अनुवाद करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I must tell Shri Madhu Limaye that this is a matter on which certain light must be thrown. I cannot follow Shri J. H. Patel.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, अनुवाद आप नहीं करेंगे, वह उसका अनुवाद करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव: उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था दी जा चुकी है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I had neither called him nor permitted him. He may write to me.

SHRI Y. B. CHAVAN: This Bill relates to a subject which tends to arouse passions and about which there have been misapprehensions in the past.... (*Interruptions*) Language is a subject which touches the feelings and sentiments of people, and this is not so only in India.... (*Interruptions*). It is, therefore, all the more necessary that we in this august House to which the whole country looks up, consider the matter coolly and dispassionately, take a long view of things and enact a legislation which would promote harmony and understanding among people and strengthen the unity of the country.

The framers of our Constitution recognised the needs of our multilingual society in which while the States must have the freedom to use for their purposes their own respective languages, there should be a language for the Union which is widely used and which can serve also as a channel of communication between the Union and the States and between one State and another with different official languages. This recognition is reflected in the relevant provisions of our Constitution. Under article 345 it is for the State Legislature to adopt one or more of the language in use in the State or Hindi to be used for all or any of the purposes of the State. Hindi has been made by the Constitution itself as the official language of the Union. There is no conflict between Hindi and our other major languages. They must develop side by side, enriching one another in the process, providing opportunity to all our people for fullest cultural development and self-expression, and in the field of governmental administration to serve their purposes in their respective spheres.

श्री जार्ज फरनेंडीज : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may write to me; he may translate it and write to me, and I shall consider it. (*Interruptions*)

SHRI Y. B. CHAVAN: While making Hindi the official language of the Union, our Constitution-makers recognised that the period of 15 years provided for the continued use of English for the official purposes of the Union might not be sufficient for dispensing with English language, and they, therefore, empowered Parliament to provide by law for the use of English beyond that period. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let Shri Patel write to me.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : ऐसा कैसे हो सकता है, वह लिख कर कैसे देंगे । उनको पहले से क्या पता कि कौन सा मसला यहां पर आने वाला है ।

श्री मधु लिमये : आप उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनियें, उसका अनुवाद होगा, तब आप उसका फैसला दीजियें और तब आप बढ़ियें ।

**Not recorded.

SHRI Y. B. CHAVAN : The Official Language Commission, and later on the Committee of Parliament on Official Language, which went into the recommendations made by the Commission, recommended, with virtual unanimity, that the use of English should be continued beyond 26 January, 1965 (*Interruptions*).

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : On a point of order. We cannot hear anything of what the Minister is reading (*Interruptions*).

SHRI NATH PAI : Don't we have orderly proceedings ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The Official Languages Act passed by Parliament in 1963 gave effect to those recommendations.

It was hoped that with English having been given the status of an associate official language of the Union without any time-limit, the non-Hindi-speaking people would have no apprehensions that they would have any difficulties or handicaps (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not permitted Shri Patel to raise his point of order. I do not follow him. Let him write to me.

श्री मधु लिमये : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, एक मिनट में उनका प्वाइंट आफ़ आर्डर हो जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने आपके सामने एक मोशन रखा है, आपको वह मोशन लेना होगा ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Subsequent events, however, showed that their apprehensions had continued and that there were misgivings, which for the happiness of people in all parts of the country, and in the national interest, must be removed. Pandit Jawaharlal Nehru had given assurances in Parliament to the non-Hindi-speaking people that English would continue as an associate official language of the Union till those people themselves agreed to a change. These assurances were repeated by Shri Lal Bahadur Shastri early in 1965. The present Bill was accordingly drafted. It represents a broad national consensus. Every provision of the Bill may not satisfy everyone. But it does represent a workable scheme in which, to the utmost extent possible, different points of view have been sought to be harmonised. The essence of this legislation is bilingualism in the conduct of the affairs of the Union (*Interruptions*).

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : The Deputy Speaker is saying something. The Minister is reading something else. He has ignored even you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Will the hon. Minister yield for a moment. Shri Nath Pai wants to raise a point.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not yielding.... (*Interruptions*).

We are anxious that Hindi should spread and more and more of the employees of the Central Government should acquire proficiency in that language and use it for official work (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मैं नियम सं० 340 के अन्दर स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता हूं, आप मुझे उसकी अनुमति दीजिये । मैं नियम 340 के अन्तर्गत किसी भी समय यह प्रस्ताव रख सकता हूं, इस लिये मैं प्रक्रिया के अनुसार बोल रहा हूं, आप मुझे अनुमति दीजिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि बैठक की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाये । मैं इस सम्बन्ध में आपको मोशन लिख कर दे चुका हूं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : But I would appeal for patience. Any impatience in this matter would revive the fears and suspicions which we wish to allay through this legislation. Any step which is likely to create difficulties for those who do not know Hindi, or even a demand that such a step should be taken, would be unwise and do harm. Goodwill and co-operation of the non-Hindi speaking people are necessary for Hindi coming into its own as the official language of the Union, and as a link language. It should be remembered that not only in the offices of the Central Government but for the continued smooth functioning of our higher judiciary, and of the All India Services, as unifying factors

[Shri Y. B. Chavan]

a long period of bilingualism is necessary (*Interruptions*).

(*Shri Vajpayee and some other hon. Members left the House*).

A link language is meant for uniting the country, not dividing it. We have kept this in mind while preparing this Bill. I would like my friends from the Hindi-speaking areas to remember that those whose mother-tongue is not Hindi have to make special efforts to learnt that language, acquire proficiency in it for official purposes. Some sacrifice on their part is involved, and we must take their difficulties and susceptibilities into account. We must carry them along with us. To the people from non-Hindi speaking areas, I would say that we have taken their views and problems fully into consideration while evolving this legislation. It represents a consensus, and it seeks to synthesise as far as possible different views, and to accommodate various interests. It is in the nature of a compromise, and every compromise is exposed to criticism from both sides. And yet compromise and mutual accommodation are the essence of the democratic way of functioning.

With these words, I appeal to all sections of the House to give their support to the Bill (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : The motion and the Resolution are now before the House.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 340 के तहत इस वक्त इस कार्यवाही को स्थगित रखने का प्रस्ताव कर रहा हूं । नियम 340 इस प्रकार है :

"At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned."

इस वक्त हमारे सामने दो चीजों पर बहस हो रही है । एक तो यह कि विधेयक पर विचार किया जाये । एक प्रस्ताव तो यह हुआ । दूसरे इनके द्वारा जो तजवीज रक्खी गई है, जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसके ऊपर विचार किया जाये इसके ऊपर भी बहस चल रही है । इसलिये नियम 340 और 109 में जहां तक विधेयक का सवाल है वह मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं .....

एक माननीय सदस्य : 341 भी पढ़ दीजिये ।

श्री मधु लिमये : हां, हां सब पढ़ूंगा आप घबड़ाइए नहीं । 109 इस प्रकार है :

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may me moved with the consent of the Speaker."

इसमें आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी लेकिन मेरे दो प्रस्ताव हैं । इस संकल्प पर रेजोलूशन पर जो बहस चल रही है उसको भी मैं स्थगित करना चाहता हूं और जो विधेयक पर बहस चल रही है उसको भी मैं मुल्तवी करना चाहता हूं । विधेयक के लिये आपकी अनुमति की जरूरत है लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है रेजोलूशन का सवाल है उसमें आपकी अनुमति का सवाल नहीं है और उस पर सदन फैसला कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव क्यों रक्खा है उसके बार में मैं दो मिनट में खत्म करूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रस्ताव को और इस विधेयक को लेकर काफ़ी गर्मी इस सदन में और बाहर पैदा हुई है इसलिये इन से मेरी प्रार्थना है कि इन्होंने जो इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रक्खा है उसको स्थगित कर उसकी जगह पर इस विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया जाये । अगर उसमें भेजने का यह प्रस्ताव करते हैं तो मेरा खयाल है कि कोई रास्ता निकल सकता है ऐसा रास्ता कि जिससे गैर हिन्दी इलाक़ों पर हिन्दी लादी न जाये और हिन्दी को स्वीकार करने वाले इलाक़ों पर अंग्रेजी न लादी जाये । इसके आधार पर, मेरा खयाल है, रास्ता निकल सकता है । लेकिन अगर मेरे इस प्रस्ताव को यह ठुकरा

देंगे तो देश को आग लगाने का काम गृह-मंत्री जी कर रहे हैं यह आरोप मैं कर सकूंगा। आज मैं समझौते के लिये एक रास्ता खोल रहा हूं इसलिये यह स्थगन प्रस्ताव मैं ला रहा हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : On this I am not permitting anyone. He has moved, but before that, according to the rules, Mr. Vajpayee approached me and gave in writing that I should adjourn the House. I said I would consider it, I did not immediately give any reply.

So far as rule 340 is concerned, there are two aspects. If you want to make a motion that the Bill be referred to a Joint Committee, you have every right. That is a different motion altogether.

Then, there is rule 341 :

"If the Speaker is of opinion....

SHRI S. A. DANGE (Bombay Central South) : What I want to propose, without reference to the rules, is this. You know in what state we are now. We are almost atomised into linguistic, sub-linguistic groups. The reflection outside also is there now. In fact, all party divisions are finished, all loyalties of this kind or that kind are overcome, by this linguistic question. So, I would propose to the Government and to all the parties, whether we could not adjourn for sometime and see if a common solution can be found. (*Interruptions*)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : We also represent the country.

SHRI S. A. DANGE : Nobody.... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order.

SHRI S. A. DANGE : The point that I am making is, nobody.... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have permitted Shri Dange to speak.

SHRI S. A. DANGE : Nobody wants to suppress Hindi; nobody wants to suppress any language. I only suggest that the Leader of the House may call a meeting to come to a common understanding on this issue. I submit that this suggestion may be considered. (*Interruption*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने आपके सामने प्रस्ताव रक्खा है । यह इस सदन में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am giving my ruling.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस मोशन का क्या हुआ ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Sir, excuse me. I want to submit one thing. Now the House is in tension. We must follow certain procedures and then all these difficulties about the points of order would be over. If you want to overrule it or give any ruling on it, you might dispose of it. But we should proceed with the Bill. There should be no other question now before the House; the Home Minister has already moved it. We should all place our points of view before the House. Let us not waste the time of the House.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : So far as the adjournment is concerned...

SOME HON. MEMBERS : No, no.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am giving my ruling. I will call Mr. Dwivedy again to speak.

SHRI P. K. DEO (Kendrapara) : We want our point of view to be heard.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डिबेट कैसे हो सकता है ? गृह-मंत्री जी क्या बोले मैंने एक शब्द भी नहीं सुना तब मैं इस डिबेट में कैसे भाग ले सकता हूं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whose fault ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी ग़लती नहीं है । दरअसल आप इस सदन को बिलकुल कंट्रोल नहीं कर सकते ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is difficult for you to control your own people.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : It has already started. Arson and stone-throwing and beating of students in the English-medium schools have already started.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये । इस तरीक़े से बार-बार उठ कर विघ्न डालना यह बर्दाश्त नहीं होगा । इनको बाहर निकालिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sreekantan Nair, is it proper ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आप के साथ सहयोग करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर ठीक तरीक़े से बहस हो लेकिन अगर इस सदन के सभी लोग सहयोग के लिये तैयार नहीं हैं तो इस तरीक़े से राजभाषा विधेयक पर बहस ठीक नहीं है । गृह-मंत्री जी हम चाहते थे कि बोलें मगर वह क्या बोले मेरे कान में एक अक्षर भी नहीं पड़ा । मेरा निवेदन है कि आप मेरा प्रस्ताव लें । देखिये भावना उभरी हुई है । अगर हम चाहें तो थोड़ी देर में मिल सकते हैं। इस विधेयक पर बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I fully support the suggestion made by Shri Surendranath Dwivedy and I oppose the motion moved by Shri Madhu Limaye as also the suggestion given by Shri Vajpayee, because the Bill has already been moved and the hon. Minister has spoken on the motion. Therefore, the discussion should be allowed to proceed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप ज़रा मेरी मदद करिये । मंत्री महोदय क्या बोले आपने सुना ?

ऐसा आरोप मेरे ऊपर आप नहीं लगा सकते हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You would not allow me to listen. What can I do ? (*Interruptions*). So far as the request for the adjournment of the debate is concerned, I am not prepared to adjourn it. I will request the Home Minister to repeat his speech, provided he is listened to, with silence.

श्री मधु लिमये : एक बात बताइये । मेरे स्थगन प्रस्ताव को क्या आपने ठुकरा दिया है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have overruled it. I am not allowing it. (*Interruptions*).

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप कैसे ठुकरा सकते हैं । सदन के सामनें रखना चाहिये ।

DR. RAM SUBHAG SINGH : If they agree to be silent, the Home Minister will repeat his speech.

SHRI J. H. PATEL *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : After the Home Minister gets a hearing from the House, I will hear the hon. Member.

श्री राम सेवक यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ····

श्री मधु लिमये : उनका भाषण हम सुनेंगे । साथ-साथ इसका भी व्यवस्था का प्रश्न सुना जाए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, if you translate it.

Now, the Home Minister may repeat his speech.

श्री मधु लिमये : बाद में सुनेंगे न आप ।

(*The Home Minister then repeated his speech made earlier*—vide *Cols.* 5447—51.)

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह बड़ा महत्व का विधेयक है और इस सदन के एक सदस्य के नाते मैं यह जरूर चाहूंगा कि मुझे बोलने की अनुमति मिले । किन्तु आज की जो व्यवस्था चल रही है उसको आप देखें । अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इसके ऊपर बारह घंटे का समय दिया गया है । कई लोगों ने संशोधन दिये हैं । मैं ने भी दिया है । लेकिन होता क्या रहा है । मैंने महाजन कमिशन की रिपोर्ट के बारे में सवाल किया था । मुझे जवाब आया—

I was told there will be a debate on the 6th, please refer to that.

मैंने तब सुबह दस बजे नोटिस दिया ।

Then I said I would like to participate in the debate.

किन्तु फिर बैलट हुआ । बैलट में मेरा नाम नहीं निकला । मैं चुप रह गया । अब जिन लोगों ने इस विधेयक पर संशोधन दिये हैं । उनके संशोधनों का चयन होगा

उस चयन में यदि मेरा नाम नहीं निकलेगा तो क्या मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा ? ऐसे हम सदन में बैठे रहें यह तो हो नहीं सकता है । एक सदस्य के नाते मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का और अपने संशोधन पर बोलने का ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his point. This morning this point was raised and the Speaker, before he left—because there were several suggestions for extension of time—observed that at 4.45 P.M. today the Business Advisory Committee was meeting where all leaders would be present I can assure you, Shri Joshi, that you will get an opportunity. You should get it. You will not be forced to watch the debate silently.

SHRI J. H. PATEL *spoke in Kannada.*

15.40 Hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI YASHPAL SINGH (Dehra Dun) : I beg to move :

"This House is of opinion that the Official Languages (Amendment) Bill, 1967, be referred to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court under Article 143 of the Constitution on the question of constitutional validity of the Bill." (1)

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th June, 1968." (2)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th March, 1968." (3)

DR. GOVIND DAS : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 2nd March, 1968." (4)

SHRI YAJNA DATT SHARMA : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st May, 1968." (5)

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : I beg to move .

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 12th February, 1968." (6)

SHRI ONKAR LAL BERWA (Kota) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th February, 1968."

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI (Bhagpat) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1968." (8)

SHRI SHARDA NAND (Sitapur) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th June, 1968." (9)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

"That the Bill to amend the Official Languages Act, 1963, be referred to a Joint Committee of the House consisting of 37 members, 25 from this House, namely :—

(1) Shri Bibhuti Mishra
(2) Shri Y. B. Chavan
(3) Shri Valmiki Choudhury
H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo
(5) Shri Hem Barua
(6) Shri S. M. Joshi
(7) Shri Liladhar Kotoki
(8) Shri J. B. Kripalani
(9) Shrimati Sucheta Kripalani
(10) Shri V. Krishnamoorthi
(11) Shri Madhu Limaye
(12) Dr. Sarojini Mahishi
(13) Shri Bakar Ali Mirza
(14) Shri H. N. Mukerjee
(15) Shri Nath Pai
(16) Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit
(17) Shri Mrityunjay Prasad
(18) Shri S. R. Rane
(19) Shri S. C. Samanta
(20) Shri A. K. Sen
(21) Shrimati Jayaben Shah
(22) Shri Vidya Charan Shukla
(23) Dr. Ram Subhag Singh
(24) Shri Atal Behari Vajpayee, and
(25) Shri Prakash Vir Shastri;

and 12 from Rajya Sabha.

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

[Prakash Vir Shastri]

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 12 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee (10)

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : He has included my name; I am not at all a party to this.

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH (Gorakhpur) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of elicting opinion thereon by the 16th March, 1968." (80)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th June, 1968." (90)

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East Delhi) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st April, 1968." (95)

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR (Kishanganj) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1968." (129)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD (Maharajganj) : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 1, —

for "Hindi shall be the official language of the Union"

substitute "Hindi is the official language of the Union" (1)

SHRI SEQUEIRA (Marmagoa) : I beg to move :

That in the resolution,—

for first part of para 2, *substitute*—

"2. WHEREAS the Eighth Schedule to the Constitution specifies to date only 15 of one languages in use in India, and this House is of the opinion that all remaining languages should be placed on this Schedule, and that concerted measures should be taken for the full development of all these languages;" (2)

That in the resolution,—

after para 2, *insert*—

"2A. WHEREAS for improved national integration it is essential that the large non-ambulatory sections of our people should be able to communicate with each other, and have easier access to knowledge disseminated through the other languages;

This House resolves that a common script for all languages in use in the country be evolved, adopted and vigorously propagated. (3)

SHRI YASHPAL SINGH : I beg to move :

That in the resolution,—

omit paras 3 and 4. (4)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 4,—

after "non-Hindi speaking" *insert*—

"or Hindi speaking". (5)

SHRI AMRIT NANATA : I beg to move :

That in the resolution, —

for Part (a) of para 4, *substitute*—

(a) that compulsory knowledge of Hindi for non-Hindi speaking people and of English for Hindi speaking people shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi or English knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post; and (6)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi"

insert "or English" (7)

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL (Samastipur) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "shall not be required" *substitute*

—"(minimum standard) shall be required" (8)

SHRI FRANK ANTHONY : I beg to move :

That for the original resolution the following be *substituted,* namely :—

"This House resolves :—

(i) That any programme for accelerating the development of Hindi undertaken by the Central Government shall be met to the extent of half the total cost by the Hindi States;

(ii) That a programme shall be prepared and implemented by the Government of India in collaboration with the State Governments for coordinating the development of the languages of the Eight Schedule of the constitution and any language that may be the official language of a State;

(iii) That a compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection, confirmation or promotion of candidates recruited to the Union services or posts except any special post for which a high standard of Hindi is essential."

SHRI NAMBIAR : I beg to move :

That in the resolution,—

(i) in first part of para 1,—

(a) *after* "official language" *insert* "ultimately"

(b) *after* "Hindi language" *insert*— "voluntarily"

(c) *after* "India" *insert*— "and with the full consent of all the non-Hindi speaking States";

(ii) in second part of para 1,—

after "for accelerating the" *insert* "voluntary" (10)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 1,—

for "shall be" *substitute* "be" (11)

That in the resolution :—

in first part of para 2,—

for "concerted measures should be taken"

substitute "concerted measures be taken" (12)

That in the resolution,—

in part 2 of para 2,—

for "a programme shall be prepared and implemented"

substitute "a programme be prepared and implemented" (13)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 2,—

for "alongside Hindi" *substitute* "alongside Sanskrit" (14)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 3,—

for "should be taken" *substitute* "be taken" (15)

SHRI N. S. SHARMA (Dowasiganj) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

omit 'preferably one of the Southern languages" (16)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

for "of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi speaking areas"

substitute "of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas and in case there are at least 10 students in any one section." (17)

SHRI SRINIBAS MISRA :

That in the resolution,—

for part (a) of para 4, *substitute*—

(a) that except for services/posts directly connected with propagation or teaching of Hindi, compulsory knowledge of Hindi, elementary or otherwise, shall not be required at the stage of recruitment to Union Services/posts; nor shall such knowledge be required at the stage of promotion except an elementary knowledge of Hindi for promotions to posts requiring public contact; and" (18)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates"

substitute "compulsory general knowledge of Hindi shall be required at the stage of selection of candidates". (19)

SHRI N. S. SHARMA : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

(i) *after* "that compulsory knowledge of Hindi *insert* "or English"

(ii) *after* "for which a high standard of Hindi" *insert* "or English" (20)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I beg to move.

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi" *insert* "or English" (21)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English" (22)

SHRI N. S. SHARMA : I beg to move :

That in the resolution,—

after part (b) of para 4, *insert*—

(c) Hindi and English shall be permitted as the alternative media for examination for recruitment to posts of class II, class III and class IV of the Central services to be conducted on or after April 1, 1968 :

Provided that where the recruitment is in respect of posts sanctioned for an office situated in a particular State, the language or languages adopted by that State as its official language or languages will also be permitted to be used by the examinees in addition to Hindi or English." (23)

SHRI YAJNA DATT SHARMA : I beg to move:

That in the resolution,—

omit para 3. (24)

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

for para 3, *substitute*—

"With a view to promote the sense of unity it is necessary to make arrangements for the study of any of the South Indian languages in the Hindi-speaking areas in addition to Hindi and of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas;" (25)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

That in the resolution,—

for part 2 of para 3, *substitute*—

"This House resolves that arrangement should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages apart from Hindi in the Hindi-speaking areas, and of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas." (26)

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

omit "preferably one of the Southern languages" (27)

SHRI YAJNA DATT SHARMA : I beg to move :

That in the resolution,—

for first part of para 4, *substitute*—

"4. And, whereas it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi speaking areas and Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;" (28)

That in the resolution,—

for part (a) of para 4, *substitute*—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi for non-Hindi-speaking people and of English for Hindi-speaking people shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi or English knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post; and (29)

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

for part (a) of para 4,— *substitute*—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi shall be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts; and" (30)

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "compulsory knowledge of Hindi"

substitute—

"compulsory knowledge of Hindi or English" (31)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

add at the end

"but non-Hindi speaking persons having knowledge of Hindi would be given preference over Hindi-speaking persons" (32)

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English" (33)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

add at the end

"but knowledge of Hindi would be compulsory for non-Hindi-speaking persons although not for the purposes of competition" (34)

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal) : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 1,—

for "shall be" *substitute* "is". (35)

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : I beg to move:

That in the resolution,—

in first part of para 3 *add* at the end—

"to make this more effective, and to bring about greater appreciation and understanding, and purposeful mingling of people especially teachers, from different regions, it is further necessary, that those whose mother-tongue, is one of the Aryan Group of languages, should choose one of the Dravidian languages in the three language formula and *vice versa;*" (36)

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

for 'one of the Southern languages"

substitute "one of the South Indian Dravidian languages" (37)

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : I beg to move :

That in the resolution,—

In part 2 of para 3, *add* at the end—

"and that the arrangements should be so directed as to expedite the spread of Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression all over the country within a reasonably limited period;" (38)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi" *insert*—

"or English" (39)

SHRI HEM RAJ (Kangra) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4, —

(i) *after* "that compulsory knowledge of Hindi" *insert*—"or English"

(ii) *after* "high standard of Hindi" *insert* "or English" (40)

SHRI BAKAR ALI MIRZA : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4, *add* at the end—

"but all other things being equal preference in the matter of selection will be given to a candidate, who is proficient in another Indian language besides his regional language;' (41)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing." (42)

SHRI MADHU LIMAYE : I beg to move :

That in the resolution,—

for para 3, *substitute*—

"WHEREAS it is necessary for promoting a climate of tolerance and unity and also mutual understanding between people in different parts of the country.

This House resolves that neither English nor Hindi shall be a compulsory subject of study nor a compulsory medium of instruction or examination throughout the country and that the State Governments and the students in the non-Hindi speaking States shall have the freedom to choose between Hindi and English as an additional language;" (43)

That in the resolution,—

for parts (a) and (b) of para 4 *substitute*—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi or English shall not be required from the candidates for the Union Services or posts excepting the post of translators and interpreters for which a high standard of Hindi and English knowledge may be considered essential from the non-Hindi speaking and Hindi-speaking States respectively; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution shall be the media for all the All India and Higher Central Services examinations within a year from the passing of this resolution." (44)

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4.—

for "compulsory knowledge of Hindi shall not be required" *substitute*—

"compulsory knowledge of Hindi or English and preferably of both shall be required" (45)

"That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English" (46)

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I beg to move :—

"That for the original resolution, the following be substituted, namely :—

"WHEREAS India is a polyglot country with many national languages spoken by millions of people in well-defined regions and States.

WHEREAS any attempt to impose or give priority to a particular regional language with a view to bring in a linguistic uniformity will cut at the very roots of democracy and the unity of the country;

This House resolves that a re-thinking is necessary on the whole question of the official language policy of the Union and that a re-appraisal of the constitutional position be made with a view to provide equal status and opportunity for development to all linguistic groups in the country." (47)

SHRI S. M. BANERJEE *rose*—

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैंने भी सशोधन दिया है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैंने भी संशोधन दिया है ।

श्री न० प्र० यादव : मैंने भी संशोधन दिया है ।

MR. SPEAKER : These are all the things which I have received. Even if it comes after one hour, I will read it again. You need not be worried about it.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Yesterday after 3.30 myself and Shri Vasudevan Nair ....

MR. SPEAKER : I do not mind it being moved. I will give your names also, Shri Banerjee and Shri Vasudevan Nair.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) I beg to move :—

That in the resolution,—

in part 2 of para 1,—

after "development of Hindi", *insert*

—"and make it more simple". (48)

SHRI R. RAMAMURTI (Madurai) : I beg to move :—

That in the resolution,—

omit para 3. (49)

SHRI MEETHA LAL MEENA : I beg to move :—

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

add at the end

"ultimately with a view to see that the Hindi Language is developed and introduced to serve as a medium of instruction and expression in the country within a limited period'. (50)

SHRI S. M. BANERJEE : I beg to move :—

That in the resolution,—

for part (a) and (b) of para 4,—

Substitute—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi or English shall not be needed from the candidates for the services under the Union Government or posts excepting the posts of translators and interpreters for which a higher standard of Hindi and English knowledge may be considered essential from the non-Hindi speaking and Hindi speaking States respectively; and

(b) that all the language included in the Eighth Schedule to the Constitution shall become the media for all All-India and higher Central Services examinations within year from the adoption of this resolution." (51)

SHRI MANUBHAI PATEL : I beg to move :—

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi"

insert—

"or English". (52)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :—

That in the resolution,—

in part (a) of para 4

after "a high standard of Hindi"

insert—

"or English" (53)

SHRI MANUBHAI PATEL : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "the future scheme of the examinations." (54)

SHRI VALMIKI CHOUDHURY (Hajipur): I beg to move :

"That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required".

substitute—

"That compulsory knowledge of Hindi shall be essential." (55)

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required".

Substitute—

"that knowledge of either Hindi or English shall be essential." (56)

SHRI BIBHUTI MISHRA : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

(i) *after* "that compulsory knowledge of Hindi"

insert—

"or English"

(ii) *after* "that compulsory knowledge of Hindi shall"

omit "not" (57)

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

omit "excepting any special services /posts for which a high standard of Hindi knowledge may be con-

[Shrimati Sucheta Kripalani]

sidered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post". (58)

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "a high standard of Hindi" *insert*— .. ..

"or English". (59)

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing". (60)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि संकल्प में,—

पैरा १ के पहले भाग में—

संघ की राजभाषा हिन्दी होगी

के स्थान पर

"संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी"

रखा जाये । (६१)

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट वाइज मौका दिया जाय ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि विधेयक के ऊपर जो संशोधन दिए गए थे जिस में कहा गया था कि जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाये या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय क्या वह नहीं लिए गये हैं ?

MR. SPEAKER : All of them have been moved.

श्री कंवर लाल गुप्त : वह जनमत के लिए भेजा जायें यह मेरी उसमें एक तरमीम थी ।

MR. SPEAKER : Even if you give it after one hour, it will be considered as moved. The office will verify it. If anybody's amendment is missing now and we find it, we will include that also. We are having the discussion for three or four days. There is nothing wrong in that.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Not so many of you; one by one.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने नाम पढ़े हैं यह केवल रेजोल्यूशन पर पढ़े हैं या बिल पर भी ?

अध्यक्ष महोदय : बिल पर पहले या बाद में रजोल्यूशन पर ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : बिल पर तो हमारा भी है ।

MR. SPEAKER : All that will be verified by the office. I am also giving you some time.

श्री राम सेवक यादव : यह जो विधेयक पर ऐसे संशोधन आये हैं कि विधेयक जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय उस के ऊपर जब चर्चा कराएंगे तो क्या जो प्रस्तावक हैं उन्हें आप समय देंगे ?

MR. SPEAKER : May be so.

SHRI K. LAKKAPPA (Tomkur) : On a point of order, Sir. Article 348 of the Constitution is regarding the language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc. The point for consideration here is this. Some amendments have been moved in Hindi. I want to know whether the Constitution has conferred any right on the Members to move their amendments in Hindi. That is not so because the Constitution does not provide that. Article 348 of the Constitution says :

"(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of

Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language."

MR. SPEAKER : You need not read the whole thing. I have followed it.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, some of the amendments have been moved in Hindi and, therefore, they are not valid. The Constitution does not confer such a right on the Members to move any amendment in Hindi. I feel that Article 348 of the Constitution is thereby vitiated. They are not entitled to do so. So, all those amendments moved in Hindi should be rejected unless those amendments are moved in English. I want a clear ruling on this point.

MR. SPEAKER : Shri Surendranath Dwivedy.

AN HON. MEMBER : What is the ruling ?

MR. SPEAKER : While discussing all these things, it will come up. Mr. Lakkappa can again talk on this and can explain it more clearly.

Mr. Surendranath Dwivedy.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से चूंकि राजभाषा विधेयक पर विचार हो रहा है, मैं अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है इस में कुछ नई बात नहीं है। जहां तक हमारी राजभाषा का संबंध है 1950 से जब से संविधान मंजूर हुआ और चालू हुआ हम यह तय कर चुके हैं कि हमारे देश में हिन्दी ही हमारी राजभाषा होगी और हिन्दी में ही देश की भाषा के रूप में कार्य होगा। अब उस के बाद हमारे विधान में यह भी था कि 15 साल के बाद 1965 साल से हिन्दी ही चालू हो जायगी और 15 साल तक अंग्रेजी हमारे देश में चले। यह बदनसीबी है कि 15 साल के बाद इस देश में, बल्कि 15 साल पूरा होने के पहले ही यह झगड़ा शुरू हो गया कि हिन्दी को चालू करना है या नहीं। अगर यह शुरू हुआ तो इस की क्या वजह है? यह बिल्कुल साफ है कि अगर हिन्दी के लिए आज देश के इतने इलाकों में विरोध है तो उस विरोध की एक ही वजह कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि हिन्दी भाषा को डेवलप करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे कि जिससे कि यह भाषा सर्वसम्मत हो, सारा देश इस को मंजूर कर सके, मान कर चले, वह काम कुछ किया नहीं गया। 15 साल तक हमारी सरकार ने हिन्दी को बिलकुल सीरिअसली नहीं लिया और कुछ काम नहीं किया। आगे नहीं बढ़ाया। मैं यहां याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा स्वतन्त्रता का संग्राम चल रहा था तो जो नारे हम देश में लगा रहे थे उस में एक नारा हमारा था कि राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। यह नारा चारों तरफ था। मद्रास में भी था। देश के कोने-कोने में, गैर-हिन्दी इलाकों में भी था। कहीं पर विरोध नहीं हुआ था कि यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज यह क्यों हुआ? उसके दो कारण मैं समझता हूं। एक कारण है कि हमारी सरकार ने संविधान को लागू करने के लिए जो उस का कर्त्तव्य था वह नहीं किया। और दूसरा मैं ज्यादातर दोष देना चाहता हूं हमारे जो हिन्दी भाषी भाई हैं उन को कि हिन्दी के विरोध में कुछ आवाज उठी है। मैं बहुत विचार कर के इस राय पर पहुंचा हूं कि हमारे देश में हिन्दी हमारी भाषा है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन अगर हमारी भाषा चालू करने के लिए विरोध

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

उठता है तो वह विरोध इसीलिए है कि जो लोग हिन्दी भाषी बोले जाते हैं उन की कार्यवाही की वजह से देश में यह विरोध हो गया। यह जो अंग्रेजी हटाओ नारा देश में उठा इस नारे की वजह से दूसरी तरफ से इस के विरोध का भी नारा शुरू हुआ। कभी इस देश में हिन्दी और अंग्रेजी का झगड़ा नहीं था। अगर लोग हिन्दी का कभी विरोध करते थे तो इसी खयाल से करते थे कि जो गैर-हिन्दी इलाके हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अगर हिन्दी चलती है तो उन रीजनल लैंग्वेजेज को डेवलप करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। और इस से वे लोग नुक्सान में रहेंगे, सर्विसिज में नुक्सान में रहेंगे, रीजनल लैंग्वेज से केवल इसीलिये पहले हिन्दी का विरोध था। लेकिन कभी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में विरोध नहीं था।

16 Hrs.

हिन्दी वालों को आज भी इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये, जो हिन्दी-हिन्दी कहते हैं, उन को जरा भी विरोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि हिन्दी, आप को मालूम है, सब को मालूम है, कोई इतनी बड़ी अच्छी भाषा नहीं है, जिसका आदर कर के सब उस को ग्रहण कर लें। बंगला, तमिल के मुकाबले हिन्दी कुछ नहीं है, हिन्दी एक रिजनल लैंग्वेज है, इस को अगर हम सारे हिन्दुस्तान की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो धीरज से काम लेना चाहिए और इस को उस जगह पर लाना पड़ेगा, जिससे कि वह सारे हिन्दुस्तान की भाषा हो सके। इस के लिये थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सहिष्णुता रखनी पड़ेगी। आज जो यह नारा उठ रहा है—हिन्दी चाहिये, हिन्दी चाहिये—यह कहां से उठ रहा है? हिन्दी भाषा-भाषी इलाकों से, यू० पी० से, दिल्ली से, इन इलाकों से यह नारा उठता है। लोग पब्लिक प्रापर्टी को नष्ट कर रहे हैं—आखिर किस लिये? जहां पर कोई अंग्रेजी साइन-बोर्ड देखते हैं—कहते हैं हटा दो। मैं कहता हूं कि अगर हिन्दी वालों को हिन्दी चालू करनी है तो जो हिन्दी के राज्य हैं, वहां इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, वहां पर आन्दोलन करने की क्या जरूरत है। वे नान-हिन्दी इलाकों में जाएं, वहां पर जा कर कहें कि अंग्रेजी हटाओ—यहां पर क्यों कह रहे हैं?

श्री मधु लिमये: पहले यहां तो हटायें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: यहां तो हट गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से हिन्दी राज्य हैं, जो हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। कोई हिन्दी राज्य ऐसा नहीं है जो हिन्दी का विरोध कर रहा है। तो यह मूवमन्ट किस लिये है? यह मूवमेन्ट है—इम्पोजीशन के लिये, जदरबस्ती के लिये, जो नहीं मानते हैं उन पर जबरदस्ती लादी जाए—यह स्प्रिट इस के अन्दर है और जब तक यह जबरदस्ती रहेगी, मैं साफ कह देना चाहता हूं—हमारी पार्टी की तरफ से भी कई दफा साफ कहा गया है—हम मानते हैं कि हमारी राज भाषा हिन्दी होगी, इस में कोई शक नहीं है, लेकिन जब ऐसी मांग आती है कि कांस्टीट्यूशन में अमेण्डमेंट कर के अंग्रेजी को चालू रखो, तो आपको देखना होगा कि यह मांग कहां से आती है—मद्रास से आती है, दूसरी जगहों से आती है—तो आप को सोचना होगा कि नान-हिन्दी इलाके, जो कि इस देश का दो-तिहाई भाग हैं, हमारे देश का एक-तिहाई भाग हिन्दी इलाके हैं, अगर उन के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, तो सारे नान-हिन्दी इलाके इस का विरोध करेंगे और तब हम देखेंगे कि आप कैसे हिन्दी चलायेंगे।

हम हिन्दी का विरोध नहीं करते हैं और न करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह जो काम है सब को साथ ले कर किया जाय। मैं मानता हूं कि यह हमारी पहले से गलती है—सारी दुनिया में कोई कांस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है, जिसमें यह लिखा हो या इस प्रकार का

कोई प्रोवीजन हो कि भाषा कौन-सी होगी। हमारा जो इतिहास रहा है, उस में पहले से यह रहा है कि माइनोरिटी को देखो—इन्डीपेन्डेंस से पहले भी यह झगड़ा उठा था कि उर्दू को रखें या हिन्दी को रखें। सन् 1928 में आपको याद होगा—पं० मोती लाल नेहरू के सभापतित्व में जो एक आल पार्टी कान्फ्रेंस हुई थी वहां पर भी यह सवाल उठा था कि हिन्दुस्तान की हमारी भाषा क्या हो, उस वक्त शायद हिन्दुस्तानी को रखा गया था — ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि शुरू से हम माइनोरिटी को खुश रखना चाहते थे और वही बात हमारे कांस्टीट्यूशन मेकर्स के दिल में भी पैदा हुई थी कि इस बारे में हम को कुछ करना चाहिये। जब विरोध हुआ तो हिन्दुस्तानी निकाल दी गई और हिन्दी को रखा गया, जोकि नहीं होना चाहिये था। मेरे विचार में तो संविधान में ऐसा कोई प्रोवीजन ही नहीं होना चाहिये था कि हमारी भाषा क्या है। इसीलिये यह सब झगड़ा होता है। हमारी भाषा भारतीय भाषायें हैं और वही भाषायें रहेंगीं। इस देश में दूसरी भाषा नहीं चल सकती है—इसलिये इस को रखने की क्या जरूरत है, इस के लिये झगड़ा पैदा करने की क्या जरूरत है, इस तरह से यह कभी नहीं हो सकेगा।

आज क्या हालत है? आज इस बात को मानना पड़ेगा, सब को मानना पड़ेगा कि बदकिस्मती से हमारे देश में कई इलाकों के लोग हिन्दी को अभी मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं हैं—उनका कारण वाजिब है। वह समझते हैं कि हम हिन्दी सीखेंगे, तो इतनी दूर तक जो हम आये हैं, जितनी अंग्रेजी हमने पढ़ी है, जितना हमारा कारोबार है, उस हद तक हिन्दी सीखने में, हिन्दी को अपनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन यदि देर तक इस को चलाया जाय. तो धीरे-धीरे अंग्रेजी हट जायेगी, इससे हम को मुश्किल भी कम होगी। इस लिए इस को फौरन लाकर इम्पोजीशन नहीं करना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि हम उन लोगों को किस तरह से साथ ले कर चलें। अब यहां एशोरेन्स की बात आई है—हम एशोरेन्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वह तो एक पौलिटीकल चाल थी। प्रधान मंत्री ने लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये कह दिया कि हम एशोरेन्स देते हैं कि जब तक सारे अहिन्दी भाषी लोग राजी नहीं होते हैं, अंग्रेजी रहेगी। उस एशोरेन्स को पूरा करने के लिये हम पार्लियामेंन्ट में विधेयक पेश करते हैं—लेकिन उसके कोई मायने नहीं हैं। कल वह विधेयक हम बदल भी सकते हैं। इसलिये उस एशोरेन्स का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक बात हम को ज़रूर देखनी पड़ेगी कि जो लोग हिन्दी लाने के लिये बाध्य कर रहे हैं उन हिन्दी वालों के दिलों में एक शक आया हुआ है कि ये लोग हिन्दी नहीं सीखेंगे, क्योंकि यह सरकार कांस्टीट्यूशन के उस प्रावीजन को पूरा करने के लिये कोई ठोस कदम उठाने वाली नहीं है। जब 20 साल तक उस ने नहीं किया, तो आगे भी करने वाली नहीं है—इसीलिये उनके मन में शक है। जिस तरीके से यह विधेयक आया है, उस से यही जाहिर होता है कि यहां पर अंग्रेजी को कुछ दिनों तक रखेंगे। मैं मानता हूं कि प्रोलौंग्ड बाइलिंगुलिज्म इस देश में कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन हम को देखना चाहिये कि अंग्रेजी भाषा क्यों जरूरी है? मैं यह मानता हूं कि जिस देश में दो प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते, उस देश में अंग्रेजी भाषा ज्यादा दिन तक चलेगी — यह सम्भव नहीं है। लेकिन उन लोगों को राजी करने के लिये यह ज़रूरी है कि हम ऐसे कुछ कदम उठायें, ऐसा प्रावीजन रखें कि उनके दिल में जो यह शक पैदा हो गया है कि हिन्दी हम पर लादी जा रही है, यह शक दूर हो जाए।

जहां तक मैंने इस बिल को पढ़ा है, इसमें इधर-उधर कोई परिवर्तन होना चाहिए तो वह संशोधन कर लें, लेकिन वैसे यह बिल हिन्दी का विरोधी नहीं है। हिन्दी किस तरह

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

से सर्वसम्मति से चालू होगी, इस के लिये कुछ रास्ता इस में सुझाया गया है, रास्ता निकाला गया है । इसीलिये जो रेजोल्यूशन आया है, मैं उस को भी बहुत महत्व देता हूं । यह रेजोल्यूशन पहले से आना चाहिये था । यह गवर्नमेन्ट का फर्ज था कि कांस्टीट्यूशन में 343 से 348 तक जो धारायें रखी गई हैं, उनको काम में लेती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, अब इस विधेयक के साथ उस को लाये हैं । हम जानते हैं कि इस सरकार ने इस कांस्टीट्यूशन के अनुसार प्राइमरी एजूकेशन के लिये क्या किया, प्राहिविशन के लिये क्या किया, डिस्पैरिटी हटाने के लिये क्या किया, कांस्टीट्यूशन के इन सारे प्रावीजन्ज को काम में लाने के लिये क्या किया— कुछ काम नहीं किया है । यह निकम्मी सरकार है इस को हटाओ ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विधेयक हिन्दी के खिलाफ़ नहीं है, इस विधेयक में केवल देश के अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिये व्यवस्था की गई है । मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम अपने देश के दो-तिहाई लोगों को क्या तसल्ली देंगे, उनमें सिर्फ मद्रास के डी०एम० के० वाले भाई नहीं हैं, मैं खुद भी आपके सामने खड़ा हूं मैं भी हिन्दी भाषी नहीं हूं— इसलिये हम ऐसी चीजों के पीछे नहीं जायेंगे, जिसमें झगड़ा हो, हम उस रास्ते को कभी अख्तियार नहीं करेंगे जिसमें हमारी एकता भंग हो । ये जो हमारे भाई हैं, जो अहिन्दी भाषी हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं, उन की अवज्ञा कर के, उन को छोड़ कर, क्या हम आगे बढ़ सकेंगे । यह बात आज हम को पार्लियामेन्ट में विचार करनी है । इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यह जो विधेयक आया है इस में जो प्रावीजन किया गया है, वही ठीक है ।

16·09 HRS.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair.*]

एक मांग है कि हिन्दी पूरी तरह अमल में लाने के लिए एक टाइम लिमिट कर दी जाय कि पांच साल के अन्दर हिन्दी चालू हो जाएगी तो वह भी इस तरीके से हिन्दी लादने की ही बात होगी क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि अभी इस को लाने में कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे? हिन्दी पांच साल की अवधि में लाने के लिए आप ने क्या प्रबन्ध किया है आप ने अहिन्दी भाषी प्रान्तों में, कि वहां पर पांच साल के अन्दर उन को इतनी दक्षता हो जाएगी कि वह सब काम-काज हिन्दी में भली-भांति चला सकें? क्या प्रबन्ध आप ने इस के लिए किया है कि पांच साल के अन्दर जैसे मैं आज अंग्रेजी में बोल सकता हूं वैसे ही मैं हिन्दी में भी बोल पाऊंगा? मेरी समझ में ऐसी दक्षता नहीं हो पायेगी । इसलिए इस बारे में कोई टाइम लिमिट करना और वह भी आज के हालात में जब कि इतनी मुखालफ़त हो, उचित नहीं है और अगर वैसा हम करते हैं तो जिस उद्देश्य से हम यह विधेयक पास करना चाहते हैं वह उद्देश्य बिलकुल बर्बाद हो जायगा, नष्ट हो जायगा । वह उद्देश्य काम में नहीं आयेगा । मैं नहीं समझता हूं कि आज की हालत में इस तरह की कोई टाइम लिमिट फिक्स करनी जरूरी है । आज जो लोग कहते हैं कि इस तरह का विधेयक लाना बिलकुल अनकांस्टीट्यूशनल है, यह संविधान के विपरीत है तो मेरा कहना है कि वह तो जिस रोज 1963 में हम ने यह विधेयक ग्रहण किया उसी दिन से हम ने अनकांस्टीट्यूशनल काम करना शुरू कर दिया । सन् 1965 की जो अवधि हम ने रक्खी थी हिन्दी को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए, वह लानी सम्भव नहीं दिखाई दे रही थी इसलिए सन् 1963 में ही कांस्टीट्यूशन को तोड़ कर और विधेयक करके यह कर दिया कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ रहेगी : इसलिए जो इस संशोधन विधेयक को अनकांस्टीट्यूशनल होने की बात करते हैं तो वह तो उस तरह से पहले से ही सन्

1963 ने ही अनकांस्टीट्यूशनल था इसलिए यह अनकांस्टीट्यूशनल होने की बात आज नहीं उठती है । मेरी समझ में हमारे जो हिन्दी भाषी लोग हैं उन का इस बारे में अपेक्षाकृत अधिक कर्त्तव्य व दायित्व है कि वह प्रेम से अपने साथ अहिन्दी भाइयों को हिन्दी की दिशा में ले चलने का धीरे-धीरे प्रयास करें। इस चीज में सेंटीमैंट की बात आ गई है, कुछ पालिटिक्स की भी बात आ गई है और अगर हम इस पालिटिक्स को छोड़ कर विचार करें तो मैं समझता हूं कि हिन्दी देश में चालू होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा अगर इसी को दुहरायेंगे, इसी पर इम्फैसिस देंगे तब मैं समझता हूं कि यह देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। आखिर कैनाडा एक छोटा सा देश है लेकिन उस में कई भाषाएं हैं, इजरायल में भी इसी तरह २-३ भाषाएं हैं तो हमारे इतने विशाल देश में अगर कुछ दिन तक एक से अधिक भाषा चले तो इस में हमें घबड़ाना नहीं चाहिए । हमारा देश मल्टीलिंग्वल है, काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेज यहां पर हैं और हम ने कांस्टीट्यूशन में उन के लिए प्राविजन किया है और कांस्टीट्यूशन में फिर अमैंडमेंट आता है कि अमुक प्रादेशिक भाषा को भी उस सूची में शामिल करो। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में काफ़ी प्रादेशिक भाषाएं हैं और संविधान ने उन्हें मान्यता भी प्रदान की हुई है ऐसी हालत में क्या बिगड़ता है। अगर कुछ दिन तक हमारे देश में दो भाषाएं चलें? आखिर देश की एकता हम सब के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए । अब अगर कोई मुझ से पूछे कि तुम देश की एकता चाहते हो या हिन्दी चाहते हो तो मैं फौरन जवाब दे दूंगा कि भाई हिन्दी ५, १०, या २० साल के अन्दर भले ही आवे उस से कुछ विशेष नहीं बिगड़ने वाला है लेकिन देश की एकता का खतरा हम एक क्षण के लिए भी नहीं मोल ले सकते। आज हमारे सामने प्रश्न देश की एकता, इंटैग्रिटी और यूनिटी की रक्षा करने का है और उस की रक्षा करने का रास्ता सिर्फ यही है, अन्य कोई रास्ता नहीं है कि हमें सब को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं फिर एक दफा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर से जो आन्दोलन होता है और भीतर हम जिस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं उस पर हम जरा गम्भीरता से विचार करके देखें कि इसके परिणामस्वरूप कहीं हम देश की एकता को तो कमजोर नहीं कर रहे हैं। अभी भी देश में कहीं से यह मांग उठ रही है कि इस कांस्टीट्यूशन को बदलो, कांस्टीट्यूशन को हटा दो और अगर देश में इसी प्रकार का बर्ताव चलता रहा तो यह प्रवृत्ति घटने वाली नहीं है बढ़ने ही वाली है और देश की एकता छिन्न-भिन्न हो जायगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो भाषा सम्बन्धी संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उस को हम सब को मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि इस में मैं एकता को कायम रख सकने की आशा देखता हूं।

भाषा सम्बन्धी डिबेट जो सन् 1963 में सदन में हुआ था उस का मैं अध्ययन कर रहा था तो उस समय डी० एम० के० के जो यहां नेता होते थे श्री मनोहरन, उन का उस वक्त यह कहना था कि जब तक हम एग्री न हो जायें। तब तक इसको मत करो। अब एग्री करने का दायित्व किस का है? मैं आशा करता हूं कि वह लोग भी आज नहीं तो कल, वह दिन आने वाला है, जब इस के लिए एग्री हो जायेंगे, क्योंकि अगर उन को तामिल के प्रति श्रद्धा है, तामिल भाषा के लिए श्रद्धा है तो मैं समझता हूं कि उसी तरीके से उन को और भी भारतीय भाषाओं के लिए श्रद्धा होगी। अब जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के लिए श्रद्धा होनी है तो देश में हिन्दी के सिवाय और कोई भी अन्य भारतीय भाषा इस देश की लिंक लैंग्वेज नहीं हो सकती है। वह भी कुछ दिन के बाद इसे मंजूर करेंगे।

आज करीब-करीब हमारा फैसला हो गया है कि युनिवरसिटीज में एजूकेशन का मीडियम रीजनल भाषा होगी और वहां पर पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में चलेगी और अगर यह चलती

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

है तो यह मानी हुई बात है कि अंग्रजी का आज जो स्थान है वह और कमजोर हो जायगा। जब अंग्रेजी कमजोर हो जाती है, रीजनल लैंग्वैज युनिवरसिटीज में होती है तो भारतीय प्रादेशिक भाषाओं का निश्चित रूप से प्राधान्य बढ़ता है। साथ ही यह भी मानी हुई बात है कि जब उन के बीच कोई एक लिंक लैंग्वैज की बात होगी तो वह किसी भारतीय भाषा को ही पसन्द करेंगे, अंग्रेजी को नहीं पसन्द करेंगे और जैसा मैंने अभी कहा वह भारतीय भाषा हिन्दी ही हो सकती है।

आज लोग पूछते हैं कि कैसे यहां पर काम चल सकेगा क्योंकि हिन्दी सारे लोग समझते नहीं हैं तो मेरा उन से कहना है कि अगर कोई भाव प्रकट करना है तो उस के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई एक भाषा हो ही। जब शंकराचार्य महाराज केरल से आये और वह कश्मीर तक गये तो उन्होंने किस भाषा में लोगों को अपना संदेश व उपदेश दिया? इसलिए हमें देश की एकता का मूलाधार क्या है उस को समझना चाहिए। पहली जरूरत इस बात की है कि हम देश में हिन्दी के लिए अनुकूल हवा व वातावरण पैदा करें, लोगों को प्रेम से उस दिशा में चलाने का प्रयास करें क्योंकि हम देश की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जिस दिन तक हमारे दूसरे अहिन्दी भाई हिन्दी को अमल में लाने के लिए राजी नहीं होते हैं उस दिन तक हमारे देश में दो भाषायें चलें हम को कोई ऐतराज नहीं है।

इस विधेयक के द्वारा अलबत्ता एक बात उठती है और वह है कि किसी भी स्टेट को एक वीटो पावर मिल जायगी और उस के लिए हमें देखना चाहिए और आवश्यक संशोधन के लिए विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आप को बतलाऊं कि नागालैंड एक छोटी सी स्टेट बन गई है भले ही वह कुछ भल के कारण बनी हो लेकिन वह बन गयी है। अब उन के लिए हमारे मन में पहले से यह विचार है कि वह एक क्रिश्चियन स्टेट होगी और वह अपनी राजभाषा अंग्रेजी को करेंगे। अब अगर दूसरे भाषा-भाषियों को आप यह अधिकार देते हैं कि वह अपनी-अपनी स्टेट में अपनी खुशी के मुताबिक जो लैंग्वैज चाहें उसे चलावें तो नागालैंड वाले चूंकि समझते हैं कि उन के लिए अंग्रेजी चलाने में सहूलियत है इसलिए वह अंग्रेजी चला रहे हैं लेकिन यह गलत बात होगी। विधेयक में अभी जो प्राविजन रहता है कि नागालैंड जो एक स्टेट है वहां अंग्रेजी चलती है क्योंकि वहां के लोग ऐसा चाहते हैं तो सारे देश में अगर मेजारिटी कहती है कि हिन्दी चालू करना है लेकिन चूंकि युनेनिमिटी नहीं है तो वह नहीं चालू की जा सकती है तो यह बात गलत होगी। वह देश के लिए भी गलत होगी। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि यह जो अभी कहा गया है उस का यह मतलब है कि सारी की सारी स्टेट राजी होगीं तभी हिन्दी को चालू किया जा सकेगा। अगर मेजारिटी स्टेट्स इस को चालू करने के लिए राजी हो जायेंगी तो उसे अमल में ले आया जायेगा। अगर एक उस के खिलाफ़ होगी तो एक के लिए पार्लियामेंट बैठी नहीं रहेगी और उसे वीटो पावर नहीं होगी और न होनी ही चाहिए। प्राविजन आप कुछ भी करें जैसा मैंने कहा अगर समूचे देश में आप हिन्दी के लिए प्रेम से व्यवहार करके अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं, देश में इस बारे में तमाम झगड़े और प्रदर्शन आदि बन्द हो जाते हैं और उस समय अगर हर एक नौन-हिन्दी स्टेट हिन्दी को अमल में लाने के लिए राजी हो जाती है तब मेरे दिल में जरा भी शक नहीं है कि वह क्यों न समूचे देश में आ सके। भले ही उस समय एक टुकड़ा नागालैंड हो या इर्दगिर्द और कोई भाई हों जोकि इसके विरुद्ध हों तो वह उसे अमल में आने से रोक नहीं सकेंगे और सारे देश में हिन्दी चालू होगी, इसलिए हमें इस बारे में धीरज से काम लेना चाहिए।

यह बिल एक अच्छी आबहवा पैदा करता है और अगर लोगों के दिलों में इस तरह से एक

गलतफ़हमी न पैदा कर दी जाती, लोगों के अन्दर इस तरह का भ्रामक प्रचार न कर दिया जाता तो सभी लोग इस का स्वागत करते। यह मैं साफ दिल से कहता हूं कि यह जो आबहवा अब फैल गई है उस में मालूम ऐसा देता है मानों यह संशोधन विधेयक हिन्दी के विरुद्ध हो। मैं कहता हूं कि यह हिन्दी को बढ़ाने वाला बिल है, हिन्दी की अभिवृद्धि का बिल है। इस बिल द्वारा सभी देशवासियों को साथ लेकर हिन्दी को चलाने की दिशा में एक प्रयास है लेकिन अभाग्यवश आबहवा ऐसी पैदा की जाती है कि यह हिन्दी के विरुद्ध है और इस को लेकर देश में गड़बड़ी मच गई है।

सभापति महोदय, मुझे इस अवसर पर और अधिक नहीं कहना है क्योंकि जब इस पर धारा-वार विचार होगा तब जो मैंने इस पर संशोधन दिये हैं उन की रोशनी में मैं इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक कहूंगा। मेरी समझ में एक-आध संशोधन इस में अपेक्षित हैं जैसे कि मैंने एक संशोधन इस पर दिया भी है कि अगर एक हिन्दी भाषा-भाषी स्टेट है और वह एक अहिन्दी भाषा-भाषी स्टेट से हिन्दी में वार्तालाप करना चाहती है और इस बारे में अगर उन में परस्पर राजीनामा हो जाय तो यह हो सकता है। बिल में यह प्राविजन हो। अगर नान-हिन्दी वाले हिन्दी भाषा में हिन्दी वालों से बात करना चाहते हैं या यूनियन के साथ करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं लेकिन यह काम रजामन्दी से ही हो सकता है। इस में एक बात की सफाई नहीं है। अगर हिन्दी में लिखा जाता है तो हिन्दी में जवाब आएगा और साथ में अंग्रेजी ट्रांस्लेशन आएगा। जो नान-हिन्दी वाले लिखेंगे वे अपनी भाषा में और अंग्रेजी में लिखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास यहां से हिन्दी में जवाब जाएगा? मुझे मालूम है कि शायद नन्दा जी जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कोई सर्क्युलर निकाला था कि जहां से जिस भाषा में पत्र आएगा उसी भाषा में उसका जवाब भी जाएगा। लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि इस चीज को लागू किया जाए। मैं चाहता हूं कि केन्द्र के पास अगर हिन्दी में या किसी अन्य भारतीय भाषा में या अंग्रेजी में पत्र आता है तो उस पत्र का उत्तर उसी भाषा में उनके पास पहुंचना चाहिये। इस चीज को साफ कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तब किसी के दिल में जरा भी शक नहीं रह जाएगा कि उस पर कोई भाषा थोपी जा रही है।

यह जो रेजोल्यूशन है इस में कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमिशन की जो परीक्षाएं होती हैं उन में हिन्दी का ज्ञान रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यह कह कर अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं कहना गलत होगा।

हिन्दी को लाने के लिए छोटे-मोटे इधर-उधर जो संशोधन करने की आवश्यकता है उन के बारे में हम बैठ कर सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो विधेयक है इसको सब मंजूर करें। यह कहा गया है कि एक नैशनल कंसैंसस के आधार पर इसको तैयार किया गया है। मैं कहूंगा कि इसको हम अमल में लाएं। अगर अमल में लाते वक्त कोई दिक्कत दिखाई दी तो हाउस सुप्रीम है और वह फिर से इसमें संशोधन कर सकता है। पहले भी हम कर चुके हैं और बाद में 1968 में या 1969 में अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर भी हम संशोधन कर सकते हैं, फिर भी हम इसको एमेंड कर सकते हैं। अगर हिन्दी को बढ़ाने के रास्ते में मुश्किलात पेश आती हैं और उसके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा-भाषियों को या अहिन्दी भाषा-भाषियों को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम फिर इस में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो देश की हालत है और जिस तरह से भांति-भांति की मनोभावना बनी है, मनोवृत्ति बनी है और जिस तरह से झगड़े पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से टैंशन पैदा हो रहा है और लगता है कि हिन्दुस्तान जैसे टुकड़े-टुकड़े होने वाला है, इसको अगर रोकना है तो मैं निवेदन

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

करूंगा कि अभी हम इस विधेयक को मंजूर कर लें और इसको आगे बढ़ाने में हम सब मदद दें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सभापति महोदय, सदन में कुछ समय पहले जिस तरह का तनाव का वातावरण हो गया था उसमें श्री द्विवेदी जी के भाषण ने मरहम का काम किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देती हूं। कुछ लोगों की जुबान के कोड़े से हिन्दुस्तान की पीठ छीली जा रही थी और द्विवेदी जी ने मरहम लगा कर उस घाव को ठंडा करने की कोशिश की है।

यहां पर आध घंटा पहले कुछ लोगों ने जो वातावरण बनाया चाहे वे हिन्दी भाषी हों और चाहे अहिन्दी भाषी, मैं कहना चाहती हूं कि उन लोगों ने देश के साथ बड़ा अन्याय किया। इसको देख कर मुझे यह शेर याद आया और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि होश में भी हैं या नहीं।

जनू का दौर है किस-किस को जायें समझाने,
इधर भी अक्ल के दुश्मन, उधर भी दीवाने।

आखिर किया क्या जाए? लोगों को समझना चाहिये कि एक शब्द जो तीर की तरह जबान से निकल जाता है तो फिर वह लौट कर जबान पर नहीं आता है और न जानें कहां-कहां कितने गहरे घाव करता है। जब उनकी समझ में नहीं आता है यह तो मैं उनके लिए क्या कहूं। क्या मैं यह कहूं कि उनको पागलपन का दौर है। श्री श्रीकंठन नायर साहब ने क्या.....

एक माननीय सदस्य : दौड़ या दौर।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दौर।

एक माननीय सदस्य : हमने समझा था दौड़।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे दुख हुआ उस सब पर जो कुछ श्री श्रीकंठन नायर जी ने और श्री कछवाय जी ने किया। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये थी। हिन्दी को अगर गाली दी जाती है तो यही नहीं कि यह उचित नहीं है बल्कि आप यह भी देखें कि इससे देश में इस प्रकार की हवा बनेगी कि जिस की कोई दवा नहीं होगी। साथ-साथ आप यह भी देखें कि अगर अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के मन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पैदा होते हैं और वे समझते हैं कि हम उनकी बात की कद्र नहीं करते हैं तो जो नुक्सान इससे पहुंचता है, उसकी भी कोई दवा नहीं हो सकेगी।

हम जब बच्चे थे तो इसी संसद् की उन दिनों की याद आज भी हमारे दिलों में ताजा है। यहां की एक-एक आवाज को सुन कर देश उठ पड़ता था और जाग जाता था। उस समय हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वह जंग हमने इसलिए नहीं लड़ी कि बिहार या उत्तर प्रदेश में आजादी आएगी और देश के दूसरे भागों में आजादी नहीं आएगी। इसलिए वह जंग हमने लड़ी कि देश के कोने-कोने में आजादी आएगी, हम सब लोगों ने खून-पसीना बहाया था इसलिए कि हमारा देश आजाद हो। उस वक्त हम सब ने साथ जीने की और साथ मरने की कसम खाई थी।

उन दिनों की बात को सोच कर ऐसा लगता है जो कि संसद् एक आवाज पर सारे देश को जगा सकता था वही संसद् आज एक आवाज बन कर देश में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम इस बात को माने कि हम जो यहां बैठ कर बात करते हैं, हम लाखों-लाखों आदमियों की जबान और लाखों-लाखों आदमियों के कान और आंख से हम बात करते हैं। चाहे हिन्दी भाषी हों या अहिन्दी भाषी। हम इस को महसूस करें कि कहीं की भी कोई ऐसी चीज न हो जिससे हिन्दुस्तान की एकता भंग हो, हिन्दुस्तान की एकता को हम किसी तरह से खंडित करने में सहायक हों। और यही काफी नहीं है कि हम इस चीज को अपने मुंह से कहें। हमें चाहिए कि हमारे दिलों की धड़कनें भी इस बात को महसूस करें।

अगर आज दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या उत्तरी भारत का एक कोना भी खंडित होता है तो हमारी पार्टी के लोग खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेफा और लद्दाख में जो कुछ हुआ, बिहार का आदमी शायद न गया होगा वहां, परंतु जब उन इलाकों को अलग करने की कोशिश हुई उससे हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। अगर कोई हिन्दुस्तान के सुनहरे नाम पर धब्बा भी लगाने की कोशिश करता है, कारण चाहे जो हो तो, हम सब एक हो कर उसका मुकाबला करते हैं। कौन दावा कर सकता है कि वह हिन्दुस्तान से अलग हो कर कहेगा। मैं समझती हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास हिन्दुस्तान की यथार्थता, हिन्दुस्तान की जमीन कभी हिन्दुस्तान का आसमान अलगाव, नहीं मांगेगा और न वह इसको बरदाश्त करेगा।

इस बात को मैं मानती हूं कि हिन्दी मेरी मातृभाषा है। लेकिन किन लोगों ने इस को राज भाषा माना है और किन लोगों ने इस को राज भाषा का पद दिया है? क्यों हमारे ऊपर आप इस बात की तोहमत लगाते हैं कि हम ने इसको राज भाषा बनाया है। अहिन्दी भाषियों ने ही तो इसको राज भाषा के रूप में माना है। हम यहां उस समय कहां थे इस संसद् में। हमारे बच्चे कहां थे संसद् में और पार्लिमेंट में जब आपने राज भाषा हिन्दी को माना था? क्या आपने हमारे कंधों पर हिन्दी को राज भाषा का स्थान दिलाने की जिम्मेदारी नहीं डाली थी, अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली थी? जब हम सब के कंधों पर बराबर का बोझ डाला गया है तो ये कंधे कह सकते हैं कि हिन्दी को राज भाषा बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ हिन्दी वालों की है और अहिन्दी भाषा-भाषियों की नहीं है? आज यह कहना कि हिन्दी गलत भाषा है, आज यह कहना कि हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है, आज यह कहना कि हिन्दी कुछ नहीं है, यह अपने प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, राज भाषा के प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, अपनी उस संविधान सभा के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, जिस संविधान सभा में आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने, अहिन्दी भाषा भाषी लोगों ने हमारे लिए यह तोहफा दिया था और इस तोहफे को वे हमारी झोली में दे कर चले गय थे। हमारी गोदी में आज हिन्दी आई है तो क्या हम इसको जबर्दस्ती ले आए हैं? हमारी गोदी में हिन्दी आई है इसलिए कि अहिन्दी भाषी लीगों ने उस हिन्दी का नाम लिया और उसको राजभाषा बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाज उस समय नहीं गूजती थी। आवाज गूंजती थी तो केरल की, मद्रास की, आंध्र की, और जैसा कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने उस दिन हमारी सभा में कहा था कि खादी और हिन्दी देश की स्वतन्त्रता की एक अनुभूत बन गए थे, देश की स्वतन्त्रता में ऐसे लिपट गये थे कि हम जब खादी की आवाज उठाते थे तो देश की स्वतन्त्रता की दुंदुबी बज जाती थी, जब हिन्दी की आवाज उठाते थे तो हर जगह जनता के हाथ उठ जाते थे, देश की आजादी के लिए। गांधी जी ने इस भाषा के लिए जो एक सद्भाव पैदा किया था उस सद्भाव के में जबर्दस्ती वाली कोई बात नहीं थी बल्कि आप लोगों का अपना प्यार था, अपना स्नेह था। आज भी यह हिन्दी वही हिन्दी है। इस वास्ते अगर कुछ लोग इस बात की तोहमत लगाते हैं, अगर आज कुछ लोग इस तरह से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हिन्दी अहिन्दी भाषी लीगों पर हम लादना चाहते हैं तो इस बात को मैं बिल्कुल निरर्थक समझती हूं। परन्तु मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। और कोई कह दे कि हमारी नाक नहीं है तो हम पहले अपनी नाक को देखें या दूसरों की बात को मान कर इस बात का फैसला कर लेंगे कि हमारे मुंह पर हमारी नाक नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि हम हिन्दी को लादना चाहते हैं, तो अहिन्दी-भाषी राज्यों ने इस बात को क्यों मान लिया, यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा कि जब हिन्दी आई थी, तो उस को लाने वाले वे थे, हम नहीं।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

हिन्दी को वे लाए थे और हम ने उनका साथ दिया था और इस प्रकार हिन्दी को यह स्थान दिया गया । कब किसी ने कहा है कि हिन्दी बहुत बड़ी है ? कब किसी ने कहा है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय भाषाओं में सिर्फ हिन्दी ही इस स्थान के लिए दावा कर सकती है, और भाषाएं नहीं ?

हिन्दुस्तान के बारे में सोचने वाले लोग उन दिनों को याद रखें, जबकि हजारों बरस पहले ये भाषाएं भी नहीं थीं, रेलगाड़ियां नहीं थीं और आने-जाने के रास्ते नहीं थे । तब भी अगर बिहार का एक आदमी सेतु-रामेश्वरम् में पूजा कर के आता था, तो बिहार के गांवों में उस की पूजा होती थी, उसका चरणामृत लिया जाता था । हिन्दू शास्त्र के अनुसार चार धामों की जो इतनी महिमा थी, उस का कोई और मतलब नहीं था, उस का मतलब सिर्फ यह था कि हिन्दुस्तान की संस्कृति के जरिये हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांध कर रखा जाये ।

वे चार धाम कहां-कहां थे : पूर्व में वैद्यनाथ था जहां बंगला बोली जाती थी । पश्चिम में द्वारिका था, जहां गुजराती बोली जाती थी । दक्षिण में सेतु रामेश्वरम् था, जहां तामिल बोली जाती थी और उत्तर में बदरीनाथ था, जहां पहाड़ी भाषायें और संस्कृत बोली जाती थी । इन चारों धामों की यात्रा करने वाला आदमी देवता-तुल्य हो जाता था और लोग उस के चरण धो कर उस की पूजा करते थे । उस समय हिन्दुस्तान को एक-सूत्र में बांधने के लिए न तो यह संविधान था और न ही यह पार्लियामेंट थी । वह हमारे राष्ट्र की संस्कृति, उस की एकता, यहां के लोगों का परस्पर प्यार और स्नेह था, जिस ने शंकराचार्य बुद्ध और महावीर को पैदा किया । वह थी हमारी असलियत, जिस को आज हम सब भूलते जा रहे हैं ।

कुछ लोग हिन्दुस्तान से अलग होने की बात करते हैं । वे कहां जा कर रहेंगे हिन्दुस्तान से अलग होकर ? हिन्दुस्तान के सब लोगों को सोचना चाहिए कि वे इसी मिट्टी और इसी जमीन पर घर बना सकते हैं, यहां ही अपनेपन की बात पैदा कर सकते हैं और यहां ही अपने कहला सकते हैं । उन को और कहां चिराग ले कर ढूंढ़ने पर भीपनाह नहीं मिलेगी और वे तरसते-तरसते लौट कर फिर इसी ठिकाने पर चले आयेंगे । कौन है जो हिन्दुस्तान को खंडित करने की बात करता है ? हिन्दुस्तान को न तो भाषा खंडित कर सकती है और ऐसी पार्टियां कर सकेंगी, जिस के नुमायन्दे बनकर श्री श्रीकान्तन नायर आए हैं और न वे कर सकेंगे, जिन की नुमायंदगी डी० एम० के० वाले कर रहे हैं ।

मैं इस संसद् में 1952 से आई हूं । डी० एम०के० आज हिन्दुस्तान की एकता की बात करता है । मैं उन के जीवन का पहला पन्ना खोल कर दिखाना चाहती हूं । उन्होंने कहा था कि हम हिन्दुस्तान से अलग हो जायेंगे । जिस मुंह से यह बात निकली थी, उस मुंह से आज हिन्दुस्तान की एकता की बात सुन कर मुझे यह महसूस होने लगा कि अगर कोई दिन भर का भूला-भटका आदमी शाम को घर चला जाता है, तो हमें उस को भूला-भटका नहीं कहना चाहिए । हम माफ कर देने के लिए तैयार हैं उन लोगों की उस भावना को, कि हम अपने को हिन्दुस्तान के अलग करना चाहते हैं—जिस को उन्होंने बरसों तक अपनी विचार-धारा के रूप में अपनाये रखा । लेकिन आज वे एकता की बात कर के हम को सबक देने की कोशिश न करें । एकता की भावना को हम ने उस समय देखा था, जब कि राजाजी के नेतृत्व में 1937 में मद्रास की विधान सभा ने हिन्दी के बारे में प्रस्ताव पास किया था । मद्रास को हम ने उस समय भी देखा था, मद्रास हमारे जीवन का हिस्सा है । किसने इन लोगों को हक दिया है कि ये मद्रास को अपनी थाती बना लें । पूरा हिन्दुस्तान हमारी थाती है, केवल बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं । मद्रास और आन्ध्र प्रदेश पर हमारा भी उतना ही हक है, जितना कि वहां के लोगों का हो सकता है । उसी तरह

डी०एम०के० के सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि देश का एक हिस्सा होने के नाते बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी उन का उतना ही हक है, जितना कि उन का अपनी जमीन और आस्मान पर हक है।

इसलिए इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहती हूं कि हम हिन्दी को लादना चाहते हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कुछ बातों के साथ मैं इस का समर्थन करना चाहती हूं। हम ने हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया और उस को उस स्थान से हटाने का किसी का इरादा नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो प्रदेश हिन्दी में काम करना चाहें, चाहे वह उनकी मातृभाषा हो या न हो,—शायद आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम ने भी यह फैसला किया है कि वे हिन्दी में अपने सब कामों को करने की कोशिश करेंगे—उन पर अंग्रेजी न लादी जाये।

मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि एक महाराष्ट्रियन होते हुये भी तिलक ने गीता का जो भाष्य लिखा था, उतना अच्छा भाष्य हिन्दी के किसी भाष्यकार या टीकाकार ने भी नहीं लिखा। उस किताब को केवल हिन्दी वाले ही नहीं, बल्कि अहिन्दी-भाषी भी पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दी-भाषी लोगों में ऐसे लोग पैदा हों, जो हमारे साहित्य में एकता लायें। हम यह भी चाहते हैं तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाओं के अच्छे शब्द हिन्दी में समाविष्ट हों और हिन्दी में उन का प्रयोग हो। अगर हमारे देश की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषायें हम पर लादी जायें, तो हम उस को सिर आंखों पर बिठाएंगे। अहिन्दी-भाषी लोग अपने आप को हम पर लादें, हम उन को कलेजे से लगा कर रखेंगे। परन्तु अंग्रेजी को हम पर लादने की कोशिश न की जाए। मैं कहना चाहती हूं कि अंग्रेजी हमारे लिए ऐसी चीज हो गई थी जिस के खिलाफ हमने आन्दोलन किया। अंग्रेज और अंग्रेजी में हम ने कोई फर्क नहीं किया। इसलिए अंग्रेजी कभी भी हमारी अपनी भाषा नहीं बनी और न कभी बनेंगी। जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, जब अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी को उन लोगों पर न लादा जाए, जिन्हों ने हिन्दी में अपना काम करने का निश्चय किया है।

माननीय सदस्य यह भी मानें कि इस बिल की ताईद करने से पहले हम ने उन लोगों की बड़ी मिन्नत की है, जो काफी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, कहते हैं कि किसी को वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए। मैं उन से भी मिन्नत कर के कहना चाहती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम को यह कोशिश करनी चाहिए कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों पर हिन्दी भी लादने की कोशिश न की जाए।

श्री मधु लिमये : कौन कर रहा है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इसलिए मैं श्री द्विवेदी की इस बात की ताईद करती हूं कि हम को अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के लिए पांच या दस बरस का समय निर्धारित करने की बात यहां नहीं लानी चाहिए। परन्तु यह भी फैसला हो जाए कि हिन्दीभाषी प्रदेशों में अंग्रेजी में काम नहीं किया जाएगा। उस के बाद जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, हमें दो-तिहाई आदि की बात नहीं करनी चाहिए। हम उस को छोड़ देते हैं। किसी ने खूब कहा है, "न हंस कर सीखा है, न हम ने रो कर सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, किसी का हो कर सीखा है।" आज हम जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी पायेंगे, वह हम एक दूसरे के हो कर पाएंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ा कर या एक दूसरे के प्रति रोना रोकर नहीं पायेंगे। जिन लोगों को बिना बात, बिना मौसम, हंसी आती है, उन से मैं यह बात कहना चाहती हूं कि एक दूसरे पर हंस कर, मजाक उड़ा कर, रो कर और गाली दे कर अपनापन नहीं आने वाला है और नहीं आयेगा। अगर अपनेपन की

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

भावना लानी है, तो वह एक दूसरे का हो कर ही लानी होगी। इसलिए मैं श्री वाजपेयी, श्री मधु लिमये, कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों और डी० एम० के० के सदस्यों से अदब के साथ यह अपील करना चाहती हूं कि—"उन को आता है मेरे प्यार पर गुस्सा, हम को गुस्से पर प्यार आता है"—वे एकता की भावना के साथ और एकता की भाषा में बोलने की कोशिश करें। कम से कम मजाक न उड़ायें। कम से कम एक बात का तो फैसला कर लें कि हिन्दी की बात आए और हिन्दी के विरोध में कोई बात बोली जाए तो आप तालियां बजाना बन्द कर दें। आप ताली बजाते हैं तो लाखों और हजारों लोगों के कलेजे पर छुरी चलती है। इस बात का एहसास करें। एक बात का फैसला और आप करें। हिन्दुस्तान की एकता को कसम खाने वाले लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम से आप उम्मीद करते हैं कि हम आप के जख्मों पर मरहम लगाएं, हम आपको समझने की कोशिश करें तो मेहरबानी कर के हम को समझने की कोशिश कीजिए।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी जी ने दिए हैं और जो अमेंडमेंट्स सुचेता जी ने दिए हैं, उनका यही एक विचार है कि उस में यह साफ हो जाय कि अंग्रेजी-हिन्दी पर नहीं लादी जायगी और हिन्दी अहिन्दी-भाषियों पर तब तक नहीं लादी जाएगी जब तक वह न चाहें। इस की मान्यता सरकार को माननी चाहिए। इस के साथ-साथ मैं एक बात और भी कहती हूं उन लोगों के लिए जो आज इस बात को समझते नहीं हैं। हमारे बच्चे जो आन्दोलन कर रहे हैं शायद वह इस बात को नहीं समझते हैं अध्यक्ष महोदय। परन्तु मैं यहां पर एक बात आप के सामने रखना चाहती हूं। वह यह कि हमारे देश में हम ने मान्यता दे दी क्षेत्रीय भाषाओं को। तमिल मद्रास में पढ़ायी जाएगी। बिहार में हिन्दी पढ़ायी जाएगी। आन्ध्र में तेलुगू पढ़ायी जाएगी। पंजाब में पंजाबी पढ़ायी जाएगी। बंगाल में बंगाली पढ़ायी जाएगी। सारे हिन्दुस्तान की सीमाओं को हम ने एक माना है अपनी नौकरियों के लिए। मैं आप के सामने कहती हूं इस बात को, एक मद्रासी नवजवान अफसर या एक तेलुगू प्रदेश का अफसर हमारे बिहार में आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जातीयता, प्रान्तीयता आदि से ऊपर उठकर वह काम करता है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की एकता हमारे देश में आए। परन्तु मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जिन्हों ने इस बात को मान लिया कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, उस के बाद क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होने के बाद जब हम सीमा में बंध जाएंगे, जब तमिलनाड की भाषा तमिल होगी, तेलुगू प्रदेश की भाषा तेलुगू होगी, मैसूर की भाषा कन्नड़ होगी, पंजाब की भाषा पंजाबी होगी, तो कौनसी भाषा में तामिलनाड का आदमी महाराष्ट्र में जाएगा और महाराष्ट्र का आदमी बंगाल में जाएगा तो बात करेगा? कौन सी भाषा में बात करेगा? इस बात का मुझे जवाब दें?

SHRI NAMBIAR : We will learn Hindi when we go to Bengal but do not impose it on us.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं मानती हूं इस बात को। मैं भी सिर्फ यही चाहती हूं कि दस वर्षों के अन्दर आप इस बात को महसूस करें कि आपको करना है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूं, आप एक उदाहरण के लिए ले लें कि एक तामिलनाड के लड़के ने तामिल में शिक्षा पाई, हिन्दुस्तान की नौकरी में उसको चुन लिया गया और अखिल भारतीय सरकार का वह मुलाजिम हो गया। उसके बाद जो भी आल इंडिया सर्विसेज के लिए आए उससे कहा जाता है कि आप अपने प्रदेश में नही जाएंगे, आप दूसरे किस प्रदेश में

में जाना चाहते हैं लिख कर दे दीजिए। वह लड़का या लड़की लिख कर दे देते हैं कि हम इन प्रदेशों में जाएंगे। उस समय भी वही प्रथा रहेगी और हिन्दुस्तान को आप को एक में रखना है। तो जब उन प्रदेशों में वह लड़का या लड़की जाएगा, मान लीजिए मद्रास के किसी नवजवान लड़के ने यह कहा कि मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब वह महाराष्ट्र जाएगा तो उस के लिए जरूरी होगा या नहीं कि भाषा ऐसी जाने जिससे कि महाराष्ट्र के लोगों से आदान प्रदान कर सके। उस के बाद वह हो सकता है कि गुजरात जाए, बंगाल जाए। तो उस के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सीखना तो मुश्किल होगा। इसीलिए उस के लिए जरूरत इस बात की होगी कि एक ऐसी भाषा वह जाने जिससे वह कम से कम हिन्दुस्तान के हर कोने में उस को लोग समझ सकें और वह लोगों को समझ सके। और हिन्दी.....(**व्यवधान**).....यह आप के चाहने या न चाहने से नहीं, बल्कि यह सत्य है, यथार्थ है, इससे आप आंखें बन्द नहीं कर सकते कि हिन्दी जान कर कन्याकुमारी जा कर के भी लोगों को हम पाते हैं जिनसे बातचीत कर सकें। मैं तो अभी मद्रास गई पब्लिक एकाउंटस कमेटी की मीटिंग थी। मद्रास के गेस्ट हाउस का जो बेयरा था मैं उससे अंग्रेजी में बात करूं वह हिन्दी में जवाब दे। मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि भइया, मैं तो समझती थी कि तुम हिन्दी नहीं जानते, पर तुम तो इतनी अच्छी हिन्दी बोलने लगे तो मैं तो हिन्दी में ही तुम्हारे साथ बात करूंगी। अभी भी डी०एम०के० के लोग हमें हमेशा कहते हैं कि तारकेश्वरी जी, हिन्दी में बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। तो ऐसी बात तो है न कि चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे हिमालय हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो चाहे महाराष्ट्र में सांगली हो, हिन्दी जानने वाला आदमी कहीं भी अपने को समझा सकता है और दूसरे की बातें समझ सकता है। इसलिए इस बात की जरूरत है.....

SHRI NAMBIAR : Go slow with Hindi.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परन्तु मैं नम्बियार साहब से यही कहना चाहती हूं कि कोट-पैंट पहन लेने के बाद और फाउंटेन पेन लगा लेनेके बाद इस बात का एहसास रखें कि आप के बच्चों को भी कोट-पैंट पहनने और फाउंटेन पेन लगाने की सुविधा हो जाये। मैं यही कहना चाहती हूं। यह लड़के तो तामिलनाड वालों ने कहा कि हम हिन्दी नहीं पढ़ायेंगे, मैं कहती हूं कि तामिलनाड ने अपने बच्चों के साथ अन्याय किया है। हिन्दी नहीं पढ़ायेंगे तो जायेंगे कहां ?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : Don't bother about that. We know how to protect our children.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जरूर बादर करेंगे। जरूर कहेंगे क्योंकि मद्रास हमारे देश का हिस्सा है। आप को नहीं जरूरत है लेकिन देश ने आप को वकालत नहीं करने को कहा है मद्रास की। मद्रास की वकालत हम को भी करने को कहा है। इस बात की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप न बात कीजिये और आप नहीं चाहते हैं। लेकिन यह अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो मद्रास के बारे में बात कर सकते हैं तो यह बात नहीं है। हम लोगों को हक है सारे देश के बारे में बात करनें का। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि उन बच्चों के लिए इस बात का इन्तजाम कीजिये कि कम से कम वह हिन्दी पढ़ें, वह दूसरी भारतीय भाषा पढ़ें, मराठी पढ़ें, पंजाबी पढ़ें, गुजराती पढ़ें, बंगाली पढ़ें, तेलुगू पढ़ें, कन्नड़ पढ़ें, जिससे कि उन का रास्ता थोड़ा फैलाव का हो जाये, खुल जाय सारे हिन्दुस्तान में भ्रमण करने के लिए। उन को रेगिस्तान में मत चलाइए। वह बच्चे नासमझ हैं। उन बच्चों को समझाने की जरूरत है। परन्तु आप उन बच्चों के साथ इतने बच्चे न बन जाइए कि अपने को भी ले डूबिए और उन बच्चों को भी ले डूबिये।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए फिर से अपील कर के बैठती हूं कि यह सदन इस भाषा विधेयक को पास करेगा संशोधन के साथ जो संशोधन मुख्यत: इस बात

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

का है कि हिन्दी अहिन्दी-भाषी प्रान्तों पर नहीं लादी जायेगी और अंग्रेजी हिन्दी भाषी प्रान्तों पर नहीं लादी जायगी। इस संशोधन के साथ भाषा विधेयक पास हो। और एक खूबसूरती से, एकता की भावना से हम आठ दिन के बाद इस संसद भवन के बाहर निकलें तो हम हिन्दुस्तान की एकता के नाम पर सिर उठा कर चल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कह कर बैठना चाहती हूं कि हम एक हैं, एक हो कर रहेंगे। सिर्फ ऐसे लोगों को जरा समझा दीजिए कि उस एकता पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश न करें। अगर कुल्हाड़ी चलाने का ढंग नहीं आता हो तो कुल्हाड़ी हाथ में नहीं पकड़नी चाहिए। मैं इतना ही कह कर बैठती हूं।

SHRI R. R. SINGH DEO (Bolangir): Mr. Chairman, Sir, even though the Official Language (Amendment) Bill, 1967 is not what I should have wished it to be I intend to support it.

The purpose of the Bill is very clearly mentioned in the Statement of Objects and Reasons. It is in accordance with the assurances given by the Prime Ministers from time to time that Hindi will not be imposed on any non-Hindi speaking State which is not prepared to accept it. I appreciate this stand fully because in a federal democratic country like India, we have to take the views of every State into consideration and nothing can be imposed against the will of the people, and more so a language.

A great amount of heat is generated by the Hindi protagonists about this Bill. They forget the basic fact that over-enthusiasm and over-doing are very often misunderstood and, therefore, resented. Even a just cause might evoke resentment if it is overdone. Their love for their mother-tongue is perfectly justified....

श्री रामसेवक यादव : यह उच्चारण ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय।

SHRI R. R. SINGH DEO: You keep quiet. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: Don't interrupt him.

SHRI R. R. SINGH DEO: But their mother-tongue is not the mother-tongue of everybody in India. If that was so there would have been no problem. But India being a multi-lingual country, the lovers of Hindi must learn to respect the other people's mother-tongue. Hindi has already got the official recognition and to that extent they must feel happy. No other language has received so much official patronage and till now, the other languages have developed on their own.

There is an opinion expressed now to do away with English. It seems that those who say this cannot see the realities. If every State develops its own language, how would they communicate with their neighbours? No State would understand the other and it would lead to utter confusion. We must develop a common link before such a step could be taken. Do they want the Indians to become foreigners in their own country?

At a time when each Indian should strive for national integration, regionalism and unhealthy attempts to impose Hindi would be a great blow. We have provincialism, casteism, and communalism, which have hindered the progress of national integration substantially. If we add to all these another disturbing element known as linguism, it would lead to further weakening of national integration. Country comes above everything else. No sacrifice is great enough for the preservation of the country. We had an unfortunate Partition for political reasons. Having become wiser after that Partition, nothing should be done to further weaken India.

Hindi protagonists do not know the feelings of the non-Hindi-speaking States. They are all mobilising public opinion in Hindi-speaking States only where it is easy to gather support on a popular issue like this. If they are so confident about their cause, why do they not go to the non-Hindi-speaking States to popularise Hindi? If they succeed in convincing the non-Hindi-speaking States that the panacea is the acceptance of Hindi by them and if they accept it, the problem would be solved. But instead of that, mobilising public opinion in a place which gets benefited, only isolates the area from others and does no good to it.

I know of certain areas in Bihar where linguistic minorities are forced to learn Hindi. Even the minimum concessions provided in the Constitution are not made available to them. There is a systematic and regular attempt to abolish the Oriya language, culture and tradition from that area by the use of all official machinery and when that does not yield results, schools are closed, Oriya teachers are re-trenched and even hooliganism is used to intimidate the Oriya-speaking population to learn Hindi. But is that possible all over India ?

Political parties are trying to draw their strength from this means. It is a wrong move for any political party to gain strength by weakening India. Sir, if India lives, they live. Therefore, they would be well advised not to try to play up people's sentiments for partisan ends at the risk of the disintegration of the country.

16.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The Bill offers all facilities to Hindi for those who accept it. In fact it has a better status than English. Time is given to lovers of Hindi to convince more and more people to accept it and until it is accepted, use of English is permitted. Therefore, there is nothing wrong in allowing more time for persuasion.

I do not want to repeat whatever has been said about English before, but the point which needs reiteration is that English is the international language, understood all over, developed in literature, science and technology. Those of them who are educated in English can make the best use of it. Sir, world has become much smaller after scientific advancement and we can now cover months' distance in hours. So, what is the idea in trying to insulate ourselves in the world which is growing smaller and smaller, by refusing an advantage we enjoy ?

Hindi language needs a lot of development to come to the level of languages like Bengali and Tamil. Even with spoon-feeding by this Government that has not been achieved. Original literature in Hindi is still lacking. Efforts must be made by Hindi writers to make the Hindi language more attractive. I know of people learning Bengali just to read Rabindranath in original, not because Bengali is a national language. So it is the quality of literature which attracts people of other languages to it.

In conclusion, Sir, I would appeal that no attempt should be made to oppose this Bill, which gives only the minimum facilities to non-Hindi speaking areas. The tolerance shown by non-Hindi speaking States should be appreciated by the Hindi-speaking States. According to the three-language formula, non-Hindi States seriously and sincerely started learning Hindi, but it is a matter of great regret that no South Indian language could make any headway in the north. Sir, unless the people of the north follow the maxim of give-and-take, they should not expect the same from others.

SHRI NAMBIAR : We will start Tamil classes for M.Ps. here.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : We have already started Tamil classes in U.P.

SHR R. R. SINGH DEO : In the end I would again appeal to the Hindi lovers to make our country their first love and then their language.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री द्विवेदी तथा माननीय सदस्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का आदर करता हूं और उन का समर्थन करता हूं ।

श्रीमन्, आज हमारे देश में सब से बड़ी जरूरत राष्ट्रीय एकता की है, मैं राष्ट्रीय एकता को सब से अधिक महत्व देता हूं । आखिर भाषा हमें किस लिये चाहिये, हमें हिन्दी चाहिए राष्ट्र की एकता के लिये, लेकिन यदि हम ने भाषा के प्रश्न को लेकर राष्ट्र की एकता को कमजोर किया तो न हम राष्ट्र की सेवा करेंगे न भाषा की सेवा करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजों की गुलामी फिर से मंजूर कर लो ।

श्री अमृत नाहाटा : अगर इसी आजादी से देश के टुकड़े होते हों तो मैं निश्चय ही

[श्री अमृत नाहाटा]

गुलामी पसन्द करूंगा बनिस्बत इसके कि देश के टुकड़े हो जायें... (**व्यवधान**)।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज प्रश्न हिन्दी का है, राजभाषा का है लेकिन मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर क्या करेंगे ? कौन से राष्ट्र की भाषा हम बोलेंगे ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न अंग्रेजी के हटाने का है हिन्दी लाने का नहीं है।

17 hrs.

श्री अमृत नाहाटा : यहां मैं उस के साथ सहमत हूं।

एक माननीय सदस्य : आप राष्ट्र के माने समझते हैं ? राष्ट्र के माने कांग्रेस नहीं है।

श्री अमृत नाहाटा : मैं राष्ट्र के माने आप से अधिक समझता हूं बाक़ी मैं इस समय उलझना नहीं चाहता।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भाषा के प्रश्न को लेकर जिस प्रकार की हिंसा, जिस प्रकार की भावनाओं को उभारने का, जिस प्रकार के उद्वेगों को उद्वेलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है मैं इन के साथ अपने आप को सहमत होता हुआ नहीं पाता हूं। गैल्सवर्थी ने अपने 'लायलटीज' नामक नाटक में एक जगह लिखा है :

"People take sides quite outside the issue."

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि आज उत्तर-प्रदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में या आगरे में जो विद्यार्थी आज फरनीचर तोड़ रहे हैं, या कांच तोड़ रहे हैं या आग लगा रहे हैं वह अनुचित व गलत काम कर रहे हैं और देश की एकता के लिए वह नुक्सानदेह बात है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन को गलत तरीक़े से भड़काया गया है और इस बिल के विरुद्ध उन में भ्रामक प्रचार किया गया है, सही तौर से इस बिल के बारे में विद्यार्थियों को बताया नहीं गया है। केवल उन की भावनाओं को उभारने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार से अंग्रेजी लादी जा रही है और हिन्दी को खत्म किया जा रहा है। इस प्रकार का ग़लत प्रतिनिधित्व करके गलत किस्म के भावनाओं को उभार कर हम हिन्दी की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में लोगों को चाहे वह जयपुर के हों, चाहे जोधपुर के हों और चाहे वे जैसलमेर के हों उन के दिलों में हिन्दी के लिए वही प्यार है, हिन्दी के लिए वही उत्साह है जैसे कि अन्य हिन्दी भाषा भाषी लोगों के दिलों में है। हिन्दी को वह अपनी राजभाषा मानते हैं। वह चाहते हैं कि हिन्दी समूचे देश की भाषा हो और सारे देश में हिन्दी बोली जाये लेकिन यदि कोई दल वहां ग़लत तरीक़े से प्रचार करके उन को भड़काने की कोशिश करेंगे तो हम उन के सामने सीना तान कर खड़े हो जायेंगे।

मेरा यह मत है कि जो बिल और प्रस्ताव आज सदन के सामने आया है वह हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए है, हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए है, हिन्दी की वह सेवा करने के लिए है न कि हिन्दी के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए है। मैं उन का सामना करने को तैयार हूं मैं उन्हें समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि वह इस बात को मानेंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जब हम इतनी गम्भीर समस्या पर विचार करते हैं तो ज़रा संयम से, ज़रा संजीदगी से और ज़रा भावनाओं से ऊपर उठ कर इस विधेयक और इस प्रस्ताव को बहुत ही औबजैक्टिव ढंग से देखें कि आया वह आज की परिस्थिति में हमारी आशाओं की पूर्ति करता है अथवा नहीं करता है ? इसी दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं।

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जो त्रिभाषी फारमूला बनाया गया वह बहुत ही संजीदगी से, बहुत गम्भीर विचार विमर्श

करने के बाद और बहुत दृढ़ता के साथ बनाया गया और मैं उस का तहेदिल से समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही मेरी निश्चित मान्यता है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इस त्रिभाषी फारमूले को अपनाने के बाद ईमानदारी से, दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ इस त्रिभाषी फारमूले को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। मुश्किल यही है कि जब कुछ सही निश्चय लिया जाता है और जब उस सही निश्चय को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो तरह तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, तरह तरह की गलतफहमियां उठ खड़ी होती हैं और फिर हम उन में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन यह केवल त्रिभाषी फारमूले की ही बात नहीं है हमारी सरकार के बारे में अक्सर यह राय है कि वह बहुत अच्छी नीतियां निर्धारित करती है, बहुत अच्छा फारमूला निर्धारित करती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाती है लेकिन उनका क्रियान्वन नहीं होता। यह कम से कम जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है, जो विधेयक हमारे सामने आया है एक आशा बंधती है कि भविष्य में कम से कम बहुत दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ इस त्रिभाषी फारमूले पर अमल किया जायगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं अभी दो महीने पहले करीब करीब देश के सभी राज्यों का दौरा करके आया हूं और मुझे इस बात की खुशी हुई यह देख कर कि तामिलनाड में, मैसूर में, आंध्र में बड़ी तेजी के साथ विद्यार्थी लोग हिन्दी सीख रहे हैं। आंध्र और मैसूर में मिडिल स्कूलों तक हिन्दी विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। वह हिन्दी पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस है और मैं शर्म से अपना माथा झुकाता हूं यह देख कर कि हमारे जो हिन्दी समर्थक लोग हैं, जो हिन्दी भाषा भाषी लोग हैं और जोकि हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाना चाहते हैं उन्होंने हिन्दी के प्रचार के लिए, हिन्दी के सृजन के लिए और हिन्दी के विकास के लिए उतना कार्य नहीं किया है जितना कि करना चाहिए था। केवल राजनीतिक प्रश्न बना कर हम ने हिन्दी को देश के सामने रक्खा। इसी के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह निश्चित बात है कि हम ने किसी भी दक्षिण भारत की भाषा को उतना सम्मान और प्यार नहीं दिया जितना कि हमें देना चाहिए था। आज मैं मानता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राजस्थान में दक्षिण भारत की किसी भी भाषा को प्रोत्साहन दिया होता, हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया होता तो आज दक्षिण के लोग बड़ी खुशी से हिन्दी को अपनाते और हिन्दी के प्रयोग का कोई विरोध नहीं होता। दक्षिण के लोगों की भी मेरी समझ में यह गलती है कि जो वह ऐसा समझते हैं मानों हिन्दी कोई पराई भाषा हो और वह हिन्दी के मुकाबले में अंग्रेजी को अपना लेते हैं और हिन्दी को वह पराई भाषा मानते हैं। जहां दक्षिण भारत के लोगों की यह गलती है वहां हम भी इस अपराध से बरी नहीं हो सकते कि हम ने भी दक्षिण के लोगों को यह प्यार नहीं दिया, वह बंधुत्व नहीं दिया। उन के दिलों में यह विश्वास नहीं बैठाया कि हम भी उन की भाषाओं का उतना ही आदर करते हैं जितना कि हम अपनी भाषा के लिए उन के आदर की अपेक्षा करते हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि भविष्य में कम से कम सरकार की ओर से, हम सभी हिन्दी भाषा भाषी लोगों की ओर से बराबर इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि हम त्रिभाषी फारमूले को बहुत ईमानदारी के साथ और सही मायनों में कार्यान्वित करें ताकि हम जल्दी ही इस सारे देश में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिला सकें।

इस त्रिभाषी फारमूले का अर्थ क्या था वह मैं जरा स्पष्ट करना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह मंशा कभी नहीं थी कि त्रिभाषी फारमूले के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए अनन्त काल तक के लिए अंग्रेजी को हिन्दु-

[श्री अमृत नाहाटा]

स्तान के अन्दर रहने दिया जाय । मैं जहां तक इस त्रिभाषी फारमूले का अर्थ समझा हूं और जिसको काफ़ी हद तक हमारे इस विधेयक में और इस प्रस्ताव में प्रतिबिम्बित किया गया है और वह यह है कि अंग्रेजी को शनैः शनैः रोकना क्यों जरूरी है ? मैं उसे इस प्रकार समझता हूं कि एक स्थिति है जिसमें अंग्रेजी हमारे देश में छाई हुई है एक ऐसी स्थिति थी जब हम ने त्रिभाषी फारमूला अपनाने की बात की थी उस समय यह स्थिति थी । हम इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जहां हम अंग्रेजी से हट कर हिन्दी पर आना चाहते हैं । यह संक्रमण काल जो होगा यह एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता । यह समय की सीमा बांध कर भी नहीं हो सकता । इंग्लैण्ड में अंग्रेजी भाषा कैसे प्रभुत्व में आई ? कहां पर अंग्रेजी को युनिवरसिटी में मान्यता प्राप्त करने के लिए 600 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था । इसलिए अगर आप यह समझें कि एक दिन में या एक सप्ताह में या एक साल में यह संक्रमण काल समाप्त हो जायगा और अंग्रेजी देश से चली जायगी और उस का स्थान हिन्दी ग्रहण कर लेगी तो यह सम्भव नहीं है । अब वह संक्रमण काल कितना हो हम कोशिश कर रहे हैं कि वह कम से कम हो, 5 साल हो, 4 साल हो, 2 साल हो, हमें उसे यथासम्भव कम करने के लिए प्रयत्न करना है और उस में हमें अंग्रेजी को अपदस्थ करना है और उस के स्थान पर हिन्दी को आसीन करना है । उस संक्रमण काल के लिए त्रिभाषी फारमूला हम ने अख्तयार किया है जिसका कि अर्थ यह है कि शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर ले । शनैः शनैः हम एक ऐसी स्थिति में आयें कि जब हम हिन्दी को सारे देश में राजभाषा बना सकें और अंग्रेजी को वह स्थान न रहे जोकि इस देश में उसे प्राप्त रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह दृष्टिकोण हमारे सामने है, यदि यह दिशा हमारे सामने है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और हमें भले ही धीरे धीरे क्यों न हो लेकिन निश्चित रूप से उस के लिए प्रयत्न करना है तो हमें अवश्य अपने उद्देश्य में कामयाबी मिलेगी । यह तो ठीक है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और एकदम से हिन्दी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती लेकिन इसके साथ साथ यह तय हो जाना चाहिए कि हमें निश्चित रूप से हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर बिठाना है भले ही यह कल हो, पांच वर्ष बाद हो, 10 वर्ष बाद हो, भले ही 50 वर्ष बाद क्यों न हो हम उस समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं लेकिन यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक न एक दिन अन्ततोगत्वा हिन्दी इस समूचे राष्ट्र की राजभाषा बनेगी और अंग्रेजी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा । दृष्टिकोण हमारा यह होना चाहिये, दिशा हमारी यह होनी चाहिए कि इस संक्रमण काल में हम शनैः शनैः इस दिशा की ओर अग्रसर हों ताकि अंग्रेजी को उसके वर्तमान स्थान से अपदस्थ करके हिन्दी को उसके स्थान पर आसीन कर सकें । उस दिशा की ओर अगर हमें बढ़ना है तो हमें इस संशोधन में और इस बिल में उस स्थिति को प्रतिबिम्बित करना होगा ।

चव्हाण साहब ने कहा है कि यह विधेयक और यह प्रस्ताव प्रतिबिम्बित करता है एक राष्ट्रीय कंसैंस को । एक बहुत ही नाजुक समझौते के आधार पर यह बना है । यदि हमें आज के संक्रमण काल की स्थिति में अभी समझौता करना है तो उस समझौते का केवल एक ही आधार हो सकता है और वह आधार यह हो सकता है कि अहिन्दी भाषी लोगों पर अगर हम हिन्दी न थोपें तो हिन्दी भाषी लोगों पर अंग्रेजी भी न थोपें । एक बार फिर मैं दौहराना चाहता हूं कि संक्रमण काल की दिशा यह होनी चाहिए कि शनैः शनैः अंग्रेजी को अपदस्थ कर हिन्दी को हम पदासीन करने की कोशिश करें । यदि इस दिशा की ओर हमें जाना है और इस दिशा की ओर बराबर बढ़ते जाना है और इस संक्रमण काल में

समझौता करना है तो समझौते का एक मात्र यही आधार हो सकता है कि हम दक्षिण के लोगों पर, अहिन्दी भाषा भाषी लोगों पर हिन्दी न थोपें तो हिन्दी भाषी लोगों पर भी हम अंग्रेजी को न थोपें। आज जो यह सोचते हैं कि हम हिन्दी नहीं चाहते हैं और हम इस त्रिभाषा फार्मुले को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें यह मान कर चलना होगा कि आज नहीं तो कल हिन्दी लानी है और अंग्रेजी के स्थान को हमें हिन्दी को देना होगा और इसके लिए हम को यथोचित प्रयत्न भी करने होंगे। इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता है कि हमें इस बिल और इस संकल्प को इस समझौते का आधार मानना पड़ेगा, इस समझौते की बुनियाद मानना पड़ेगा।

यह कहा गया है कि इस विधेयक में एक राज्य तक को वीटो का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि वह चाहे तो हिन्दी को देश की राज भाषा बनने से रोक सकता है। अलग अलग इसके बारे में सुझाव दिए जाते हैं। कोई कहता है कि बहुमत के अहिन्दी राज्य, कोई कहता है कि दो तिहाई अहिन्दी राज्यों में से राज्य अगर हिन्दी को अपना लें तो फिर सारे राज्यों पर हिन्दी लागू कर दी जाए। मैं इस तरह के जो संशोधन हैं इनकी भावना का आदर करता हूं। लेकिन श्रीमन्, हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि अगर कुछ समय बाद देश के अधिकांश राज्य हिन्दी राज्य और अहिन्दी राज्य भी, हिन्दी को अपना लेते हैं तो क्या उस हालत में चाहे वह नागालैंड हो और चाहे मद्रास हो इस स्थिति में रह सकेगा कि वह हिन्दी को मानने से इन्कार करे ? कदापि नहीं रह सकेगा। उनको देश में प्रवाहित हो रही धारा के साथ चलना पड़ेगा और उनको भी हिन्दी माननी पड़ेगी। लेकिन आज अगर हम यह कहते हैं कि सब राज्यों के बजाय दो तिहाई या एक तिहाई राज्य भी जो आज हिन्दी का विरोध करते हैं, वे कल को विरोध करना बन्द कर दें तो हिन्दी को लागू कर दिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि उनके विरोध को हम और अधिक दृढ़ बनाते हैं, उनको और अधिक अपने से दूर हम फैंकते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक राज्य हिन्दी को अपना लें तो यह दृष्टिकोण हमारा सही है कि अपनी तरफ से हम कहें कि जब तक सारे के सारे अहिन्दी राज्य हिन्दी को नहीं अपना लेंगे तब तक अंग्रेजी भी हिन्दी के साथ साथ चलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह वीटो का अधिकार नहीं है। यह एक व्यावहारिक पक्ष है।

यदि हम इसको मानते हैं कि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है और अंग्रेजी को शनैः शनैः हटना है तो कुछ इस प्रकार की धारायें इस विधेयक में और इस प्रस्ताव में हैं कि जो इस समझौते के आधार के अनुरूप नहीं हैं, जो इस समझौते के आधार के प्रतिकूल हैं। जो इस त्रिभाषा फारमूले की भावना के प्रतिकूल हैं, जो दिशा आपके सामने मैंने रखी है उसके प्रतिकूल हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि यदि केन्द्रीय विभाग का एक हिस्सा हिन्दी में पत्र लिखेगा तो साथ में अंग्रेजी का अनुवाद भी नत्थी करना पड़ेगा, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उसको निरुत्साहित कर रहे हैं, उसके ऊपर अंग्रेजी की मुहर लगा रहे हैं। इस प्रकार आप वास्तव में जिस दिशा में हमें आना चाहिये उस दिशा में आने से रोक रहे हैं। उस दिशा की ओर अग्रसर आप नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जहां-जहां बन्धन हिन्दी के प्रयोग पर लगाये गये हैं, जो जो रुकावटें हिन्दी के प्रयोग पर डाली गई हैं उन रुकावटों को आप हटायें, अविच्छिन्न रूप से हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें ताकि जो हिन्दी में लिखना चाहें वे हिन्दी में लिख सकें और लोग मजबूर भी हों कि वे हिन्दी सीखें, हिन्दी पढ़ें। जो हिन्दी नहीं पढ़े हुए हैं उनको हिन्दी पढ़ने पर मजबूर भी तब आप कर सकते हैं।

[श्री अमृत नाहाटा]

जब तक हमारे देश की जनपदीय भाषाओं को, हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं को, हमारे देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को उनका पूरा तथा वांछित स्थान नहीं दिलायेंगे, उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक हम सही मानों में राष्ट्रीय एकता की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे । मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री को जिन्होंने यह निश्चय किया है कि हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा क्षेत्री भाषाओं के माध्यम से दी जाएंगी । इसके साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि यू० पी० एस० सी० के बारे में जो प्रस्ताव में कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें होंगी, उसके बारे में कोई निश्चित तिथि तय की जानी चाहिये । यह कह देना कि हम यू० पी० एस० सी० से सलाह करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, काफी नहीं है । मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं को यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं का माध्यम बनाने के लिए दो साल के भीतर भीतर अवधि निश्चित की जानी चाहिये और उसके बाद हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि यू० पी० एस० सी० में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षायें हो सकें । कहा जाता है कि इससे देश विच्छिन्न होगा । मेरी निश्चित मान्यता है कि एक रूपता एकता नहीं है और विविधता विच्छिन्नता नहीं है । जिस रोज हम क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलायेंगे स्वतः ही अंग्रेजी अपने वर्तमान स्थान से गिर जाएगी और इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि अंग्रेजी हटने के बाद उसका एक मात्र स्थान लेने वाली भाषा जो इस देश में है वह हिन्दी है । पिछले दरवाजे से लाने की यह बात नहीं है । असल बात यह है कि अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है, इस धरती में उसकी जड़ें नहीं हैं, यहां की जनता अंग्रेजी को अपनी भावनाओं के साथ एकरूप कर नहीं सकती है । इसलिए जो क्षेत्रीय भाषायें हैं, जो मातृभाषायें हैं उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको आप यू० पी० एस० सी० परीक्षाओं का माध्यम बनायें, विश्वविद्यालयों में उनको आप शिक्षा का माध्यम बनायें । अगर आपने ऐसा किया तो अपने आप हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा बन जाएगी । मैं चाहता हूं कि एक निश्चित अवधि इसके लिए तय कर दी जानी चाहिये, एक निश्चित तारीख तय कर दी जानी चाहिये, एक सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये कि जब यू० पी० एस० सी० परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाएगा ।

असल में सारे झगड़े की जड़ क्या है ? यहां कहा गया है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी परीक्षाओं के लिए । यह एक अजीब बात है । हिन्दी हमारे देश की राज भाषा है और हम कहते हैं कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी परीक्षाओं के लिए । यह बात किसी को मान्य नहीं हो सकती । अगर हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए तो हिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं हो सकती है । लेकिन यह झगड़ा होता क्यों है ? इसलिए होता है कि डर है दक्षिण भारत के लोगों को कि फिर उत्तर भारत वाले, जिन की हिन्दी मातृभाषा है, वे लोग सेवाओं में अधिक चले जायेंगे । आज हकीकत यह है कि क्योंकि सब से पहले अंग्रेजी भाषा को दक्षिण वालों ने अपनाया और क्योंकि अंग्रेजी भाषा को उन्होंने अपने गले का हार बनाया, इस वास्ते आज अंग्रेजी भाषा के बल पर ही वे आगे बढ़ गए हैं और केन्द्रीय सेवाओं में उनका आज बहुमत है, उनका आज प्रभुत्व है, उन पर वे छाए हुए हैं । जो दक्षिण भारत के लोगों को डर है कि हिन्दी आएगी तो उत्तर भारत वाले नौकरियों में छा जायेंगे और उत्तर भारत वाले सोचते हैं कि अंग्रेजी रहेगी तो दक्षिण भारत वाले छा जायेंगे तो इस डर को दूर करने के लिए इसका एक मात्र हल यह है कि चूंकि प्रतिभा का ठेका, प्रतिभा की बपौती, प्रतिभा की इजारेदारी किसी एक प्रान्त वालों की नहीं है, सभी प्रान्तों में लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं और उन्हें

अवसर मिलना चाहिये, इस वास्ते हर प्रान्त की जनसंख्या के अनुपात में सेवाओं में उन प्रान्तों के लोगों के लिए स्थान निश्चित कर दिये जायें, उन का कोटा निर्धारित कर दिया जाए। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाषा की बहुत सी गलतफहमी, बहुत से झगड़े खत्म हो जायेंगे और हम देखेंगे कि हर राज्य अपनी-अपनी भाषा में आगे बढ़ेगा और हिन्दी सभी राज्यों को मान्य हो जाएगी।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह दिशा निर्धारित कर लेनी चाहिये और इस दिशा की ओर हमें तेजी से बढ़ना चाहिए। त्रिभाषा फार्मुले को बहुत दृढ़ता के साथ लागू करते हुए हिन्दी को बहुत तेजी से बढ़ाते हुए हिन्दी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाते हुए, शनैः शनैः हम एक ऐसा वातावरण बनायें, एक ऐसा जल वायु देश में निर्मित करें कि जो हमारे सारे संशय हैं, सारे मतभेद हैं, सारी गलतफहमियां हैं, वे मिट सकें। भावनाओं से ऊपर उठ कर और बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत संजीदगी और संयम के साथ हम इन तमाम प्रश्नों पर विचार करें तो मुझे विश्वास है कि हम हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा करेंगे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएंगे।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : उपाध्यक्ष महोदय, समय मुकर्रर कर दीजिये ताकि हमें भी बोलने का अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सब को मौका मिलेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : बीस साल के बाद इस दिन में यह एक ऐसा विधेयक उपस्थित हुआ है जो मैं देश के लिए बड़ा भारी दुर्भाग्य समझता हूं। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, पढ़ाई मराठी में हुई है और बोलता मैं हिन्दी हूं। जिन्होंने संविधान बनाया उनके सामने भी एक कल्पना थी और इसलिए उन्होंने समय को बांधा था कि पंद्रह साल के अन्दर हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं ताकि देश में 26 जनवरी 1965 के पश्चात हिन्दी राज भाषा बन जाए। किन्तु आज पंद्रह साल के बाद फिर दुबारा यह विधेयक पेश किया गया है। इसके पहले भी एक बार इस विषय में एक कानून बना था लेकिन उस में भी कोई अवधि नहीं रखी गई थी। 1963 में जो एक संशोधन आया था, उस में भी अवधि का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि संविधान में पंद्रह साल की जो व्यवस्था की गई थी, उस का कोई एक अर्थ था।

स्वराज्य के कुछ तकाजे होते हैं। स्वराज्य के पश्चात् माउंटबेटन केवल एक साल के लिए हमारा गवर्नर जेनरल रहा। लेकिन यदि कोई यह तुलना करे कि स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और माउंटबेटन में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो यह सवाल खड़ा नहीं होता है। स्वराज्य का यह तकाजा है कि देश का राष्ट्रपति इसी देश का होना चाहिए। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। माउंटबेटन बहुत अच्छा है, लेकिन वह इंग्लैण्ड में किसी पद पर रह सकता है।

वैसे ही हमारी सेना का प्रमुख आज सर क्लाड आचिन्लेक नहीं रह सकता है। यह सवाल तो खड़ा ही नहीं होता है कि जेनरल चौधरी, जेनरल करिआप्पा और सर कलाड आचिन्लेक में से गुणवत्ता किस में ज्यादा है। यह स्वाराज्य का तकाजा है कि अब इस देश का सेनापति कोई जेनरल करिआप्पा या जेनरल चौधरी या जेनरल थोरट हो। इस के लिए कोई पर्याय नहीं होता है।

वैसे ही यह स्वराज्य का तकाजा है कि देश का व्यवहार स्वभाषा में हो। इस के लिए कोई पर्याय नहीं होता है। अब हिन्दी कोई बड़ी विकसित, बड़ी समृद्ध और साहित्यिक दृष्टि से मौलिक भाषा है, इस कारण वह स्वभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हुई। सब का मूल स्रोत संस्कृत होने के नाते काश्मीरी से ले कर मलयालम तक हर भारतीय भाषा उतनी ही समृद्ध हो सकती है और है। हिन्दी

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

को इसलिए स्वीकार किया गया कि अपने इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी भाषा को समझते हैं। मुझे अनुभव है कि 1930-31 के दिनों में जब मैं स्वयं प्रभात-फेरी में जाया करता था, तो कन्नड़-भाषी होने पर भी हम लोग ये हिन्दी गीत गाते थे, "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" और चरखा चला-चला कर लेंगे, स्वराज्य लेंगे। उस समय हमारे मन में यह भाव पैदा नहीं हुआ कि कन्नड़ भाषी होते हुए हम हिन्दी का गीत क्यों गायें। हम को लगता था कि टूटी-फूटी ही क्यों न हो, हिन्दी बोलना ही देश-भक्ति है। वह कपड़ा चाहे कितना भी मोटा या घटिया क्यों न हो, खद्दर पहनना देश भक्ति है; देश के बारे में गीत गाना देशभक्ति है। बचपन में, पाठशाला में पढ़ते समय भी, हमारा यह जो भाव था मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी आने के पश्चात् इन बीस सालों में हम लोगों ने इस के सम्बन्ध में जो कुछ किया, आज का यह विधेयक उस में हमारी असफलता का परिचायक है।

क्या इन बीस सालों में हम हिन्दी को प्रचलित करने और लोकप्रिय बनाने का जिम्मा केवल चलचित्र-पट पर नहीं छोड़ बैठे? अर्थात् देश भर में हिन्दी के चलचित्र, फ़िल्म्ज़ बनें और उन को देख कर लोग हिन्दी सीखें? क्या इस के आगे जाने की हमने कोशिश की? खैर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ अच्छे सुझाव दिये गये थे जैसे तंत्रकी और शासकीय पारिभाषिक शब्दावली एक हो, हम ने उन पर अमल नहीं किया। आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे दिल में, मन में, हृदय में अपने देश के बारे में एक उत्कट भावना नहीं होगी, तो वह प्रत्यक्षतः प्रकट व्यवहार में नहीं आ सकती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लैंड में जा कर पढ़ें, तो कहना पड़ता है कि विद्या का मतलब हमारी समझ में नहीं आया।

भारतीय विचारधारा के अनुसार "सा विद्या या विमुक्तये"। मुक्ति इस देश का ध्येय है। किसी का बंधन, किसी की दासता, यह विद्या वाले का लक्षण नहीं हो सकता है। विद्यावान् वही है, जो इस से मुक्त है। मैं कहना चाहता हूं कि जितेन्द्रिय होना इस देश का ध्येय है। रसना और वासना तक का भी जो गुलाम नहीं बनना चाहता, रसना और वासना को भी काबू में रख कर जो मुक्ति पाना चाहता है, वह अंग्रेजी की दासता और गुलामी सहन करे, यह नहीं हो सकता है। अंग्रेजी अच्छी है या बुरी, यह सवाल नहीं है। इस में तुलना की बात आती ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोई भाषा है या नहीं।

हमारी हर भाषा को समृद्ध करने वाला संस्कृत का बड़ा विशाल महासागर देश हमारे में है। इसके बल-बूते पर हम हजारों वर्षों से हिन्दुस्तान में एक सुसंस्कृत दर्शन दे कर जीवन का आदर्श खड़ा कर के रहते आये हैं। हमारे कई कांग्रेसी मित्रों ने देश की एकता की बात कही। मैं उस का स्वागत करता हूं। देश बहुत बड़ा है, किन्तु इस देश में भाषायें भी कई चलती हैं, इस देश में कई जातियां हैं, इस देश में कई पन्थ हैं। इतना होने के बाद भी एक हजार साल पहले केरल में कालड़ी में पैदा हुए आचार्य श्री शंकराचार्य को कभी यह नहीं लगा कि पूरे देश भर में स्थान-स्थान पर मठों की स्थापना करने में दिक्कतें या अड़चनें आयेंगी। वे नहीं आईं। इन को यह नहीं लगा कि मैं यहां से वहां कैसे जाऊं, वहां से यहां कैसे जाऊं।

मुझे आप क्षमा करें, बार-बार दक्षिण वालों को दोष दिया जाता है, लेकिन दक्षिण वालों की बदनामी क्यों की जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। दक्षिण वाले अंग्रेजी के पक्ष में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भी मद्रास में राजभाषा के रूप में तमिल को ही स्वीकार किया है, शिक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को ही स्वी-

कार किया। बंगाल में भी वहां के लोगों ने अपनी उन्नत, विकसित और समृद्ध भाषा बंगला को ही राजभाषा और शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, अंग्रेजी को नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी राजभाषा के और विद्या के माध्यम के रूप में कन्नड़, तेलगू, उड़िया और मलयालम आदि को ही स्वीकार किया गया है। अपने देश में हर एक भाषा समृद्ध है। इस लिए मैं दक्षिण वालों को दोष देने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर मैं भी तो दक्षिण से आता हूं।

किन्तु सवाल यह है कि भाषा भाव को प्रकट करती है। कोई भाषा भाव को प्रकट करने की क्षमता रखती है या नहीं, यह सवाल है। भाषा क्या प्रकट करता है? आत्मा को प्रकट करती है, इस को भूलना नहीं चाहिए। जैसे, यदि हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना हो, तो हम कहते हैं, "ही इज डेड"। किन्तु अपनी भाषा में हम कहेंगे, "उस का देहान्त हुआ" क्योंकि अपने विचार के अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा मरती नही है। ही इज नेवर डेड, आई एम नेवर डेड,—देहान्त होता है, देह जाता है : भाषा आत्मा को प्रकट करती है। ज्यों-ज्यों हम दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं, त्यों-त्यों हम अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं। जैसे, अंग्रेजी का प्रयोग करते करते हम कहने लगे हैं, "बोन्ज फ़ार दि लेट-कमर्ज," यानी जो देरी से आयेगा, उस को मांस नहीं, हड्डी मिलेंगी। यह यहां का रिवाज नहीं है। हमारे यहां कहते हैं, "अतिथिदेवो भव" इसी लिए भगवान् श्री कृष्ण ने रात के बारह बजे द्रौपदी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। हमारे यहां कोई जब भी आयेगा, तो उस को भोजन मिलेगा। अगर देरी से आयेगा, तो दूसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा अगर उस से भी देरी से आयेगा, तो तीसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा। हमारे यहां बोन्ज फ़ार दि लेट-कमर्ज नहीं है। अपनी आत्मा को जो भाषा प्रकट नहीं कर पाती है, उस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाषा आत्मा को प्रकट करती है। उस में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस लिए भारत की कोई भी भाषा क्यों न हो, आसेतु हिमाचल, वह भारत की आत्मा को प्रकट करती है। श्री चव्हाण ने जो प्रस्ताव रखा है, उस में "काम्पोजिट कल्चर" का जिक्र किया गया है। भारत में जो विविधता है, अकारण ही उसके बारे में यह भ्रम हो गया है कि वह एक "काम्पोजिट कल्चर" है। हर देश के लिए एक संस्कृति होती है। कोई पूछे कि यह राष्ट्र है कैसे? हमारे और आप के बीच में कौन सा सम्बन्ध है? क्या समान्नता है? वह है हमारी राष्ट्रीयता। वह सिद्ध करती है हमारी संस्कृत। हमारे राजदूतों के लड़के मास्को में पैदा हों या वाशिंगटन में उन की संस्कृति रूसी या अमेरिकी नहीं बनती। वह भारतीय रहती है। क्यों रहती है? मां बाप का जीवन दर्शन ले कर यदि लड़का आये तभी हम कहते हैं कि वह भारतीय है। तभी हम कहते हैं कि वह हिन्दुस्तान का है। वह तो इस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु यह संस्कृति विविधता में विश्वास रखती है। Unity should never be misunderstood for uniformity सब को एक सांचे में ढालने का यहां का काम नहीं है। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल जो होता है उस की हर पंखुड़ी से खुशबू निकलती है। पंखुड़ियां हजार हों लेकिन खुशबू एक निकलती है। यहां भाषा अनेक हैं भाव एक है। पंथ अनेक हैं परमात्मा एक है। आंखें दो हैं दिखता एक है। कान दो हैं सुनाई एक देता है। हाथ दो हैं कृति एक है। पांव दो हैं गति एक है। ऊपरी दिखने वाली जो विविधता है उस के अन्दर छिपी हुई मौलिक एकता को ले कर अगर हम चलेंगे तो आसेतु हिमाचल तक देश के अन्दर एकता भरी हुई है। यह एकता कई हजार वर्षों की संस्कृति के जरिए हमारे पूर्वजों ने दी है। भगवान श्री शंकर कैलाश के ऊपर बैठे है और माता पार्वती कन्या कुमारी में तप करने बैठी हैं कि विवाह करूं तो भगवान श्री शंकर से। पार्वती परमेश्वर के नाम पर

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

तपस्या करती हुई बैठी है। पूरे देश की एकता की कल्पना जिन महानुभावों ने की उस के दर्शन से, उस की केवल स्मृत्ति से मस्तक विनम्र होता है। उन्होंने देश को एक रखने की कोशिश की है। भाषा जाति सम्प्रदाय रहन-सहन खान-पान यह सब कुछ अलग होने के बाद भी हम एक हैं। जब हम यह कहते हैं कि खायें क्या ? इडली खायें, डोसा खायें, बड़ा खायें, कचौड़ी खायें या रोटी खायें तो इस का कोई सवाल नहीं है। जब तक हम को यह लगता है कि मैं जो कुछ खा रहा हूं वह जीवन का यंत्र चलाने के लिए खाता हूं, अहोरात्र यह जो एक यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ की सगिधा के रूप में खाता हूं, यह भाव जगत जब तक एक है, तब तक झगड़ा पैदा नहीं होता।

भाषा के नाम पर झगड़ा पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। किन्तु दुर्दैव से 20 वर्षों में वह एकता का भाव नहीं आया। मन में जो एक प्यार था अंग्रेजी भाषा के लिए, उस प्यार के कारण, उस मोह के कारण देश भर में वह वातावरण पैदा नहीं किया गया। आज जो तर्क दिए जाते हैं, मुझको याद आता है अंग्रेजी राज के वास्ते यही तर्क दिए जाते थे। जब अंग्रेजों का शासन यहां कायम हुआ यही कहा जाता था कि अंग्रेजों ने शांति लायी वरना यहां बहुत गड़बड़ियां थीं और ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने में काशी से लकड़ी में सोना बांध कर आप काश्मीर तक घूमो या नीचे रामेश्वरम तक घूमो कोई उस को छूएगा नहीं। Not even Morarjibhai would dare touch under the Gold Control Order इतनी शांति इस देश के अन्दर उन्होंने पैदा की। कहने लगे कि अंग्रेजी राज अच्छा है और जब यहां अंग्रेजी राज को हटा कर स्वराज्य की मांग होने लगी तो यही विचार सामने आया कि :

Whether you want a good government or self-government.

स्वराज्य चाहिए या सुराज्य चाहिए ? आम भाषा चाहिए या अन्तर्राष्ट्रीय भाषा चाहिए? कोई कोई कहने लगे कि स्वराज्य चलाने की क्षमता भी है ? तो लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को आगे बढ़ कर जवाब देना पड़ा कि इस देश के अन्दर स्वराज्य चलाने के लिए आई० सी० एस० अफसरों की जरूरत नहीं है। देश धर्म के नाते आपत धर्म के नाते 22 साल की विधवा स्त्री झांसी की रानी हाथ में हथियार लेकर अंग्रेज से लड़ने बाहर निकल आई तो ब्रिटिश जनरल भी देखता रह गया। तो वह देहरादून के किसी मिलिटरी कालेज में पढ़ी हुई नहीं थी। स्वराज्य के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य प्राप्त किया, अष्ट प्रधान मंडल बनाया तो क्या उन्होंने लाक आन डेमोक्रेसी पढ़ी थी ? उस की कोई जरूरत नहीं है। तो उस समय जो तर्क दिए जाते थे कि आप स्वराज्य नहीं चला सकते क्योंकि आपके पास इतने आई० सी० एस० आफिसर नहीं हैं, आपके अंदर इतना सुधार नहीं हुआ है, इतनी शिक्षा नहीं हुई है, यह नहीं हुआ है, वह नहीं हुआ है, वही तर्क आज भी दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी चली जायगी तो क्या होगा ? तो अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ ? वही तर्क आज भी है। और कहीं कहीं तो यह भी बताया जाता है कि जब तक हिन्दी विकसित नहीं होगी तब तक उस को स्वीकार नहीं किया जायगा। एक बड़े महानुभाव ने कहा था, मैं उन का नाम नहीं लूंगा, जब कि पहले पहले विधवा विवाह लोग करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब तक वह प्रचलित हो कर लोकप्रिय नहीं होता तब तक किसी को नहीं करना चाहिए। तो आज हम यदि यह समझें कि हिन्दी को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह समृद्ध नहीं हो जाती, जब तक विकसित नहीं हो जाती, तो यह भी वैसी ही बात है। जब उस का उपयोग होने लगेगा जैसे कि आज यह बहस आई कि शैल का मतलब हिन्दी में क्या होता है ? 'होगी'

होता है 'रहेगी' होता है ? क्या होता है ?

Every word has got a connotation and a denotation; it denotes something, it connotes something.

उस का आन्तरिक भी एक विचार रहता है, एक बाहर का भी विचार रहता है । भाषा जैसे जैसे व्यवहार में आती जाती है वैसे वैसे शब्द का अर्थ निश्चित होता जाता है । उसी दृष्टि से शब्द का प्रयोग होने लगता है । तब जा कर उसी शब्द को लेकर हर एक चलता है । इसीलिए जब भाषा प्रयोग में ही नहीं आयेगी और जब बिलकुल विकसित और समृद्ध हो जायगी तब उसका विचार करेंगे, यह अगर तर्क है तो यह तो बिलकुल वैसा ही है जैसे किनारे पर बैठ कर यह सोचना कि जब तैरना आ जायगा तभी मैं पानी में पैर रखूंगा। आप हिन्दी को स्वीकार करें देशभक्ति के भाव से ।

कोई भी चीज जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे प्रेरणाएं होती हैं । एक प्रेरणा होती है धर्म की, कर्त्तव्य की । दूसरी प्रेरणायें हैं अर्थ और काम की । यानी अर्थ और काम के लिए भी आदमी बहुत कुछ करता है । यह भाषा कई लोगों ने अर्थ और काम के लिए सीखी है । आज चलचित्र पर आप देखेंगे तो कई हमारी दक्षिण की जो अभिनेत्रियां हैं वह हिन्दी में काम करती हैं, हिन्दी में अग्रसरत्व उन्होंने प्राप्त किया । जब उन को पता चला कि तमिल तेलुगू और कन्नड़ में काम करने से बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा तो संगम जैसे चित्रपट में काम करने वाली नायिका ने हिन्दी में काम किया और वह दक्षिण की ही हैं । तो लोग भाषा को सीखते तो हैं, भाषा को पसंद भी करते हैं किन्तु प्रेरणा अर्थ और काम की रहती है । इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि

If you want to learn a new thing, either you live alive or you marry a wife.

पुराने जमाने में योरप का इतिहास हम देखें तो ऐसे ही होता था । इंगलैंड और जर्मनी का भी जो संबंध रहता था तो क्या होता था ? जर्मनी से जो आते थे राजा वह क्या अंग्रेजी पढ़ कर आते थे ? यानी आपस में शादी चलती थी । अपने देश में भी चलती थी । अपने देश के राजा महाराजाओं का इतिहास आप देखें तो वहां भी आप को पता चलेगा कि शादी के बाद पत्नी की भाषा पति को या पति की भाषा पत्नी को सीखनी पड़ी है । सीखते थे । क्यों ? प्रेम । इसके कारण लोग बहुत बार भाषा सीखते हैं । मैं एक बार आन्ध्र में प्रवास कर रहा था । वहां एक साहब मिले, वह बोले कि बढ़िया घोड़ा देखोगे ? मैं ने कहा चलो । मैं देखने के लिए गया । घोड़े को सामने बुलाया यह कह कर कि बेटा सामने आओ । मुझ को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह कैसे हिन्दी बोलते हैं ? फिर वह घोड़ा सामने आया तो बोले बेटा मेहमान आया है सलाम करो तो उसने गर्दन झुका कर सलाम किया । तो मैंने पूछा कि चौधरी साहब, आप तेलुगू भाषी होते हुए घोड़े के साथ हिन्दी में कैसे बोलते हैं ? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थयात्रा पर गया था । यह घोड़ा मुझे देखने को मिला । मुझे लगा कि यह जो बताया जाता है वह करता है इसलिए मैं ने खरीद लिया । घर आकर पता चला कि इस को केवल हिन्दी समझ में आती है तो मैं ने यह सोचा कि अब घोलुड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय मैं स्वयं हिन्दी सीख लूं तो अच्छा है । तो घोड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय उन्होंने स्वयं हिन्दी सीखी । यानी आदमी घोड़े को प्यार करता है तो घोड़े की भाषा सीख लेता है । यदि हम भारत मां को सही अर्थों में प्यार करें तो क्या भारत की भाषा नहीं सीखेंगे ? सवाल यह है कि हम भारत मां को पिछले 20 साल में प्यार करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं । इसलिए हर मामले में विदेशी चीजें हमें प्रिय हो रही हैं । विदेशी रहन सहन, विदेशी व्यवहार और इसलिए विदेशी भाषा में भी क्या लगता है ? जब सब कुछ विदेशी से रहे हैं तो विदेशी भाषा ने ही क्या

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

किया है ? यह वजह है इस के पीछे । मैं कहना चाहता हूं कि हजारों हजार साल जिस देश के अन्दर एक सुसंगठित जीवन दर्शन के नाते हम लोग एक हो कर रहते आये हैं । कई हजार संक्रमणों को परास्त करते हुए, आज भी हम खड़े हैं और आगे चलकर भी हम खड़े रहना चाहते हैं । इसलिये कोई यह कहे कि दक्षिण वालों को यह नहीं आता, वह नहीं आता, मैं उस को मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं । कोई भी भाषा हो उस का ठीक ढंग से प्रचार हो । मैं अभी केरल गया था । अर्नाकुलम, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में हिन्दी का प्रचार बहुत अधिक है । केरल से तो हिन्दी की एक मासिक पत्रिका भी निकलती है । वास्तव में हम लोगों को उसे गौरव दे कर के प्रशस्ति देकर आगे बढ़ाना चाहिए । उस की लोकप्रियता को पूरे देश भर में बढ़ाने का काम बहुत आवश्यक है । किन्तु सब से बुरी बात तो यही होती है, विदेशी शासन के खिलाफ जब हम झगड़ा करते हैं तो इसी लिए · · · · ·

SHRI NAMBIAR : Do it by love, not by force.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : That is what I am saying. I am saying the same thing.

तो देश की भक्ति सारे प्रदेश के अन्दर एकता का भाव—इन बातों को लेकर वास्तव में यह भाषा की समस्या कोई कठिन नहीं है । अंग्रेजी की दास्ता जो है, यह दास्ता सब से ज्यादा खराब होती है, यह स्वत्व के खिलाफ है । यह विदेशी आक्रमण जो आता है, विदेशी राज्य जो रहता है, उस में खराबी यही है कि वह धीरे-धीरे हमारे मन का जो भाव है वह उस भाव को खत्म कर देता है । कोई कहे—कि खत्म हो तो हो, क्या है ? लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक का विकास हो—तो बंधन में विकास नहीं होता, विकास मुक्ति में होता है । जब मैं अपनी मातृभाषा के साथ नहीं बंध सकता, जब दूसरी भाषा रखनी पड़ती है, तो मेरा पूर्ण विकास नहीं होगा । इसलिये हर देश में स्वभाषा में व्यवहार होता है ।

अब स्वभावतः यह बात जरूर आयेगी कि हमारे देश में विभिन्न भाषायें हैं, परन्तु जैसे संस्कृत हमारी सब से पुरानी भाषा है और लिपि चाहे अलग हो, परन्तु वर्ण-माला अलग नहीं है, सब का श्रोत संस्कृत है, केवल तमिल में कुछ वर्ण कम हैं, परन्तु वहां भी क–ङ, च–ञ, ट–ण, त–न, प–म, उसी वर्ण माला से हैं, तो जब एक ही श्रोत को लेकर हम इस देश में खड़े हैं, तो फिर इस में कोई कठिनाई नहीं आती है ।

मेरा विरोध इस से इस लिये है कि जो विधेयक लाया गया है, उस के अन्दर कोई योजना नहीं है बातें तो हम बहुत करते हैं, प्लानिंग की बात चलती है, परन्तु स्वदेश में स्वभाषा के व्यवहार के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि न दे कर इस को बीच में ही छोड़ दिया है । इस लिये यह विधेयक स्वयं जो मूल संविधान बनाने वालों की भावनायें हैं, उन के विपरीत है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाय । 1963 के पहले जो हुआ है, उस में तो खुली छुट्टी है, उस में अवधि भी बिलकुल बांधी नहीं है, लेकिन इस विधेयक के कारण तो एक छोटा सा नागालैंड यदि पूरे भारत पर अंग्रेजी थोपने का काम करे, तो कर सकता है । गांधी जी ने साफ कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं, इस का मतलब यह है कि हम अंग्रेजी राज्य के खिलाफ हैं । जब हम कहते हैं कि अंग्रेजी हटाओ, तो उसका मतलब यह नहीं है कि देश से अंग्रेजी को निकाल दो । हमारा मतलब है कि उस को सिंहासन से हटाओ, कालिज के स्थान पर लाइब्रेरी में बैठाओ । उस का स्थान वहीं पर रहे, हम और आप आजाद हैं, किन्तु भाव खोल

कर दुनिया की तरफ क्यों देखें, हर एक के लिये वह महाद्वार खुला है, उस के द्वारा हम सब को देखें, सब से साथ व्यवहार करें, लेकिन स्व-व्यवहार के लिये हिन्दी और देश की सभी भाषाओं को लेकर चलना होगा, हमारे लिये देश की सब भाषायें एक रूप हैं, केवल सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करना होगा । हिन्दी को लोकप्रिय करने के लिये यदि हम अब तक कार्य करते तो क्या सफलता नहीं मिलती और क्या यह विधेयक लाकर हिन्दी जल्दी आयेगी ? नहीं आयेगी, आपकी मंशा ठीक नहीं दिखती, 20 साल तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, अब वे क्या करेंगे—यह कहना बहुत मुश्किल है । इसलिये हम कहते हैं कि समय निर्धारित करो, इस विधेयक से आप बंधते नहीं हैं, बल्कि यह विधेयक तो अंग्रेजी को बांधने का काम करता है, इस लिये इस को वापस लीजिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजभाषा संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है, जिस शक्ल में यह विधेयक आया है, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मैं और मेरे साथ बहुत से कांग्रेस जन होंगे, जो इस शक्ल में इसको अपनी मन्जूरी देने में परेशानी पायेंगे ।

यह भी बहुत खेद की बात है कि 20 साल बाद ऐसा विधेयक हमें यहां लाना पड़ा । इस में यही प्रतीत होता है कि जो काम करने के लिये हम ने प्रारम्भ किया था, उस काम में हम नाकामयाब रहे और अगर हम लोग सम्पूर्ण रूप से चेष्टा करते तो आज भारत काफी हिन्दीमय हो जाता और भारत के दूसरे प्रान्तों में भी लोगों में हिन्दी के प्रति प्रेम होता और लोग सीखते ।

मुझे याद है बहुत पुराने दिनों की बात है, मैं मद्रास में पहले-पहल गई थी, शायद 30 साल पहले गई थी, जब महात्मा जी वहां गये थे, और वहां की हिन्दी प्रचार समिति ने एक सभा रखी थी । उस सभा में कितने तमिल भाइयों और बहनों ने उनसे अपना प्रमाणपत्र लिया था और उस समय उन लोगों में कितना उत्साह था । उस उत्साह का कारण क्या था ? गांधी जी प्रेम से लोगों के अन्दर हिन्दी का प्रचार करवा रहे थे । उस समय क्योंकि हम लोग गुलाम थे, हम लोग हिन्दी को अपनी भारतीय भाषा होने में गौरव समझते थे । उस समय हम लोग अंग्रेजी भाषा को जबरन बोलते थे, क्योंकि हम समझते थे कि इससे हमें काम लेना है—ऐसी भावना थी । यह बात सही है कि हमारा राष्ट्र एक फैडरल स्टेट है, यहां नाना भाषायें हैं, नाना मत हैं, नाना प्रकार की वेशभूषायें हैं, नाना प्रकार के रस्मो रिवाज हैं, लेकिन इतना वैषम्य होते हुए भी एक समन्वय है—जैसा कि मुझ से पहले बहुत सुन्दर ढंग से जोशी जी बता रहे थे । हमारी एक संस्कृति है, उसी से हम हिन्दुस्तान हैं । हमारे देश की इतनी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी संस्कृति इतनी विकसित है, इतना होते हुए भी कोई एक भाषा इस देश की भाषा न बन सके, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता की कोई कद्र नहीं है, इस का कौड़ी का मूल्य नहीं है ।

मैं आपको बतलाऊं, अभी कल ही विजय लक्ष्मी जी बतला रही थीं, उन के साथ क्या क्या पेश आया था । जब वह रूस में गई और जब वह अपना क्रिडेन्शल पत्र देने लगीं तो उन्होंने बहुत लांछित किया कि तुम कैसे जंगली हो, क्या तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है । मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसा ही बीता था—मैं जर्मनी में घूम रही थी । हम लोगों को अंग्रेजी लिखने की आदत पड़ी हुई है, मैं अपनी नोट बुक में अंग्रेजी में लिख रही थी, वहां के एक व्यक्ति ने देख लिया—उन्होंने पूछा—क्या बहिन, आप लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है, जो आप अंग्रेजी में लिख रही हैं, मेरा सिर शर्म से झुक गया ।

SHRI NAMBIAR : She could have done it in Hindi.

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं अपना दोष बता रही हूं । तो इस मुल्क की इतनी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, इतनी भाषायें होने के बाद भी कोई एक भाषा इस देश की भाषा न हो सके, जिस के द्वारा हम आपस के मनोभावों को दूसरों को प्रकट कर सकें, जिसको लिंक-लैंग्वेज कह सकें—तो यह बड़े शर्म की बात है, तौहीन की बात है । कोई न कोई भाषा जरूर बन सकती है, जो हमारी देश की हो ।

20 साल पहले हिन्दी के पक्ष में क्यों फैसला लिया गया था ? हिन्दी के पक्ष में इसलिये फैसला लिया गया था—जैसा हमारे जोशी जी ने बताया—इस लिये नहीं कि सब से ज्यादा विकसित भाषा हिन्दी थी, इसलिये कि हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में हिन्दी बोली जाती थी । इस लिये समझा गया कि जब देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं, इस लिये इसको राज भाषा बनाया जाय । अगर हम देखते कि तमिल भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं, तो हम तमिल के पक्ष में ही फैसला करते । हिन्दी की तरफदारी के लिये हिन्दी को नहीं बनाया, वास्तविक परिस्थितियों को देख कर ही यह फैसला हुआ कि सब से ज्यादा संख्या में लोग हिन्दी को बोलते हैं, इस लिये हिन्दी को बनाया गया ।

मैं अपने तमिल और दक्षिण के भाइयों से एक विनती करना चाहती हूं । हम लोग इतने होशियार हैं, हिन्दुस्तान भर के लोग, कि अंग्रेजी भाषा को हम ने अपना लिया और अंग्रेजी को अपनाने के बाद हम में कुछ इतना जोश चढ़ गया कि हम उस को मातृ भाषा ही समझने लगे और उसका इस्तेमाल करने में बड़ा गौरव समझते हैं और अपनी भाषा को ठीक प्रकार से बोल भी नहीं सकते हैं । मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम अंग्रेजी सीख सकते हैं—जब कि अंग्रेजी का हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं से कोई मेल नहीं है, हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं का तो कुछ हद तक मेल भी है, तमिल भाषा जो संस्कृति से अलग मानी जाती है, उस में अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं, क्या उसको नहीं सीख सकते ? तमिल, तेलुगू तथा दक्षिण की अन्य भाषाओं को लीजिये, वहां के कवियों ने, मनीषियों ने लेखकों ने अपने लेखों में, कविताओं में संस्कृति के अनेकों शब्दों का प्रयोग किया है । उन्होंने अपनी भाषा के साथ संस्कृत का व्यवहार किया है—त्यागराज, दीक्षितार, श्याम शास्त्री —आप इनकी कृतियों को पढ़िये, जब आप इनकी कृतियों को सुनते हैं, तो उन में बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो समझ में आते हैं, संस्कृत को उन्होंने बहुत हद तक अपनाया है । ठिकाना, रामराज्य भूषण, विश्वनाथ सत्यनारायण—इन सब को आप सुनें तो आप देखेंगे कि इनकी कृतियों में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग है । इसके अलावा दक्षिण में जो प्रबन्धम् स्तुति वैष्णव गाते हैं, उनमें संस्कृत भरी पड़ी है । तो वह वे लोग समझते हैं—इसका मतलब यह है कि सारा भारत संस्कृत भाषा से कुछ न कुछ वाकफियत, परिचय रखता है । जब दक्षिण के भाई इन कृतियों को समझते हैं, तो इस का मतलब है कि संस्कृत से उन का परिचय है और हिन्दी में तो संस्कृत भरी पड़ी है । कम से कम हिन्दी और तमिल, हिन्दी और तेलुगू, हिन्दी और कन्नड़, हिन्दी और मलयालम के कुछ न कुछ शब्दों से अवश्य परिचित हैं, परन्तु अंग्रेजी का कौन सा शब्द उन की भाषा से मिलता है । अंग्रेजी के दो-चार शब्द मामा, पापा—माता और पिता से थोड़े बहुत मिलते हैं, परन्तु जब हम इतने होशियार हैं कि हम अंग्रेजी को इतनी भिन्नता हुए भी सीख सकते हैं और समझते हैं कि अंग्रेजी के सिवाय दूसरी लिंक लैंग्वेज नहीं बन सकती, क्या हिन्दी को उस से कहीं आसानी से नहीं समझ सकते ? मैं बहुत विनती से उन से कहना चाहती

हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे प्रयास करें तो आपने जितनी बढ़िया अंग्रेजी सीखी है, (बजाय इसके कि हम गलत अंग्रेजी बोलते हैं), उससे कहीं ज्यादा अच्छी हिन्दी हम बोल पाएंगे, और जल्दी सीख पाएंगे ।

हां यह बात सही है कि गलतियां हमारी हैं, हमारी सरकार की हैं । गलती हमारी पार्टी की है गलती सब पार्टियों की है । अगर विगत २० सालों में हम ने हिन्दी का प्रचार और प्रसार जैसे करना चाहिए था किया होता, जैसे लोगों को हिन्दी सिखाने का प्रयास करना चाहिए था ऐसा किया होता तो आज हमें यह नौबत देखने को नहीं मिलती ।

मुझे यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे कुछ ऐसे हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी के लिए अधिक उग्र तरीके से प्रचार किया । बहुत उग्र तरीके से प्रचार करना भी अच्छा नहीं होता । अति उग्र जब हो जाता है तो उस की प्रतिक्रिया भी उग्र भाव से होती है । इन्हीं सब कारणों से आज एक परिस्थिति ज़रूर देश में हो गई है जहां एक रैजिस्टैंस उस के लिए हो गयी है कि अहिन्दी भाई यह सोचने लगे हैं कि हम हिन्दी नहीं सीखेंगे चाहे कुछ क्यों न हो जाये । उस रैजिस्टैंस की भावना को उन के बीच में से उड़ा देने के लिए उस पृष्ठभूमि में आज यह विधेयक लाया गया है । आज देश के सामने एक परेशानी है, दिक्कत है और मैं समझती हूं कि अगर आज हम कहें कि हिन्दी भाषा सीखने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए, अहिन्दी भाषा भाषी थोड़ा समय और ले लें तो उस में कोई अनुचित बात नहीं होगी । इस मकसद से अगर यह विधेयक लाया गया है तो वह ठीक ही किया गया है ।

राजभाषा संशोधन विधेयक में बहुतसी बातें ऐसी हैं जो हमें पसन्द नहीं हैं और उन के लिए हम ने संशोधन मूव करने का नोटिस भी दिया हुआ है । जब इस पर बारीकी से बहस चलेगी तो मैं उन पर डिटेल में चर्चा करूंगी । अगर वह संशोधन स्वीकार नहीं किये जाते हैं तो मेरी समझ में वह लोग जो हिन्दी भाषा सीख रहें हैं उन के साथ हम अन्याय करने वाले हैं । एक तरफ़ जहां यह ज़रूरी है कि हम प्रेम से अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी अपनाने की तरफ़ खींचें, जबरदस्ती करने से नुकसान हो जायेगा वहां हमें यह भी देखना होगा कि जहां-जहां लोगों ने हिन्दी भाषा को अपना लिया है, उन स्टेटों में जहां युनिवरसिटीज़ में हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई होने लग गई है, जहां पर कि लड़के हिन्दी में पढ़ने लग गये हैं क्योंकि हम ने २० साल पहले फैसला किया था कि हम सारे देश में राजभाषा हिन्दी को करेंगे उस सरकार के फैसले के अनुसार वह बेचारे हिन्दी पढ़ने लगे तो आज बैठे-बैठाये उन से कहा जाय कि तुम हिन्दी में अगर पत्र-व्यवहार आदि काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर यह पैनाल्टी लगेगी कि उस हिन्दी पत्र के साथ साथ तुम्हें उस का अंग्रेज़ी अनुवाद भी नत्थी करके भेजना पड़ा करेगा तो यह उन के साथ अन्याय होगा । आज इस विधेयक में जो झलक हमें दिखाई पड़ रही है और जिसके लिए हम लोगों को एतराज़ है वह झलक यही है कि जो यह कहा जा रहा है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, मतलब पहली राज-भाषा हमारी हिन्दी है और दोयम नम्बर यह अंग्रेज़ी एसोसिएट भाषा है, सह भाषा है मगर वास्तविक रूप जो अमल में इस में दिया जा रहा है.....

SHRI NAMBIAR. If you write it . .

SHRI SHEO NARAIN: What is this?

SHRI NAMBIAR: I am not objecting. If you write it in Hindi, without English translation, we are unable to understand it.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: I will explain that. मैं यह कह रही हूं कि जहां हिन्दी की प्रगति हो गई है उन के ऊपर जबरन अंग्रेज़ी मत डालो । अब नम्बियार साहब ने सवाल पूछा कि अगर आप हिन्दी में हमें बगैर उस के इंग्लिश ट्रान्स-

[श्रीमति सुचेता कृपलानी]

लेशन से लिखोगे तो हम उस को समझ नहीं सकेंगे और उस हालत में क्या होगा ? मैं उन की यह बात मानने को तैयार हूं कि आप को जब हम चिट्ठी आदि लिखेंगे, हम अगर दो ऐसी स्टेटों में खतोकिताबत चलायेंगे जहां एक स्टेट में हिन्दी नहीं होगी तो वहां "इंग्लिश शैल बी यूज्ड नौटविदस्टेंडिंग एनीथिंग, इंग्लिश शैल बी यूज्ड"। अगर आप अभी हिन्दी नहीं समझते तो हम इंग्लिश में आप को समझायेंगे । हम चाहते हैं कि अपनी मनोभावना हम आप को समझाएं । भाषा हमारी हिन्दी है । चिट्ठी हम हिन्दी में लिखें लेकिन आप चूंकि उसे समझ सकें इस के लिए हम तैयार हैं कि उसका अंग्रेजी तर्जुमा साथ में जब तक आप हिन्दी न समझ सकें तब तक भेजें । हिन्दी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है, दोयम भाषा है इसलिए अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के साथ हम हिन्दी भाषी लोग पत्र व्यवहार करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि आप हमारी बात समझ सकें और जब तक आप हिन्दी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हम अंग्रेजी में आप को समझायेंगे । मैं ऐसा अव्यवहारिक रुख नहीं अपनाना चाहती कि आप समझें या न समझें मैं हिन्दी में ही आप को अपनी बात लिखूं । लेकिन यदि एक हिन्दी भाषी राज्य केन्द्र से पत्रव्यवहार कर रहा है तो हिन्दी पत्र के साथ इंग्लिश ट्रान्सलेशन होना जरूरीन हीं होना चाहिए या केन्द्र में ही परस्पर विभिन्न मंत्रालयों में या सबार्डिनेट आफिसैज से जो आपसी पत्र व्यवहार, सरकारी कामकाज हो वह अंग्रेजी में हो ऐसा मैं नहीं मानती हूं । वहां अंग्रेजी में होने का कोई सवाल नहीं है । वहां हिन्दी में काम होना चाहिए । अगर जरूरत पड़े तो अलबत्ता उस का अंग्रेजी ट्रान्सलेशन दे दिया जाय । लेकिन वैसे सारा काम सैंटर के विभिन्न मंत्रालयों में आपस में हिन्दी में ही होना चाहिए ।

संविधान नें आज १७ ने वर्ष पूर्व हिन्दी को राजभाषा के सिंहासन पर बिठा दिया है लेकिन व्यवहार में देखा जाय तो वह सिर्फ नाम के लिए ही है और इस विधेयक से भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नाम के वास्ते तो कह दिया गया है कि हां हिन्दी तुम ऊपर सिंहासन पर बैठी हो लेकिन वह वैसे ही है जैसे किसी को फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग स्टेशन से बैठा तो दिया गया लेकिन दूसरे ही स्टेशन पर उसे फर्स्ट क्लास से उतार लिया गया हो । अब इस तरह का कैद रखना कि अगर कोई हिन्दी में चिट्ठी लिखने की जुर्रत करे तो साथ-साथ उस के उसे अंग्रेजी ट्रान्सलेशन जरूर देना पड़ेगा दोनों पार्टीज के लिए ट्रान्सलेशन देना जरूरी होगा तो इस से लोग हिन्दी में लिखने के लिए बजाय इनकरेज होने के डिस्करेज ही होंगे । हांलाकि हम यह कहते हैं

Hindi is our main language. Hindi is our official language, we accept it.

इस पर भी जब तक अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते थोड़े दिन तक उनको हिन्दी पत्रादि का अंग्रेजी तर्जुमा देने को हम तैयार हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा हिन्दी को महज नाम के वास्ते राजसिंहासन पर बैठाया गया है व्यवहार में हिन्दी नहीं है, जैसे मुझे यह कहने के लिए माफ़ किया जाय कि हमारे हिन्दुस्तान में औरतों को देवी की तरह सिंहासन पर पूजने के लिए रख दिया गया है हालांकि सब जानते हैं कि औरतों की क्या हालत है ? घर पर औरत को झाड़ू, बुहारू, आदि सारे काम करने पड़ते हैं और उनको वह आदर नहीं मिलता जो मिलना चाहिए । ऐसा दोरुखा व्यवहार हिन्दी के बारे में आज चल रहा है । वैसे तो हिन्दी इतनी भारी देवी है लेकिन अगर उसे तुम ने इस्तेमाल करने का साहस किया, हिन्दी में तुम ने पत्र व्यवहार आरम्भ किया तो वैसा करने वाला डिसएडवान्टेज (असुविधा) में रहेगा और अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देने के लिए उस पर पैनाल्टि लगेगी तो वह चीज ठीक नहीं है । इसीलिए मैं आज यह कहना चाहती हूं कि आज जो भावना है

कांस्टीट्यूशन में और जिस राजभाषा के पद पर हम ने हिन्दी को 18 साल पहले से ही बैठाया हुआ है उसे व्यवहार में भी मान्यता दिलायें। इन 18 सालों में भले ही अपनी नालायक़ी से अथवा और किन्हीं कारणों से हिन्दी को हम व्यवहार में नहीं लाये और उस को अपेक्षित स्थान नहीं दिला पाये हैं कम से कम आज इस विधेयक के जरिए यह भावना साफ़ दिखाई पड़नी चाहिए कि उत्तरोतर हम हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेजी जब तक कुछ लोगों के लिए वास्तविक जरूरत हो उतने वक्त तक उस को चलायें लेकिन उस के लिए हिन्दी को डिसऐडवांटेज (नुकसान) में नहीं डालना चाहिए। बाक़ी दरअसल इस हिन्दी और अंग्रेजी के पीछे सारे झगड़े की जड़ में नौकरियां हैं। हमारे भारतवर्ष में आज से नहीं मैकाले के समय से सरकारी नौकरी की महत्ता समझी जाती रही है, हर एक शिक्षित नौजवान नौकरी पाने के लिए उत्सुक रहता है और अलावा नौकरी करने के उस की दृष्टि और कहीं नहीं जाती है। हमारे देश के नौजवानों के विकास की प्रगति का कुछ भी फाटक खुला है तो वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति है। उस के ही सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए जैसा मैं ने कहा है इस हिन्दी अंग्रेजी के पीछे सारा झगड़ा यह सरकारी नौकरियां ही हैं। अंग्रेजी भाषा चूंकि वह किसी की भाषा नहीं थी वह एक विदेशी भाषा थी इसलिए सब को उस में बराबर डिसऐडवांटेज (असुविधा) थी लेकिन अगर हिन्दी हो जायेगी तो जाहिर है कि हिन्दी भाषा भाषी लोगों को औरों के मुक बले ऐडवांटेज (सहूलियत) हो जायेगी। They will have an edge over some दरअसल बात यह है, और उस में मैं मानती हूं कि कुछ सचाई भी है। इस के लिए हम ऐडजस्टमैंट कर सकते हैं लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि पिछले 20 साल में तो हम ने हिन्दी के लिए कुछ किया नहीं, हिन्दी हम लाय नहीं। अब 1965 के बाद आज यह मानना चाहिए कि कांस्टीट्यूशनल पोजीशन (संवैधानिक स्थिति) यह है कि हिन्दी इस देश की आफिशिएल लैंग्वेज है तब किसी न किसी तरीक़े से उसे सरकम्बैंट करके अंग्रेजी को ऊपर लाने की कोशिश की जाय। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी के साथ और एक निश्चित प्रोग्राम के साथ हम हिन्दी का विकास करें और व्यवहार में उसे लायें लेकिन यह शर्त्त आप ने क़ायम रखी कि अगर किसी ने हिन्दी में चिट्ठी लिखने की हिम्मत की तो उसे उस का अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देना पड़ेगा तो कोई हिन्दी में लिख कर क्यों इतना फजीता मोल लेगा और हिन्दी कोई नहीं सीखेगा, किसी को पर्वाह नहीं होगी और उस हालत के रहते कौन इतनी तकलीफ़ उठायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कल को अपना भाषण जारी रक्खें।

17.59 Hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to present the Tenth Report of the Business Advisory Committee.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka).

L93LSS(CP)/67—1010—2-3-68—GIPF.